इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2025—वैशाख 19, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2025

क्र. ई-5-913-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री हरजिंदर सिह, भाप्रसे, (2011), संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का दिनांक 28 अप्रैल से 2 मई 2025 तक पाँच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 26, 27 अप्रैल एवं 3, 4 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री हरजिंदर सिह, भाप्रसे, (2011), संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अवकाश अवधि में संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल का प्रभार श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे (2008), आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रुप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री हरजिंदर सिह, भाप्रसे, संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री हरजिंदर सिह, भाप्रसे, द्वारा संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे को सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री हरजिंदर सिह, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरजिंदर सिह, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2025

क्र. GAD-6-0013-2025-GAD-1-एक (GAD).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 मार्च 2025 द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 10 से 12 मार्च 2025 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई थी.

(2) उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, डी.आर.-कम-पी.पी.एस. के प्रस्ताव क्रमांक ए-1883 (दो-1-21-2024), दिनांक 19 मार्च 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 11 से 12 मार्च 2025 तक दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित स्वीकृत अवकाश उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत निरस्त किया जाता है. शेष यथावत् रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, उपसचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

क्र. एफ 1-1-10-07-2025-ब-2.दो—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल (ग्रामीण) को दिनांक 5 से 23 मई 2025 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं 3-4 व 24-25 मई 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में उनके यू. एस. ए. में अध्यनरत् पुत्रों की ग्रेजुएशन सेरेमनी में सम्मिलित होने के लिए सपत्नी यू. एस. ए. में अटलांटा एवं हयूस्टन की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है: —

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे.

(2) श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, के अवकाश अवधि में पुलिस उपमहानिरीक्षक, भोपाल (ग्रामीण) का कार्य प्रभार श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, पुलिस उप महानिरीक्षक (विसबल), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल (ग्रामीण) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2025

क्र. एफ 1 (ए) 59-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 7 से 13 मार्च 2025 तक, कुल सात दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार, आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2025

क्र. 1-1-1-0177-2025-ब-2(दो).—राज्य शासन, श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (रेलवे), मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 4 से 9 अप्रैल 2025 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक (रेलवे), मध्यप्रदेश, भोपाल का चालू कार्य श्री अरविन्द दुबे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (रेलवे), भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, (रेलवे), मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. एफ-1-1-1-0180-2025-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग एवं आर. टी. आई., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 24 से 28 मार्च 2025 तक, पाँच दिवस लघुकृत / परिवर्तित अवकाश एवं दिनांक 22-23 व 29-31 मार्च 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से दस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1-1-3-34-2025-ब-2.दो—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, उमनि / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो), मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 13 मई से 6 जून 2025 तक, पच्चीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10-12 मई व 7-8 जून 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में आस्ट्रेलिया (सिडनी) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है: —

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे.

(2) श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, के अवकाश अवधि में उमनि / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो), मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्य प्रभार श्री अंकित शुक्ला, रापुसे, पुलिस अधीक्षक (रेडियो), सीसीटीवी, पुलिस दूरसंचार मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उमनि / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो), मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2025

क्र. एफ 1-1-10-0010-2025-ब-2.दो—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे, महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 13 से 16 मई 2025 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं 10-12 मई 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भ्रमण हेतु बाली (इंडोनेशिया) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है: —

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे.

(2) श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे, के अवकाश अवधि में महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार प्रभार मो. शाहिद अबसार, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1-1-10-0011-2025-ब-2.दो—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती किरणलता केरकेट्टा, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (महिला सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 2 से 20 मई 2025 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित रोम, इटली, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल एवं स्विटजर्लेण्ड की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है: —

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे.

(2) श्रीमती किरणलता केरकेट्टा, भापुसे, के अवकाश अवधि में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (महिला सुरंक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार प्रभार सुश्री पिंकी जीवनानी, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (महिला सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरणलता केरकेट्टा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सहायक पुलिस महानिरीक्षक (महिला सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती किरणलता केरकेट्टा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती किरणलता केरकेट्टा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती किरणलता केरकेट्टा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जार्ती तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. एफ 1-1-1-0206-ब-2025-2-दो.—राज्य शासन श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, निदेशक, एफ. एस. एल., मध्यप्रदेश, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 4 से 10 अप्रैल 2025 तक, कुल सात दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत श्रीनगर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

1. श्री शशिकांत शुक्ला — स्वयं
2. श्रीमती मोनिका शुक्ला — पत्नी
3. कु. देवांषी शुक्ला — पुत्री

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न निदेशक, एफ. एस. एल., मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 1 मई 2025

क्र. 1-1-3-0010-2025-ब-2(दो).—राज्य शासन, श्री जगत सिंह राजपूत, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, योजना, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 21 अप्रैल से 2 मई 2025 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 18-20 अप्रैल व 3-4 मई 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री जगत सिंह राजपूत, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक योजना, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री संजय तिवारी, पुलिस महानिरीक्षक, योजना, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जगत सिंह राजपूत, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, योजना, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जगत सिंह राजपूत, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जगत सिंह राजपूत, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जगत सिंह राजपूत, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2025

पंजी. क्र. 1129-इक्कीस-ब(दो), 2025.—राज्य शासन, श्रीमती सुषमा सिंह, नोटरी, जिला टीकमगढ़ के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर समुचित जाँच उपरांत नोटरी नियम, 1956 के नियम-13 (ख) III के अधीन श्रीमती सुषमा सिंह, नोटरी, जिला टीकमगढ़ द्वारा ''नोटरी के सिद्ध हुए अवचार की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुसार'' ''चेतावनी'' की शास्ति अधिरोपित करता है.

पंजी. क्र. 1133-इक्कीस-ब(दो), 2025.—राज्य शासन, श्री कौशल किशोर भटट्, नोटरी, जिला टीकमगढ़ के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर समुचित जाँच उपरांत नोटरी नियम, 1956 के नियम-13 (ख) III के अधीन श्री कौशल किशोर भटट्, नोटरी, जिला टीकमगढ़ द्वारा ''नोटरी के सिद्ध हुए अवचार की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुसार'' ''चेतावनी'' की शास्ति अधिरोपित करता है.

पंजी. क्र. 1136-इक्कीस-ब(दो), 2025.—राज्य शासन, श्री गया प्रसाद पटेल, नोटरी, तहसील रामनगर, जिला सतना के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर समुचित जाँच उपरांत नोटरी नियम, 1956 के नियम-13 (ख) III के अधीन श्री गयाप्रसाद पटेल, नोटरी, तहसील रामनगर, जिला सतना द्वारा ''नोटरी के सिद्ध हुए अवचार की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुसार'' ''चेतावनी'' की शास्ति अधिरोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण हजारे, अतिरिक्त सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2025

क्र. 734-2477025-2024-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, साधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 26 दिसम्बर 2024 द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) [किशोर न्याय नियम, 2022 (नियम 2016) का नियम 88 (10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित किया गया था.

रतलाम जिले में बाल कल्याण समिति के 01 सदस्य, श्रीमती मनीषा शर्मा द्वारा निजी कारण से कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से वरिष्ठताक्रम के आधार पर श्रीमती रूपा कुँवर देवड़ा को बाल कल्याण समिति रतलाम में सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिए पदांकित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2025

क्रमांक-यूडीएच-3/0037/2025/18-5 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा 5 की सहपठित धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 3860-वि.यो.-इंदौर-उपां-नग्रानि-2024 भोपाल दिनांक 06/09/2024 द्वारा प्रकाशित इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनूसूची के अनुसार मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23(5)(एक) सहपठित धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात--

1. आयुक्त, इंदौर संभाग-इंदौर म0प्र0।
2. कलेक्टर, जिला इंदौर म0प्र0.।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम इंदौर म.प्र.।
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इंदौर म.प्र.।

उपांतरण का विवरण

1. इंदौर विकास योजना, 2021 के अध्याय -3 की कंडिका क्रमांक 3.25.2 की सारणी- 3.6 के सरल क्रमांक-39 के पश्चात सरल क्रमांक 41 निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाता है :-

3.25.2

सारणी- 3.6

क्रमांक	मार्ग का नाम	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3
41	ए.बी. रोड बायपास (उत्तर में रहू खेड़ी जंक्शन से दक्षिण में राउ जंक्शन तक)	105

2. इंदौर विकास योजना, 2021 के अध्याय -6 की कंडिका क्रमांक 6.10.13 के पश्चात नवीन कंडिका क्रमांक 6.10.14 निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाता है:-

6.10.14 – इंदौर बायपास के कंट्रोल एरिया में आने वाले खसरों की भूमियों को मार्ग एवं मिश्रित उपयोग के संबंध में।

ए.बी.रोड बायपास में (उत्तर में रहू खेड़ी जंक्शन से दक्षिण में राउ जंक्शन तक)आने वाले ग्रामों के खसरों में ए.बी. रोड बायपास के वर्तमान राईट ऑफ वे (R.O.W.) लाईन से दोनों ओर 22.50 मीटर तक (22.50 मीटर की पट्टी) (दोनों ओर अतिरिक्त 22.50 मीटर R.O.W, उपांतरित R.O.W,- कुल 105.00 मीटर) तक मार्ग प्रस्तावित एवं प्रस्तावित 105 मीटर मार्ग के दोनों ओर 22.50 मीटर तक मिश्रित भूमि उपयोग * किया जाता है।

नोट-

*भूमि उपयोग में प्रस्तावित उपान्तरण, उक्त भूमि के भूस्वामी द्वारा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, इंदौर से ले-आउट प्लान के अनुमोदन के समय शहरी निर्धारित ग्रामीण स्थानीय निकाय को यहां/दर पर मिश्रित भूमि उपयोग प्रीमियम का भुगतान करने एवं निम्नलिखित विकास नियंत्रण नियमों के पालन करने की शर्त पर लागू होगा: -

1. मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्र की 22.50 मीटर की पट्टी (ए.बी. रोड बायपास के उपान्तरित R.O.W. लाइन से दोनों ओर 22.50 मीटर तक स्थित भूमि) या उसके किसी भी भाग में, किसी भी उपयोग/ प्रयोजन के लेआउट अनुमोदन के समय, भूमि स्वामी के लिए मिश्रित भूमि उपयोग उपान्तरण शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। मिश्रित भूमि उपयोग उपान्तरण शुल्क, केवल एक मुश्त व एक बार ही देय होगा।

2. मिश्रित भूमि उपयोग के लिए देय मिश्रित भूमि उपयोग उपान्तरण शुल्क, उक्त भूमि के क्षेत्र के आसपास प्रचलित Collector Guideline में आवासीय भूखंड के मूल्यांकन के दरों के अनुसार उक्त भूमि के मूल्य का 10% होगा।

3. उपान्तरित मिश्रित भूमि उपयोग में आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग में इंदौर विकास योजना 2021 के अनुसार सभी स्वीकार्य गतिविधियों/उपयोग परिसर पूर्ण रूप से अनुज्ञेय होंगे।

4. मध्य प्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम 2018 (MP TDR Rales 2018) के अनुसार (Development Rights Certificate एवं Additional Buildlable Area प्रीमियम) का उपयोग नियमानुसार कर सकेंगे ।

5. एबी रोड बायपास के उपान्तरित ROW लाइन से दोनों ओर उपांतरित मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्र में आने वाली भूमि पर भूखण्डीय विकास (स्वीकृत अभिन्यास में विक्रय हेतु आरक्षित भूखण्डीय क्षेत्र x कलेक्टर गाईडलाईन का 3%) उन्नयन विकास प्रभार राशि तथा बहु-इकाई भवनों को निर्मित किये जाने पर स्वीकृत फर्शी क्षेत्र अनुपात के आधार पर भूमि स्वामी को उन्नयन विकास प्रभार राशि, [स्वीकृत फर्शी क्षेत्र अनुपात (1:2.0 तक) x कलेक्टर गाईडलाईन का 3%] राशि देय होगी। 1: 2.0 से अधिक 1:4.0 तक फर्शी क्षेत्र अनुपात का लाभ प्राप्त किये जाने पर उपरोक्त कंडिका क्र. 4 के प्रावधान लागू होंगे।

6. मिश्रित भूमि उपयोग के लिए ग्राउंड कवरेज भूखंड क्षेत्र का अधिकतम 40% मान्य होगा, और अन्य उपयोग के भूमियों के लिए नियोजन मापदण्ड इंदौर विकास योजना 2021 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

यह विकास योजना मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मई 2025

क्रमांक/PCCF/7/0013/2024-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहा तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रुपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला- सिंगरौली **तहसील - सरई**

वनमंडल - सिंगरौली **वन परिक्षेत्र- पश्चिम सरई**

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमायें
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	ताल	भीखाझरिया	राजस्व वन भूमि	289/2	6.50 हेs0	उत्तर- प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से मुनारा क्रमांक 7 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से मुनारा क्रमांक 14 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
				योग	6.50 हे.0	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. **पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 14.02.2024 (प्रकरण क्रमांक 145025) में अधिरोपित शर्त के अनुसार म0प्र0 जल निगम मर्यादित परि.क्रि.ई. की स्वीकृत पाईप लाईन बिछाने में प्रभावित 3.1519 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त रकवा 6.50 हे. राजस्व वन भूमि उपरोक्त वर्णित भूमि 6.50 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक**

10/अ-20-(3)/22-23 सिंगरौली दिनांक 10.06.2022 से हस्तांतरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 10/अ-2(3)/22-23 सिंगरौली, दिनांक 10.06.2022 अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 मई 2025

क्र. PCCF-7-0013-2024-FLR-PCCF .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0013-2024-FLR-PCCF दिनांक 1 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 1st May 2025

N0./PCCF/7/0013/2024-FLR-PCCF in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas. Specified in the schedule below, Subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modified by that state Government form time to time.

SCHEDULE

District -Singrauli Tahsil - Sarai Forest
Division -Singrauli Forest Range – West Sarai

S. No.	Name of proposed Forest Block	Details of Land included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No. Old/New	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Taal	Bhikhajhriya	Revenue Forest Land	289/2	6.50	**North:-** Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 2 of proposed protected forest block.

						East:- Artificial forest boundary from Pillar No. 2 to Pillar No. 7 of proposed protected forest block. **South:-** Artificial forest boundary from Pillar No. 7 to Pillar No. 14 of proposed protected forest block. **West:-** Artificial forest boundary from Pillar No. 14 to Pillar No. 1 of proposed protected forest block.
				Total:-	**6.50**	

A. **Reason for Publication of Notification :-**

1 – in accordance with condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi Letter No dated 14.02.2024 (Principal Approval Proposal number 145025) and in lieu of 3.1519 hectare out of 6.50 hectare sanctioned. Affected forest land under the sanctioned Pipe Line Project of Jal Nigam the above mentioned Revenue Forest Land of 6.50 Hectare Transferred or muted in favor of m.p. forest Department by order No. 10/अ-2(3)/22-23 Singrauli, Dated 10.06.2022 of Collector, Distt. Singrauli for the Purpose of Compensatory aforestation.

2- Detail of other Reasons – Nil

B. The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report No. 10/अ-2(3)/22-23 Singrauli, Dated 10.06.2022 of Collector, Distt. Sidhi are as Under.

1. - Individuals Rights :- Nil.
2. - Communities Rights :- Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 मई 2025

क्रमांक/PCCF/7/0183/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम] 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम, के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - खरगोन
तहसील- भीकनगांव

वनमण्डल-खरगोन
वन परिक्षेत्र - भीकनगांव

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
1	जोसिंगपुरा	जोसिंगपुरा	निस्तार चरनोई.	12/2/1 16/1 18 20 37/1/2	8.800 3.830 1.378 12.299 13.408	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 39 से 55 एवं 1 तक तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 16 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से मुनारा क्रमांक 34 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 34 से मुनारा क्रमांक 39 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	39.715	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलावायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक/6-MPC054/2021-BHO दिनांक 29/09/2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग, खण्डवा एवं खरगोन (आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना रोशिया तालाब योजना (परियोजना का नाम) में प्रभावित 39.715 हेक्टेयर को वनभूमि के एवज में प्राप्त 39.715 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/849/वाचक-2/2020 दिनांक 11.06.2020 हस्तांरित अथवा नामांतरित किये जाने का कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण- क्षतिपूर्ति वनीकरण ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार भीकनगांव/अनुविभागीय अधिकारी, भीकनगांव के प्रतिवेदन क्रमांक-5202 दिनांक 16-12-2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत आधिकार - निरंक
2. सामुदायिक अधिकार - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 मई 2025

क्र. PCCF-7-00183-2025-FLR-PCCF .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-00183-2025-FLR-PCCF दिनांक 1 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 1st May 2025

No.PCCF/7/0183/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District- Khargone
Forest Division- Khargone

Tahsil- Bhikangaon
Forest Range- Bhikangaon

S.N.	Name of proposed Forest Block	Detail of Land Included				Forest Block Boundries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (ha.)	
1	Jaisinghpura	Jaisinghpura	Nistar Charnoi	12/2/1 16/1 18 20 37/1/2	8.800 3.830 1.378 12.299 13.408	**North:-** Artificial forest boundary from pillar no. 39 to 55 and 1 of Proposed Protected Forest Block.

						East :- Artificial forest boundary from pillar no. 1 to 16 of Proposed Protected Forest Block. **South**:- Artificial forest boundary from pillar no. 16 to pillar no. 34 of Proposed Protected Forest Block. **West** :- Artificial forest boundary from pillar no. 34 to 39 of Proposed Protected Forest Block.
				Total	**39.715**	

(A) Reason for publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Regional Office, Bhopal order No.6-MPC054/2021-BHO dated 29.09.2024 and in lieu of **39.715** hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rosiya Talab Yojana (Name of Project) of Water Resources Department, in Khandwa & Khargone District of Madhya Pradesh (Name of User Department/ Agency/Person), the above mentioned Non forest land of **Area 39.715** hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No./894/Reader-2/2020 dated 11.06.2020 of Collector District, Khargone for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons:-Compensatory Afforestation

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no. **5202** dated 16-12-2024 of **Tehsildar Bhikangaon/Sub Divisional Magistrate** are as under.

1.Individual Rights- **Nil**

2.Community Rights- **Nil**

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 16 अप्रैल 2025

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014)

प्र. क्र. 20-अ-82-2024-25-क्र. 1088-भू-अर्जन 2025.—एतद्द्वारा, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "अनुभाग जावरा के अंतर्गत ग्राम बरगढ़ फंटा से भैसाना फंटा टू लेन बायपास निर्माण हेतु जिला रतलाम की तहसील पिपलोदा के प. ह. नं. 47 के ग्राम श्यामपुरा के 32 खाताधारकों की निजी भूमि परियोजना के लिये आवश्यकता होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2ए-भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत् आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है.

अतः, निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें. नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा :—

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	भरत पिता नाथुराम	286/1	0.17	-	0.17	-
2	कन्हैयालाल राधेश्याम कमलेश पिता नन्दराम व राजूबाई बेवा नन्दराम.	288	0.11	-	0.11	-
3	आमनाबी स्व. पति मुन्ना खां शहजाद खां आजाद खां हसिना बी शमीम बी पिता मुन्ना खां.	280/1	0.170	-	0.170	-
4	इब्राहीम मोहम्मद रफीक जफर पिता मोज्जमखां	270/1	0.175	-	0.175	-
5	इब्राहीम मोहम्मद रफीक जफर पिता मोज्जमखां	271	0.06	-	0.06	कुआँ-1
6	इब्राहीम मोहम्मद रफीक जफर पिता मोज्जमखां	269	0.02	-	0.02	-
7	अफसानाबी पति इब्राहिम खां	268	0.025	-	0.025	-
8	आमनाबी स्व. पति अकरम खां व अनवार खां अलताफ रबिया बी पिता अकरम बां.	272	0.25	-	0.25	-
9	सलीम खां पिता गुलमोहम्मद	254/1	0.09	-	0.09	-
10	रशीदखां भुरूखां इमरान खां पिता शरीफ खां व हसिनाबी बेवा शरीफ.	252	0.02	-	0.02	-
11	रशीदखां भुरूखां इमरान खां पिता शरीफ खां व हसिनाबी बेवा शरीफ.	253/1	0.02	-	0.02	-
12	रशीदखां भुरूखां इमरान खां पिता शरीफ खां व हसिनाबी बेवा शरीफ.	249/1	0.11	-	0.11	-
13	आरिफखां सरदारखां बाबुखां पिता चांदखां गफुरखां शब्बीरखां सिद्धकखां शहनाज फेरोज रहमत सईदा पिता छोटेखां साहराबखां शोयबखां सलमा पिता रूस्तमखां शकुरबी पति रूस्तम.	248/1	0.06	-	0.06	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	आमनाबी पति अकरम खां	248/2/2	0.05	–	0.05	–
15	गुलामनबी पिता नाहरूशाह ईब्राहिम उस्मानशाह सिकन्दरशाह शाहिदाबी सलमाबी नुरबानोबी जाहीदाबी साहीस्ता पिता सरदारशाह शब्बोबी साईनबी आमनाबी नाहरीबी पिता नाहरूशाह सत्तारशाह गफ्फारशाह गुफरशाह छोटीबी शाबराबी पिता शकुरशाह.	246	0.15	–	0.15	–
16	राजाराम चेनीराम मगनीराम भंवरलाल शान्तीलाल अनोखीलाल रामकन्या सम्पतबाई पिता लच्छीराम शंकर नागु प्यारीबाई कैलाशीबाई पिता रूपा.	245	0.07	–	0.07	–
17	साबिर खां पिता इस्माइल खां	244/2	0.03	–	0.03	–
18	अमरू पिता गोबा कस्तुरीबाई बेवा गोबा	177	0.05	–	0.05	–
19	अमरू पिता गोबा कस्तुरीबाई बेवा गोबा	176	0.03	–	0.03	–
20	शरद आशा संगीता मनीषा निशा पिता फुलचंद	289	0.02	–	0.02	–
21	राजाराम चेनीराम मगनीराम भंवरलाल शान्तीलाल अनोखीलाल रामकन्या सम्पतबाई पिता लच्छीराम शंकर नागु प्यारीबाई कैलाशीबाई पिता रूपा.	166	0.015	–	0.015	–
22	राजाराम चेनीराम मगनीराम भंवरलाल शान्तीलाल अनोखीलाल रामकन्या सम्पतबाई पिता लच्छीराम शंकर नागु प्यारीबाई कैलाशीबाई पिता रूपा.	172	0.01	–	0.01	–
23	राजाराम चेनीराम मगनीराम भंवरलाल शान्तीलाल अनोखीलाल रामकन्या सम्पतबाई पिता लच्छीराम शंकर नागु प्यारीबाई कैलाशीबाई पिता रूपा.	167	0.065	–	0.065	–
24	भेरूसिंह पिता चन्दसिंह	102	0.027	–	0.27	–
25	सरला परफार्मे फेबर्स लिमिटेड जावरा श्री सदानन्दना कृपानायक.	57	0.016	–	0.16	–
26	जुझारसिंह पिता भेरूसिंह	11/3	0.1	–	0.1	–
27	राधेश्माम पिता कचरूलाल	12	0.08	–	0.08	–
28	राधेश्माम पिता कचरूलाल	20	0.08	–	0.08	–
29	जेबुनबी भुरीबी रहमतबी बेवा याकुबशाह जाफर पिता याकुबशाह.	21	0.01	–	0.01	–
30	शाहिनबी पति सलीमखां	22	0.21	–	0.21	–
31	शहजादखां पिता मुन्नाखां	35	0.12	–	0.12	–
32	आजादखां पिता मुन्नाखां	38	0.11	–	0.11	–
		योग . .	2.91	–	2.91	–

राजेश बाथम, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

सागर, दिनांक 11 अप्रैल 2025

मौजा हरदुआ बलेह, पट. ह. नं. 45, तहसील रहली

क्र.-0023-अ-82-24-25-भू-अर्जन-2025-3452.—राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :—

(1)	परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर.
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण.	1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रहली 2. राजस्व निरीक्षक, छिरारी 3. सरपंच ग्राम पंचायत, हिनोती, वि. ख. रहली 4. सचिव, ग्राम पंचायत, हिनोती, वि. ख. रहली
(4)	भूमि का विवरण.—	
	(क) जिला	सागर
	(ख) तहसील	रहली
	(ग) ग्राम / नगर	हरदुआ बलेह
	(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र	23.54 हे.
	(ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र	23.58 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	23.540 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है.	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख.	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

मौजा चनगुआँ, पट. ह. नं. 46, तहसील रहली

क्र.-0019-अ-82-24-25-भू-अर्जन-2025-3453.—राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :—

(1)	परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर.
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण.	1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रहली 2. राजस्व निरीक्षक, छिरारी 3. सरपंच ग्राम पंचायत, हरदुआ रहली, वि. ख. रहली 4. सचिव, ग्राम पंचायत, हरदुआ रहली, वि. ख. रहली
(4)	भूमि का विवरण.—	
	(क) जिला	सागर
	(ख) तहसील	रहली
	(ग) ग्राम / नगर	चनगुआँ
	(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र	35.40 हे.
	(ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र	35.40 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	35.40 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है.	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख.	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

मौजा खाईखेड़ा, पट. ह. नं. 45, तहसील रहली

क्र.-0022-अ-82-24-25-भू-अर्जन-2025-3454.—राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :—

(1)	परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर.
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण.	1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रहली 2. राजस्व निरीक्षक, छिरारी 3. सरपंच ग्राम पंचायत, हिनोती, वि. ख. रहली 4. सचिव, ग्राम पंचायत, हिनोती, वि. ख. रहली
(4)	भूमि का विवरण.—	
	(क) जिला	सागर
	(ख) तहसील	रहली
	(ग) ग्राम / नगर	खाईखेड़ा
	(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र	120.48 हे.
	(ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र	120.48 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	120.480 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है.	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख.	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

प्ररूप–क

(नियम 4 देखिए)

मौजा सलैया, पट. ह. नं. 46, तहसील रहली

क्र.–0018–अ–82–24–25–भू–अर्जन–2025–3455.—राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :—

(1)	परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक–एक सागर जिला सागर.
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण.	1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रहली 2. राजस्व निरीक्षक, छिरारी 3. सरपंच ग्राम पंचायत, हरदुआ रहली, वि. ख. रहली 4. सचिव, ग्राम पंचायत, हरदुआ रहली, वि. ख. रहली
(4)	भूमि का विवरण.—	
	(क) जिला	सागर
	(ख) तहसील	रहली
	(ग) ग्राम / नगर	सलैया
	(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र	18.10 हे.
	(ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र	18.10 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	18.10 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है.	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख.	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

संदीप जी. आर, कलेक्टर

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मई 2025

क्र.-एफ-8-0002-2024-सात-शा-7 .—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ नं. 11-36 2024 एम एण्ड जी, दिनांक 9 अप्रैल 2025 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्द्वारा, शाजापुर जिले के ग्राम ''**सेमली चाचा**'' का नाम परिवर्तित कर ''**सेमली धाम**'' करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 मई 2025

क्र.-एफ-8-0002-2024 सात-शा-7 .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-8-0002-2024-सात-शा-7, दिनांक 7 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

Bhopal, the 7th May 2025

No. F. 8-0002-2024-VII-Sec-7.—In pursuance of no objection conveyed by Government of India, Ministry of Home Affairs *vide* their letter No. 11-36-2024-M&G, dated the 9th April 2025, the State Government here by change the name of village of **"SEMLI CHACHA"** District SHAJAPUR as **"SEMLI DHAM"** with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH KUMAR KAUL, Under Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2025

प्र. क्र. 0013-अ-82-2024-25.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः ''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)'' की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बड़ामलहरा	पिपरिया कलां	306.14	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा.	काठन बांध वृहद परियोजना

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पार्थ जैसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–2696 भू–अर्जन–2025

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 अप्रैल 2025

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः **"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा–19** के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

–:अनुसूची:–

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	**छिन्दवाड़ा**
ख.	तहसील	**चौरई**
ग.	नगर / ग्राम	**ग्राम–सीताझिर** **प0ह0न–08** **ब.न.–292** **रा.नि.मं.–कपूर्दा**
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	**कुल रकबा–0.250 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां**

कमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	151/1, 152/1	0.250
	योग :–	**कुल रकबा–0.250 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां**

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:–पेंच व्यपवर्तन परियोजना के माण्डवा होज इरिगेशन सिस्टम के पंप हाउस निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू–अर्जन अधिकारी, तहसील–चौरई, जिला–छिन्दवाड़ा **के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।**

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क0 2, छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–84–भू अर्जन–2025 मैहर, दिनांक 28 अप्रैल 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**मैहर**

(ख) तहसील– **अमरपाटन**

(ग) नगर /ग्राम – **ओबरा**

(घ) क्षेत्रफल– **3.5080** हे0

क0	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	2	3
1	405/1	0.0030
2	405/2	0.0210
3	404/1	0.0450
4	404/2	
5	404/3	
6	404/4	
7	406/1	0.0140
8	406/2	0.1430
9	407	0.0170
10	408	0.0180
11	412/1	0.0170
12	412/2	0.0020
13	414/1	0.0100
14	414/2	0.0220
15	413/1	0.0620
16	413/2	0.0620
17	415/1	0.1540
18	415/2	0.0030

19	483	0.0240
20	482	0.3260
21	481	0.0240
22	479	0.1270
23	436/1	0.0240
24	440	0.0020
25	441	0.0020
26	442/2	0.0230
27	443/1	0.0710
28	443/2	0.0200
29	444	0.1450
30	445	0.0130
31	446	0.0020
32	447/1	0.0240
33	447/2	0.0120
34	448	0.0180
35	449	0.1150
36	450	0.0300
37	451	0.0130
38	452/2	0.1570
39	453/1	0.0140
40	453/3	0.0020
41	453/4	0.0020
42	435/1	0.2170
43	435/2	0.0480
44	431/2	0.0190
45	432/1	0.0200
46	432/2	
47	454/1	0.1020

48	454/2	0.0150
49	454/3	0.0070
50	454/4	0.0390
51	664	0.0120
52	665	0.1270
53	666	0.0120
54	667	0.0200
55	827/1	0.0040
56	826/1	0.4020
57	826/2/1/1	
58	826/2/1/2	
59	826/2/2	
60	825/2/2	0.0180
61	824/1	0.1310
62	824/2/2	0.1830
63	792/2	0.0100
64	794	0.1820
65	795	0.1570
	कुल योग	3.5080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अजवानी वितरिका के निर्माण हेतु ।

3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–85–भू–अर्जन–2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:– (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला मैहर

(ख) तहसील– अमरपाटन

(ग) नगर / ग्राम – कठहा

(घ) क्षेत्रफल– 1.8570 हे0

क0	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	2	3
1	481/2	0.022
2	482	0.0110
3	484/2	0.1490
4	485	0.2320
5	486	0.1490
6	487/2/1	0.0090
7	487/2/2	0.0170
8	487/3	0.0020
9	504/1	0.0080
10	561/1	0.0420
11	561/2	0.0060
12	561/3	0.0690
13	562/1	0.0250
14	562/2	0.0910
15	563/1	0.1080
16	563/2	0.1120
17	588	0.3020
18	589/1	0.0960
19	589/2	0.1200
20	589/3	0.0440
21	604/2/1/1/2	0.0020
22	608/1/1/4/1	0.0680
23	608/1/1/4/2	0.0380
24	608/1/2/3	0.0800
25	608/1/2/5	0.0550
	कुल योग	1.8570

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अजवानी वितरिका के निर्माण हेतु ।

3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रानी बाटड़, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 अप्रैल 2025

प्रकरण कमांक 25/अ–82 वर्ष 2022–23 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः–

(क) जिला – पन्ना

(ख) तहसील – पवई

(ग) ग्राम – पवई

(घ) क्षेत्रफल – 0.730 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	3772	0.110	निजी भूमि
2	3773	0.085	निजी भूमि
3	3774/2	0.010	निजी भूमि
4	424/2/1	0.010	निजी भूमि
5	579/3	0.060	निजी भूमि
6	434/1	0.060	निजी भूमि
7	524/1	0.220	निजी भूमि
8	3589/1	0.011	निजी भूमि
9	1451/1	0.050	निजी भूमि
10	345/1/1	0.010	निजी भूमि
11	346/1/1	0.004	निजी भूमि
12	594	0.010	निजी भूमि
13	595/2	0.050	निजी भूमि
14	762	0.010	निजी भूमि
15	424/1/3	0.030	निजी भूमि
	योग–	0.730 हे0	

(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :–पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अतर्गत माइनर एंव सब माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा 19 का प्रकाशन, ग्राम–पवई तहसील एंव अनुभाग पवई ।

(3)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 17 अप्रैल 2025

क्रमांक/भू–अर्जन/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित सम्पत्ति की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 0029/लेम्स/अ–82/2024–25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ जिला राजगढ के अंतर्गत नगर राजगढ की हेडगेवार कालोनी राजगढ की आबादी के अन्तर्गत 09 मकानों के लिए आवश्यक वर्णित परिसम्पत्ति जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 1 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

–: अनुसूची (1) :–

रामगंजमण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन में अर्जित नगर राजगढ की हेडगेवार कालोनी में स्थित 09 मकान

रा क	आबादी का विवरण है0मे		अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर	मकान न	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्गमीटर मे
	आबादी के सर्वे न	कुल रकबा			
1	2	3	4	5	6
1	779/2/1	3.289	उमेशसिंह पिता बापुसिंह	ई–11	115.50
2			महेश कुमार पिता नारायण प्रसाद	ई–09	138.00
3			शोभा पाण्डेय पति प्रमानन्द पाण्डेय	ई–08	93.00
4			अरूण विजयवर्गीय पिता नारायण प्रसाद विजयवर्गीय	ई–06	156.875
5			दुर्गाप्रसाद व्यास	ई–05	135.00
6			अजीत सिंह पंवार	ई–07	112.83
7			भंवर कुंवर पति भंवरसिंह	ई–10	67.50
8			सुदर्शन यादव पिता रमेश यादव	डी–05	185.77
9			निर्भयसिंह उमठ पिता नारायणसिंह उमठ	डी–04	138.00
				योग	**1142.475**
				रकबा है0 में	**0.114** है0

क्र. 3989—भू—अर्जन—2025 राजगढ़, दिनांक 25 अप्रैल 2025

क्रमांक/01/अ-82 भू-अर्जन/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र 01 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेललाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है,

अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क्र.(6) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम :- सेमलीकलां		तहसील :-खिलचीपुर		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे0		
		सिंचित	असिंचति	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	1.454	-	35

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

रामगंजमंडी मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

रामगंजमंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के आर ओ बी -6 के सर्विस रोड लिएअतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण						
क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान ग्राम सेमलीकला	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जन किया जाने वाले भूमि का रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित भूमि का प्रकार	भूमि पर स्थित परिसंपत्ति

1	देवीलाल पिता कालू जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	390/3	0.016	0.006	सिंचित	
		योग	**0.016**	**0.006**		
2	धापूबाई बेवा सींगा जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	390/2	0.017	0.006	सिंचित	मकान कच्चा-1, नीम-1,यूक्लिपटस-1,बबूल-1
		योग	**0.017**	**0.006**		
3	ग्यारसी राम, केशर ,गोरधन पिता रामा, मांगीबाई बेवा रामा ,बालू पिता मदन मेहताब बाई बेवा मदन जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	391	0.065	0.012	सिंचित	मकान -1
		योग	**0.065**	**0.012**		
4	परथी सिंह पिता सेवा जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	392/1	0.013	0.004	सिंचित	नीम-1 ,मकान-1
		योग	**0.013**	**0.004**		
5	रतन पिता पुरिया , गुलाब ,मेहताब , कंकु पुत्री पुरिया जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	392/2	0.038	0.004	सिंचित	मकान रहवासी -1
		योग	**0.038**	**0.004**		
6	जानीबाई, नाथीबाई पिता गेंदा जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	393	0.113	0.012	सिंचित	बबूल-1 मकान रहवासो -6
		योग	**0.113**	**0.012**		
7	रतनलाल पिता बापूलाल जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	376/1/1	0.073	0.015	सिंचित	बोरवेल-1 मकान रहवासी -2
		योग	**0.073**	**0.015**		
8	गंगाराम पिता बापूलाल जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	376/1/2	0.072	0.015	सिंचित	नीम-1
		योग	**0.072**	**0.015**		
9	जितेन्द्र राहुल पिता प्रेमसिंह, मनोहर बेवा प्रेमसिंह जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	376/1/3	0.072	0.015	सिंचित	
		योग	0.072	**0.015**		
10	शंकर पिता उँकार जाति बलाई निवासी ग्राम भूस्वामी	375/1/1/1	0.067	0.011	सिंचित	
		योग	**0.067**	**0.011**		

11	शिव पिता उँकार जाति बलाई निवासी ग्राम भूस्वामी	375/1/2/1	0.121	0.011	सिंचित	
		योग	**0.121**	**0.011**		
12	बालू पिता बापू , भवरीबाई बेवा बापू जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	375/2/1	0.284	0.006	सिंचित	
		योग	**0.284**	**0.006**		
13	प्रभुलाल पिता कालू जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	375/2/2	0.284	0.006	सिंचित	नीम-1,बबूल-1
		योग	**0.284**	**0.006**		
14	नन्दा, रामचंदर पिता माधू सरदारबाई बेवा माधू, देवीलाल रामलाल मांगीबाई पिता खेमराज शैतानबाई बेवा खेमराज, छीताबाई बेवा सींगा, सेवा, गेंदिया पिता पुरा, मोती पिता खेमा जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	458/1/1	0.228	0.012	सिंचित	
		योग	**0.228**	**0.012**		
15	शैतानबाई पति रमेश जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	458/1/2	0.253	0.012	सिंचित	
		योग	**0.253**	**0.012**		
16	चैना धन्ना जगन्नाथ बद्री पिता धूला , बिरम रामसिंह पिता नन्दा धापूबाई बेवा नन्दा, मांग्या पिता नाथू जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	460/1	0.506	0.007	सिंचित	
		योग	**0.506**	**0.007**		
17	पुरा पिता कालू जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	460/3	0.168	0.007	सिंचित	
		योग	**0.168**	**0.007**		
18	सुल्तान प्रेम पिता रामामु, सोरमबाई बेवा रामा जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	461/4	0.186	0.003	सिंचित	
		योग	**0.186**	**0.003**		

19	नोटः–, पूर्व में त्रुटिवश धारा 11 में सुल्तान प्रेम पिता रामा मु. सोरमबाई बेवा रामा जाति ब्राहमण के नाम लिखे गये थे, जो गलत है। अब सही नाम नंदराम पिता रतन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भूस्वामी	388	0.150	0.023	सिंचित	मकान रहवासी-4, बाथरूम-1,नीबू-2,पपीता-6,जामुन-8,नीम-2, यूक्लिपटस-10,आम-2
		योग	**0.150**	**0.023**		
20	बालु पिता बापु, भंवरीबाई बेवा बापु जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	394/2	0.025	0.016	सिंचित	
		योग	**0.025**	**0.016**		
21	कालू पिता मांगीलाल जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	395	0.101	0.003	सिंचित	
		योग	**0.101**	**0.003**		
22	रामलाल ग्यारसी ललता धापू रामी कृष्णा चन्द्रकला पिता रतनलाल मथरी बेवा रतनलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भूस्वामी	398	0.061	0.017	सिंचित	
		योग	**0.061**	**0.017**		
		कुलयोग	**2.913**	0.223		

राजगंज मंडी से भोपाल तक नई बडी रेल लाईन परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली पूर्वक प्रस्ताव की भूमि का विवरण ग्राम सेमलीकलां

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए पूरक भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण						
क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान ग्राम सेमलीकला	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जनकिया जाने वाले भूमि का रकबा (हेक्टेयर)		
1	श्यामाबाई पिता गोपीलाल जाति बेड़िया निवासी ग्राम भूस्वामी	532/1/1/1/1	0.604	0.110	सिंचित	
		योग	**0.604**	**0.110**		

2	रामलाल बिहारी लाल बनेसिंह भवरीबाई धूलीबाई पिता किशन, राधेश्याम रमेश रामप्रसाद फूलचंद कृष्णाबाई सोरमबाई पिता कालूसिंह नंदूबाई बेवा कालूसिंह, लक्ष्मण गंगाराम पिता हीरालाल जाति लोड़ा निवासी ग्राम भूस्वामी	530/3	0.148	0.020	सिंचित	
		योग	0.148	0.020		
3	मदन पिता मोतीलाल जाति ब्राह्मण, रामचंदर पिता घीसालाल , मोहन पिता प्रभुलाल जाति लुहार, बापूलाल पिता गैंदा लाल दुर्गा लाल पिता घीसालाल जाति लोडा निवासी ग्राम भूस्वामी	526/1/1	0.768	0.135	सिंचित	
		योग	0.768	0.135		
4	लीलाबाई नोरंगबाई प्रभुलाल मांगीलाल रामप्रसाद बिरम पिता छोटुलाल जाति कहार निवासी ग्राम भूस्वामी	526/2/3	0.230	0.018	सिंचित	
		योग	0.230	0.018		
5	आगीरथ पिता गोपीलाल जाति ब्रहमण निवासी ग्राम भूस्वामी	529/1/2	0.562	0.013	सिंचित	
		योग	0.562	0.013		
6	अनोखबाई बेवा अनारसिंह गुड्डीबाई राधाबाई सोतलाबाई मंजुबाई धापूबाई पुत्री अनारसिंह सोतलाबाई बेवा कालूसिंह रामपाल हेमराज जाति सोध्यानिवासी ग्राम भूस्वामी	525/1/1	0.056	0.028	सिंचित	
		योग	0.056	0.028		
7	करणसिंह पिता जगन्नाथ कंचन बाई बेवा जगन्नाथ रतनबाई पुत्री जगन्नाथ जाति सोध्यानिवासी ग्रामभूस्वामी	525/2	0.112	0.018	सिंचित	
		योग	0.112	0.018		
8	कोशल्याबाई पत्नी आत्माराम जाति ब्रहमण निवासी	536/1/1	0.941	0.259	सिंचित	
		योग	0.941	0.259		
9	शिवनारायण पिता बिरम दरियाव बाई बेवा बिरम जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	375/2/3/2	0.186	0.100	सिंचित	
		योग	0.186	0.100		
10	बापूलाल पिता भंवरलाल जाति सोध्या निवासी ग्राम भूस्वामी	1/4/1	0.436	0.034	सिंचित	
		योग	0.436	0.034		
11	भगवतीप्रसाद पिता मांगीलाल जाति ब्रहमण निवासी ग्राम भूस्वामी	527/2/2/1	0.407	0.121	सिंचित	
		योग	0.407	0.121		
12	दुलीचंद पिता बिहारी लाल जाति ब्रहमण निवासी ग्राम भूस्वामी	1/1	1.137	0.253	सिंचित	
		योग	1.137	0.253		
13	गंगाराम पिता बापूलाल जाति चमार निवासी ग्राम भूस्वामी	376/5/2	0.122	0.122	सिंचित	
		योग	0.122	0.122		
		कुल योग	5.709	1.231		

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय मे किया जा सकता हैं।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 01/अ–82/2024–25 मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:-Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 24-03-2025 रेल्वे विभाग को इस बात का समाधान हो गया है कि निचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 मे रामगंज मंडी–भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर के ग्राम खुरचन्याकलां में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची–2 मे उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है। तदनुसार निम्न अधिग्रहित कि जाने वाली भूमि का धारा 11 का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में किया जाना है।

–: अनुसूची–2 :–

रामगंज मंडी–भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर के ग्राम खुरचन्याकलां की भूमि रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि एवं पूरक भूमि का विवरणः–

ग्राम खुरचन्याकलां तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र.

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान खिलचीपुर	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर)
1	धीरप पिता भंवरलाल, कुशालसिंह पिता उदालाल जाति दांगी निवासी जामोन्या	252/45/1/2/1	0.644	0.050
2	भवरलाल उदालाल पिता शिवलाल जाति दांगी निवासी जामोन्या	252/48/3/1/1	0.644	0.066
	महायोग	किता 02	1.288	0.116

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी खिलचीपुर–जीरापुर जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2024

क्रमांक 4077 /भू–अर्जन/2024 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना **तहसील–सुठालिया, जिला–राजगढ़** के **ग्राम–टोडी (पूरक)** के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की **धारा–11** के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग; ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति म.प्र. राज्य पर्यावरण प्रभाव आकंलन प्राधिकरण (भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) पर्यावरण योजना और समन्वय संगठन, पर्यावरण परिसर ई–5, अरेरा कॉलोनी भोपाल के पत्र क्रं. 1111/ SEIAA दिनांक 03.06.2021 द्वारा जारी की गयी है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये जाते समय विभाग द्वारा प्रस्तुत अंतिम ई.आई.ए/ई.एम.पी. प्रतिवेदन में भी सामाजिक समाघात निर्धारण अध्याय को सम्मिलित कराया गया था। तत्पश्चात प्रथक से सामाजिक समाघात निर्धारण भी कराया जा चुका है।

–: अनुसूची (1) :–

तहसील : सुठालिया **जिला : राजगढ़**

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू–अर्जन प्रस्ताव, ग्राम–टोडी

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित **ग्राम–टोडी (पूरक)** की भूमि की आवश्यकता।	**284.246**	**189.551**
	कुल योगः–	**284.246**	**189.551**

–: अनुसूची (2) :–

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	दयाराम पिता बाबरू जाति धोबी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	2/1	0.433	0.200
		484/2	0.038	0.038
	योग :–	कुल 2 किता	**0.471**	**0.238**
2	बिहारी पिता बाबरू जाति धोबी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	2/2	0.433	0.240
		299/3	0.109	0.109
		484/3	0.038	0.038
	योग :–	कुल 3 किता	**0.580**	**0.387**
3	बद्रीलाल पिता बाबरू जाति धोबी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	2/3	0.101	0.101
		5/1/1	0.184	0.184
		299/4	0.109	0.109
		484/4	0.038	0.038
		312/1/1	0.091	0.091
	योग :–	कुल 4 किता	**0.523**	**0.523**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
4	राममरोसी बाई पति करनसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	2/4/1	0.387	0.070
		5/1/2/1	0.083	0.083
	योग :–	कुल 2 किता	**0.470**	**0.153**
5	सुनील लोधी पिता अभय सिंह लोधी जाति लोधी पता निवासी ग्राम निवारा तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	2/4/2	0.290	0.070
		5/1/2/2	0.050	0.050
	योग :–	कुल 2 किता	**0.340**	**0.120**
6	कैलाश लोधी पिता धन्नालाल लोधी जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	2/4/3	0.290	0.070
		5/1/2/3	0.050	0.050
	योग :–	कुल 2 किता	**0.340**	**0.120**
7	दोलतराम पिता मिश्रीलाल जाति लोधी पता सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	38/1/1	0.345	0.265
		332/1/2	0.110	0.110
	योग :–	कुल 2 किता	**0.455**	**0.375**
8	मोडसिंह पिता मिश्रीलाल जाति लोधी पता सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	38/1/2	0.345	0.335
		332/1/3	0.109	0.109
	योग :–	कुल 2 किता	**0.454**	**0.444**
9	खुशीलाल पिता रामप्रसाद जाति लोधी पता सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3/1/3	0.336	0.010
		38/1/3	0.690	0.690
		332/1/1	0.148	0.148
		941/2	0.137	0.137
	योग :–	कुल 4 किता	**1.311**	**0.985**
10	जगन्नाथ पिता रामप्रसाद जाति लोधी पता सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3/1/4	0.152	0.080
		38/3	0.460	0.150
		332/1/4	0.127	0.127
		332/2	0.164	0.164
		941/1	0.065	0.065
		943	0.139	0.050
	योग :–	कुल 6 किता	**1.107**	**0.636**
11	लक्ष्मीनारायण, कुमेरसिंह पिता रामकिशन जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3/2	0.379	0.150
		38/2	0.613	0.210
	योग :–	कुल 2 किता	**0.992**	**0.360**
12	बापूलाल, सरजन पिता जयसिंह जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	276/2/2	1.012	1.012
	योग :–	कुल 1 किता	**1.012**	**1.012**
13	मांगीलाल पिता मिश्रीलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6	1.126	0.976
		41/2	0.266	0.090
		63/2	0.139	0.050
		149/4	0.094	0.094
	योग :–	कुल 4 किता	**1.625**	**1.210**
14	पृथ्वीसिंह पिता गोरेलाल जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	7	1.101	1.101
	योग :–	कुल 1 किता	**1.101**	**1.101**
15	राधेश्याम पिता रामसिंह जाति लोदी पता ब्यावरा राजगढ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	539/1/1	0.316	0.316
	योग :–	कुल 1 किता	**0.316**	**0.316**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
16	कन्हैयालाल पिता जगरूप जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	11/1/1	1.201	1.201
		124/1	0.316	0.030
		155/2	0.184	0.184
		160/2	0.164	0.010
	योग :–	कुल 4 किता	**1.865**	**1.425**
17	नरेन्द्रसिंह पिता लाखनसिंह जाति गूजर पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	13/1	0.595	0.595
		16/1	0.100	0.100
	योग :–	कुल 2 किता	**0.695**	**0.695**
18	रूकमा बाई पति शिवचरण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	15/1	1.164	1.164
		16/2	0.216	0.216
	योग :–	कुल 2 किता	**1.380**	**1.380**
19	कमलेश पिता धनराज जाति गूजर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	15/2	1.163	1.163
	योग :–	कुल 1 किता	**1.163**	**1.163**
20	बनेसिंह पिता गुलाबसिंह हिहि. 1/2 भाग, रामचरण पिता गुलाबसिंह हि. 1/2 भाग जाति लोडागूर्जर पता निवासी गूजरखेडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	15/3	1.518	1.518
	योग :–	कुल 1 किता	**1.518**	**1.518**
21	शिवचरण पिता अमरतंलाल जाति गुर्जर पता निवासी गूजरखेडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/1	0.645	0.645
	योग :–	कुल 1 किता	**0.645**	**0.645**
22	लाड़सिंह पिता धनराजसिंह जाति गुर्जर पता निवासी गूजरखेडी तहसील ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/2	0.645	0.645
		17/3	0.645	0.645
	योग :–	कुल 2 किता	**1.290**	**1.290**
23	पर्वतसिंह पिता करणसिंह, प्रकाशबाई वेवा करणसिंह जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/4	0.645	0.645
		156/1/1	0.079	0.079
	योग :–	कुल 1 किता	**0.724**	**0.724**
24	प्रकाश पिता कन्हैया हि. 1/5 भाग, फूलसिंह पिता कन्हैया हि. 1/5 भाग, मोतीलाल पिता कन्हैया हि. 1/5 भाग, चेनसिंह पिता कन्हैया हि. 1/5 भाग, सूरजबाई बेवा कन्हैया हि. 1/5 भाग जाति भोई पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34/1/1	0.030	0.030
	योग :–	कुल 1 किता	**0.030**	**0.030**
25	हरिओम पिता शम्भूसिंह हि. 1/2 भाग, रामविलास पिता शम्भूसिंह हि. 1/2 भाग जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	49/3	1.410	0.200
		34/1/2	0.076	0.076
		35/2	0.303	0.303
		100	0.746	0.070
	योग :–	कुल 4 किता	**2.535**	**0.649**
26	रघुवीरसिंह पिता बद्रीलाल जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	49/2	1.410	0.130
		34/1/3	0.759	0.759
		35/1	0.203	0.203
		59/1	0.375	0.275
	योग :–	कुल 4 किता	**2.747**	**1.367**
27	रामराज पिता गोपालसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34/2/2	0.190	0.175
	योग :–	कुल 1 किता	**0.190**	**0.175**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
28	यशवंतसिंह पिता गोपालसिंह जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34/2/3	0.189	0.119
	योग :–	कुल 1 किता	**0.189**	**0.119**
29	हजारीलाल पिता देवालाल हि. 1/2 भाग, मुगियाबाई वेवा देवालाल हि. 1/2 भाग जाति भोई पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34/3	0.865	0.865
	योग :–	कुल 1 किता	**0.865**	**0.865**
30	खुशीलाल पिता रामप्रशाद हि. 1/4 भाग, जगन्नाथ पिता रामप्रसाद हि. 1/4 भाग, लक्ष्मीनारायण पिता रामकिशन हि. 1/4 भाग, कुमेरसिंह पिता रामकिशन हि. 1/4 भाग जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	37/1	0.477	0.477
	योग :–	कुल 1 किता	**0.477**	**0.477**
31	गुलाबसिंह पिता खुशीलाल हि. 1/4 भाग, सुन्दरलाल पिता खुशीलाल हि. 1/4 भाग, कमलसिंह पिता खुशीलाल हि. 1/4 भाग, जेबोबाई बेवा खुशीलाल हि. 1/4 भाग जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	37/2	0.952	0.952
	योग :–	कुल 1 किता	**0.952**	**0.952**
32	रामभरोसा पिता नाबालक्ष्मीनारायण पिता रामचरण सूरजबाई बेवा रामचरण सर माता सूरजबाई जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	40/1	0.618	0.130
	योग :–	कुल 1 किता	**0.618**	**0.130**
33	गोलू, समन्दरसिंह पिता इमरतसिंह जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	40/2	0.506	0.506
		49/1	1.411	0.250
	योग :–	कुल 2 किता	**1.917**	**0.756**
34	शिवचरण पिता गोपीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	40/3	1.177	0.170
	योग :–	कुल 1 किता	**1.177**	**0.170**
35	नवलसिंह पिता भंबरलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	41/1	0.265	0.250
		63/3	0.279	0.070
		149/3	0.095	0.095
	योग :–	कुल 3 किता	**0.639**	**0.415**
36	गोपालसिंह पिता खुशीलाल जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	49/4/3	1.000	0.020
		49/4/5	0.410	0.070
		50/1/1	0.272	0.135
		59/4/2	0.375	0.020
	योग :–	कुल 4 किता	**2.057**	**0.245**
37	नृपतसिंह पिता रणजीतसिंह हि. 1/5 भाग जगदीश पिता रणजीतसिंह हि. 1/5 भाग, चैनसिंह पिता रणजीतसिंह हि. 1/5 भाग, दीपाबाई पिता रणजीतसिंह हि. 1/5 भाग, मु0 कलाबाई बेवा रणजीतसिंह हि. 1/5 जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	49/4/2	1.000	0.015
		49/4/6	0.410	0.080
		50/1/3	0.272	0.252
		59/4/3	0.211	0.010
	योग :–	कुल 4 किता	**1.893**	**0.357**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
38	अमरसिंह पिता धूलजी जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	50/2	0.816	0.816
	योग :–	कुल 1 किता	**0.816**	**0.816**
39	दुर्गा पिता हजारी हि. 1/2 भाग, प्रेमबाई पत्नी दुर्गा हि. 1/2 भग जाति भंगी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	56/2	1.581	1.581
	योग :–	कुल 1 किता	**1.581**	**1.581**
40	कमलसिंह पिता खुशीलाल जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	49/4/4	0.410	0.080
		59/4/1	0.375	0.020
	योग :–	कुल 2 किता	**0.785**	**0.100**
41	बबलू पिता रामसिंह जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	61/2	0.325	0.090
	योग :–	कुल 1 किता	**0.325**	**0.090**
42	बद्रीलाल पिता पन्नालाल जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	68	0.632	0.080
		113/2	0.383	0.190
	योग :–	कुल 2 किता	**1.015**	**0.270**
43	धमेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण जाति लोधी पता सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	69/2	0.702	0.020
		186	0.126	0.126
	योग :–	कुल 2 किता	**0.828**	**0.146**
44	रामबाबू पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	353/2	0.443	0.253
	योग :–	कुल 1 किता	**0.443**	**0.253**
45	सूरजसिंह पिता रामसिंह जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	94/1	0.300	0.210
		94/2	0.200	0.130
	योग :–	कुल 2 किता	**0.500**	**0.340**
46	मुकेश पिता बद्रीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	94/3	0.500	0.250
	योग :–	कुल 1 किता	**0.500**	**0.250**
47	अमृतलाल पिता नरभेसिंह हि. 1/2 भाग, कोशल्या पति नरभेसिंह हि. 1/2 भाग जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	95	0.848	0.390
	योग :–	कुल 1 किता	**0.848**	**0.390**
48	घीसालाल पिता रामरतन जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	98/1	0.809	0.150
	योग :–	कुल 1 किता	**0.809**	**0.150**
49	धनसिंह पिता खुशीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	561/1/1	0.107	0.107
	योग :–	कुल 1 किता	**0.107**	**0.107**
50	कल्याणसिंह पिता खुशीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	561/1/2	0.107	0.107
	योग :–	कुल 1 किता	**0.107**	**0.107**
51	प्रेमसिंह पिता खुशीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	98/2/3	0.203	0.015
		561/1/3	0.108	0.108
	योग :–	कुल 2 किता	**0.311**	**0.123**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
52	जगन्नाथ पिता खुशीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	561/1/4	0.108	0.108
		98/2/4	0.202	0.100
	योग :–	कुल 2 किता	**0.310**	**0.208**
53	शंकरलाल पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	97/1	0.114	0.114
		117/7	0.187	0.187
		120/1	0.057	0.057
	योग :–	कुल 3 किता	**0.358**	**0.358**
54	प्रेम पिता गंगाधर जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	97/2	0.114	0.114
		120/2	0.057	0.057
		121/7	0.024	0.024
	योग :–	कुल 3 किता	**0.195**	**0.195**
55	लाखनसिंह पिता रामसिंह जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	99/1	1.012	0.600
	योग :–	कुल 1 किता	**1.012**	**0.600**
56	मोहन पिता करनसिंह जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	102/5/1	0.012	0.012
		243/1	0.198	0.198
		246/2	0.101	0.101
	योग :–	कुल 3 किता	**0.311**	**0.311**
57	अर्जुनसिंह पिता करनसिंह जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	102/5/2	0.013	0.013
		226	0.190	0.190
		246/3	0.102	0.102
	योग :–	कुल 3 किता	**0.305**	**0.305**
58	बाबूलाल पिता करनसिंह जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	102/5/3	0.013	0.013
		243/3	0.199	0.199
	योग :–	कुल 2 किता	**0.212**	**0.212**
59	बद्रीलाल पिता करनसिंह जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	102/5/4	0.013	0.013
		243/2	0.198	0.198
		246/1	0.101	0.101
	योग :–	कुल 3 किता	**0.312**	**0.312**
60	पप्पू पिता शंकरलाल जाति लोदी पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	105	0.253	0.060
	योग :–	कुल 1 किता	**0.253**	**0.060**
61	धनसिंह पिता प्रभूलाल जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	114/1/1	0.050	0.050
		255/3	0.253	0.253
		248	0.695	0.585
	योग :–	कुल 2 किता	**0.998**	**0.888**
62	बंशीलाल पिता गंगाधर जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	114/2	0.367	0.130
		117/2	0.676	0.140
		121/6	0.080	0.080
		127	0.240	0.240
	योग :–	कुल 4 किता	**1.363**	**0.590**
63	प्रभूलाल पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	117/3	0.186	0.095
		121/3	0.046	0.046
	योग :–	कुल 2 किता	**0.232**	**0.141**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
64	जगदीश, अभयसिंह, सुगनबाई पिता मांगीलाल गुलाबबाई बेवा मांगीलाल जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	117/4	0.186	0.110
		121/1	0.049	0.049
	योग :–	कुल 2 किता	**0.235**	**0.159**
68	फुलसिंह पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	117/5	0.186	0.156
		121/2	0.046	0.046
		140/3	0.044	0.044
	योग :–	कुल 3 किता	**0.276**	**0.246**
66	धापूबाई पत्नी फूलसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	117/6	0.186	0.186
		121/4/2	0.023	0.023
	योग :–	कुल 2 किता	**0.209**	**0.209**
67	बनेसिंह पिता बालमुकन्द जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	118/1	0.414	0.284
		118/2	0.350	0.230
		118/3/1	0.172	0.112
		237	0.392	0.392
		238/2	0.347	0.347
	योग :–	कुल 5 किता	**1.675**	**1.365**
68	विक्रम पिता बंशीलाल जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	118/3/2	0.246	0.130
	योग :–	कुल 1 किता	**0.246**	**0.130**
69	छोटेलाल पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	121/4/1	0.023	0.023
	योग :–	कुल 1 किता	**0.023**	**0.023**
70	रमेश पिता गंगाधर जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	121/5	0.080	0.080
	योग :–	कुल 1 किता	**0.080**	**0.080**
71	बापूलाल पिता जयसिंह जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	124/2/1	0.158	0.079
		160/1/1	0.082	0.042
	योग :–	कुल 2 किता	**0.240**	**0.121**
72	सरजनसिंह पिता जयसिंह जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	124/2/2	0.158	0.020
		137/2/2	0.057	0.030
		160/1/2	0.083	0.043
	योग :–	कुल 3 किता	**0.298**	**0.093**
73	प्रेमसिंह लोधी पिता धुरीलाल जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	133/1	0.120	0.120
	योग :–	कुल 1 किता	**0.120**	**0.120**
74	बापूलाल पिता जयसिंह हि. 1/2 भाग, सरजन पिता जयसिंह हि. 1/2 जाति लोदी पता टोड़ी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	125	2.149	0.030
		133/2/2	0.152	0.152
		156/1/2	0.079	0.079
		156/2	0.158	0.158
	योग :–	कुल 4 किता	**2.538**	**0.419**
75	धनसिंह पिता हरकिशन जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	134/2	0.063	0.048
		253/1/2	0.103	0.103
		254/2/1	0.379	0.379
	योग :–	कुल 3 किता	**0.545**	**0.530**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
76	जितु नाबालिग पिता भारतसिंह संरक्षक माताा कष्णाबाई बेवा भारतसिंह हि. 1/2 भाग, सोनु नाबालिग पिता भारतसिंह संरक्षक माता कष्णाबाई बेवा भारतसिंह हि. 1/2 जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	135/2	0.101	0.051
		253/1/1	0.379	0.379
	योग :–	कुल 1 किता	**0.480**	**0.430**
77	प्रेमसिंह लोधी पिता धुरीलाल जाति लोधी पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	136/2	0.149	0.139
	योग :–	कुल 1 किता	**0.149**	**0.139**
78	नरभेसिंह पिता कंवरलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	138	0.164	0.164
		158	0.569	0.110
		162/1/1	0.230	0.015
	योग :–	कुल 3 किता	**0.963**	**0.289**
79	प्रेमसिंह पिता गंगाधर हि. 1/3 भाग, बंशीलाल पिता ग्रंगाधर हि. 1/3 भाग, रमेश पिता गंगाधर हि. 1/3 जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	139/2	0.069	0.069
	योग :–	कुल 2 किता	**0.069**	**0.069**
80	धारू पिता मथरालाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	143/1	0.200	0.050
	योग :–	कुल 1 किता	**0.200**	**0.050**
81	चन्दनसिंह पिता हजारीलाल जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	143/3/1	0.033	0.010
	योग :–	कुल 1 किता	**0.033**	**0.010**
82	पर्वतसिंह पिता हजारीलाल जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	143/3/2	0.033	0.023
		185/2/2	0.176	0.090
	योग :–	कुल 2 किता	**0.209**	**0.113**
83	निरंजनसिंह पिता रूगनाथ हि. 1/2 भाग, ग्यारसी बेवा रूगनाथ हि. 1/2 भाग जाति लोदी पता टोड़ी ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	149/2	0.095	0.095
	योग :–	कुल 1 किता	**0.095**	**0.095**
84	मोतीलाल पिता गिरधारी जाति लोदी पता टोडी ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	147/1	0.191	0.050
	योग :–	कुल 1 किता	**0.191**	**0.050**
85	अजबबाई बेवा हीरालालबालिग सुशीलाबाई नाबा मिथलेशबाई नाबा विनोद नाबा सुनीता पिता हीरालाल सरमाता अजबबाई पति हीरालाल जाति लोधी पता टोडी निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	147/2	0.328	0.050
		149/1	0.095	0.040
	योग :–	कुल 1 किता	**0.423**	**0.090**
86	गुलाब पिता गिरधारी जाति लोदी पता टोड़ी ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	147/4	0.192	0.090
	योग :–	कुल 1 किता	**0.192**	**0.090**
87	अर्जुनसिंह पिता रामप्रसाद जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	152/1	1.896	0.850
		153/2	0.551	0.400
	योग :–	कुल 2 किता	**2.447**	**1.250**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
88	लाखनसिंह पिता कन्हैयालाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	152/2	0.253	0.120
	योग :–	कुल 1 किता	**0.253**	**0.120**
89	परमानन्द नाबा. पिता बापूलाल संरक्षक पिता बापूलाल पिता जयसिंह जाति लोदी पता राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	152/3	0.253	0.040
	योग :–	कुल 1 किता	**0.253**	**0.040**
90	अनारसिंह पिता कंवरलाल जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	159/2	0.192	0.035
	योग :–	कुल 1 किता	**0.192**	**0.035**
91	रामसिंह पिता कंवरलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	162/1/2	0.974	0.020
	योग :–	कुल 1 किता	**0.974**	**0.020**
92	नरबदीबाई पत्नि धुरीलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	162/2	0.340	0.050
	योग :–	कुल 1 किता	**0.340**	**0.050**
93	नारानसिंह पिता हरिसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	164/1	2.283	0.030
	योग :–	कुल 1 किता	**2.283**	**0.030**
94	सोनू पिता धनसिंह, पुरषोत्तम पिता कल्याणसिंह, प्रेमसिंह, जगन्नाथ पिता खुशीलाल हि. 20/100 भाग, निर्भयसिंह पिता मदनलाल हि. 80/100 भाग जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	166	0.493	0.085
	योग :–	कुल 1 किता	**0.493**	**0.085**
95	नारान पिता मथरालाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/1/1	0.380	0.080
	योग :–	कुल 1 किता	**0.380**	**0.080**
96	भूरियाबाई पति धारू जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/1/2	0.379	0.010
	योग :–	कुल 1 किता	**0.379**	**0.010**
97	गुलाबसिंह पिता हजारीलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/2/1	0.176	0.100
	योग :–	कुल 1 किता	**0.176**	**0.100**
98	मोहनसिंह पिता हजारीलाल जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/2/3	0.176	0.090
	योग :–	कुल 1 किता	**0.176**	**0.090**
99	लक्ष्मीनारायण पिता शोभाराम जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/3	0.332	0.060
		220	0.215	0.100
		329	0.379	0.339
	योग :–	कुल 3 किता	**0.926**	**0.499**
100	तुलसीराम,भरोसाराम,पप्पू, नरभेसिंह,शैतानबाई पिता छीतर हि. 1/2 भाग, दुर्गाप्रशाद, महेश, बद्री, सुरेश, भागीरथ पिता दोला जाति धोबी पता टोड़ी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	187	3.060	0.710
		300	0.443	0.393
		489	0.063	0.032
		901	0.911	0.911
	योग :–	कुल 4 किता	**4.477**	**2.046**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
101	ओमप्रकाश पिता मोरसिंह हि. 1/3 भाग, राजेंद्र पिता मोरसिंह हि. 1/3 भाग, कंचनबाई बेवा मोरसिंह हि. 1/3 भाग हि. 1/3 जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	191/2	0.759	0.020
		210/1	0.128	0.010
	योग :–	कुल 2 किता	**0.887**	**0.030**
102	ना.बा. केशरसिंह कैलाश पिता फूलसिंह रामकली बेवा फूलसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1	0.411	0.150
	योग :–	कुल 1 किता	**0.411**	**0.150**
103	नारानसिंह पिता हरिसिंह जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	200/2	0.411	0.361
	योग :–	कुल 1 किता	**0.411**	**0.361**
104	प्रेमनारायण पिता खुशीलाल जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	210/2	0.120	0.010
		618/1/2	0.477	0.477
	योग :–	कुल 2 किता	**0.597**	**0.487**
105	बबरीबाई पति फूलसिंह जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	210/3	0.030	0.010
	योग :–	कुल 1 किता	**0.030**	**0.010**
106	फूलसिंह पिता रामसिंह जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	211/1/1	0.015	0.015
		387/2/1	0.443	0.100
	योग :–	कुल 2 किता	**0.458**	**0.115**
107	बद्रीलाल पिता रामसिंह जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	211/1/2	0.016	0.016
		357/1	0.494	0.494
		387/2/2	0.486	0.230
	योग :–	कुल 3 किता	**0.996**	**0.740**
108	राकेश पिता जमनालाल हि. 1/3 भाग, गोखलेश पिता जमनालाल हि. 1/3 भाग, लीलाबाई बेवा जमनालाल हि. 1/3 जाति लोदी पता सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	212	0.101	0.091
	योग :–	कुल 1 किता	**0.101**	**0.091**
109	मेताबसिंह पिता शंकरलाल हि. 1/2 भाग, मोतीलाल पिता शंकरलाल हि. 1/2 जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	215	0.291	0.261
	योग :–	कुल 1 किता	**0.291**	**0.261**
110	निरपतसिंह पिता बंशीलाल जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	216/1	0.102	0.010
	योग :–	कुल 1 किता	**0.102**	**0.010**
111	रणजीतसिंह पिता रामसिंह जाति लोदी पता इन्दोर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	225/1	0.360	0.281
	योग :–	कुल 1 किता	**0.360**	**0.281**
112	प्रतिसिंह पिता गोपाल हि. 1/2 भाग, मनिया पिता गोपाल हि. 1/2 भाग जाति लोदी पता ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	225/2	0.361	0.316
		394/1	0.183	0.183
	योग :–	कुल 2 किता	**0.544**	**0.499**
113	निरपत पिता भागीरथ बहादुर पिता मानसिंह , धापूबाई बेवा मानसिंह बालकिशन पिता देवा जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	227	0.076	0.076
		244	0.063	0.063
	योग :–	कुल 2 किता	**0.139**	**0.139**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
114	मुल्लोबाई बेवा रोडजी जाति लोधी पता तहसील ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	228	0.278	0.278
	योग :–	कुल 1 किता	0.278	0.278
115	हरीश नाबा. पिता जयसिंह संरक्षक माता ममताबाई पत्नी जयसिंह जाति लोदी पता राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	242/1	1.526	1.526
	योग :–	कुल 1 किता	1.526	1.526
116	शिवचरण पिता देवीलाल हि. 1/3 भाग, जयसिंह पिता देवीलाल हि. 1/3 भाग, रघुवीर पिता देवीलाल हि. 1/3 जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	242/2	0.011	0.011
	योग :–	कुल 1 किता	0.011	0.011
117	राजेन्द्रसिंह पिता शिवचरण हि. 1/2 भाग, दिनेशकुमार पिता शिवचरण हि. 1/2 भागग जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	242/3	1.527	1.527
	योग :–	कुल 1 किता	1.527	1.527
118	नाबा. महेन्द्रसिंह , प्रीतमसिंह पिता रघुवीरसिंह सर. माता सुशीलाबाई पति रघुवीरसिंह जाति लोदी पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	242/4	1.527	1.527
	योग :–	कुल 1 किता	1.527	1.527
119	जशोदीबाई पिता बालमुंकद जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	245	0.392	0.392
		247	0.126	0.126
	योग :–	कुल 2 किता	0.518	0.518
120	सागरसिंह पिता बालमुकुन्द जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	253/2	0.482	0.482
	योग :–	कुल 1 किता	0.482	0.482
121	विजयसिंह पिता करणसिंह जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	253/3	0.574	0.574
	योग :–	कुल 1 किता	0.574	0.574
122	लक्ष्मण पिता देवीसिंह जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	254/1	0.835	0.835
		256/1	0.900	0.900
		256/2	0.529	0.529
	योग :–	कुल 3 किता	2.264	2.264
123	जगमोहन पिता मोतीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	254/2/2	0.456	0.456
	योग :–	कुल 1 किता	0.456	0.456
124	हेमेंद्रसिंह, राजकुमार सिंह पिता प्रेमसिंह विजयकुंवर शीलाबाई पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	276/1	1.012	1.012
	योग :–	कुल 1 किता	1.012	1.012
125	प्रेमनारान पिता खुमान हि. 1/3 भाग, भारतसिंह पिता खुमान हि. 1/3 भाग, प्रभुलाल पिता खुमान हि. 1/3 पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	285	0.506	0.506
		381/2	0.106	0.106
		464	0.076	0.076
		540/1	0.822	0.822
	योग :–	कुल 4 किता	1.510	1.510

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
126	पार्वती पति गंगाधर जाति तेली पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	381/1	0.210	0.210
	योग :–	कुल 1 किता	**0.210**	**0.210**
127	रामबाबू पिता अर्जुनसिंह जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	290/1	0.426	0.426
	योग :–	कुल 1 किता	**0.426**	**0.426**
128	जगदीश पिता अर्जुनसिंह जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	290/2	0.427	0.427
	योग :–	कुल 1 किता	**0.427**	**0.427**
129	बनेसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	290/3	0.426	0.426
	योग :–	कुल 1 किता	**0.426**	**0.426**
130	छोटेलाल पिता सेवाराम जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	291	0.228	0.228
		540/3	0.822	0.822
	योग :–	कुल 2 किता	**1.050**	**1.050**
131	रूपसिंह पिता करनसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	292	0.215	0.215
	योग :–	कुल 1 किता	**0.215**	**0.215**
132	धनरूप पिता नन्नूलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	293	0.253	0.253
	योग :–	कुल 1 किता	**0.253**	**0.253**
133	पर्वतसिंह पिता बाबरू जाति धोबी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	484/1	0.038	0.038
		299/2	0.109	0.109
	योग :–	कुल 2 किता	**0.147**	**0.147**
134	पर्वतसिंह पिता बाबरू हि. 1/4 भाग, बद्रीलाल पिता बाबरू हि. 1/4 भाग, बिहारीलाल पिता बाबरू हि. 1/4, दयाराम पिता बाबरू जाति धोबी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	299/5	0.108	0.108
	योग :–	कुल 1 किता	**0.108**	**0.108**
135	जगदीश पिता लालचन्द जाति धोबी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	484/5	0.152	0.152
	योग :–	कुल 1 किता	**0.152**	**0.152**
136	रम्भाबाई बेवा खुशीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	315	0.101	0.101
	योग :–	कुल 1 किता	**0.101**	**0.101**
137	कमला बेवा मांगीलाल हि. 1/2 भाग, अमृतलाल पिता मांगीलाल हि. 1/2 भाग जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	350/1	0.386	0.196
	योग :–	कुल 1 किता	**0.386**	**0.196**
138	रोडजी पिता गजाधर हि. 86/100 भाग, भारतसिंह पिता गजाधर हि. 14/100 जाति लोधी पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	350/2	0.385	0.385
	योग :–	कुल 1 किता	**0.385**	**0.385**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
139	मेहताबसिंह पिता शंकरलाल हि. 1/5 भाग, मदनलाल पिता शंकरलाल हि. 1/5 भाग, नवलसिंह पिता शंकरलाल हि. 1/5 भाग, मोतीलाल पिता शंकरलाल हि. 1/5 भाग, शांतिबाई बेवा शंकरलाल हि. 1/5 भाग जाति लोदी पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	350/3	0.772	0.772
	योग :–	कुल 1 किता	**0.772**	**0.772**
140	नितेश नाबा. पिता शिवचरण सिंह संरक्षक माता विमलाबाई बेवा शिवराज जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	352/1	0.253	0.253
	योग :–	कुल 1 किता	**0.253**	**0.253**
141	पार्वती पति गंगाधर जाति तेली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	357/3	0.493	0.493
	योग :–	कुल 1 किता	**0.493**	**0.493**
142	बंशीलाल पिता हीरालाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	372	0.190	0.190
	योग :–	कुल 1 किता	**0.190**	**0.190**
143	गंगाधर पिता मांगीलाल जाति तेली पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	383	0.139	0.139
	योग :–	कुल 1 किता	**0.139**	**0.139**
144	मथरालाल पिता मांगीलाल जाति तेली पता सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	384	2.086	2.086
	योग :–	कुल 1 किता	**2.086**	**2.086**
145	सुनील लोधी पिता धीरप सिंह पता टोड़ी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	386/1	0.418	0.418
		388/1/2	0.251	0.060
	योग :–	कुल 2 किता	**0.669**	**0.478**
146	धर्मेन्द्र लोधी पिता धीरप सिंह पता टोड़ी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	388/1/1	0.251	0.150
	योग :–	कुल 1 किता	**0.251**	**0.150**
147	धीरपसिंह पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता टोड़ी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	618/1/1	0.240	0.240
	योग :–	कुल 1 किता	**0.240**	**0.240**
148	बनेसिंह पिता अमरलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	386/2	0.417	0.417
	योग :–	कुल 1 किता	**0.417**	**0.417**
149	कमलाबाई पति धीरजसिंह जाति लोदी पता टोड़ी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	388/2	0.250	0.010
	योग :–	कुल 1 किता	**0.250**	**0.010**
150	नेपालसिंह पिता बनेसिंह हि. 1/3 भाग, प्रीतमसिंह पिता बनेसिंह हि. 1/3 भाग, मूलसिंह पिता बनेसिंह हि. 1/3 भाग जाति लोधी पता सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	388/3/2	0.252	0.180
	योग :–	कुल 1 किता	**0.252**	**0.180**
151	चोसरलाल पिता किशनलाल जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	388/4	0.504	0.150
		618/4	0.956	0.956
	योग :–	कुल 2 किता	**1.460**	**1.106**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
152	उमरावसिंह पिता अमरलाल जाति लोधी पता निवसी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	388/6	0.252	0.040
	योग :–	कुल 1 किता	**0.252**	**0.040**
153	सातूबाई बेवा देवचन्द्र हि. 1/8 भाग, गोकलेश पिताा देवचन्द्र हि. 1/8 भाग, कलाबाई पिता देवचन्द्र हि. 1/8 भाग, गुरूचरण पिता देवचन्द्र हि.. 1/8 भाग, अनुसुईयाबाई पिता देवचन्द्र हि. 1/8 भाग, सुशीलाबाई पिता देवचन्द्र हि. 1/8 भाग, प्रकाशबाई पिता देवचन्द्र हि. 1/8 भाग, शोरभबाई पिता देववन्द्र हि.. 1/8 भाग जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	394/2	0.184	0.184
	योग :–	कुल 1 किता	**0.184**	**0.184**
154	किशनलाल,मोतीलाल आ. भंबरलाल हि. 40 पैसे मोरसिंह, करनसिंह,मोहनलाल,चन्दन जगदीस आ. सोजीराम उमराव बेवा सोजीराम हि. 40 पैसे, रामकिशन आ गोरेलाल हि. 10 पैसे, उमराव आ जगन्नाथ, सुआ, कस्तूरी आ जगन्नाथ हि. 10 पैसे निवासी ग्राम भूमि स्वामी	420/1	0.162	0.162
		1131	0.076	0.020
		1148	0.215	0.050
		1196	0.139	0.050
	योग :–	कुल 4 किता	**0.592**	**0.282**
155	अमरलाल, कमलसिंह, भरोषीबाई, सावित्रीबाई पिता नाथूलाल सुन्दरबाई वेवा नाथूलाल जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	471/2	0.120	0.120
		475/1	0.088	0.088
		477/2	0.146	0.146
	योग :–	कुल 3 किता	**0.354**	**0.354**
156	समन्त्राबाई पति पदमसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	423/1/1	0.295	0.295
	योग :–	कुल 1 किता	**0.295**	**0.295**
157	अमृतलाल पिता बालमुंकद जाति धोबी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	423/2	0.500	0.500
		516/2	0.055	0.015
	योग :–	कुल 2 किता	**0.555**	**0.515**
158	गुलाब पिता बालमुंकद जाति धोबी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	423/3	0.500	0.500
	योग :–	कुल 1 किता	**0.500**	**0.500**
159	करणसिंह पिता देवालाल हि. 1/2 भाग, कस्तुरीबाई बेवा देवालाल हि. 1/2 भाग जाति लोदी पता टोड़ी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	449	1.783	1.783
	योग :–	कुल 1 किता	**1.783**	**1.783**
160	गीताबाई पत्नी शिवचरण जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	452	0.139	0.139
	योग :–	कुल 1 किता	**0.139**	**0.139**
161	मोहनबाई बेवा लक्ष्मीनारायण, राकेश, समंदरसिंह पुत्रगण लक्ष्मीनारायण विमलाबाई, राजकुमारी पुत्रिया लक्ष्मीनारायण जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	471/1/1/1	0.020	0.020
		475/2/1	0.013	0.013
		477/4/1	0.024	0.024
		542/2/2	0.453	0.453
	योग :–	कुल 4 किता	**0.510**	**0.510**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
162	राधेश्याम पिता रामबगस जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	471/1/1/2	0.020	0.020
		475/2/2	0.013	0.013
		477/4/2	0.024	0.024
		542/2/1	0.445	0.445
	योग :–	कुल 4 किता	**0.502**	**0.502**
163	हेमराज पिता हरकिशन जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	471/1/2/1	0.020	0.020
	योग :–	कुल 1 किता	**0.020**	**0.020**
164	पहलवानसिंह पिता हरकिशन जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	471/1/2/2	0.020	0.020
	योग :–	कुल 1 किता	**0.020**	**0.020**
165	रामचरण पिता छीतर जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	471/3	0.040	0.040
		477/3	0.049	0.049
		542/1	0.898	0.898
		653/1	0.590	0.590
		477/1/1	0.048	0.024
	योग :–	कुल 5 किता	**1.625**	**1.601**
166	धूल्या पिता भंवरिया जाति धोबी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	483/1	0.140	0.140
		517/2	0.070	0.060
		320/1	0.297	0.014
	योग :–	कुल 2 किता	**0.507**	**0.214**
167	रमेश, सेतानसिंह पिता अमरलाल समत्राबाई, कल्लीबाई पिता अमरलाल शांतीबाई वेवा अमरलाल जाति धोबी पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	483/2	0.140	0.140
		517/1	0.069	0.050
	योग :–	कुल 2 किता	**0.209**	**0.190**
168	मांगीलाल पिता भोना हि. 1/4 भाग, मथरालाल पिता भोना हि. 1/4 भाग, शिवचरण पिता भोना हि. 1/4 भाग, बेजनाथ पिता भोना हि. 1/4 भाग जाति धोबी पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	486/1	0.285	0.265
		516/3/1	0.044	0.015
	योग :–	कुल 2 किता	**0.329**	**0.280**
169	मांगीलाल पिता भोना हि. 1/2 भाग, बेजनाथ पिता भोना हि. 1/2 भाग जाति धोबी पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	486/2	0.120	0.120
		516/3/2	0.010	0.010
	योग :–	कुल 1 किता	**0.130**	**0.130**
170	शिवकांत पिता लक्ष्मीनारायण हि. 1/2 भाग, राघवेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण हि. 1/2 जाति महाजन पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	507	0.190	0.190
		508	0.126	0.116
		510	0.177	0.100
	योग :–	कुल 3 किता	**0.493**	**0.406**
171	योगेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण हि. 1/2 भाग, नरेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण हि. 1/2 भाग जाति महाजन पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	512/1	0.064	0.020
		513/2	0.735	0.735
	योग :–	कुल 2 किता	**0.799**	**0.755**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
172	रामबाबू पिता दुलीचन्द हि. 1/7 भाग, सुगन पिता दुलीचन्द्र हि. 1/7 भाग, भारत पिता दुलीचन्द्र हि. 1/7 भाग, कमलाबाई पिता दुलीचन्द्र हि.. 1/7 भाग, कुसुमबाई पिता दुलीचन्द्र हि. 1/7 भाग, लीलाबाई पिता दुलीचन्द्र हि. 1/7 भाग, अमृतलाल पिता दुलीचन्द हि. 1/7 भाग जाति महाजनपता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	513/1	3.337	3.317
	योग :–	कुल 1 किता	**3.337**	**3.317**
173	गोरेलाल पिता मिश्रीलाल जाति धोबी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	515/2/1	0.097	0.097
	योग :–	कुल 1 किता	**0.097**	**0.097**
174	मोहनलाल पिता मिश्रीलाल जाति धोबी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	515/2/2	0.097	0.097
	योग :–	कुल 1 किता	**0.097**	**0.097**
175	प्रेमसिंह पिता मिश्रीलाल जाति धोबी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	515/2/3	0.097	0.097
		312/1/3	0.064	0.064
	योग :–	कुल 2 किता	**0.161**	**0.161**
176	भारतसिंह पिता रामसिंह जाति लोदी पता ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	539/1/2	0.316	0.316
	योग :–	कुल 1 किता	**0.316**	**0.316**
177	पदमसिंह पिता रामसिंह जाति लोदी पता तहसील ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	539/1/3	0.316	0.316
	योग :–	कुल 1 किता	**0.316**	**0.316**
178	रामभरोसे पिता नानजी मेवाबाई, कलाबाई, धापूबाई पुत्री नानजी बादामबाई बेवा नानजी जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	540/2	0.822	0.822
	योग :–	कुल 1 किता	**0.822**	**0.822**
179	पहलवान सिंह पिता हरकिशन जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	542/3	0.897	0.897
		653/3	0.590	0.590
	योग :–	कुल 2 किता	**1.487**	**1.487**
180	छमाबाई पत्नी शादीलाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम गुजरखेडीखुर्द तहसील ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	579/3	0.443	0.443
	योग :–	कुल 1 किता	**0.443**	**0.443**
181	मोरबाई पति हरिसिंह जाति गुर्जर पता निवासी गुजरखेडी तहसील ब्यावररा राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	579/4	0.442	0.442
	योग :–	कुल 1 किता	**0.442**	**0.442**
182	विक्रमसिंह पिता नारायणसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	585/4/2	0.247	0.247
		585/2/2	0.153	0.153
	योग :–	कुल 1 किता	**0.400**	**0.400**
183	दरियावसिंह पिता बंषीलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	607/2	0.304	0.304
	योग :–	कुल 1 किता	**0.304**	**0.304**
184	लाडबाई पति जगदीश जाति भोई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	618/3/1	0.239	0.239
		618/3/2	0.239	0.239
	योग :–	कुल 2 किता	**0.478**	**0.478**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
185	जगमोहनसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	620/1/2	0.529	0.529
	योग :–	कुल 1 किता	**0.529**	**0.529**
186	वीरेन्द्रसिंह पिता राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	618/2	0.239	0.239
		624/2	0.190	0.190
		625	0.215	0.215
	योग :–	कुल 3 किता	**0.644**	**0.644**
187	जगन्नाथ पिता बद्रीलाल जाति तमोली पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	626/1/1	0.253	0.253
	योग :–	कुल 1 किता	**0.253**	**0.253**
188	रामबगस पिता छीतर जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	653/2	0.590	0.590
	योग :–	कुल 1 किता	**0.590**	**0.590**
189	सरवन पिता प्रभू हि. 1/5 भाग, जमनालाल पिता प्रभू हि. 1/5 भाग, रामचरण पिता प्रभू हि. 1/5 अमरसिंह पिता रामप्रसाद हि. 1/40 भाग, लाखन पिता रामप्रसाद हि. 1/40 भाग, दिलीप पिता रामप्रसाद हि. 1/40 भाग, जतनबाई पुत्री रामप्रसाद हि. 1/40 भाग, अजबबाई पुत्री रामप्रसाद हि. 1/40 भाग, धापूबाई पुत्री रामप्रसाद हि. 1/40 भाग, भूरीबाई पिता रामप्रसाद हि. 1/40 भाग, कमलाबाई वेवा रामप्रसाद हि. 1/40 भाग, राकेश पिता गुलाबसिंह हि. 1/25 भाग, शिवपाल पिता गुलाबसिंह हि. 1/25 भाग, संतोषबाई पुत्री गुलाबसिंह हि. 1/25 भाग, सुनीताबाई पुत्री गुलाबसिंह हि. 1/25 भाग, सम्पतबाई पत्नी गुलाबसिंह हि. 1/25 भाग जाति चमार पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	660	0.481	0.481
	योग :–	कुल 1 किता	**0.481**	**0.481**
190	ओमपालसिंह पिता महिपालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	681/1/1	1.309	1.309
	योग :–	कुल 1 किता	**1.309**	**1.309**
191	विजयपालसिंह पिता महिपालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	681/1/2	1.309	1.309
	योग :–	कुल 1 किता	**1.309**	**1.309**
192	जगपालसिंह पिता रघुवीर सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	681/3/1/1	0.106	0.106
	योग :–	कुल 1 किता	**0.106**	**0.106**
193	शिवपालसिंह पिता रघुवीर सिंह जाति राजपूत पता राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	681/3/1/2	0.105	0.105
	योग :–	कुल 1 किता	**0.105**	**0.105**
194	विक्रमसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	681/3/3	1.053	1.053
	योग :–	कुल 1 किता	**1.053**	**1.053**
195	हरपालसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	681/3/4	0.210	0.210
	योग :–	कुल 1 किता	**0.210**	**0.210**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
196	प्रतापसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	681/3/5	0.210	0.210
		683/3	0.429	0.100
	योग :–	कुल 1 किता	**0.639**	**0.310**
197	सत्येन्द्रसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	681/3/6	0.210	0.210
		719/2	2.000	2.000
		719/3	0.175	0.175
	योग :–	कुल 3 किता	**2.385**	**2.385**
198	कल्लूसिंह पिता बलबहादुरसिंह जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	685/2/4	0.291	0.291
	योग :–	कुल 1 किता	**0.291**	**0.291**
199	महेन्द्रसिंह पिता प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	692/1/1	0.280	0.280
		828/4/1	0.013	0.013
		830/6/1	0.067	0.067
	योग :–	कुल 3 किता	**0.360**	**0.360**
200	अमरसिंह पिता कुमेरसिंह हि. 1/6 भाग, हिन्दूसिंह पिता कुमेरसिंह हि. 1/6 भाग, छोटीकंवर पिता कुमेरसिंह हि. 1/6 भाग, गुडडीकंवर पिता कुमेरसिंह हि. 1/6 भाग, टमाकंवर पिता कुमेरसिंह हि. 1/6 भाग, भूपेन्द्रसिंह पिता गोविन्दसिंह हि. 1/18 भाग, देवेन्द्रसिंह पिता गोविन्दसिंह हि. 1/18 भाग, विष्णुकंवर बेवा गोविन्दसिंह हि. 1/18 भाग, जाति राजपूत पता टोडी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	692/3/1/1	0.633	0.633
	योग :–	कुल 1 किता	**0.633**	**0.633**
201	गोकुलसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	692/3/1/2	0.632	0.632
	योग :–	कुल 1 किता	**0.632**	**0.632**
202	गजेन्द्रसिंह पिता दशरथ जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	719/4	2.175	2.175
		1289	0.101	0.101
	योग :–	कुल 2 किता	**2.276**	**2.276**
203	धुन्धालाल पिता गोरीलाल हि. 1/3 भाग, अमृतबाई पिता गोरीलाल हि. 1/3, धापूबाई पिता गोरीलाल हि. 1/3 भाग जाति भोई पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	730	0.177	0.090
	योग :–	कुल 1 किता	**0.177**	**0.090**
204	राजबहादुरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह हि. 1/7 भाग, विजयबहादुरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह हि. 1/7 भाग, धनराजसिंह पिता लक्ष्मणसिंह हि. 1/7 भाग, ऋषिराजसिंह पिता लक्ष्मणसिंह हि. 1/7 भाग, यशवंतराज कुमारी पिता लक्ष्मणसिंह हि. 1/7 भाग, ब्रजराज कुमारी पिता लक्ष्मणसिंह हि. 1/7 भाग, उषाराज कुमारी पिता लक्ष्मणसिंह हि. 1/7 भाग जाति राजपूत पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	731	0.089	0.089
		732	0.025	0.025
		843/2/2	1.000	1.000
	योग :–	कुल 3 किता	**1.114**	**1.114**
205	सरजूबाई बेवा कन्हैयालाल जाति भोई पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	738/2	0.475	0.425
		839/2	0.709	0.709
	योग :–	कुल 2 किता	**1.184**	**1.134**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
206	अमृत पिता भंवरलाल जाति भोई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	741	0.139	0.139
	योग :–	कुल 1 किता	**0.139**	**0.139**
207	श्याम, मांगीबाई, रामकलाबाई, धापूबाई, भूरीबाई पिता सौल्या केशरबाई पिता सौल्या सरदारबाई वेवा सौल्या अभिषेक, अजय पिता नारायण, भूरीबाई वेवा नारायण जाति कुम्हार पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	760	0.063	0.020
	योग :–	कुल 1 किता	**0.063**	**0.020**
208	सरवन पिता प्रभूलाल जाति चमार पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	762	0.089	0.030
	योग :–	कुल 1 किता	**0.089**	**0.030**
209	रामचरण पिता भंबरिया हि. 1/4 भाग, प्रभुलाल पिता भंबरिया हि. 1/4 भाग, ग्यारस्या पिता भंबरिया हि. 1/4 भाग, कैलाश पिता भंबरिया हि. 1/4 भाग जाति भंगी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	776	0.126	0.020
	योग :–	कुल 1 किता	**0.126**	**0.020**
210	काशीराम पिता नाथू जाति चमार पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	779	0.329	0.070
	योग :–	कुल 1 किता	**0.329**	**0.070**
211	हरि पिता दोला जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	780	1.189	0.500
	योग :–	कुल 1 किता	**1.189**	**0.500**
212	ऋषिराजसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत पता राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	799	0.089	0.089
	योग :–	कुल 1 किता	**0.089**	**0.089**
213	हीरा पिता बंशी हि. 1/2 भाग, मोती पिता बंशी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	809/1	0.243	0.243
	योग :–	कुल 1 किता	**0.243**	**0.243**
214	फुलसिंह पिता कन्हैयालाल जाति भोई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	809/2	0.250	0.250
	योग :–	कुल 1 किता	**0.250**	**0.250**
215	किशन कॅवर बेवा बिसनसिंह बॅशी कॅवर, सुषमा कॅवर, पिन्टुकॅवर पिता बिसनसिंह जाति राजपूत पता सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	828/1	0.050	0.050
	योग :–	कुल 1 किता	**0.050**	**0.050**
216	हरिसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत पता तहसील ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	828/2	0.051	0.051
		837	0.405	0.405
		839/1	0.923	0.923
	योग :–	कुल 3 किता	**1.379**	**1.379**
217	महेन्द्रसिंह, प्रेमसिंह, बलवीरसिंह पिता प्रभूनाथसिंह, राधाकवर, सुगनकॅवर, लाडकॅवर, कृष्णाकॅवर पिता प्रभुनाथसिंह चंदाकॅवर बेवा प्रभूनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	828/4/2	0.025	0.025
		830/6/2	0.135	0.135
		889/2	0.076	0.076
	योग :–	कुल 3 किता	**0.236**	**0.236**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
218	बलरामसिंह पिता रावतसिंह जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	830/2	0.342	0.342
		830/4	0.143	0.143
	योग :–	कुल 2 किता	**0.485**	**0.485**
219	देवेन्द्रसिंह नाबा. पिता बलरामसिंह सर. माता नर्मदाकवर पति बलराम जाति राजपूत पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	830/5	0.143	0.143
	योग :–	कुल 1 किता	**0.143**	**0.143**
220	मोतीसिंह पिता भवरलाल जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	842/1/1	0.253	0.253
	योग :–	कुल 1 किता	**0.253**	**0.253**
221	सुमेरसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	842/1/2	0.253	0.253
	योग :–	कुल 1 किता	**0.253**	**0.253**
222	पुष्पाकुंवर पुत्री नारायणसिंह पति भंवरसिंह जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	842/2/2	0.708	0.708
	योग :–	कुल 1 किता	**0.708**	**0.708**
223	शिवपालसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	842/3	0.253	0.253
	योग :–	कुल 1 किता	**0.253**	**0.253**
224	रामप्रसाद पिता गोपीलाल हि. 1/2 भाग, उमरावबाई बेवा हजारीलाल हि. 1/6 भाग, कंवरलाल पिता हजारीलाल हि. 1/6 भाग, ममताबाई पिता हजारीलाल हि. 1/6 भाग जाति हरिजन पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	860/1	1.227	1.227
	योग :–	कुल 1 किता	**1.227**	**1.227**
225	बल्ला पिता गणपत हि. 1/4 भाग, जगा पिता गणपत हि. 1/4 भाग, हीरा पिता गणपत हि. 1/4 भाग, रामप्रसाद पिता गणपत हि. 1/4 भाग जाति चमार पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	860/2	0.367	0.367
	योग :–	कुल 1 किता	**0.367**	**0.367**
226	कैलाश पिता बंशीलाल जाति बलाई पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	860/3/1/1	0.053	0.053
		1726/1/3	0.253	0.253
	योग :–	कुल 2 किता	**0.306**	**0.306**
227	रामचरण पिता बंशीलाल जाति बलाई पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	860/3/1/2	0.053	0.053
	योग :–	कुल 1 किता	**0.053**	**0.053**
228	सुरेश पिता जमनालाल जाति मेहर पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	860/3/2	0.105	0.105
	योग :–	कुल 1 किता	**0.105**	**0.105**
229	पून्या पिता नाथू, शंकर पिता नाथू, कालू पिता सरवन, पन्या पिता सरवन, गुलाब बेवा सरवन जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	860/4	1.138	1.138
	योग :–	कुल 1 किता	**1.138**	**1.138**
230	जानकी बेवा भागीरथ जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	879/1	0.167	0.167
	योग :–	कुल 1 किता	**0.167**	**0.167**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
231	कन्हैयालाल पिता देवचंद जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	918/1	0.500	0.140
		918/3	0.632	0.632
	योग :–	कुल 2 किता	**1.132**	**0.772**
232	गोविन्द पिता शिवनारायण जाति ब्राहम्ण पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	918/4	0.658	0.480
	योग :–	कुल 1 किता	**0.658**	**0.480**
233	राजेन्द पिता भागीरथ जाति ब्राहम्ण पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	918/5	0.759	0.170
	योग :–	कुल 1 किता	**0.759**	**0.170**
234	घीसालाल पिता कन्हेयालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	918/7	0.500	0.330
	योग :–	कुल 1 किता	**0.500**	**0.330**
235	रामप्रसाद पिता गोपीलाल हि. 1/2 भाग, लताबाई पति रामप्रसाद हि. 1/2 भाग जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	918/8	0.500	0.500
	योग :–	कुल 1 किता	**0.500**	**0.500**
236	अमरलाल पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	918/9	0.500	0.500
		1699/1	0.531	0.080
		869/1	0.080	0.080
	योग :–	कुल 3 किता	**1.111**	**0.660**
237	रमेश पिता दयाराम जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	918/10	0.500	0.500
	योग :–	कुल 1 किता	**0.500**	**0.500**
238	माधू पिता कालू जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	918/11	0.500	0.500
	योग :–	कुल 1 किता	**0.500**	**0.500**
239	रमेश पिता बल्ला हि. 1/2 भाग, मंजू पिता रमेश हि. 1/2 भाग जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	920/1	1.800	1.700
	योग :–	कुल 1 किता	**1.800**	**1.700**
240	अशोक पिता हीरा जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	920/2	1.700	1.510
	योग :–	कुल 1 किता	**1.700**	**1.510**
241	करणसिंह पिता मायाराम जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	951/2	0.088	0.058
		961/2	0.329	0.329
		965/2	0.069	0.069
	योग :–	कुल 1 किता	**0.486**	**0.456**
242	पेपकंवर पति सुमेरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	951/3	0.088	0.088
		961/3	0.164	0.164
		962/3	1.059	0.060
		965/1	0.070	0.070
	योग :–	कुल 4 किता	**1.381**	**0.382**
243	कृष्णपालसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	953/1	0.007	0.007
		954/1/1	0.297	0.227
		955/1	0.006	0.006
	योग :–	कुल 3 किता	**0.310**	**0.240**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
244	राजेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	953/2	0.006	0.006
		954/1/2	0.297	0.277
		955/2	0.007	0.007
	योग :–	कुल 3 किता	**0.310**	**0.290**
245	भगवानसिंह पिता चेनसिंह जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	954/2	0.329	0.329
		956	0.266	0.146
		959/2	0.039	0.010
	योग :–	कुल 3 किता	**0.634**	**0.485**
246	मथरालाल पिता गोपीलाल जाति दर्जी हि. 93/10 भाग, प्रेमसिंह पिता बालमुकंद जाति भोई हि. 7/100 भाग पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	958/2	1.075	0.200
		958/1	1.075	0.180
		958/3	0.796	0.050
		960/2	0.278	0.238
		960/1	0.759	0.699
	योग :–	कुल 5 किता	**3.983**	**1.367**
247	भारतकंवर पत्नी रघुवीरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	961/1	0.165	0.165
		962/1	1.016	0.010
	योग :–	कुल 2 किता	**1.181**	**0.175**
248	कमलसिंह पिता करणसिंह जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	962/2/1	1.037	0.020
	योग :–	कुल 1 किता	**1.037**	**0.020**
249	बनेसिंह पिता करणसिंह जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	962/2/2	1.037	0.030
	योग :–	कुल 1 किता	**1.037**	**0.030**
250	राजपालसिंह नाबा. पिता परताबसिंह विष्णुकंवर बैवा परताबसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	964/2	0.682	0.020
	योग :–	कुल 1 किता	**0.682**	**0.020**
251	गुडडीबाई पत्नी निरपलसिंह पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	964/3	0.429	0.020
		964/4	0.330	0.060
	योग :–	कुल 2 किता	**0.759**	**0.080**
252	गिरवरसिंह पिता पर्वतसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	966/1	0.196	0.156
	योग :–	कुल 1 किता	**0.196**	**0.156**
253	गोपालसिंह पिता करणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	966/2	0.196	0.196
	योग :–	कुल 1 किता	**0.196**	**0.196**
254	हरिसिंह पिता जगनारायण सिंह राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	970/2	2.277	0.050
	योग :–	कुल 1 किता	**2.277**	**0.050**
255	रामसिंह पिता जगनारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	971	1.050	1.050
		972	0.430	0.110
	योग :–	कुल 2 किता	**1.480**	**1.160**
256	घनश्याम पिता चतरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	978	0.885	0.063
		979/1	0.413	0.313
	योग :–	कुल 2 किता	**1.298**	**0.376**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
257	देवराजसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	979/2/1	0.253	0.253
		981/1	0.767	0.600
	योग :–	कुल 2 किता	**1.020**	**0.853**
258	नरेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	979/2/2	0.253	0.110
		981/2	0.767	0.320
	योग :–	कुल 2 किता	**1.020**	**0.430**
259	भुपेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	979/2/3	0.253	0.090
		981/3	0.767	0.700
	योग :–	कुल 2 किता	**1.020**	**0.790**
260	जितेन्द्रसिंह पिता चतरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	979/3	0.346	0.070
	योग :–	कुल 1 किता	**0.346**	**0.070**
261	कुणालप्रतापसिंह पिता बहादुरसिंह हि. 1/2 भाग, ऊषाकुंवर बेवा बहादुरसिंह हि. 1/2 भाग जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सैलाना जिला रतलाम सुठालिया तहसील राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	982/2/1	0.339	0.090
	योग :–	कुल 1 किता	**0.339**	**0.090**
262	विजयसिंह पिता छोटेलाल जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	982/2/2	0.338	0.120
	योग :–	कुल 1 किता	**0.338**	**0.120**
263	जगदीश पिता लटूर हि. 1/2 भाग, मातरीबाई वेवा लटूर हि. 1/2 भाग जाति चमार पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	987	0.405	0.300
	योग :–	कुल 1 किता	**0.405**	**0.300**
264	दिलीपसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	989/1	0.392	0.392
		989/2	0.253	0.253
	योग :–	कुल 2 किता	**0.645**	**0.645**
265	विष्णु पिता मांगीलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	990	1.316	0.760
	योग :–	कुल 1 किता	**1.316**	**0.760**
266	रेखाकंवर पति मूलसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	997/1/1	0.587	0.100
	योग :–	कुल 1 किता	**0.587**	**0.100**
267	मानकुंवर पति मंगूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	997/1/2	0.586	0.040
	योग :–	कुल 1 किता	**0.586**	**0.040**
268	रामचरण पिता मांगीलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	997/2	0.542	0.130
		998	1.050	0.765
		1648/1	0.050	0.030
		1649	0.607	0.507
	योग :–	कुल 4 किता	**2.249**	**1.432**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
269	कमलाकॅवर बेवा भंवरलाल हि. 1/6 भाग, हरपालसिंह, नीरजपाल, उर्मिलाकुमारी पिता मंगूसिंह मानकवर बेवा मंगूसिंह हि. 1/6 भाग, मूलसिंह पिता लालसिंह हि. 1/6 भाग, सुगनकंवर पिता ज्ञालसिंह हि. 1/6 भाग, जयवर्धनसिंह रितिकाकंवर नाबा. पिता मदरूपसिंह, पूजाकंवर बेवा मदरूपसिंह हि. 1/6 भाग, बीनाकंवर पिता लालसिंह हि. 1/6 भाग जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1000	0.595	0.170
	योग :–	कुल 1 किता	**0.595**	**0.170**
270	गजाधर पिता मिश्रीलाल जाति भोई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1002/3	0.114	0.040
	योग :–	कुल 2 किता	**0.114**	**0.040**
271	सौदानसिंह पिता प्रहलादसिंह हि. 1/2 भाग, भेरूसिंह पिता प्रहलादसिंह हि. 1/2 भाग जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1076	0.949	0.050
		1082	0.152	0.080
	योग :–	कुल 2 किता	**1.101**	**0.130**
272	भारतसिंह पिता परसराम जाति चमार पता टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1081	0.215	0.065
	योग :–	कुल 1 किता	**0.215**	**0.065**
273	रामभरोसा, जगन्नाथ पिता मदनलाल जाति चमार पता टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1122	0.392	0.060
	योग :–	कुल 1 किता	**0.392**	**0.060**
274	अमृत पिता गंगाधर धापू बेबा गंगाधर जाति गाडरी पता टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1124/1	0.101	0.101
		1135/1	0.272	0.190
		1140/1	0.310	0.040
	योग :–	कुल 3 किता	**0.683**	**0.331**
275	जगदीश पिता प्रभूलाल जाति गाढरी पता टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1124/2/1	0.034	0.034
		1135/2/1	0.090	0.030
	योग :–	कुल 2 किता	**0.124**	**0.064**
276	गणपत पिता प्रभुलाल जाति गाडरी पता सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1124/2/2	0.033	0.015
		1135/2/2	0.091	0.030
	योग :–	कुल 2 किता	**0.124**	**0.045**
277	दोलतराम पिता प्रभुलाल जाति गाडरी पता सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1124/2/3	0.034	0.018
	योग :–	कुल 1 किता	**0.034**	**0.018**
278	चंदनसिंह पिता सोजीराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1125/2/2	0.095	0.040
		1129	0.101	0.020
	योग :–	कुल 2 किता	**0.196**	**0.060**
279	बिरजमोहन पिता जमनालाल जाति खाती पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1145/1	0.106	0.106
	योग :–	कुल 1 किता	**0.106**	**0.106**
280	सुमेरसिंह, अजबसिंह, राजेश, संतोषबाई पिता जगन्नाथ मु. कृष्णाबाई बेबा जगन्नाथ जाति गुर्जर पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1145/2	0.106	0.106
	योग :–	कुल 1 किता	**0.106**	**0.106**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
281	खुशीलाल पिता बिहारीलाल जाति गुर्जर पता सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1145/3/1	0.041	0.041
		1143/1	0.154	0.020
	योग :–	कुल 2 किता	**0.195**	**0.061**
282	हरिकिशन पिता बिहारीलाल हि. 1/2 भाग, बाबरीबाई बेवा हरीसिंह जाति गुर्जर पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1145/3/2	0.051	0.051
		1143/2	0.112	0.060
	योग :–	कुल 2 किता	**0.163**	**0.111**
283	दिनेश पिता मानसिंह हि.1/4 भाग, मंगूसिंह पिता मानसिंह हि. 1/4 भाग, जशवंतसिंह पिता मानसिंह हि. 1/4 भाग, भंवरीबाई बेवा मानसिंह हि. 1/4 भाग जाति गुर्जर पता टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1149	0.139	0.060
		1150	0.126	0.063
	योग :–	कुल 2 किता	**0.265**	**0.123**
284	गंगा बेबा भागमल, रोडिया पिता भागमल जाति धोबी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1159	0.126	0.060
	योग :–	कुल 1 किता	**0.126**	**0.060**
285	दरयावसिंह पिता वंशीलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1160	0.253	0.150
	योग :–	कुल 1 किता	**0.253**	**0.150**
286	सुनील, प्रदीप पिता मिश्रीलाल जाति तमोली पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1168/1	0.164	0.020
		1168/2	0.165	0.020
	योग :–	कुल 2 किता	**0.329**	**0.040**
287	कमलाबाई पति जगमोहनसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1169	0.190	0.020
	योग :–	कुल 1 किता	**0.190**	**0.020**
288	प्रेमसिंह पिता बालमुकुंद जाति भोई पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1287/2	0.114	0.114
	योग :–	कुल 1 किता	**0.114**	**0.114**
289	दोलतराम पिता प्रभुलाल जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1350/1	0.146	0.046
	योग :–	कुल 1 किता	**0.146**	**0.046**
290	भारतसिंह पिता रामतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मोरिखो भूमि स्वामी	1647	0.139	0.040
	योग :–	कुल 1 किता	**0.139**	**0.040**
291	विष्णू पिता मांगीलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1648/2	0.133	0.040
	योग :–	कुल 1 किता	**0.133**	**0.040**
292	राधेश्याम पिता मोतीलाल हि. 1/10 भाग, कमलसिंह पिता मोतीलाल हि. 1/10 भाग, ,टीकमसिंह पिता मोतीलाल हि. 1/10 भाग, रविराज पिता मोतीलाल हि. 1/10 भाग, उमरावबाई बेवा मोतीलाल हि. 1/10 भाग, अम्रतलाल पिता किशनलाल हि. 1/10 भाग, पर्वतसिंह पिता किशनलाल हि. 1/10 भाग, नारायणसिंह पिता किशनलाल हि.. 1/10 भाग, दौलतसिंह पिता किशनलाल हि. 1/10 भाग, शैतानबाई पिता किशनलाल हि. 1/10 भाग जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1652	0.202	0.090
		1653	2.655	0.050
		1654	1.328	0.700
		1655	0.443	0.413
	योग :–	कुल 4 किता	**4.628**	**1.253**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
293	वालमुकन्द पिता अमरचन्द जाति गाडरी पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1660/1	1.973	1.973
	योग :–	कुल 1 किता	**1.973**	**1.973**
294	इमरत पिता भागमल मु. अमरी बेवा भागमल नाबा. विजय मनीषा पिता भगवानसिंह सरमाता राजूबाई बेवा भगवानसिंह, राजूबाई बवा भगवानसिंह, जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1660/2	2.719	2.719
	योग :–	कुल 1 किता	**2.719**	**2.719**
295	सरजनसिंह पिता प्रभुलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1660/3	1.973	1.600
	योग :–	कुल 1 किता	**1.973**	**1.600**
296	रामकिशन पिता मोतीलाल जाति धोबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1661/1	1.049	0.700
	योग :–	कुल 1 किता	**1.049**	**0.700**
297	जगदीश पिता मोतीलाल जाति धोबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1661/2	1.050	0.550
	योग :–	कुल 1 किता	**1.050**	**0.550**
298	रामबाबू पिता प्रभुलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1662/1	1.090	0.180
		1663/1	0.067	0.067
	योग :–	कुल 2 किता	**1.157**	**0.247**
299	राधेश्याम पिता प्रभूलाल जाति गाडरी पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1662/2	0.839	0.260
		1663/2	0.311	0.250
	योग :–	कुल 2 किता	**1.150**	**0.510**
300	निरपतसिंह पिता शंकरलाल जाति लोदी पता सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1664/1	1.185	0.090
	योग :–	कुल 1 किता	**1.185**	**0.090**
301	कन्हैयालाल पिता भंवरलाल जाति धोबी पता सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1665	0.569	0.150
	योग :–	कुल 1 किता	**0.569**	**0.150**
302	विश्रामसिंह पिता रामरतन जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम मोरिखो भूमि स्वामी	1667	1.783	0.983
	योग :–	कुल 1 किता	**1.783**	**0.983**
303	अमृतसिंह पिता शिवनाथसिंह जाति राजपूत पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1689/1	0.449	0.210
	योग :–	कुल 1 किता	**0.449**	**0.210**
304	भेरूसिंह पिता कमलसिंह जाति राजपूत पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1689/2/1	0.212	0.160
	योग :–	कुल 1 किता	**0.212**	**0.160**
305	राजेन्द्रसिंह पिता कमलसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1689/2/2	0.288	0.220
	योग :–	कुल 1 किता	**0.288**	**0.220**
306	मोतीलाल पिता मोहनलाल जाति चमार पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1699/2	0.278	0.238
	योग :–	कुल 1 किता	**0.278**	**0.238**
307	नन्नूलाल पिता भवंरलाल जाति धोबी पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1704/1	0.611	0.100
	योग :–	कुल 1 किता	**0.611**	**0.100**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
308	रूकमणीबाई बेवा मथरालाल जाति खाती पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1705	0.266	0.216
		1708/1/1	1.682	0.700
	योग :–	कुल 2 किता	**1.948**	**0.916**
309	सावित्रीबाई बेवा बिष्णुप्रसाद हि. 1/12 भाग, महेश पिता पुनमचंद हि. 1/4 भाग, राजकुमार नाबा. पिता विष्णुप्रसाद संरक्षक सरपरस्त माता सावित्रीबाई बेवा विष्णुपसाद हि. 1/12 भाग, बबलू नाबा. पिता विष्णुप्रसाद संरक्षक सरपरस्त माता सावित्रीबाई बेवा विष्णुप्रसाद हि. 1/12 भाग, दिनेश पिता पुनमचंद हि. 1/4 भाग, मनीष पिता पुनमचंद हि. 1/4 भाग जाति खाती पता तहसील सुठालिया राजगढ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1707/1	0.797	0.797
	योग :–	कुल 1 किता	**0.797**	**0.797**
310	हरीबाई पत्नी रामदयाल जाति धोबी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1707/2	0.253	0.253
	योग :–	कुल 1 किता	**0.253**	**0.253**
311	महेश पिता रामचरण जाति धोबी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1713/2	1.012	0.020
		1718/2	0.253	0.100
	योग :–	कुल 2 किता	**1.265**	**0.120**
312	दिनेश पिता कन्हैयालाल जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1715/1/1	0.759	0.100
		1717/1/1	0.063	0.040
	योग :–	कुल 2 किता	**0.822**	**0.140**
313	जगदीश पिता कन्हैयालाल जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1715/1/2	0.739	0.250
		1717/1/2	0.063	0.040
	योग :–	कुल 2 किता	**0.802**	**0.290**
314	प्रेमसिंह संजू पिता मानसिंह जसोदीबाई बेवा मानसिंह जाति लोदी पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश	1715/2	1.499	0.500
		1717/2	0.127	0.127
	योग :–	कुल 2 किता	**1.626**	**0.627**
315	देवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1716/1	0.838	0.530
		1722	0.632	0.140
	योग :–	कुल 2 किता	**1.470**	**0.670**
316	दिगविजय नाबालिग पिता देवराजसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1716/2	0.647	0.050
		1719/1	0.189	0.189
		1719/2	0.380	0.290
	योग :–	कुल 3 किता	**1.216**	**0.529**
317	यंशवतसिंह गोविन्दसिंह थानुसिंह प्रेमसिंह नगेन्द्रसिंह पिता गजराजसिंह हेमाकुवर बेवा गजराजसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1716/3	0.327	0.030
	योग :–	कुल 1 किता	**0.327**	**0.030**
318	गजराजसिंह पिता हनमतसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1716/4	0.705	0.350
	योग :–	कुल 1 किता	**0.705**	**0.350**
319	राजेन्द्रसिंह पिता पर्वतसिंह जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1721/1	0.150	0.150
	योग :–	कुल 1 किता	**0.150**	**0.150**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
320	गिरधरसिंह पिता पर्वतसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1721/2	0.191	0.191
	योग :–	कुल 1 किता	**0.191**	**0.191**
321	बालमुकंद पिता जमनालाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1726/1/2	0.379	0.379
	योग :–	कुल 1 किता	**0.379**	**0.379**
322	लक्ष्मीनारायण पिता काशीराम जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1726/2	1.454	1.454
	योग :–	कुल 1 किता	**1.454**	**1.454**
323	सज्जनसिंह पंवार पिता श्री रणजीतसिंह पंवार जाति राजपूत पता राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1730/1	1.109	0.500
		1730/2	1.110	0.280
		1730/4	1.110	0.080
	योग :–	कुल 3 किता	**3.329**	**0.860**
324	सुरेन्द्रसिंह पिता सज्जनसिंह जाति राजपूत पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1730/3	1.110	0.130
	योग :–	कुल 1 किता	**1.110**	**0.130**
325	सुरेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1732/2/1	0.190	0.120
	योग :–	कुल 1 किता	**0.190**	**0.120**
326	मोतीलाल पिता घीसालाल जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1702/44/1	0.146	0.106
	योग :–	कुल 1 किता	**0.146**	**0.106**
327	मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1702/44/2	0.127	0.020
	योग :–	कुल 1 किता	**0.127**	**0.020**
328	गोपाल पिता मोतीलाल जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1702/44/3	0.127	0.010
	योग :–	कुल 1 किता	**0.127**	**0.010**
329	हरिराम पिता जगन्नाथ हि. 1/2 भाग, मुंकदराम पिता जगन्नाथ हि. 1/2 भाग जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1702/41	0.800	0.290
	योग :–	कुल 1 किता	**0.800**	**0.290**
330	कैलाशनारायण पिता जमनालाल जाति महाजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1702/1/42/1	0.800	0.290
	योग :–	कुल 1 किता	**0.800**	**0.290**
331	धर्मेन्द्रसिंह पिता भारतसिंह जाति राजपूत पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1747	0.581	0.140
		1748	0.670	0.390
		1750	1.176	0.220
	योग :–	कुल 3 किता	**2.427**	**0.750**
332	वलबीरसिंह पिता कल्याणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1752	1.088	0.430
	योग :–	कुल 1 किता	**1.088**	**0.430**
333	राजपालसिंह पिता श्यामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1755	0.557	0.557
	योग :–	कुल 1 किता	**0.557**	**0.557**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
334	भंवरलाल पिता जगन्नाथ हि. 1/8 भाग, भूराजी पिता जगन्नाथ हि. 1/8 भाग, गंगाराम पिता जगन्नाथ हि. 1/8 भाग, देवसिंह पिता जगन्नाथ हि. 1/8 भाग, कमलेश पिता रामप्रसाद हि. 1/4 भाग, गीता पिता रामप्रसाद हि. 1/4 भाग जाति भोई पता सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1767	0.911	0.911
	योग :–	कुल 1 किता	**0.911**	**0.911**
335	मुलचंद पिता देवीराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1736/1/1	0.506	0.300
	योग :–	कुल 1 किता	**0.506**	**0.300**
336	मुलचंद पिता देवीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1736/1/2/2	0.126	0.080
	योग :–	कुल 1 किता	**0.126**	**0.080**
337	जगदीश पिता लटूर जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1736/1/2/1	0.037	0.020
	योग :–	कुल 1 किता	**0.037**	**0.020**
338	दुलीचन्द पिता हरिनारायण जाति दर्जी पता ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1736/2/1	0.506	0.350
	योग :–	कुल 1 किता	**0.506**	**0.350**
339	फरियादखां पिता काशम खां हि. 1/2 भाग, लियाकतखां पिता काशमखां हि. 1/2 भाग पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1736/2/2/1	0.036	0.018
	योग :–	कुल 1 किता	**0.036**	**0.018**
340	गुलाब बाई वेवा सरवन जाति चमार पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1736/2/2/2	1.138	0.380
	योग :–	कुल 1 किता	**1.138**	**0.380**
341	गोविन्दसिंह, शंकरसिंह, चिडियाकुंवर पिता प्रतापसिंह जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	694/6	1.448	1.448
		828/3	0.038	0.038
		830/1	0.203	0.203
		889/1	0.076	0.076
		890/1	0.038	0.036
		891/2	0.715	0.715
	योग :–	कुल 6 किता	**2.518**	**2.516**
342	जगन्नाथ पिता मदनलाल जाति चमार पता तहसील ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	879/2	0.200	0.200
	योग :–	कुल 1 किता	**0.200**	**0.200**
343	जमनालाल पिता काशीराम जाति चमार पता निवसी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1726/1/1	0.822	0.822
	योग :–	कुल 1 किता	**0.822**	**0.822**
344	देवेन्द्रसिंह पिता जगमोहन जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	681/2	2.665	2.655
		719/1/2	1.665	1.615
	योग :–	कुल 2 किता	**4.330**	**4.270**
345	निरपतसिंह पिता चौसरलाल जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	255/1	0.392	0.392
	योग :–	कुल 1 किता	**0.392**	**0.392**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
346	जगमोहन पिता मोतीलाल, शांतिबाई, सावित्रीबाई, धापूबाई पिता मोतीलाल प्यारीबाई बेवा मोतीलाल हि. 50 पैसे जीतू, सोनू पिता भारतसिंह कृष्णाबाई बेवा भारतसिंह , कल्याणसिंह धनसिंह पिता हरिकिशन द्रोपतीबाई पुत्री हरिकिशन, गयाबाई बेवा हरकिशन हि. 50 पैसे जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	255/2	0.443	0.443
	योग :–	कुल 1 किता	**0.443**	**0.443**
347	कमलसिंह पिता प्रभूलाल जाति गाडरी पता टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1663/3	0.659	0.659
	योग :–	कुल 1 किता	**0.659**	**0.659**
348	महिपालसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	719/1/1	1.070	1.047
	योग :–	कुल 1 किता	**1.070**	**1.047**
349	पुष्पेन्द्रसिंह नाबा. पिता विरेन्द्रसिंह संरक्षक सरमाता सीमाकँवर पति विरेन्द्र जाति राजपूत पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	719/1/3	1.728	1.701
	योग :–	कुल 1 किता	**1.728**	**1.701**
350	किशोर सिंह पिता विजयसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	830/3	0.144	0.144
	योग :–	कुल 1 किता	**0.144**	**0.144**
351	पन्नालाल पिता देवालाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	51/2	0.694	0.694
	योग :–	कुल 1 किता	**0.694**	**0.694**
352	धूरीलाल पिता देवालाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	51/3	0.441	0.300
	योग :–	कुल 1 किता	**0.441**	**0.300**
353	कन्हैयालाल पिता देवालाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	51/4	0.383	0.180
	योग :–	कुल 1 किता	**0.383**	**0.180**
354	धनराज पिता देवबगस हि. 1/3 भाग, चंदरसिंह पिता देवबगस हि. 1/3 भाग, मोरबाई बेवा देवबगस हि. 1/3 भाग जाति गुर्जर पता टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	420/2	0.221	0.216
	योग :–	कुल 1 किता	**0.221**	**0.216**
355	बालकिशन पिता हजारीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	420/3	0.222	0.217
	योग :–	कुल 1 किता	**0.222**	**0.217**
356	अजय लोधी नाबालिग पिता अमरतलाल संरक्षक पिता अमरतलाल पिता नर्बेसिंह जाति लोधी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	143/2	0.031	0.031
	योग :–	कुल 1 किता	**0.031**	**0.031**
357	हरिसिंह पिता गंगाधर हि. 1/2 भाग, कमलाबाई पिता गंगाधर हि. 1/2 जाति भोई पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34/2/1	0.516	0.486
	योग :–	कुल 1 किता	**0.516**	**0.486**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
358	गोपालसिंह पिता किशन सिंह जाति राजपूत पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	562/1/2	0.019	0.019
	योग :–	कुल 1 किता	**0.019**	**0.019**
359	गोविन्द सिंह पिता किशन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	562/2/2	0.019	0.019
	योग :–	कुल 1 किता	**0.019**	**0.019**
360	लक्ष्मीनारायण पिता दयाराम जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	250/1	0.084	0.020
	योग :–	कुल 1 किता	**0.084**	**0.020**
361	त्रिलोककुमार पिता दयाराम जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	250/2	0.986	0.010
	योग :–	कुल 1 किता	**0.986**	**0.010**
362	रामबाबू पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	387/1	0.937	0.390
	योग :–	कुल 1 किता	**0.937**	**0.390**
363	लक्ष्मीनारायण पिता रामकिशन हि. 1/2 भाग, कुमेरसिंह पिता रामकिशन हि. 1/2 भाग जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	951/1	0.170	0.100
	योग :–	कुल 1 किता	**0.170**	**0.100**
364	सुमेरसिह पिता बलबहादुरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	685/2/2	0.291	0.291
	योग :–	कुल 1 किता	**0.291**	**0.291**
365	दयालसिंह पिता काशीराम जाति गुर्जर पता गुर्जरखेड़ी राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	11/2	0.632	0.632
	योग :–	कुल 1 किता	**0.632**	**0.632**
366	मोहनसिंह, दरियावसिंह पिता विजयसिंह लाड़बाई बेवा विजयसिंह जाति राजपूत पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	276/2/1	1.378	1.378
	योग :–	कुल 1 किता	**1.378**	**1.378**
367	प्रतिसिंह, मनियाबाई पिता गोपाल जाति लोधी पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	375/2	0.057	0.057
	योग :–	कुल 1 किता	**0.057**	**0.057**
368	चन्दनसिंह नाबालिक पिता ग्यारसीराम जाति भोई पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	624/1	0.379	0.379
	योग :–	कुल 1 किता	**0.379**	**0.379**
369	मांगीलाल, मथरालाल, शिवनारायण पिता भोना बैजनाथ पिता भोना जाति धोबी पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	423/1/2	0.601	0.601
	योग :–	कुल 1 किता	**0.601**	**0.601**
370	देवा पिता कनीराम पता टोड़ी सुठालिया राजगढ़ म.प्र.भूमि स्वामी	860/3/3	0.105	0.105
	योग :–	कुल 1 किता	**0.105**	**0.105**
371	उक्त सर्वे नं. वर्तमान खसरे मे दर्ज नही है।	797/1	0.144	0.144
	योग :–	कुल 1 किता	**0.144**	**0.144**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
372	उक्त सर्वे नं. वर्तमान खसरे मे दर्ज नही है।	900/1/1	0.491	0.491
	योग :–	कुल 1 किता	**0.491**	**0.491**
373	शमूसिंह पिता मिश्रीलाल जाति लोधी पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	133/2/1	0.145	0.145
	योग :–	कुल 1 किता	**0.145**	**0.145**
374	बालमुकुंद पिता हरचंद पता टोडी सुठालिया राजगढ़ म.प्र.	302/4	0.048	0.048
	योग :–	कुल 1 किता	**0.048**	**0.048**
375	खसरे मे नाम अकिंत नही है।	561/2	0.430	0.430
	योग :–	कुल 1 किता	**0.430**	**0.430**
376	उक्त सर्वे नं. वर्तमान खसरे मे दर्ज नही है।	585/3/2	0.153	0.153
	योग :–	कुल 1 किता	**0.153**	**0.153**
377	हरकिशन पिता छीतर जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	477/1/2	0.048	0.024
	योग :–	कुल 1 किता	**0.048**	**0.024**
378	उक्त सर्वे नं. वर्तमान खसरे मे दर्ज नही है।	694/1/3	0.350	0.350
	योग :–	कुल 1 किता	**0.350**	**0.350**
379	उक्त सर्वे नं. वर्तमान खसरे मे दर्ज नही है।	694/7	0.428	0.428
	योग :–	कुल 1 किता	**0.428**	**0.428**
380	उक्त सर्वे नं. वर्तमान खसरे मे दर्ज नही है।	696/2	1.518	1.518
	योग :–	कुल 1 किता	**1.518**	**1.518**
381	जगन्नाथ पिता हीरालाल पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	518/3	0.098	0.098
	योग :–	कुल 1 किता	**0.098**	**0.098**
382	देव्या पिता गोपाल पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	518/4	0.099	0.099
	योग :–	कुल 1 किता	**0.099**	**0.099**
383	चंदरसिह पिता ग्यारसीराम जाति अहीर पति निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	312/1/2	0.017	0.017
	योग :–	कुल 1 किता	**0.017**	**0.017**
384	भंवरीबाई बेवा बालमुकुंद, कस्तुरी बेवा गोपीलाल, घीसा, मोती, गंगाधर, रमेश पिता मिश्री, परस्या, गोरिया, सेवाराम, भंवरया, ग्यारस्या पिता अमरा, गजरी बेवा अमरा जाति भोई पता टोडी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	737/4	0.056	0.056
	योग :–	कुल 1 किता	**0.056**	**0.056**
385	अर्जुनसिंह पिता नाथूलाल हि. 1/5 भाग, रमेश पिता नाथूलाल हि. 1/5 भाग, अभयसिंह पिता नाथूलाल हि. 1/5 भाग, मोहनबाई पिता नाथूलाल हि. 1/5 भाग, शांतिबाई पिता नाथूलाल हि. 1/5 भाग जाति लोदी पता टोडी तहसील ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	144/1	0.481	0.050
		51/1/1	0.063	0.063
	योग :–	कुल 2 किता	**0.544**	**0.113**
386	खसरे मे नाम अकिंत नही है।	144/2	0.481	0.051
	योग :–	कुल 1 किता	**0.481**	**0.051**
387	हरकिशन पिता छीतर जाति लोदी पता टोडी सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	529/4	0.065	0.065
	योग :–	कुल 1 किता	**0.065**	**0.065**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
388	उक्त सर्वे नं. वर्तमान खसरे मे दर्ज नही है।	626/1/2/1	0.148	0.148
	योग :–	कुल 1 किता	**0.148**	**0.148**
389	उक्त सर्वे नं. वर्तमान खसरे मे दर्ज नही है।	424/4	0.597	0.597
	योग :–	कुल 1 किता	**0.597**	**0.597**
390	उक्त सर्वे नं. वर्तमान खसरे मे दर्ज नही है।	94/4	0.088	0.088
	योग :–	कुल 1 किता	**0.088**	**0.088**
391	प्रीतमसिंह, निरंजनसिंह पिता अर्जुनसिंह कलाबाई बेवा अर्जुनसिंह जाति लोधी पता टोडी सुठालिया राजगढ़ म.प्र.	118/3/3	0.252	0.172
	योग :–	कुल 1 किता	**0.252**	**0.172**
392	दरियावसिंह पिता बंषीलाल जाति लोधी पता टोडी सुठालिया राजगढ़ म.प्र.	118/3/4	0.021	0.021
	योग :–	कुल 1 किता	**0.021**	**0.021**
393	दरियावसिंह पिता बंषीलाल जाति लोधी पता टोडी सुठालिया राजगढ़ म.प्र.	238/1	0.045	0.045
	योग :–	कुल 1 किता	**0.045**	**0.045**
394	उक्त सर्वे नं. वर्तमान खसरे मे दर्ज नही है।	1721/3	0.190	0.190
	योग :–	कुल 1 किता	**0.190**	**0.190**
395	खसरे मे नाम अकिंत नही है।	14/2	0.417	0.417
	योग :–	कुल 1 किता	**0.417**	**0.417**
396	खसरे मे नाम अकिंत नही है।	50/1/2	0.272	0.260
	योग :–	कुल 1 किता	**0.272**	**0.260**
367	खसरे मे नाम अकिंत नही है।	139/1	0.070	0.070
	योग :–	कुल 1 किता	**0.070**	**0.070**
398	खसरे मे नाम अकिंत नही है।	149/5	0.094	0.094
	योग :–	कुल 1 किता	**0.094**	**0.094**
399	खसरे मे नाम अकिंत नही है।	150/6	0.034	0.034
	योग :–	कुल 1 किता	**0.034**	**0.034**
400	खसरे मे नाम अकिंत नही है।	509	0.025	0.025
	योग :–	कुल 1 किता	**0.025**	**0.025**
401	खसरे मे नाम अकिंत नही है।	548	0.632	0.632
	योग :–	कुल 1 किता	**0.632**	**0.632**
402	खसरे मे नाम अकिंत नही है।	572/1	0.418	0.418
	योग :–	कुल 1 किता	**0.418**	**0.418**
403	गंगाधर पिता कन्हैयालाल जाति भोई पता टोडी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	631/1	0.136	0.136
	योग :–	कुल 1 किता	**0.136**	**0.136**
404	खसरे मे नाम अकिंत नही है।	735	0.126	0.126
	योग :–	कुल 1 किता	**0.126**	**0.126**
405	खसरे मे नाम अकिंत नही है।	744	0.089	0.089
	योग :–	कुल 1 किता	**0.089**	**0.089**
406	खसरे मे नाम अकिंत नही है।	826/2	0.017	0.017
	योग :–	कुल 1 किता	**0.017**	**0.017**
407	खसरे मे नाम अकिंत नही है।	848/2	0.063	0.063
	योग :–	कुल 1 किता	**0.063**	**0.063**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
408	खसरे मे नाम अकिंत नही है।	985	0.405	0.190
	योग :–	कुल 1 किता	**0.405**	**0.190**
409	खसरे मे नाम अकिंत नही है।	1692/2/2	0.113	0.113
	योग :–	कुल 1 किता	**0.113**	**0.113**
410	खसरे मे नाम अकिंत नही है।	1760	0.658	0.658
	योग :–	कुल 1 किता	**0.658**	**0.658**
411	देवराज पिता नाथू हि. 1/2 भाग, भवरीबाई बेवा नाथू हि. 1/2 भाग जाति राजपूत पता तहसील ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	991/1	3.971	0.210
	योग :–	कुल 1 किता	**3.971**	**0.210**
412	तुषारसिंह नाबालिग पिता प्रदीपसिंह संरक्षक सरमाता सपना कुंवर बेवा प्रदीपसिंह हि. 1/6 भाग, धरासिंह नाबालिग पिता प्रदीपसिंह संरक्षक सपनाकुंवर बेवा प्रदीपसिंह हि. 1/6 भाग, दीपकसिंह पिता देवीसिंह हि. 1/2 भाग, सपनाकुंवर बेवा प्रदीपसिंह हि. 1/6 भाग जाति राजपूत पता निवासी शाजापुर राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1734/1	2.113	2.113
	योग :–	कुल 1 किता	**2.113**	**2.113**
413	सपनाकुंवर बेवा प्रदीपसिंह जाति राजपूत निवासी शाजापुर राजगढ़ मध्य प्रदेश भमि स्वामी	1734/2	0.253	0.253
	योग :–	कुल 1 किता	**0.253**	**0.253**
414	नगेन्द्रसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम	681/3/2	3.367	3.367
	योग :–	कुल 1 किता	**3.367**	**3.367**
415	कमलाबाई बेवा भंवरलाल भंवरबाई बेवा लालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	687/2/1	1.785	1.426
	योग :–	कुल 1 किता	**1.785**	**1.426**
416	मोती पिता मोहन जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	869/3	0.080	0.076
	योग :–	कुल 1 किता	**0.080**	**0.076**
417	जगन्नाथ पिता मदन जाति चमार हि. 1/2 भाग, भारोसा पिता मदन हि. 1/2 भाग जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	869/2	0.080	0.076
	योग :–	कुल 1 किता	**0.080**	**0.076**
418	रमेश सेतानसिंह पिता अमरलाल समन्त्राबाई कल्लीबाई पिता अमरलाल शांतिबाई बेवा अमरलाल जाति धोबी पता निवासी ग्राम टोडी तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	320/2	0.297	0.015
	योग :–	कुल 1 किता	**0.297**	**0.015**
419	करनसिंह पिता नाथूलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	241/2	0.246	0.007
	योग :–	कुल 1 किता	**0.246**	**0.007**
420	राजेन्द्रसिंह जगमोहनसिंह महिपालसिंह पिता भंवरलाल मु. हेमकंवर बेवा भंवरलाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	620/1/1	1.000	1.000
	योग :–	कुल 1 किता	**1.000**	**1.000**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्ट.में)	प्रभावित रकबा (हेक्ट.में)
421	ग्यारसीबाई पिता जगन्नाथ जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसीलदार सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	609/4/1	0.100	0.100
	योग :–	कुल 1 किता	**0.100**	**0.100**
422	छोटिया पिता जालम जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	429/2	0.400	0.260
	योग :–	कुल 1 किता	**0.400**	**0.260**
423	भरोसा पिता मांगीलाल हि. 1/2 भाग, मेहताब पिता मांगीलाल हि. 1/2 भाग जाति लोदी पता निवासी गाम तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	267	1.543	0.040
	योग :–	कुल 1 किता	**1.543**	**0.040**
424	करनसिंह पिता देवालाल जाति लोधी पता टोडी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	526/2	0.010	0.010
	योग :–	कुल 1 किता	**0.010**	**0.010**
425	मोहनलाल पिता मिश्रीलाल जाति धोबी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	312/1/4	0.018	0.018
	योग :–	कुल 1 किता	**0.018**	**0.018**
	महायोग :–	कुल 646 किता	**284.246**	**189.551**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–73–भू–अर्जन–2025 मैहर, दिनांक 28 अप्रैल 2025

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013]

(धारा 25 के अन्तर्गत)

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्रधिकरण के रीवा शाखा नहर अंतर्गत वितरिका/माइनर/सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत पूर्व मे भूमि अर्जन के प्रस्ताव पर म0प्र0 राजपत्र में दिनांक 29.09.2023 को धारा–11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम बठिया की भू–अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है।

म0प्र0 शासन की अधिसूचना कमांक एफ 16–15–(1)–2014–सात–शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा।

प्रभावित ग्राम बठिया तह0 मैहर की निजी भूमि के भू–अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के उपबंधो के अनुसार राजपत्र में दिनांक 15.03.2024 को कराया जाकर धारा– 20 एवं 21 के तहत अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी, मैहर को अधिकृत किया गया था।

(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 19 के प्रकाशन दिनांक 15/03/2024 से 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन एक वर्ष की तिथि के मध्य अवार्ड पारित नहीं हो सका है जिसके निम्नांकित कारण हैं:–

(क) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि तक अवार्ड पारित नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क) वर्णित कारण विद्यमान थे ।

(B) इस प्रकार प्रस्तुत भूअर्जन का प्रकरण, नहरों के माध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बंद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित हैं ।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की अवार्ड पारित करने की समयावधि मे 12 माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील मैहर की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढायी जाती है।

1. भूमि का वर्णनः–

क0	ग्राम का नाम	निजी भूमि रकवा (क्षे0 लगभग)	धारा 19 के जारी होने का दिनांक	धारा 19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा 25 के अंतर्गत समयावधि में की गयी वृद्धि	टीप
1	बठिया	5.8600	15.03.2024	14.03.2025	धारा 25 अंतर्गत अवार्ड पारित करने हेतु 12 माह की वृद्धि की जाती है।	बिन्दु कमांक A एवं B के अनुसार

2. इस प्रकार ग्राम बठिया की धारा–19 की अधिसूचना प्रकाशन से धारा–25 के अन्तर्गत 12 माह की वृद्धि की जाती है ।
3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :– बरगी व्यपवर्तन परियोजना की रीवा शाखा नहर/ उपशाखा नहर/ वितरिका नहर/ माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग मैहर जिला मैहर एवं कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर के भू–अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है ।

क्र.–74–भू–अर्जन–2025

[भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013]

(धारा 25 के अन्तर्गत)

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्रधिकरण के रीवा शाखा नहर अंतर्गत वितरिका/माइनर/सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत पूर्व में भूमि अर्जन के प्रस्ताव पर म0प्र0 राजपत्र में दिनांक 28.04.2023 को धारा–11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम सिरमिली की भू–अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है।

म0प्र0 शासन की अधिसूचना कमांक एफ 16–15–(1)–2014–सात–शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा।

प्रभावित ग्राम सिरमिली तह0 मैहर की निजी भूमि के भू–अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के उपबंधो के अनुसार राजपत्र में दिनांक 16.02.2024 को कराया जाकर धारा– 20 एवं 21 के तहत अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी, मैहर को अधिकृत किया गया था।

(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 19 के प्रकाशन दिनांक 16/02/2024 से 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन एक वर्ष की तिथि के मध्य अवार्ड पारित नहीं हो सका है जिसके निम्नांकित कारण हैं:–

(क) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि तक अवार्ड पारित नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क) वर्णित कारण विद्यमान थे ।

(B) इस प्रकार प्रस्तुत भूअर्जन का प्रकरण, नहरों के माध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बंद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित हैं ।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की अवार्ड पारित करने की समयावधि में 12 माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील मैहर की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढायी जाती है।

1. भूमि का वर्णनः–

क0	ग्राम का नाम	निजी भूमि रकवा (क्षे0 लगभग)	धारा 19 के जारी होने का दिनांक	धारा 19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा 25 के अंतर्गत समयावधि में की गयी वृद्धि	टीप
1.	सिरमिली	1.7430	16.02.2024	15.02.2025	धारा 25 अंतर्गत अवार्ड पारित करने हेतु 12 माह की वृद्धि की जाती है।	बिन्दु कमांक A एवं B के अनुसार

2. इस प्रकार ग्राम सिरमिली की धारा–19 की अधिसूचना प्रकाशन से धारा–25 के अन्तर्गत 12 माह की वृद्धि की जाती है ।
3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :– बरगी व्यपवर्तन परियोजना की रीवा शाखा नहर/ उपशाखा नहर/ वितरिका नहर/ माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग मैहर जिला मैहर एवं कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर के भू–अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है ।

क्र.–75–भू–अर्जन–2025

[भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013]

(धारा 25 के अन्तर्गत)

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्रधिकरण के रीवा शाखा नहर अंतर्गत वितरिका/माइनर/सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत पूर्व मे भूमि अर्जन के प्रस्ताव पर म0प्र0 राजपत्र में दिनांक 29.09.2023 को धारा–11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम रेउसा की भू–अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है।

म0प्र0 शासन की अधिसूचना कमांक एफ 16–15–(1)–2014–सात–शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा।

प्रभावित ग्राम रेउसा तह0 मैहर की निजी भूमि के भू–अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के उपबंधो के अनुसार राजपत्र में दिनांक 15.03.2024 को कराया जाकर धारा– 20 एवं 21 के तहत अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी, मैहर को अधिकृत किया गया था।

(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 19 के प्रकाशन दिनांक 15/03/2024 से 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन एक वर्ष की तिथि के मध्य अवार्ड पारित नहीं हो सका है जिसके निम्नांकित कारण हैं:–

(क) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि तक अवार्ड पारित नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क) वर्णित कारण विद्यमान थे ।

(B) इस प्रकार प्रस्तुत भूअर्जन का प्रकरण, नहरों के माध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बंद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित हैं ।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की अवार्ड पारित करने की समयावधि में 12 माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील मैहर की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढायी जाती है।

1. भूमि का वर्णनः–

क0	ग्राम का नाम	निजी भूमि रकवा (क्षे0 लगभग)	धारा 19 के जारी होने का दिनांक	धारा 19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा 25 के अंतर्गत समयावधि में की गयी वृद्धि	टीप
1.	रेउसा	1.0150	15.03.2024	14.03.2025	धारा 25 अंतर्गत अवार्ड पारित करने हेतु 12 माह की वृद्धि की जाती है।	बिन्दु कमांक A एवं B के अनुसार

2. इस प्रकार ग्राम रेउसा की धारा–19 की अधिसूचना प्रकाशन से धारा–25 के अन्तर्गत 12 माह की वृद्धि की जाती है ।
3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :– बरगी व्यपवर्तन परियोजना की रीवा शाखा नहर/ उपशाखा नहर/ वितरिका नहर/ माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग मैहर जिला मैहर एवं कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर के भू–अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है ।

क्र.–76–भू–अर्जन–2025

[भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013]

(धारा 25 के अन्तर्गत)

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्रधिकरण के रीवा शाखा नहर अंतर्गत वितरिका/माइनर/सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत पूर्व में भूमि अर्जन के प्रस्ताव पर म0प्र0 राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को धारा–11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम **मझटोलवा** की भू–अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है।

म0प्र0 शासन की अधिसूचना कमांक एफ 16–15–(1)–2014–सात–शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा।

प्रभावित ग्राम **मझटोलवा** तह0 **मैहर** की निजी भूमि के भू–अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के उपबंधो के अनुसार राजपत्र में दिनांक **15.03.2024** को कराया जाकर धारा– 20 एवं 21 के तहत अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी, मैहर को अधिकृत किया गया था।

(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 19 के प्रकाशन दिनांक 15/03/2024 से 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन एक वर्ष की तिथि के मध्य अवार्ड पारित नहीं हो सका है जिसके निम्नांकित कारण हैं:–

(क) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि तक अवार्ड पारित नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क) वर्णित कारण विद्यमान थे ।

(B) इस प्रकार प्रस्तुत भूअर्जन का प्रकरण, नहरों के माध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बंद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित हैं ।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की अवार्ड पारित करने की समयावधि में 12 माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील **मैहर** की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढायी जाती है।

1. भूमि का वर्णनः–

क0	ग्राम का नाम	निजी भूमि रकवा (क्षे0 लगभग)	धारा 19 के जारी होने का दिनांक	धारा 19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा 25 के अंतर्गत समयावधि में की गयी वृद्धि	टीप
1.	मझटोलवा	1.7040	15.03.2024	14.03.2025	धारा 25 अंतर्गत अवार्ड पारित करने हेतु 12 माह की वृद्धि की जाती है।	बिन्दु कमांक A एवं B के अनुसार

2. इस प्रकार ग्राम **मझटोलवा** की धारा–19 की अधिसूचना प्रकाशन से धारा–25 के अन्तर्गत 12 माह की वृद्धि की जाती है ।
3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :– बरगी व्यपवर्तन परियोजना की रीवा शाखा नहर/ उपशाखा नहर/ वितरिका नहर/ माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग मैहर जिला मैहर एवं कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर के भू–अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है ।

क्र.–77–भू–अर्जन–2025

[भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013]

(धारा 25 के अन्तर्गत)

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्रधिकरण के रीवा शाखा नहर अंतर्गत वितरिका/माइनर/सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत पूर्व में भूमि अर्जन के प्रस्ताव पर म0प्र0 राजपत्र में दिनांक **28.04.2023** को धारा–11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम **खोधिरा** की भू–अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है।

म0प्र0 शासन की अधिसूचना कमांक एफ 16–15–(1)–2014–सात–शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा।

प्रभावित ग्राम **खोधिरा** तह0 **मैहर** की निजी भूमि के भू–अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के उपबंधो के अनुसार राजपत्र में दिनांक **16.02.2024** को कराया जाकर धारा– 20 एवं 21 के तहत अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी, मैहर को अधिकृत किया गया था।

(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 19 के प्रकाशन दिनांक **16/02/2024** से 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन एक वर्ष की तिथि के मध्य अवार्ड पारित नहीं हो सका है जिसके निम्नांकित कारण हैं:–

(क) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि तक अवार्ड पारित नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क) वर्णित कारण विद्यमान थे ।

(B) इस प्रकार प्रस्तुत भूअर्जन का प्रकरण, नहरों के माध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बंद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है . ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित हैं ।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की अवार्ड पारित करने की समयावधि में 12 माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील **मैहर** की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढायी जाती है।

1. भूमि का वर्णनः–

क0	ग्राम का नाम	निजी भूमि रकवा (क्षे0 लगभग)	धारा 19 के जारी होने का दिनांक	धारा 19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा 25 के अंतर्गत समयावधि में की गयी वृद्धि	टीप
1.	खोधिरा	3.0280	16.02.2024	15.02.2025	धारा 25 अंतर्गत अवार्ड पारित करने हेतु 12 माह की वृद्धि की जाती है।	बिन्दु कमांक A एवं B के अनुसार

1. इस प्रकार **ग्राम खोधिरा की** धारा–19 **की अधिसूचना** प्रकाशन **से** धारा–25 **के अन्तर्गत** 12 माह की वृद्धि की जाती है ।
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :– बरगी व्यपवर्तन परियोजना की रीवा शाखा नहर/ उपशाखा नहर/ वितरिका नहर/ माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
3. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग मैहर जिला मैहर एवं कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर के भू–अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है ।

क्र. 78–भू–अर्जन–2025

[भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013]

(धारा 25 के अन्तर्गत)

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्रधिकरण के रीवा शाखा नहर अंतर्गत वितरिका/माइनर/सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत पूर्व में भूमि अर्जन के प्रस्ताव पर म0प्र0 राजपत्र में दिनांक **28.04.2023** को धारा–11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम **भेड़ा** की भू–अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है।

म0प्र0 शासन की अधिसूचना कमांक एफ 16–15–(1)–2014–सात–शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा।

प्रभावित ग्राम **भेड़ा** तह0 **मैहर** की निजी भूमि के भू–अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के उपबंधो के अनुसार राजपत्र में दिनांक **16.02.2024** को कराया जाकर धारा– 20 एवं 21 के तहत अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी, मैहर को अधिकृत किया गया था।

(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 19 के प्रकाशन दिनांक **16/02/2024** से 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन एक वर्ष की तिथि के मध्य अवार्ड पारित नहीं हो सका है जिसके निम्नांकित कारण हैं:

(क) **लोकसभा निर्वाचन** 2024 एवं उसकी **आदर्श आचरण संहिता** अवधि ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि तक अवार्ड पारित नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमाक (क) वर्णित कारण विद्यमान थे ।

(B) इस प्रकार प्रस्तुत भूअर्जन का प्रकरण, नहरों के माध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित हैं ।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की अवार्ड पारित करने की समयावधि में **12** माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील **मैहर** की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढायी जाती है।

1.भूमि का वर्णनः–

क0	ग्राम का नाम	निजी भूमि रकवा (क्षे0 लगभग)	धारा 19 के जारी होने का दिनांक	धारा 19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा 25 के अंतर्गत समयावधि में की गयी वृद्धि	टीप
1.	भेड़ा	0.5400	16.02.2024	15.02.2025	धारा 25 अंतर्गत अवार्ड पारित करने हेतु 12 माह की वृद्धि की जाती है।	बिन्दु कमांक A एवं B के अनुसार

1. इस प्रकार ग्राम **भेड़ा** की धारा–19 की अधिसूचना प्रकाशन से धारा–25 के अन्तर्गत **12** माह की वृद्धि की जाती है ।
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :– बरगी व्यपवर्तन परियोजना की रीवा शाखा नहर/ उपशाखा नहर/ वितरिका नहर/ माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
3. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग मैहर जिला मैहर एवं कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर के भू–अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है ।

क्र.–79–भू–अर्जन -2025

[भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013]

(धारा 25 के अन्तर्गत)

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्रधिकरण के रीवा शाखा नहर अंतर्गत वितरिका/माइनर/सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत पूर्व में भूमि अर्जन के प्रस्ताव पर म0प्र0 राजपत्र में दिनांक **19.05.2023** को धारा–11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम **तिलौरा** की भू–अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है।

म0प्र0 शासन की अधिसूचना कमांक एफ 16–15–(1)–2014–सात–शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा।

प्रभावित ग्राम **तिलौरा** तह0 **मैहर** की निजी भूमि के भू–अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के उपबंधो के अनुसार राजपत्र में, दिनांक **15.03.2024** को कराया जाकर धारा– 20 एवं 21 के तहत अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी, मैहर को अधिकृत किया गया था।

(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 19 के प्रकाशन दिनांक **15/03/2024** से 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन एक वर्ष की तिथि के मध्य अवार्ड पारित नहीं हो सका है जिसके निम्नांकित कारण हैं:–

(क) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि तक अवार्ड पारित नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क) वर्णित कारण विद्यमान थे ।

(B) इस प्रकार प्रस्तुत भूअर्जन का प्रकरण, नहरों के माध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बंद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित हैं ।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की अवार्ड पारित करने की समयावधि में 12 माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील **मैहर** की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढायी जाती है।

1. भूमि का वर्णनः–

क0	ग्राम का नाम	निजी भूमि रकवा (क्षे0 लगभग)	धारा 19 के जारी होने का दिनांक	धारा 19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा 25 के अंतर्गत समयावंधि में की गयी वृद्धि	टीप
1	तिलौरा	2.5900	15.03.2024	14.03.2025	धारा 25 अंतर्गत अवार्ड पारित करने हेतु 12 माह की वृद्धि की जाती है।	बिन्दु कमांक A एवं B के अनुसार

2. इस प्रकार ग्राम **तिलौरा** की धारा–19 की अधिसूचना प्रकाशन से धारा–25 के अन्तर्गत 12 माह की वृद्धि की जाती है ।
3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :– बरगी व्यपवर्तन परियोजना की रीवा शाखा नहर/ उपशाखा नहर/ वितरिका नहर/ माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग मैहर जिला मैहर एवं कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर के भू–अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है ।

क्र.–80–भू–अर्जन–2025

[भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013]

(धारा 25 के अन्तर्गत)

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्रधिकरण के रीवा शाखा नहर अंतर्गत वितरिका/माइनर/सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत पूर्व में भूमि अर्जन के प्रस्ताव पर म0प्र0 राजपत्र में दिनांक **28.04.2023** को धारा–11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम **काशा** की भू–अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है।

म0प्र0 शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16–15–(1)–2014–सात–शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा।

प्रभावित ग्राम **काशा** तह0 **मैहर** की निजी भूमि के भू–अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के उपबंधो के अनुसार राजपत्र में दिनांक **15.03.2024** को कराया जाकर धारा– 20 एवं 21 के तहत अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी, मैहर को अधिकृत किया गया था।

(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 19 के प्रकाशन दिनांक 15/03/2024 से 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन एक वर्ष की तिथि के मध्य अवार्ड पारित नहीं हो सका है जिसके निम्नांकित कारण हैं:–

(क) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि तक अवार्ड पारित नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु क्रमांक (क) वर्णित कारण विद्यमान थे ।

(B) इस प्रकार प्रस्तुत भूअर्जन का प्रकरण, नहरों के माध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बंद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित हैं ।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की अवार्ड पारित करने की समयावधि में 12 माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील **मैहर** की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढायी जाती है।

1. भूमि का वर्णनः–

क0	ग्राम का नाम	निजी भूमि रकवा (क्षे0 लगभग)	धारा 19 के जारी होने का दिनांक	धारा 19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा 25 के अंतर्गत समयावधि में की गयी वृद्धि	टीप
1.	काशा	3.0280	15.03.2024	14.03.2025	धारा 25 अंतर्गत अवार्ड पारित करने हेतु 12 माह की वृद्धि की जाती है।	बिन्दु कमांक A एवं B के अनुसार

2 इस प्रकार ग्राम काशा की धारा–19 की अधिसूचना प्रकाशन से धारा–25 के अन्तर्गत 12 माह की वृद्धि की जाती है ।

3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :– बरगी व्यपवर्तन परियोजना की रीवा शाखा नहर/ उपशाखा नहर/ वितरिका नहर/ माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।

4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग मैहर जिला मैहर एवं कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर के भू–अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है ।

क्र.–81–भू–अर्जन–2025

[भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013]

(धारा 25 के अन्तर्गत)

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्रधिकरण के रीवा शाखा नहर अंतर्गत वितरिका/माइनर/सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत पूर्व में भूमि अर्जन के प्रस्ताव पर म0प्र0 राजपत्र में दिनांक **28.04.2023** को धारा–11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम **सिलौटी** की भू–अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है।

म0प्र0 शासन की अधिसूचना कमांक एफ 16–15–(1)–2014–सात–शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा।

प्रभावित ग्राम **सिलौटी** तह0 **मैहर** की निजी भूमि के भू–अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के उपबंधो के अनुसार राजपत्र में दिनांक **16.02.2024** को कराया जाकर धारा– 20 एवं 21 के तहत अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी, मैहर को अधिकृत किया गया था।

(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 19 के प्रकाशन दिनांक **16/02/2024** से 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन एक वर्ष की तिथि के मध्य अवार्ड पारित नहीं हो सका है जिसके निम्नांकित कारण हैं:–

(क) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि तक अवार्ड पारित नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क) वर्णित कारण विद्यमान थे ।

(B) इस प्रकार प्रस्तुत भूअर्जन का प्रकरण, नहरों के माध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित हैं ।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कीं धारा –25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की अवार्ड पारित करने की समयावधि में 12 माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील **मैहर** की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढायी जाती है।

1.भूमि का वर्णनः–

क0	ग्राम का नाम	निजी भूमि रकवा (क्षे0 लगभग)	धारा 19 के जारी होने का दिनांक	धारा 19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा 25 के अंतर्गत समयावधि में की गयी वृद्धि	टीप
1.	सिलौटी	3.5409	16.02.2024	15.02.2025	धारा 25 अंतर्गत अवार्ड पारित करने हेतु 12 माह की वृद्धि की जाती है।	बिन्दु कमांक A एवं B के अनुसार

1. इस प्रकार ग्राम **सिलौटी** की धारा–19 की अधिसूचना प्रकाशन से धारा–25 के अन्तर्गत 12 माह की वृद्धि की जाती है ।
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :– बरगी व्यपवर्तन परियोजना की रीवा शाखा नहर/ उपशाखा नहर/ वितरिका नहर/ माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
3. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग मैहर जिला मैहर एवं कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर के भू–अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है ।

क्र.–82–भू–अर्जन–2025

[भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013]

(धारा 25 के अन्तर्गत)

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्रधिकरण के रीवा शाखा नहर अंतर्गत वितरिका/माइनर/सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत पूर्व में भूमि अर्जन के प्रस्ताव पर म0प्र0 राजपत्र में दिनांक 28.04.2023 को धारा–11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम बठिया की भू–अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है।

म0प्र0 शासन की अधिसूचना कमांक एफ 16–15–(1)–2014–सात–शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा।

प्रभावित ग्राम बठिया तह0 मैहर की निजी भूमि के भू–अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के उपबंधो के अनुसार राजपत्र में दिनांक 15.03.2024 को कराया जाकर धारा– 20 एवं 21 के तहत अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी, मैहर को अधिकृत किया गया था।

(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 19 के प्रकाशन दिनांक 15/03/2024 से 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन एक वर्ष की तिथि के मध्य अवार्ड पारित नहीं हो सका है जिसके निम्नांकित कारण हैं:–

(क) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि तक अवार्ड पारित नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क) वर्णित कारण विद्यमान थे ।

(B) इस प्रकार प्रस्तुत भूअर्जन का प्रकरण, नहरों के माध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित हैं ।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की अवार्ड पारित करने की समयावधि में 12 माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील मैहर की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढायी जाती है।

1. भूमि का वर्णनः–

क0	ग्राम का नाम	निजी भूमि रकबा (क्षे0 लगभग)	धारा 19 के जारी होने का दिनांक	धारा 19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा 25 के अंतर्गत समयावधि में की गयी वृद्धि	टीप
1.	बठिया	7.2340	15.03.2024	14.03.2025	धारा 25 अंतर्गत अवार्ड पारित करने हेतु 12 माह की वृद्धि की जाती है।	बिन्दु कमांक A एवं B के अनुसार

2. इस प्रकार ग्राम बठिया की धारा–19 की अधिसूचना प्रकाशन से धारा–25 के अन्तर्गत 12 माह की वृद्धि की जाती है ।
3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :– बरगी व्यपवर्तन परियोजना की रीवा शाखा नहर/ उपशाखा नहर/ वितरिका नहर/ माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग मैहर जिला मैहर एवं कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर के भू–अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है ।

क्र.–83 भू–अर्जन–2025

[भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013]

(धारा 25 के अन्तर्गत)

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्रधिकरण के रीवा शाखा नहर अंतर्गत वितरिका/माइनर/सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत पूर्व में भूमि अर्जन के प्रस्ताव पर म0प्र0 राजपत्र में दिनांक **29.09.2023** को धारा–11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम **करैया देवरी** की भू–अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है।

म0प्र0 शासन की अधिसूचना कमांक एफ 16–15–(1)–2014–सात–शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा।

प्रभावित ग्राम **करैया देवरी** तह0 **मैहर** की निजी भूमि के भू–अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के उपबंधो के अनुसार राजपत्र में दिनांक **15.03.2024** को कराया जाकर धारा– 20 एवं 21 के तहत अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन **अधिकारी, मैहर को अधिकृत किया गया था।**

(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 19 के प्रकाशन दिनांक **15/03/2024** से 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन एक वर्ष की तिथि के मध्य अवार्ड पारित नहीं हो सका है जिसके निम्नांकित कारण हैं:–

(क) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि तक अवार्ड पारित नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क) वर्णित कारण विद्यमान थे ।

(B) इस प्रकार प्रस्तुत भूअर्जन का प्रकरण, नहरों के माध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बंद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित हैं ।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की अवार्ड पारित करने की समयावधि में 12 माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील **मैहर** की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढायी जाती है।

1. भूमि का वर्णनः–

क0	ग्राम का नाम	निजी भूमि रकवा (क्षे0 लगभग)	धारा 19 के जारी होने का दिनांक	धारा 19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा 25 के अंतर्गत समयावधि में की गयी वृद्धि	टीप
1.	करैया देवरी	0.042	15.03.2024	14.03.2025	धारा 25 अंतर्गत अवार्ड पारित करने हेतु 12 माह की वृद्धि की जाती है।	बिन्दु कमांक A एवं B के अनुसार

2. इस प्रकार ग्राम **करैया देवरी** की धारा–19 की अधिसूचना प्रकाशन से धारा–25 के अन्तर्गत **12 माह की वृद्धि की जाती है** ।
3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :– बरगी व्यपवर्तन परियोजना की रीवा शाखा नहर/ उपशाखा नहर/ वितरिका नहर/ माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु।
4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग मैहर जिला मैहर एवं कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर के भू–अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है ।

रानी बाटड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, नरसिंहगढ़, जिला–राजगढ़, मध्यप्रदेश

प.क्र.–1110–प्रवाचक–पार्वती नहर–2025 नरसिंहगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2025

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित मे यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम खजूरिया तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मे म.प्र. राज्य मेसर्स पी.ई एल–पार्वती जे.वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केवल एव डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव , म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

–: अनुसूची :–

पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम खजूरिया की भूमि में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण

सरल कमांक	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर मे	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	237/2	0.544	0.015
2	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	237/1	0.759	0.002
3	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	286/1	0.294	0.007
	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	289	1.341	0.019
4	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	286/2/2	0.299	0.011
5	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	286/2/3/1	0.196	0.007
6	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	286/2/1/2	0.041	0.007
7	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	291	0.590	0.030

8	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	283	2.327	0.003
9	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	282 / 1	2.137	0.021
10	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	278 / 2	0.942	0.012
11	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	281 / 1	2.301	0.040
12	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	280	0.810	0.013
13	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	249 / 2 / 1	0.215	0.011
14	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	235 / 4	1.442	0.003
15	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	237	1.366	0.030
	राजगढ़	नरसिंहगढ	खजूरिया	11 / 1	3.244	0.017
16	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	239 / 2	0.806	0.019
17	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	239 / 1	0.130	0.022
18	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	240	0.215	0.010
19	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	12 / 2 / 2	0.287	0.007
20	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	12 / 2 / 1	0.169	0.006
	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	12 / 1 / 1	0.169	0.011
21	राजगढ़	नरसिंहगढ़	खजूरिया	11 / 2 / 1 / 2	0.525	0.014
				किता 24	21.149	0.337

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है

प.क्र.–1014 -प्रवाचक–पार्वती नहर–2025 नरसिंहगढ़, दिनांक 15 अप्रैल 2025

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित मे यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम कांकरिया मीणा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ मे म.प्र. राज्य मेसर्स पी .ई एल– पार्वती जे.वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केवल एंव डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव , म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

–: अनुसूची :–

पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम कांकरिया मीणा की भूमि में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण

सरल कमांक	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर मे	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	राजगढ़	नरसिंहगढ	कांकरिया मीणा	2	0.961	0.014
2	राजगढ़	नरसिंहगढ	कांकरिया मीणा	49	0.569	0.011
				किता 2	1.530	0.025

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है

प.क्र.–1015–प्रवाचक–पार्वती नहर–2025

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित मे यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम पीपल्याकाजी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मे म.प्र. राज्य मेसर्स पी. ई एल– पार्वती जे. वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केवल एंव डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव , म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

–: अनुसूची :–

पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम पीपल्याकाजी की भूमि में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण

सरल कमांक	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर मे	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	राजगढ़	नरसिंहगढ़	पीपल्याकाजी	184/2/1	0.414	0.013
2	राजगढ़	नरसिंहगढ़	पीपल्याकाजी	184/2/2	0.414	0.013
3	राजगढ़	नरसिंहगढ़	पीपल्याकाजी	184/2/3	0.415	0.014
4	राजगढ़	नरसिंहगढ़	पीपल्याकाजी	184/2/4	0.414	0.008
6	राजगढ़	नरसिंहगढ़	पीपल्याकाजी	167/1	0.045	0.005
7	राजगढ़	नरसिंहगढ़	पीपल्याकाजी	165	0.885	0.024
8	राजगढ़	नरसिंहगढ़	पीपल्याकाजी	166/1	1.036	0.034
9	राजगढ़	नरसिंहगढ़	पीपल्याकाजी	167/2	0.230	0.005
10	राजगढ	नरसिंहगढ	पीपल्याकाजी	170/2/1	0.800	0.030
			कुल योग	किता 10	4.653	0.146

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है

प.क्र.–1016–प्रवाचक–पार्वती नहर–2025

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित मे यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम मीरूखेडी तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ मे म.प्र. राज्य मेसर्स पी.ई एल– पार्वती जे.वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव , म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

–: अनुसूची :–

पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम मीरूखेडी की भूमि में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर मे	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मीरूखेडी	155/2/2	0.205	0.006
2	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मीरूखेडी	154	1.037	0.014
3	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मीरूखेडी	166	2.655	0.032
4	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मीरूखेडी	165/1	1.265	0.031
5	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मीरूखेडी	165/2	0.821	0.024
				172	0.025	0.002
				171/1	0.564	0.013
				170/2	0.100	0.014
6	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मीरूखेडी	164/2	0.354	0.010
7	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मीरूखेडी	171/2	1.219	0.035
8	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मीरूखेडी	205/1	0.883	0.020
9	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मीरूखेडी	202/1/2	0.139	0.005
10	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मीरूखेडी	205/3	0.715	0.012
11	राजगढ़	नरसिंहगढ	मीरूखेडी	192/2	0.171	0.005
12	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मीरूखेडी	205/4	0.715	0.010
				204/2/1	0.506	0.020
				202/1/1	0.322	0.014
13	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मीरूखेडी	204/2/2	0.506	0.015
14	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मीरूखेडी	190	0.822	0.005
				192/1	0.525	0.011
15	राजगढ़	नरसिंहगढ	मीरूखेडी	185/1	1.568	0.017
				197/1	0.916	0.031
16	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मीरूखेडी	185/2	0.841	0.007
17	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मीरूखेडी	185/3	0.841	0.029
18	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मीरूखेडी	194/1	1.208	0.032
				194/2	1.207	0.026
				193/2	0.253	0.004
		कुल योग		कित 27	19.787	0.444

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है

प.क्र. 1017–प्रवाचक–पार्वती नहर–2025

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित मे यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम मोयली कला तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मे म.प्र. राज्य मेसर्स पी. ई एल– पार्वती जे. वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केवल एंव डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव , म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

–: अनुसूची :–

पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम मोयली कला की भूमि में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर मे	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोयलीकला	728 / 1 / 2	1.012	0.014
2	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोयलीकला	945 / 1	0.569	0.023
3	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोयलीकला	945 / 2	0.557	0.013
4	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोयलीकला	946 / 1 / 1	0.489	0.015
5	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोयलीकला	947 / 2	0.632	0.024
6	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोयलीकला	951	2.918	0.032

7_	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोयलीकला	952/1_	0.823	0.022
8	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोयलीकला	952/2	0.822	0.018
				939/2	1.138	0.014
9	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोयलीकला	934/1	1.947	0.050
10	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोयलीकला	927/1	0.708	0.010
11	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोयलीकला	928	1.708	0.025
12	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोयलीकला	930/1	0.392	0.026
13	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोयलीकला	889	0.949	0.037
14	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोयलीकला	876/4	1.461	0.052
15	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोयलीकला	890	0.873	0.009
				886	1.480	0.025
16	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोयलीकला	885	0.468	0.014
17	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोयलीकला	878/1	1.152	0.029
18	राजगढ़	नरसिंहगढ़	मोयलीकला	877	0.342	0.010
		कुल योग		किता 20	20.441	0.462

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है

प.क्र.–1018–प्रवाचक–पार्वती नहर–2025

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित मे यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम नाईहेडी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मे म.प्र. राज्य मेसर्स पी.ई एल–पार्वती जे.वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव , म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन, केबल.एंव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

–: अनुसूची :–

पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम नाईहेडी की भूमि में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण

सरल कमांक	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमाक	कुल रकबा हेक्टर मे	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	राजगढ़	नरसिंहगढ़	नाईहेडी	98/4/2/1/1	0.500	0.006
2	राजगढ़	नरसिंहगढ़	नाईहेडी	98/4/2/1/2	0.253	0.006
3	राजगढ़	नरसिंहगढ़	नाईहेडी	98/4/2/2	0.506	0.010
4	राजगढ़	नरसिंहगढ	नाईहेडी	98/4/3	1.001	0.010
5	राजगढ़	नरसिंहगढ़	नाईहेडी	103/2	0.139	0.002
6	राजगढ़	नरसिंहगढ़	नाईहेडी	85	0.544	0.006
7	राजगढ	नरसिंहगढ	नाईहेडी	84/2	1.265	0.019
8	राजगढ़	नरसिंहगढ़	नाईहेडी	84/1	1.265	0.019
9	राजगढ़	नरसिंहगढ	नाईहेडी	83/1/2	0.651	0.002
10	राजगढ़	नरसिंहगढ़	नाईहेडी	75/1/3	0.498	0.013
11	राजगढ़	नरसिंहगढ़	नाईहेडी	75/1/2	1.004	0.014
12	राजगढ़	नरसिंहगढ़	नाईहेडी	75/1/1	1.004	0.014
13	राजगढ़	नरसिंहगढ़	नाईहेडी	121/3	0.379	0.009
14	राजगढ	नरसिंहगढ़	नाईहेडी	121/4	0.557	0.016
15	राजगढ	नरसिंहगढ	नाईहेडी	120/2	1.012	0.022
16	राजगढ़	नरसिंहगढ़	नाईहेडी	124/1/1	1.180	0.013
17	राजगढ़	नरसिंहगढ़	नाईहेडी	124/2	1.770	0.016
18	राजगढ़	नरसिंहगढ़	नाईहेडी	125/1	0.797	0.009
19	राजगढ़	नरसिंहगढ़	नाईहेडी	125/3	0.796	0.009
20	राजगढ़	नरसिंहगढ़	नाईहेडी	125/4	0.797	0.016
		योग–		किता 20	15.918	0.231

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ, जिला राजगढ के कार्यालय मे किया जा सकता है

प.क्र.–1019–प्रवावक–पार्वती नहर 2025

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित मे यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम बरोडी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मे म.प्र. राज्य मेसर्स पी.ई एल–पार्वती जे.वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केवल एंव डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव , म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

–: अनुसूची :–

पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम बरोडी की भूमि में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर मे	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	11/10	1.770	0.011
				31/2/1/2	0.702	0.012
2	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	11/11	0.759	0.020
3	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	11/4/2	0.421	0.012
4	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	11/4/1/4	0.496	0.013
5	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	11/4/1/3	0.496	0.011
6	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	11/4/1/2	0.496	0.011
7	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	49	0.240	0.003

8	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	47 / 1	0.558	0.025
9	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	48 / 1 / 3 / 1	0.274	0.010
				66 / 2 / 1	0.031	0.010
10	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	48 / 1 / 1	0.548	0.017
11	राजगढ	नरसिंहगढ़	बरोडी	58 / 1 / 3 / 2	0.021	0.004
				67 / 2	0.348	0.002
12	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	64 / 2 / 2	0.141	0.006
				34 / 2	0.227	0.010
13	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	64 / 1	0.282	0.021
				66 / 1	0.759	0.019
14	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	63 / 1	0.764	0.017
15	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	34 / 1	0.228	0.015
16	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	31 / 2 / 1 / 1	0.702	0.014
17	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	32 / 1	0.127	0.004
18	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	30 / 3	0.274	0.012
				29 / 3 / 2	0.203	0.003
19	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	30 / 2	0.274	0.006
				29 / 2 / 2	0.253	0.022
20	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	29 / 1	1.434	0.006
				29 / 2 / 1	0.253	0.018
				81 / 1	0.079	0.014
21	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	83 / 1	0.208	0.008
		कुल योग		किता 31	13.368	0.359

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है

प.क्र.–1020 प्रवाचक–पार्वती नहर–2025

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित मे यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम बरोडी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मे म.प्र. राज्य मेसर्स पी.ई एल–पार्वती जे.वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केवल एंव डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव , म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

–: अनुसूची :–

पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम बरोडी की भूमि में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण

सरल कमांक	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर मे	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	11/10	1.770	0.011
				31/2/1/2	0.702	0.012
2	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	11/11	0.759	0.020
3	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	11/4/2	0.421	0.012
4	राजगढ	नरसिंहगढ	बरोडी	11/4/1/4	0.496	0.013
5	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	11/4/1/3	0.496	0.011
6	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	11/4/1/2	0.496	0.011
7	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बरोडी	49	0.240	0.003
8	राजगढ	नरसिंहगढ	बिहार	135/1	0.225	0.014
9	राजगढ़	नरसिंहगढ	बिहार	111/1	0.337	0.016
10	राजगढ	नरसिंहगढ	बिहार	111/3	0.338	0.016
				113/2	0.417	0.040
				79/2	0.460	0.030
11	राजगढ़	नरसिंहगढ	बिहार	112/3	0.380	0.016
12	राजगढ	नरसिंहगढ	बिहार	82/2	2.482	0.094
13	राजगढ़	नरसिंहगढ	बिहार	82/1	1.654	0.019
14	राजगढ़	नरसिंहगढ	बिहार	84/1	0.536	0.046
15	राजगढ़	नरसिंहगढ	बिहार	83	0.860	0.034
			कुल योग	किता 19	12.947	0.587

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के कार्यालय मे किया जा सकता है

प.क्र.–1021–प्रवाचक–पार्वती नहर -2025

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित मे यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम प्रताबपुरा तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ मे म.प्र. राज्य मेसर्स पी.ई एल–पार्वती जे.वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव , म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार,उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

–: अनुसूची :–

पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम प्रताबपुरा की भूमि में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण

सरल कमांक	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर मे	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	राजगढ़	नरसिंहगढ़	प्रताबपुरा	71/3/3/2	1.063	0.037
2	राजगढ़	नरसिंहगढ़	प्रताबपुरा	71/3/3/1	1.062	0.014
3	राजगढ़	नरसिंहगढ	प्रताबपुरा	71/3/2/2	0.885	0.018
4	राजगढ़	नरसिंहगढ़	प्रताबपुरा	71/3/2/1	0.885	0.018
5	राजगढ़	नरसिंहगढ़	प्रताबपुरा	71/3/1	0.506	0.037
6	राजगढ़	नरसिंहगढ़	प्रताबपुरा	71/2	1.265	0.031
7	राजगढ़	नरसिंहगढ़	प्रताबपुरा	71/1	1.265	0.035
8	राजगढ़	नरसिंहगढ़	प्रताबपुरा	67/1	0.759	0.031
				66/1	0.253	0.012
9	राजगढ़	नरसिंहगढ़	प्रताबपुरा	66/2	0.493	0.031
			कुल योग	किता 10	8.436	0.264

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है

प.क्र.–1022–प्रवाचक–पार्वती नहर–2025

चूँकि राज्य सरकार को लोकहित मे यह अवश्यक प्रतीत होता है कि पार्वती बाँध परियोजना के भूमिगत नहर निर्माण हेतु ग्राम कोटरा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मे म.प्र. राज्य मेसर्स पी.ई एल–पार्वती जे वी कम्पनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि मे, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन , केबल एंव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव , म.प्र. भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि मे हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)नरसिंहगढ जिला राजगढ़ म. प्र को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

–: अनुसूची :–

पार्वती परियोजना के नहर प्रणाली मे प्रभावित ग्राम कोटरा की भूमि में भूमिगम पाइप लाइन बिछाये जाने के अस्थायी अर्जन का विवरण

सरल कमांक	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर मे	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	राजगढ़	नरसिंहगढ़	कोटरा	254	0.544	0.037
2	राजगढ़	नरसिंहगढ़	कोटरा	253	1.037	0.050
3	राजगढ़	नरसिंहगढ़	कोटरा	256 / 1	0.582	0.016
4	राजगढ़	नरसिंहगढ़	कोटरा	198 / 2	0.822	0.005
5	राजगढ़	नरसिंहगढ़	कोटरा	198 / 1	0.190	0.060
6	राजगढ	नरसिंहगढ़	कोटरा	200 / 2 / 1	1 346	0.028
7	राजगढ़	नरसिंहगढ़	कोटरा	200 / 2 / 2 / 1	0.673	0.014
8	राजगढ	नरसिंहगढ	कोटरा	200 / 2 / 2 / 2	0.673	0.014
9	राजगढ़	नरसिंहगढ	कोटरा	207 / 1 / 1	0.828	0.039
10	राजगढ़	नरसिंहगढ़	कोटरा	207 / 1 / 2	0.829	0.039
11	राजगढ	नरसिंहगढ	कोटरा	207 / 1 / 3	0.632	0.035
12	राजगढ़	नरसिंहगढ़	कोटरा	207 / 5	1.265	0.062
13	राजगढ	नरसिंहगढ़	कोटरा	188	0.683	0.042
				187	0.607	0 062
			कुल योग	किता 14	10.711	0.503

भूमिगत पाइप लाइन, केबल एंव डक्ट आदि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव भू अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है

सुशील कुमार, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, भू–अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला–खरगोन मध्यप्रदेश

प.क्र.–1142–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–0041 अ–74–2024–25 कसरावद, दिनांक 1 मई 2025

प्ररुप– ''घ''
(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– 528/भू–अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक** 18.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने **बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक– 05 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम– बलकवाड़ा, प.ह.नं.– 43/136, रा.नि.मं.–बलकवाड़ा, तहसील– कसरावद, जिला– खरगोन** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 07.03.2025** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– बलकवाड़ा, प.ह.नं.– 43/136,	54	0.003
			55	0.006
			56	0.008
			58/2	0.007
			80	0.001
			76	0.004
			83	0.005
			75	0.008
			107	0.006
			558/1/2	0.011

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– बलकवाड़ा, प.ह.नं.– 43 / 136,	559/1	0.004
			559/2	0.003
			560/1	0.002
			578/1	0.002
			578/2	0.001
			579/2	0.005
			593/2	0.005
			593/1	0.003
			593/3	0.001
			593/1067	0.004
			592	0.003
			584	0.005
			790	0.001
			783	0.008
			784	0.001
			782	0.008
			781	0.006
			772	0.003
			779	0.001
			752	0.003
			756	0.007
			757	0.004
			758	0.002
			767	0.006
			773/2	0.003
			768	0.003
			769	0.004
			771	0.008
			917/1	0.001
			917/2	0.002
			918	0.002
			919/1	0.002
			919/2	0.001
		कुल योग	43	0.173

प.क्र.–1148–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–6040–अ–74–2024–25

प्ररुप– "घ"
(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– 234/भू–अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक** 28.01.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने **बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक– 02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम– सुर्वा, प.ह.नं.– 42/135, रा.नि.मं.–बलकवाड़ा, तहसील– कसरावद, जिला– खरगोन** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 07.02.2025** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– सुर्वा, प.ह.नं.– 42/135,	229/2	0.001
			229/1	0.004
				0.001
			231/1	0.010
			230	0.003
		कुल योग	04	0.019

प.क्र.–1145–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–0039–अ–74–2024–25

प्ररुप– ''घ''
(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र क्रमांक– 249/भू–अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक** 28.01.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने **बलकवाड़ा उदवहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक– 02 एवं जी.एम.–02/आर.एम.–02 व जी.एम.–02/एल.एम.–01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम– जलज्योती, प.ह.नं.– 51/142, रा.नि.मं.–बलकवाड़ा, तहसील– कसरावद, जिला– खरगोन** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 07.02.2025** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– जलज्योती, प.ह.नं.– 51/142,	228/2	0.005
				0.008
				0.007
			228/1	0.002
				0.024

निरंतर– 2

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– जलज्योती, प.ह.नं.– 51 / 142	224	0.014
			225/1	0.004
			63/1	0.005
			221	0.006
			63/2	0.008
			58	0.001
			266/1	0.009
			60/2	0.005
			262	0.003
			61	0.009
			65/4	0.008
			42	0.009
				0.010
			65/5	0.002
			65/3	0.008
			65/2	0.009
			41	0.001
			38/2	0.004
			229	0.005
				0.009
			227/1	0.004
			227/2	0.006
			227/3	0.009
			234/3	0.003
			237/1	0.005
			246	0.011
			248	0.001
			180	0.007
			268/1	0.007
			253/1	0.002
			268/6	0.011
			254/1	0.003
			261/1	0.006
			257/2	0.004
			258/3	0.001
			258/1	0.015
			84/2	0.017

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– जलज्योती, प.ह.नं.– 51 / 142	84/3	0.017
			84/1	0.007
			83/7	0.008
			83/5	0.004
			83/3	0.004
			106/1	0.006
			107/1	0.021
			108/1	0.004
			109	0.009
			101	0.006
			100	0.015
			90/1	0.003
			91/2	0.003
			91/1	0.009
			92	0.003
			74	0.009
			72	0.006
			71	0.005
			220	0.007
			232/1	0.006
			232/2	0.006
			233	0.010
			52	0.008
			51	0.003
			53	0.007
			50/1	0.011
			45/3	0.011
			45/1/1	0.014
		कुल योग	**65**	**0.509**

प.क्र.–1151–भू–अर्जन–2025 -रा.प्र.क्र.–0042–अ–74–2024–25

प्ररुप– "घ"
(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र क्रमांक– 523/भू–अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक** 18.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने **बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम.–3/एल.एम.–4 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम– हतोला, प.ह.नं.– 36/129, रा.नि.मं.–बलकवाड़ा, तहसील– कसरावद, जिला– खरगोन** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 07.03.2025** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– हतोला, प.ह.नं.– 36/129,	45	0.003
			44	0.004
			130/2	0.010
			141/4	0.013
		कुल योग	04	0.030

प.क्र.–1154–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–0043–अ–74 2024–25

प्ररुप– ''घ''
(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– 421/भू–अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक** 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने **अम्बा–रोड़िया उद्वहन माईक्रो सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक–आर.एम.–02 व जी.एम.–05 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम– जामन्या, प.ह.नं.–84, रा.नि.मं.–मुलठान, तहसील– कसरावद, जिला– खरगोन** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 21.02.2025** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम– जामन्या, प.ह.नं.–84,	53	0.003
			52	0.002
			54/2/1	0.011
			54/2/2	0.021
			54/3	0.008
			55	0.014
			77	0.044
			84	0.012
			71/1	0.012
			69/2	0.021
			81/8	0.003
			81/9	0.006
			81/10	0.008
			86/1/1	0.012
			86/1/2	0.012
			86/2	0.024
			87/1	0.011
			87/2	0.010
			87/3	0.011
			87/4	0.013
			49/3/4	0.005
			49/3/2	0.008
		कुल योग	22	0.271

प.क्र.–1157–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–0044–अ–74–2024–25

प्ररुप– ''घ''
(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र क्रमांक– 411/भू–अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक** 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने **अम्बा–रोड़िया उद्वहन माईक्रो सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक– जी.एम.–02 एवं जी.एम.–02/एल.एम.–11 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम–भट्यान खुर्द, प.ह.नं.–77, रा.नि.मं.–मुलठान, तहसील– कसरावद, जिला– खरगोन** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 21.02.2025** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम–भट्यान खुर्द, प.ह.नं.–77,	378/2/2	0.004
				0.012
			378/2/1	0.017
				0.005
			378/1	0.016

निरंतर– 2

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम–भट्यान खुर्द, प.ह.नं.–77,	383	0.031
			391	0.008
			392	0.015
			368/1/2	0.010
			365/6	0.022
			59/2	0.003
			362/3	0.013
			362/2	0.008
			362/1	0.011
			361/2/2	0.011
			356/2	0.017
			351	0.013
			350/3/2	0.006
			350/1	0.006
			347/1	0.007
			346/2	0.015
			293/3	0.021
			293/4	0.016
			385/2	0.003
			386/2	0.003
			295	0.015
			298/2	0.025
			299	0.020
			301/3/1	0.010
			301/3/2	0.010
			303/2/1	0.015
			306/9	0.006
			306/8	0.008
			306/1	0.004
			266/2	0.003
			266/1	0.006
			265/2/2	0.011
			265/2/1	0.011
			265/1	0.002
			262	0.012
			247/1	0.015
			253/2	0.009
				0.001

निरंतर– 3

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम–भट्यान खुर्द, प.ह.नं.–77,	252	0.003
			251	0.014
			250/1/5	0.014
			250/2	0.004
			250/1/4	0.005
			378/4/2/2	0.003
			378/4/2/1	0.009
			378/4/3	0.003
			378/4/1	0.008
			374/2	0.004
			370/4/1	0.001
			370/3/2	0.004
			370/3/1	0.004
			374/1	0.004
			372	0.003
			370/4/2	0.005
			73	0.008
			71	0.017
			74/2	0.004
			74/3	0.014
			74/6	0.004
			74/5	0.014
			75	0.001
			76/1	0.001
			68	0.004
			77	0.003
			66	0.006
			79/6	0.009
			58/2	0.007
			58/1/1	0.010
			47/2	0.007
			21/4	0.010
			21/1	0.002
			21/2	0.013
			21/3/1	0.005
			21/3/2	0.006
			16/2/2	0.004
			16/2/1	0.004
			16/1	0.005
			15/2	0.003
			15/1	0.001
			14/2	0.003
			4/3	0.009
			4/4	0.012
			4/5	0.018
			4/1/1	0.008
			4/8	0.006
			4/1/3	0.006
			4/2	0.004
			4/6	0.002
			4/1/5	0.004
			4/1/2	0.008
			4/1/4	0.007
			3	0.021
			1	0.001
		कुल योग	**95**	**0.835**

सत्येन्द्र बैरवा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व).

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, भीकनगांव, जिला–खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र.–1780–री–1–भू–अर्जन–2025–रा.प्र.क्र.–0171–ब–121–2024–25 भीकनगांव, दिनांक 16 अप्रैल 2025

प्ररुप– "घ"

(नियम–6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– 664/रीडर/भू–अर्जन/2025, भीकनगांव, दिनांक 14.02.2025** द्वारा, राज्य सरकार ने **चोण्डी–जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक–06 में जल परिवहन हेतु ग्राम– पिपलई खुर्द, प.ह.नं.– 20/79, रा. नि.मं.–अंदड़, तहसील– भीकनगांव, जिला– खरगोन** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 07.03.2025** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम– पिपलई खुर्द, प.ह.नं.– 20/79,	28/5	0.018
			28/4	0.005
			28/6	0.004
			29/1	0.028
			29/4	0.010
			29/5	0.013
			33/1	0.024
			34/4	0.012
			34/23	0.016
			79/1	0.001
			34/8	0.005
			77/1	0.011
			75	0.013
		कुल योग	13	0.160

आकांक्षा (करोठिया) अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व).

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मई 2025

क्रमांक एफ IPI–5–0018–2025–A–11.– प्रदेश में वृहद् श्रेणी के विनिर्माण उद्योगों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24 फरवरी 2025 द्वारा जारी उद्योग संवर्धन नीति 2025 अंतर्गत प्रावधानित सुविधा/सहायता उपलब्ध कराने एवं दिशा–निर्देश जारी करने हेतु राज्य शासन, एतदद्वारा संलग्नक अनुसार मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2025 जारी करता है.

2. यह योजना उद्योग संवर्धन नीति 2025 के जारी होने के दिनांक 24 फरवरी 2025 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शाश्वत सिंह मीना, उपसचिव.

MPIDC
MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

Government of Madhya Pradesh

INVEST MADHYA PRADESH

Department of Industrial Policy and Investment Promotion
Government of Madhya Pradesh

TABLE OF CONTENTS

1. Introduction .....
2. Period and scope of effectiveness of the scheme.....
3. Definitions .....
3.1. Date of commencement of Commercial Production.....
3.2. Department .....
3.3. Eligible Fixed Capital Investment (EFCI) .....
3.4. Existing Capacity.....
3.5. Existing Industrial Unit .....
3.6. Expansion/ Diversification by an existing large unit .....
3.7. Export .....
3.8. Financial Institution .....
3.9. Fixed Capital Investment (FCI) .....
3.10. Foreign Direct Investment or FDI.....
3.11. Freight Costs.....
3.12. Installed Capacity.....
3.13. Intellectual Property Rights (IPRs).....
3.14. Large Scale Industrial Unit.....
3.15. Mega Industry .....
3.16. MPIDC .....
3.17. MSMEs .....
3.18. New Large Scale Industrial Units .....
3.19. Plug and Play Facilities.....
3.20. Priority Blocks.....
3.21. Private Industrial Parks.....
3.22. Renewable Energy Captive Power Plant.....
3.23. Standalone Industrial Utilities .....
3.24. Standalone Research and Development Facilities, Industrial Testing / Certification Labs.....
3.25. Technological Upgradation .....
3.26. Term Loan.....
3.27. Testing Facility .....
3.28. Vendor Units .....

4. Governance Structure.....
4.1. Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP).....
4.2. State Level Empowered Committee (SLEC).....
5. Application Procedure.....
5.1. Submission of Application for Customized Package.....
5.2. Submission of Application for Incentives.....
1. For Eligibility determination .....
2. For Claims.....
6. Financial Incentives.....
6.1. Investment Promotion Assistance .....
Incentive Multipliers on BIPA.....
1. Gross Supply Multiple (GSM):.....
2. Export Multiple (EM) .....
3. Employment Multiple .....
4. Geographical Multiple.....
5. FDI Multiple .....
6. Food Processing Multiple .....
7. Additional multiple for API/ Bulk Drugs .....
8. Medical Device manufacturing Multiple .....
9. Multiple for EV Manufacturing .....
10. Multiple for HVA.....
6.2. Assistance for Technological Upgradation .....
6.3. Green Industrialization Assistance.....
6.4. Infrastructure Development Assistance.....
6.5. Assistance for IPR and Organic Certification .....
6.6. Incentives to Provide Employment to Differently Abled Persons.....
6.7. Reimbursement of Cost of Transfer of International Technology (Assistance for Units Bringing in FDI more than 26%) .....
6.8. Industrial Housing.....
6.9. Export Freight Subsidy for Transportation of Goods.....
6.10. Assistance for Standalone Research and Development Facilities, Industrial Testing / Certification Labs.....
6.11. Mandi-fee Reimbursement.....

6.12. Power Tariff Reimbursement.....
6.13. Quality Certification .....
6.14. Interest subsidy.....
6.15. Training & Skill Development .....
6.16. Assistance for Employment Generation.....
6.17. Reimbursement of Stamp Duty and Registration Charges.....
6.18. Incentive for Setting up of Testing Facility .....
6.19. Concession in Development Charges .....
7. Assistance for Private Industrial Park Developers.....
8. Assistance For Developing Plug and Play Facilities for Manufacturing/Services Sectors and Units Establishing in Plug and Play Parks .....
9. Terms and Conditions.....
10. Appeal .....
11. Amendment/Relaxation/Repeal.....
12. Jurisdiction .....
13. Annexure – A List of Priority Blocks .....
14. Annexure – B List of Ineligible Industries .....
15. Annexure – C Process of CCIP Application.....
16. Forms (indicative) .....
Form 1: Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP).....
Form 2: Common Application Form (General Information) For Eligibility Determination In SLEC.....
Form 3: Application form for claiming incentives .....
Form 4: Details of Standalone R&D for Eligibility Determination.....
Form 5: Claim Form for Standalone R&D Units .....
Form 6: Application Format by Developer for Assistance for Proposed Private Industrial Park/Industrial Plug and Play Facility .....
Form 7: Application Format by Developer for Assistance Established Private Industrial Park/Industrial Plug and Play Facility .....
Form 8: Milestone completion certificate for Private Industrial Park/ Plug and Play facility .....
Form 9: Rental Subsidy for Units Established in Plug and Play Parks.....
17. Annexures .....

Annexure 1: CA Certificate for Verification of FCI, Turnover and FDI for new unit.....

Annexure 2: CA Certificate for FCI, Turnover and FDI in Case of Expansion and/or Diversification and/or Technological Upgradation .....

Annexure 3: Affidavit for Employment Under IPP 2025.....

Annexure 4: CE Certificate to Certify the Capacity of Plant and Machinery in Case of Expansion .....

Annexure 5: Affidavit under the MP Investment Promotion Scheme 2025.....

Annexure 6: CA Certificate for IPA in Case of New Unit .....

Annexure 7: CE Certificate for IPA in Case of New Unit .....

Annexure 8: CA Certificate for IPA in Case of Expansion and/or Diversification.....

Annexure 9: CE Certificate for IPA in Case of Expansion and Diversification.....

Annexure 10: CA Certificate for Technological Upgradation .....

Annexure 11: CE Certificate for Technological Upgradation.....

Annexure 12: Bank Certificate .....

Annexure 13: Loan Repayment Schedule .....

Annexure 14: Affidavit for Claiming Incentives under IPP 2025 .....

Annexure 15: CA Certificate for Claiming IPA/Technological Upgradation.....

Annexure 16: Due Diligence Certificate .....

Annexure 17: Quarterly Statement for Claiming Interest Subsidy under IPP 2025.....

Annexure 18: Affidavit for Availing Training and Skill Development Subsidy.....

Format A: Employees Details for Training Cost Reimbursement and Employment Generation Subsidy for the year ....

Annexure 19: Affidavit for Availing Assistance for Employment Generation.....

Format B: Employee Details for Assistance under IPP 2025/ Assistance for Employment Generation under Garment, Footwear, Toys and Accessories Policy .....

Annexure 20: CA Certificate for Verifying the Details of the Export Freight Cost.....

Annexure 21: CA Certificate for Private Industrial Park/ Plug and Play facility.....

Annexure 22: CA Certificate for Rent Paid.....

1. INTRODUCTION

The Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy (IPP) 2025, notified on February 24, 2025, is designed to establish the State as a leading global investment destination and build a strong industrial ecosystem. With a focus on accelerating industrialization, fostering inclusive growth, generating employment opportunities, and ensuring balanced regional development, the policy lays the foundation to ensure economic prosperity across the State.

To enable its effective implementation, the government is introducing the Madhya Pradesh Investment Promotion Scheme 2025, which provides a structured framework for administering incentives under IPP 2025. The scheme offers comprehensive guidelines on facilities, benefits, and support available to large and mega-category manufacturing industries, along with clear procedures for claiming incentives. By ensuring standardization, transparency, and clarity, the scheme serves as a crucial reference for investors and the department, reinforcing Madhya Pradesh's commitment to becoming a premier hub for industry, investment, and employment generation.

2. PERIOD AND SCOPE OF EFFECTIVENESS OF THE SCHEME

1. This scheme will remain in effect for the effective duration of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2025 (IPP 2025).
2. Large scale manufacturing units commencing production after the date of notification, 24th February 2025 of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2025, shall be eligible to avail the benefits of this scheme.
3. The committee constituted for availing benefits under previous prevalent Industrial Promotion Policy shall be dissolved and the assistance under previous policy & special package sanctioned earlier shall be carried out according to the prescribed process defined in the Madhya Pradesh Investment Promotion Scheme 2025.

4. Mega scale units for which customized package has been sanctioned by Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP) under the Industrial Promotion Policy 2014 (IPP 2014), but commencing production after the notification of the Industrial Promotion Policy 2025 (IPP 2025), shall be eligible to opt between the customized package of incentives under IPP 2014 through CCIP or incentives as provisioned under IPP 2025.

3. DEFINITIONS

3.1. DATE OF COMMENCEMENT OF COMMERCIAL PRODUCTION

The date of issue of the first sale invoice, filed as the 'Date of Commencement of Commercial Production' under IEM (Industrial Entrepreneur Memorandum) Part-B, by a new unit or after expansion, diversification, or technological upgradation.

For the purpose of incentives, the investment or turnover of the unit, as defined in the 'Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006' (hereinafter referred to as MSMED Act, 2006), on the 'Date of Commencement of Commercial Production' shall be considered for the classification of the unit as MSME or Large Industry.

3.2. DEPARTMENT

"Department" means Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh.

3.3. ELIGIBLE FIXED CAPITAL INVESTMENT (EFCI)

3.3.1. Factory sheds and Buildings excluding compound wall, internal roads and dwelling units and GST paid on construction materials.

3.3.2. Plant and Machinery as defined in the MSMED Act, 2006.

Excluding:

(i) Old Machinery

(ii) Investments made in ETP, STP, ZLD and other pollution control equipment, WHRS & Co-generation systems, and renewable & non-renewable energy devices.

3.3.3. Investment in Plant & Machinery, as defined in 3.3.2, shall also include the foundation, & cost of transportation, erection, installation (excluding consultancy charges and labour charges).

3.3.4. It is clarified that for the purpose of incentives under this policy, the plant and machinery shall only include the plant and machinery that is being used for the main manufacturing process including labs, packaging sections, or any other machinery as deemed necessary for the manufacturing process. The main manufacturing machinery shall not include furniture, fixtures, generators, transformers/ substation, commercial vehicles, office equipment's, consumables, pre-operative expenses, and GST paid on Plant and Machinery.

3.3.5. In-house R&D facility registered under Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology, Government of India:

(i) For the pharmaceuticals and biotechnology sectors, 100% of the capital cost of establishing in-house R&D is considered under Eligible Fixed Capital Investment (EFCI), but it is capped at 50% of the investment in Plant & Machinery, Factory Sheds and Buildings as defined in sections 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 and 3.3.4. This means that while the full capital cost of in-house R&D is included, it cannot exceed 50% of the investment in Plant & Machinery, Factory Sheds & Buildings.

(ii) For other sectors, 100% of the capital cost of establishing in-house R&D is considered under EFCI, but it is capped at 40% of the investment in Plant & Machinery, Factory Sheds and Buildings as defined in sections 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 and 3.3.4.

3.3.6. Up to 50% of the cost of captive power generation based on renewable energy sources, subject to a maximum limit of 20% of the total investment in Plant & Machinery, Factory Sheds and Buildings, as

defined under sections 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 and 3.3.4. Additionally, to qualify for this provision, at least 51% of the net power generated must be consumed on-site at the plant. The unit shall produce the certificate of captive power generation and consumption from renewable sources from MPERC.

In case the unit is unable to consume 51% of captive power generated and ceases to be Captive User as per MPERC in a particular year during the eligibility period, the EFCI shall be reduced proportionately, and BIPA would be recalculated accordingly.

3.3.7. Up to 20% of the cost of energy-saving devices, such as Waste Heat Recovery Systems (WHRS) and Co-generation systems, capped at a maximum of 20% of the total investment in Plant & Machinery, Factory Sheds and Buildings, as defined under sections 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 and 3.3.4.

3.3.8. Imported second-hand refurbished machinery with an expected operational life of minimum 10 years.

3.4. Existing Capacity

Existing Capacity refers to the average annual production of an industrial unit, based on:

i. The average production over the last three financial years before the commencement of commercial production under expansion or diversification,

OR

ii. The capacity declared at the time of the start of commercial production by the unit, as per the Industrial Entrepreneur Memorandum (IEM Part B)/Registration/Certificate issued by a government authority.

Whichever is higher will be considered as the Existing Capacity.

3.5. Existing Industrial Unit

'Existing Industrial Unit' refers to a unit that commenced commercial production before the notification date of the Industrial Promotion Policy

2025 or any industrial unit undergoing expansion/diversification /technical upgradation, during the period of this policy.

3.6. EXPANSION/ DIVERSIFICATION BY AN EXISTING LARGE UNIT

i. Units undertaking expansion in existing capacity and/or diversification should invest in plant and machinery at least 30% of the existing investment in plant and machinery (not less than ₹20 Crores) or ₹100 Crores, whichever is lower.

ii. In the case of expansion, there should be at least a 20% increase in the existing capacity.

iii. Units undergoing expansion and/or diversification shall be treated as new unit for the purpose of incentives.

3.7. EXPORT

The act of shipping goods and services from Madhya Pradesh to a foreign destination in accordance with applicable laws and trade agreements by Government of India. For the purposes of this policy, Export shall only mean shipping of goods only and shall not include services.

3.8. FINANCIAL INSTITUTION

Refers to financial institution as recognized by the Reserve Bank of India (RBI).

3.9. FIXED CAPITAL INVESTMENT (FCI)

Fixed Capital Investment (FCI) is defined as investment in all fixed assets excluding land.

3.10. FOREIGN DIRECT INVESTMENT OR FDI

'FDI' or 'Foreign Direct Investment' and all related terms shall carry the same meaning as defined in the Consolidated FDI Policy Circular of 2020 issued by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, as amended from time to time.

3.11. Freight Costs

Expenses incurred for transportation of finished goods from the point of production i.e. factory premises to the port of export (including seaports, air cargo facilities in India) or international borders, excluding GST.

3.12. Installed Capacity

The installed capacity shall mean the capacity declared at the time of the start of commercial production by the unit, as per the Industrial Entrepreneur Memorandum (IEM Part B)/Registration/Certificate issued by a government authority as certified by CE.

3.13. Intellectual Property Rights (IPRs)

(i) Patents refers to the patents as defined and governed under The Patents Act, 1970, as amended from time to time.

(ii) Trademarks refers to the trademarks as defined and governed under The Trademarks Act, 1999, as amended from time to time.

(iii) Copyrights refers to the copyrights as defined and governed under The Copyright Act, 1957, as amended from time to time.

(iv) Geographical Indications (GI) refers to the geographical indications as defined and governed under The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999, as amended from time to time.

3.14. Large Scale Industrial Unit

A manufacturing enterprise which is not classified as MSME as per MSMED Act, 2006 as amended from time to time.

3.15. Mega Industry

A unit having an investment of more than:

1) More than ₹500 Crore in Plant & Machinery as per MSMED Act, 2006.

2) More than ₹250 Crore in Plant & Machinery as per MSMED Act, 2006 for following sectors:

    a. Any Large Industrial Unit coming in Priority Blocks.

b. High Potential Sectors, i.e.:

i. Personal Care and Cosmetics

ii. Petrochemicals, Plastics and Polymers

iii. Pharmaceutical and Biotechnology

iv. Renewable Energy Equipment Manufacturing

v. Any sunrise sector as defined by the State government from time to time.

3) More than ₹75 Crore in Plant & Machinery as per MSMED Act, 2006 in the following sectors:

a. Agri, Dairy and Food Processing

b. Furniture Manufacturing

c. Garment, Footwear, Toys and Accessories

d. Gems & Jewellery

e. Herbal and Minor Forest Produce

f. High Value-Add Manufacturing

4) Other Sectors (Like IT, ITeS, Tourism, Healthcare, Renewable Energy, etc) as per the policies of their respective department.

5) It is clarified here that, for availing customized package, the individual proposal/ project's investment in Plant and Machinery, should qualify under the mega unit definition as mentioned above in this section.

3.16. MPIDC

"MP Industrial Development Corporation (MPIDC)" refers to MP Industrial Development Corporation (MPIDC), formed and incorporated under the Companies Act, 1956, which is under the Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of MP.

3.17. MSMEs

As defined under the MSMED Act, 2006 by the Ministry of MSME, Government of India, as amended from time to time.

3.18. New Large Scale Industrial Units

Large Industrial units shall mean the industrial unit established within the boundaries of the State of Madhya Pradesh

AND

(i) A manufacturing enterprise which is not classified as MSME as per MSMED ACT 2006 as amended from time to time.

AND

An industrial entity by which a separate intention to invest proposal has been filed with MPIDC and IEM (Industrial Entrepreneur Memorandum) Part-A and/or Part-B has been received for this purpose from the DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

AND

In which new electricity connection has been obtained from the electricity distribution company.

AND

In case there are more than one unit in the same premises, each unit should be physically identifiable.

AND

Should be registered under the GST Act.

3.19. Plug and Play Facilities

Plug and Play facilities refer to fully developed industrial spaces equipped with pre-constructed factory premises, essential utilities, and shared services that enable industrial units to commence operations with

minimal lead time and capital expenditure. The Plug and Play facilities should offer ready-to-use infrastructure like built-up space, power, water supply, roads, gas pipeline, drainage, telecommunications, waste management systems, etc.

3.20. Priority Blocks

"Priority Block" refers to blocks as defined in Annexure-A.

3.21. Private Industrial Parks

Private Industrial Parks are large-scale, planned industrial areas developed and operated by private entities having comprehensive infrastructure, like roads, power, water, drainage, telecommunications, waste management systems, and support services, and may also feature common facility centers, logistics hubs, and shared utilities.

3.22. Renewable Energy Captive Power Plant

Means a power plant set up by a unit to generate renewable energy primarily for its own use, provided that not less than net 51% of power so generated is for consumption at the plant site. The unit shall furnish the Captive User status as certified by MPERC.

3.23. Standalone Industrial Utilities

Standalone Industrial Utilities refer to independently developed and operated infrastructure facilities that cater to industries such as power, water, boiler, gas pipelines, and waste management systems like Common Effluent Treatment Plants (CETP), Zero Liquid Discharge (ZLD), etc.

3.24. Standalone Research and Development Facilities, Industrial Testing / Certification Labs

A Standalone Research and Development (R&D) unit is an independent entity engaged in advanced research, innovation, product design, and engineering development to support manufacturing. These units operate separately from production plants but must have a direct and demonstrable link to manufacturing outcomes. To qualify under this

scheme, the research must lead to tangible manufacturing benefits, such as enhanced product performance, cost-efficient production techniques, new industrial materials, or scalable technologies.

To qualify as a standalone R&D facility under this scheme, the unit must:

- Be engaged in applied research, product development, process innovation, prototyping, or engineering advancements that are directly aligned with manufacturing goals.
- At the time of application, these units must present clearly defined, time-bound R&D programs aimed at delivering innovative products or technologies.
- Provide evidence that the research outcomes are intended for integration into a manufacturing process, either by the applicant's enterprise or through industry collaboration.
- Be recognized or registered with national institutions such as the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR), Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), or any other competent authority as notified by the government.
- Units engaged solely in market research, operational or management studies, routine testing and analysis, process or quality control, or day-to-day maintenance activities shall not be considered as standalone R&D facilities under this definition.

3.25. TECHNOLOGICAL UPGRADATION

Technological upgradation refers to units upgrading their technology (only related to production) and investing at least 30% of existing investment (with a minimum of ₹20 Crore) or ₹100 Crore in Plant & Machinery, whichever is lower.

The unit should be in commercial production for last 7 years for claiming technological upgradation incentive, without the change of product.

3.26. Term Loan

Term loan for the purpose of interest subsidy refers to loan taken from financial institution/bank for investment in Plant and Machinery as defined in 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 and 3.3.4.

3.27. Testing Facility

A Testing Facility refers to an institutional or industrial infrastructure dedicated to scientific, technical, and quality assurance testing of raw materials, intermediate goods, and final products across various sectors.

3.28. Vendor Units

Industrial units located in the same factory premises or within 50 km radius of the unit to which it is supplying at least 75% of its end-product.

4. Governance Structure

4.1. Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP)

1. The Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP) has been constituted under the chairmanship of the Chief Minister. Other members shall include Ministers of Finance, Commercial Tax, and Industrial Policy and Investment Promotion and other members as notified by the General Administration Department (GAD) from time to time.
2. The CCIP is empowered to sanction a customized package of assistance over and above the provisions within the prevalent investment promotion policies of GoMP on case-to-case basis. Such packages shall be available only to Mega Industrial Units.
3. As part of the special package, CCIP may sanction fiscal concessions exemptions, waivers, deferments etc on electricity duty, stamp duty, royalty, government dues, penal interest etc.
4. CCIP is empowered to address any gaps in the implementation and interpretation of this Policy.
5. On the request of investors or Suo-moto, CCIP may review incentive packages sanctioned to any Mega industrial unit. The

investor may request for review of sanctioned CCIP order maximum upto two times. The maximum timeline permissible for submission of such request shall be one year from the date of commencement of commercial production.

6. MPIDC shall act as the Secretariat for CCIP.
7. For other sectors like MSME, Tourism, IT, Energy, Health, Renewable Energy, etc, the concerned departments shall put up the cases for CCIP through DIPIP.
8. For availing the Customised Package under CCIP, the manufacturing units must qualify the basic eligibility criterion (expansion, diversification, technological upgradation, ineligible list, employment, etc.).

4.2. STATE LEVEL EMPOWERED COMMITTEE (SLEC)

i. SLEC is headed by the Chief Secretary and consists of Principal Secretaries of Department of Finance, Commercial Tax, Energy and Industrial Policy and Investment Promotion. Managing Director, MPIDC is the Member Secretary of the committee.

ii. The SLEC shall take up inter-departmental coordination and determine the eligibility of assistance as per policy and within the overall customized packages sanctioned by CCIP for Mega industrial units.

iii. The eligibility of all the incentives **except** Green Industrialisation Assistance, Infrastructure Development Assistance, Assistance for IPR, Organic Certification, Quality Certification, Capital Subsidy on Testing Facility (only for Pharmaceuticals, Biotechnology and Medical Devices) and Cost of Transfer of International Technology shall be determined by SLEC.

iv. MD, MPIDC is empowered to sanction and disburse incentives as per the eligibility determined by SLEC and the incentives mentioned in 4.2 (iii).

5. APPLICATION PROCEDURE

5.1. SUBMISSION OF APPLICATION FOR CUSTOMIZED PACKAGE

1. Mega Industrial Unit as defined in section 3.15 may seek customized package for incentives beyond the provisions of the policy.

2. In order to avail the customized package investors must file an intention to invest on the Invest portal and submit the proposal in the prescribed format (ref-form-1) to MPIDC through INVEST portal.

3. The proposal shall be presented before the Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP). The CCIP shall sanction the customized package on case-to-case basis. The CCIP process is outlined in Annexure-C.

4. The customised package sanctioned shall be uploaded on the INVEST portal.

5.2. SUBMISSION OF APPLICATION FOR INCENTIVES

1. FOR ELIGIBILITY DETERMINATION

1. To be eligible for claiming incentives under this policy, investors must file an intention to invest on the INVEST portal.
2. After commencement of Commercial production, Investors seeking incentives under the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2025/Customised Package sanctioned by CCIP must submit the application online on the INVEST portal (ref Form-2) within 180 days from the date of commercial production against the afore-mentioned intention to invest. Also, for additional investments during one year from the date of the commercial production the application shall be submitted within 180 days from the date of completion of one year from the date of commercial production.
3. In case of delay, the State Level Empowered Committee shall determine the eligibility as mentioned below:
   a. If application is received within 01 year after 180 days from the date of commencement of commercial production, then on the

merit of reason of delay either delay may be condoned OR deduction on pro-rate basis may be made in assistance amount.

b. If application is received after 1 year and 180 days from date of commencement of commercial production, then on the merit of reason of delay, the delay may be condoned OR deduction on pro-rate basis may be made in assistance amount OR case may be rejected.

4. Industrial units that has been sanctioned customised package by CCIP must fulfil the minimum eligible investment criterion for mega scale unit as on the date of commencement of commercial production.

5. The application must be accompanied by the necessary enclosures as specified, along with affidavits duly attested by a notary on stamp paper.

6. SLEC shall determine the eligibility of incentives as per the provisions of the scheme.

7. After review and approval by the State Level Empowered Committee, the Secretary of the Committee shall issue an official order specifying the sanctioned incentives including rate, eligibility period of assistance, maximum limit of assistance, etc.

8. A unit can apply for reconsideration of the case to the SLEC only once.

2. FOR CLAIMS

1. After eligibility determination by SLEC, the unit shall apply for claim online on the INVEST Portal. (ref Form3).

2. The application must be accompanied by the necessary enclosures as specified, along with affidavits duly attested by a notary on stamp paper of the prescribed fee.

3. MD, MPIDC is empowered to sanction and disburse incentives as per the eligibility determined by SLEC.

4. Incentives, as mentioned in 4.2 (iii) i.e. Green Industrialisation Assistance, Infrastructure Development Assistance, Assistance for IPR, Organic Certification, Quality Certification, Capital Subsidy on

Testing Facility (only for Pharmaceuticals, Biotechnology and Medical Devices) and Cost of Transfer of International Technology shall be approved, sanctioned and disbursed by MD MPIDC.

However, these claims shall be processed only after the determination of eligibility for other incentives by SLEC.

5. The sanctioned assistance amount shall be disbursed to the unit via e-payment.

6. After the sanction of assistance amount, no interest will be payable in case of delay in disbursement.

6. FINANCIAL INCENTIVES

6.1. INVESTMENT PROMOTION ASSISTANCE

i. **Basic Investment Promotion Assistance (BIPA):** Basic Investment Promotion Assistance for large units shall vary between 40% to 10% based on the below formula:

BIPA=IF (EFCI>=2000, 200, IF (EFCI<=50, 0.4*EFCI, MIN (15 + 0.08*(EFCI-50) + (EFCI/12) * ((1/(1+EXP (-5.9*(1 - EFCI/2490))))*(1 - EFCI/2490)) + 9.3*(1 - EFCI/2500), 0.4*EFCI, 200)))

ii. BIPA shall be limited to maximum ₹200 Crore.

iii. BIPA shall be provided in 7 equal annual instalments defined as Yearly BIPA.

iv. The First claim year shall be the year of commencing production. The units starting production after 30th September shall have an option to choose the next financial year as the First claim year.

In view of the time taken by pharmaceutical units in getting regulatory permissions, quality certifications and international compliances, pharmaceutical units shall be eligible to avail a slack period of up to two (2) years from the date of commercial production in the unit for claiming incentives, i.e. irrespective of the date of commercial production, pharmaceutical units can choose the 2nd or 3rd year after start of commencement of commercial production as first claim year. However, it

is clarified that the time period for assistance shall remain unchanged i.e. 7 years.

v. The claim for Investment Promotion Assistance, shall be submitted on the annual basis not later than 180 days after the end of every financial year during the eligibility period.

vi. MD, MPIDC may condone the delay in submitting the applications if valid reason is provided.

vii. The incentives multipliers shall be provided over and above the Yearly BIPA as mentioned below:

INCENTIVE MULTIPLIERS ON BIPA

1. GROSS SUPPLY MULTIPLE (GSM):

a. For the 1st year, GSM shall be 1, provided utilization of the total installed capacity, is 40%.

b. For 2nd year onwards, GSM shall be 1 provided the production is 75% of previous peak year or 50% of the Total Installed Capacity, whichever is more.

c. In case the above conditions are not fulfilled, GSM shall be reduced proportionately.

d. In case of a new unit, the installed capacity shall be as defined in Section 3.12.

e. In the case of expansion, the total installed capacity shall be the sum of the Existing Capacity, as defined in Section 3.4, and the Installed Capacity under expansion, as defined in Section 3.12.

2. EXPORT MULTIPLE (EM)

a. Export Multiple (EM) is a multiplier applied to Basic Investment Promotion Assistance (BIPA) for industrial units based on their export performance.

b. EM varies from 1.0 to 1.3, for 25% to 75% of exports with respect to total production quantity for particular claim year. The minimum value of 1.0 applies to units with exports of 25% or less and the maximum value of 1.3 applies to units with 75% or more exports.

c. Export Multiple is calculated on the basis of the following formula:

Export Multiple (EM)=IF (Export Percentage<25%,1, IF (Export Percentage<75%,1+0.3*(Export Percentage-25%)/50%,1.3))

d. The multiplier increases progressively as the export percentage increases.

e. For units established in SEZ areas, the Export Multiple is fixed at 1.0, regardless of their export percentage.

f. Only direct exports shall qualify for calculation of export multiple. Deemed exports (sales within India that are treated as exports) will not be eligible.

3. EMPLOYMENT MULTIPLE

a. Employment Multiple (EYM) is a multiplier applied to Basic Investment Promotion Assistance (BIPA) to incentivize job creation by industrial units.

b. Employment Multiple varies between 1.0 and 1.5, based on the annual average number of employees in an industrial unit. The minimum 1.0 applies to units employing 100 or less employees and the maximum 1.5 applies to units employing 2,500 or more employees.

c. Employment Multiple is calculated on the basis of the following formula:

Employment Multiple (EYM) = MAX [1,MIN{1.5,(1+(AE-100)*((1.5-1)/(2500-100))}]

Average Employees in the Reviewed Year (AE):

AE = Σ (Employee count at the month end for each month of the financial year)/12

d. The multiplier increases progressively as the number of employees rises.

e. In case of expansion/ diversification, the employment multiple shall remain 1.

4. GEOGRAPHICAL MULTIPLE

a. Geographical Multiple (GM) is a multiplier applied to Basic Investment Promotion Assistance (BIPA) to encourage industrial investments in priority blocks.

b. The standard value of Geographical Multiple (GM) is 1.3 for industrial units established in Priority Blocks.

c. The geographical multiple shall remain 1, for the units that are established in non- priority blocks and cement units, irrespective of the location.

d. The list of Priority Blocks is provided in Annexure-A.

5. FDI MULTIPLE

a. FDI Multiple shall be applied to Basic Investment Promotion Assistance (BIPA) to encourage Foreign Direct Investment (FDI) in Madhya Pradesh.

b. The FDI Multiple varies between 1.0 and 1.2, depending on the percentage of foreign equity in an industrial unit. The minimum value of 1.0 applies to units with less than 26% FDI and the maximum value of 1.2 applies to units with more than 50% FDI.

c. FDI Multiple is determined using the following formula:

FDI Multiple =IF (FDI<26, 1, IF (FDI<=51, 1.1 + (FDI-26)*(0.1/(51-26)), 1.2))

d. The multiplier gradually increases as the foreign investment percentage rises.

e. The FDI equity submitted at the time of date of commercial production, shall be considered for the calculation of FDI Multiple throughout the eligibility period. However, if in any claim period, the FDI equity reduces, the FDI Multiple shall be reduced proportionally as per the formula above.

f. Irrespective of New Unit or Expansion/Diversification, FDI multiple can be claimed only once by the unit.

6. FOOD PROCESSING MULTIPLE

a. Food Processing Multiple is a special multiplier applied to Basic Investment Promotion Assistance (BIPA) to encourage investments in the Agri, Dairy, and Food Processing sector.

b. Food Processing shall carry the same meaning as defined in Chapter 9.1.1 of the IPP, 2025.

c. The Food Processing Multiple is fixed at 1.5, this means such units will receive 50% additional financial assistance over standard BIPA incentives.

d. The food processing multiple for all types of Aerated/ carbonated beverages shall remain 1.

7. ADDITIONAL MULTIPLE FOR API/ BULK DRUGS

a. API/Bulk Drug Multiple is a special multiplier applied to Basic Investment Promotion Assistance (BIPA) for industries involved in Active Pharmaceutical Ingredient (API)/Bulk Drug manufacturing.

b. API/Bulk Drug shall carry the same meaning as defined in chapter 9.5.1 (1) of the IPP, 2025.

c. The units of API/Bulk drug manufacturing unit should have a valid API license for availing this multiple.

d. The multiple for API/ Bulk Drugs is fixed at 1.3 for API and Bulk Drug manufacturing units. This means such units will receive 30% additional financial assistance over standard BIPA incentives.

8. MEDICAL DEVICE MANUFACTURING MULTIPLE

a. Medical Device Manufacturing Multiple (MDM Multiple) shall be applied to Basic Investment Promotion Assistance (BIPA) to incentivize investments in the medical device manufacturing sector.

b. Medical Devices shall carry the same meaning as defined in chapter 9.7.1 of the IPP, 2025.

c. The multiple for Medical Device Manufacturing is fixed at 1.3 for eligible medical device manufacturing units. This means such units will receive 30% additional financial assistance over standard BIPA incentives.

9. MULTIPLE FOR EV MANUFACTURING

a. EV Multiple shall be applied to Basic Investment Promotion Assistance (BIPA) for industries engaged in Electric Vehicle (EV) manufacturing.

b. For verification of plant and machinery of EV manufacturing, the unit shall furnish a certificate issued by Chartered Engineer.

c. The value of EV Multiple is fixed at 1.3 for EV manufacturing units. This means such industries will receive 30% additional financial assistance over standard BIPA incentives.

10. MULTIPLE FOR HVA

a. High Value-Add Manufacturing Multiple (HVA Multiple) shall be applied to Basic Investment Promotion Assistance (BIPA) for industries engaged in the production of high-value, high-tech, and innovation-driven products.

b. High Value-add manufacturing shall carry the same meaning as defined in chapter 9.10.1 of the IPP, 2025.

c. The value of HVA Multiple is fixed at 1.3 for high-value-add manufacturing units. This means such industries will receive 30% additional financial assistance over standard BIPA incentives.

viii. For new units, the BIPA shall be calculated on the investment made in the last three (3) years from the date of commercial production and one (1) year after the commencement of commercial production.

ix. For expansion and diversification, the BIPA shall be calculated on the investment during the last two (2) years from the date of commercial production and one (1) year after the commencement of commercial production.

6.2. ASSISTANCE FOR TECHNOLOGICAL UPGRADATION

Any type of unit undergoing technological upgradation shall only be eligible for the following incentives:

1. The units undergoing technological upgradation shall be eligible to avail only IPA (without multiples) at the rate of 10% of the

investment made in EFCI, capped at maximum of ₹20 Crore in 7 equal annual instalments.

2. The unit must have been in commercial production for the last seven years without a change in product to qualify for the technological upgradation incentive.
3. The EFCI for Technological Upgradation shall include only investments made in upgrading existing machinery.
4. The claim for assistance for technological upgradation shall be submitted on the annual basis not later than 180 days after the end of every financial year during the eligibility period.
5. MD, MPIDC may condone the delay in submitting the applications if valid reason is provided.
6. The incentive shall be calculated on the investment during the last two (2) years from the date of commercial production and one (1) year after the commencement of commercial production.

6.3. GREEN INDUSTRIALIZATION ASSISTANCE

a. Capital Subsidy for Waste Management Systems:
   - Industrial units setting up waste management infrastructure, including Effluent Treatment Plants (ETP), Sewage Treatment Plants (STP), and pollution control devices, etc are eligible to receive a capital subsidy of 50% on investment made for setting up of Waste Management Systems, with a maximum limit of ₹5 Crore.
   - A capital subsidy of 50% on investment made for setting up of Waste Management Systems with Zero Liquid Discharge (ZLD), subject to a maximum cap of ₹10 Crore.
   - The financial assistance shall be sanctioned in two equal annual instalments.

b. The incentive shall be calculated on the investment during the last two (2) years from the date on which the facility becomes operational.

c. For availing green industrialization assistance, the units shall claim within 24 months from the date of the commencement of commercial production of the unit.

d. MD, MPIDC may condone the delay in submitting the applications if valid reason is provided.

6.4. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ASSISTANCE

a. This assistance shall be available to new industrial units that are established on:
   - Private land
   - Undeveloped Government land

b. The capital subsidy of 50%, up to a maximum of ₹5 crore on expenditure incurred by the industrial units for developing the following essential infrastructure shall be made available:
   - Road: The approach road to the factory gate from the main road.
   - Water: Necessary infrastructure to source water and Water pipeline developed from the water source to the factory premises.
   - Power: Power line for sourcing electricity from the main line to the factory premises.
   - Drainage and Sewage: Necessary infrastructure developed for the establishment of drainage or sewage infrastructure from the factory gate to the main drainage/sewage infrastructure.
   - Gas pipeline: Necessary infrastructure developed from the main line till the factory gate.

c. The incentive shall be calculated on the investment during the last three (3) years from the date on which the facility becomes operational.

d. For availing infrastructure development assistance, the units shall claim within 24 months from the date of the commencement of commercial production of the unit.

e. MD, MPIDC may condone the delay in submitting the applications if valid reason is provided.

6.5. ASSISTANCE FOR IPR AND ORGANIC CERTIFICATION

To promote research, development, and sustainable practices in the State, the following reimbursements shall be provided to the units established within the State during the policy period:

IPR Assistance

i. 100% reimbursement of expenses incurred for obtaining intellectual property rights, including filing patents, copyrights, trademarks, and geographical indications (GI) obtained within first 5 years from the date of commencement of commercial production.

ii. The total reimbursement is capped at ₹10 Lakh over a period of 5 years.

iii. Units will be eligible for reimbursement of both domestic and international IPR registrations.

iv. Under the aforementioned financial limit or time limit, a unit can apply for reimbursement of expenses incurred for registering more than one patent/IPR.

v. The developed product/process for which the patent has been obtained must be used for commercial production/process by the unit in Madhya Pradesh.

vi. The unit should apply for claiming the incentive within 180 days of the date of the award of the certification.

vii. MD, MPIDC may condone the delay in submitting the applications if valid reason is provided.

Organic Certification Assistance:

i. 100% reimbursement of expenses incurred for obtaining organic certifications from APEDA-accredited agencies obtained within first 5 years from the date of commencement of commercial production.

ii. The total reimbursement is capped at ₹5 Lakh per unit over a period of 5 years.

iii. Under the aforementioned financial limit or time limit, a unit can apply for reimbursement of expenses incurred for obtaining multiple organic certifications.

iv. The certified organic product must be utilized for commercial production/process by the unit in Madhya Pradesh.

v. The unit should apply for claiming the incentive within 180 days of the date of the award of the certification.

vi. MD, MPIDC may condone the delay in submitting the applications if valid reason is provided.

6.6. Incentives to Provide Employment to Differently Abled Persons

1. The incentives shall be provided to the units employing differently abled persons.
2. The incentives shall be provided for a period of 5 years.
3. In order to avail the incentives, minimum 5% of the total workforce, as on date of Commercial Production, should consist of differently abled persons. The unit must maintain the criterion of minimum workforce for a period of 5 years. If in any claim year, the minimum criterion is not fulfilled, the unit shall not be eligible for the incentives.
4. The list of the differently abled employees shall be provided by the unit separately along with the disability certificate issued by the competent authority.
5. Following incentives shall be provided to eligible units:

    1) Skill Development:

        a) 100% reimbursement of expenses incurred on skill development training for persons with disabilities in government ITIs.

        b) The incentive shall be available for the persons appointed and obtaining training in first 5 years after date of commencement of commercial production.

        c) The incentive shall be provided to an individual only once.

2) Employees' Provident Fund (EPF) and Employee State Insurance (ESI) Assistance:
   a) Employees' contribution being deposited by the employer for differently abled employees would be reimbursed for a period of 5 years.
   b) The incentive shall be available for the employees appointed in the first five years from the date of commencement of commercial production.
   c) The amount of reimbursement shall be ₹6,000/month or the actual amount deposited, whichever is less.
3) Reimbursement of Insurance Premium:
   a) 100% reimbursement of insurance premiums paid for differently abled employees.
   b) The reimbursement is applicable only for those differently abled employees who are not eligible for free insurance under the Ayushman Bharat Scheme 2018.
   c) The assistance will be provided for a period of 5 years.
   d) The incentive shall be available for the employees appointed in the first five years from the date of commencement of commercial production.
   e) Units must provide valid proof of premium payments to claim reimbursement.

6. Deduction of Government Assistance: If the industries have received similar assistance under any Government of India scheme, such assistance will be deducted from the incentive payable.

6.7. REIMBURSEMENT OF COST OF TRANSFER OF INTERNATIONAL TECHNOLOGY (Assistance for Units Bringing in FDI more than 26%)

1. 50% reimbursement of the cost incurred for International Technology Transfer, limited to transfers completed within the first 5 years from the date of commencement of commercial production.
2. The total reimbursement is capped at ₹1 Crore, provided the unit develops local vendor units through the transferred technology.

3. Under the aforementioned financial limit or time limit, a unit can apply for reimbursement of expenses incurred for more than one technology transfer, subject to eligibility.
4. The acquired technology must be implemented for commercial production or process utilization by the unit in Madhya Pradesh.
5. The unit should apply for claiming the incentive within 180 days from the date of completion of the technology transfer to the vendor units.
6. MD, MPIDC may condone the delay in submitting the applications if a valid reason is provided.

6.8. INDUSTRIAL HOUSING

To promote the "Walk to Work" concept and enhance the work-life balance of the industrial workforce, the State Government will facilitate the development of worker housing facilities in and around industrial areas. These efforts will be aligned with guidance notes and concept papers issued by the Government of India, NITI Aayog, and international best practices.

The State Government, through its agencies, will promote industrial housing projects under a Public-Private Partnership (PPP) model, with the provision of Viability Gap Funding (VGF) of up to 40% to make such projects financially feasible. These housing facilities will be made available to industries on a rental basis and will be specifically designed to cater to the needs of industrial workers and their families. This initiative reflects the Government's commitment to ensuring sustainable industrial development alongside improved living conditions and social infrastructure for workers.

To further support labour-intensive sectors of Garments, Footwear, Toys and Accessories, as well as High Value-Add sector, the following enablers will be provided:

1) Industrial housing and worker dormitories, along with essential social infrastructure (e.g., canteens, community areas, etc.), shall be permissible on up to 20% of the land allotted by State agencies for industrial use.

2) A Floor Area Ratio (FAR) upto 2 shall be allowed specifically for the construction of industrial and worker housing.

Necessary amendments to the Land Management Rules will be undertaken to facilitate the above provisions.

6.9. EXPORT FREIGHT SUBSIDY FOR TRANSPORTATION OF GOODS

1. This incentive shall be provided to the exporting units.
2. The Freight reimbursement shall be for transportation costs incurred for moving finished goods from the factory premises to the international borders or seaport or to the air cargo facility, by road, water, air, rail.

   For Example: Unit A is shipping goods for exports to JNPT via Tihi ICD, the costs eligible for reimbursement will include Cost of Transportation from Unit A premise to Tihi ICD and Cost of transport from ICD to JNPT.
3. This subsidy is available for a period of 5 years from the date of Commercial Operation.
4. The maximum amount of reimbursement shall be 50% or ₹40 Lakh per unit per year, maximum upto ₹2 Crore for a period of 5 years.
5. Only direct exports shall qualify for calculation of export freight subsidy. Deemed exports (sales within India that are treated as exports) will not be eligible.
6. The claim shall be submitted on the annual basis not later than 180 days after the end of every financial year during the eligibility period. MD, MPIDC may condone the delay.
7. For availing the export freight subsidy, the unit shall furnish CA certificate verifying the transportation cost based on the e-way bill/transportation invoices and books of accounts.

6.10. ASSISTANCE FOR STANDALONE RESEARCH AND DEVELOPMENT FACILITIES, INDUSTRIAL TESTING / CERTIFICATION LABS

1. The standalone research and development facilities, industrial testing / certification labs as defined under section 3.24 of this scheme shall

be eligible for reimbursement of 25% of the Fixed Capital Investment, up to a maximum of ₹25 Crore.

2. The Fixed Capital Investment shall include R&D equipment and building, excluding land.
3. The units with an investment of ₹125 Crore or more in FCI shall be eligible.
4. The building shall include the main laboratory premises, office building, administrative building, restrooms/washrooms, and allied infrastructure related solely to R&D activities.
5. The reimbursement will be provided in four (4) equal annual instalments.
6. For annual disbursements, the unit must provide an affidavit certifying that the R&D unit is functional, supported by the annual reports submitted to CSIR/DSIR or any other government agency and electricity bills.
7. The date of commencement of operation of the facility shall be the same as the date of purchase of first raw material and/or IEM, whichever is earlier.

6.11. MANDI-FEE REIMBURSEMENT

1. Mandi Fee reimbursement is available to Agri, Dairy and Food Processing sector as per chapter 9.1 of IPP, 2025.
2. 100% Mandi fee will be reimbursed on procurement of agricultural produce for a period of 5 years or a maximum of 50% of investment in Plant & machinery (whichever is earlier or lower).
3. The plant and machinery in point no. 2 shall be limited to investments in main processing machinery upto date of commercial production.
4. This facility of reimbursement will be available only to those units which purchase agricultural produce of the state.
5. The unit shall provide the calculation of the mandi fees paid on the procurement of the agricultural produce of the State, verified by MP

State Agricultural Marketing Board, Department of Farmer Welfare and Agriculture development, along with the annual claim.

6. The claim shall be submitted on the annual basis not later than 90 days after verification is received from the MP State Agricultural Marketing Board.

6.12. POWER TARIFF REIMBURSEMENT

1. Power Tariff reimbursement of ₹1/unit shall be given for a period of 5 years for the following sectors:
   (i) Units in Agri, Dairy, and Food Processing as per Chapter 9.1 of IPP, 2025.
   (ii) Units in Garment & Apparel, Footwear, Toys, and Accessories as per Chapter 9.3 of IPP, 2025.
2. The unit shall provide the calculation of the assistance based on the consumption of the electricity, verified by respective DISCOMs along with the claim.
3. The claim shall be submitted on the quarterly basis not later than 90 days from the issue of the calculation by the respective DISCOMs.

6.13. QUALITY CERTIFICATION

1) Incentive for Quality Certification is available for the following sectors under IPP, 2025:
   a) Agri, Dairy, and Food Processing as per Chapter 9.1 of IPP, 2025:
      - The incentive is available for projects obtaining certifications like GMP, USFDA, ISO, ISI, BIS, FPO, AGMARK, Ecomark, or any other national or international quality certification.
      - The subsidy will be available for a period of 5 years.
      - The subsidy is available in the form or reimbursement which shall be 50% of the total cost incurred for obtaining the certification or ₹5 Lakh, whichever is lower or earlier within the specified time period.
   b) Aerospace And Defence Production Promotion as per Chapter 9.4 of IPP, 2025:

- This incentive is available for projects obtaining quality certifications related to the Aerospace and Defence sector.
- The subsidy will be available for a period of 5 years.
- The subsidy is available in the form of reimbursement which shall be 50% of the Quality Certification cost or ₹10 Lakh, whichever is lower.

c) Pharmaceuticals as per Chapter 9.5 of IPP, 2025:

- This incentive is available for Projects obtaining certifications like WHO, GMP, GLP, USFDA, UKMHRA, CE, ISO, ISI, BIS, BEE, Ecomark, HACCP, TQM, or any other national or international quality certification.
- The subsidy will be available for a period of 5 years.
- The subsidy is available in the form of reimbursement, covering 50% of the total cost incurred for obtaining the certification or ₹1 Crore, whichever is lower within the specified time period.

d) Electric Vehicle Manufacturing as per Chapter 9.8 of IPP, 2025:

- This incentive is available for the manufacturers of Electric Vehicles who are obtaining quality certifications related to the Electric Vehicles.
- The subsidy will be available for a period of 5 years.
- The subsidy will be available in the form of reimbursement of 50% of Quality Certification cost or ₹1 Lakh per model whichever is lower upto a maximum of 10 Lakh.

e) Renewable Energy Equipment Manufacturing as per Chapter 9.9 of IPP, 2025:

- This incentive is available for the manufacturers of Renewable Energy Equipment who are obtaining quality certifications related to this sector.
- The subsidy will be available for a period of 5 years.
- The subsidy will be available in the form of reimbursement of 50% of Quality Certification cost or ₹1 Lakh whichever is lower during the time period.

f) High Value-Add Manufacturing as per Chapter 9.10 of IPP, 2025:

- This incentive is available for the High Value-Add Manufacturing sector units who are obtaining quality certifications related to this sector.
- The subsidy will be available for a period of 5 years.
- This subsidy will be available in the form of reimbursement of 50% of Quality Certification cost or ₹1 Lakh whichever is lower.

2) Under the aforementioned financial limit or time limit, a unit can apply for reimbursement of expenses incurred for procuring more than one quality certification.
3) The quality certification assistance is available only to those units that are operational in Madhya Pradesh.
4) The unit should apply for claiming the incentive within 180 days of the date of the award of the certification.
5) MD, MPIDC may condone the delay in submitting the applications if valid reason is provided.

6.14. INTEREST SUBSIDY

1. Interest Subsidy shall be available to the units in the:
   a) Textile sector as per Chapter 9.2 of IPP, 2025
   b) Garment & Apparel, Footwear, Toys, and Accessories sector as per Chapter 9.3 of IPP, 2025.
2. Textile units shall be eligible to claim 5% interest subsidy on term loan taken for Plant & Machinery for 5 years from the date of commercial production.
3. Garment & Apparel, Footwear, Toys and Accessories shall be eligible to claim 5% interest subsidy on term loan taken for Plant & Machinery for 7 years from the date of commercial production.
4. The plant and machinery, for the purposes of interest subsidy, shall only include the plant and machinery that is being used for the main manufacturing process, as defined in the section 9.2.1 of the IPP 2025. It would exclude power related machinery, waste management, etc.

5. For the purpose of the assistance, the term loan disbursed by the bank upto date of commercial production plus one (1) year after the date of commercial production shall be considered.
6. The maximum amount of interest subsidy for a unit shall be ₹50 crores.
7. Unit must submit the loan sanction order, Bank certificate for term loan sanctioned and disbursed for purchase of plant and machinery, Repayment schedule, and Due diligence certificate in prescribed format for determination of eligibility by SLEC.
8. The claims can be presented on quarterly basis along with the quarterly claim statement and due diligence certificate issued by the bank.
9. The interest subsidy shall be sanctioned according to the subsidy amount mentioned in the repayment schedule or as per the quarterly claim statement, whichever is lower.

6.15. Training & Skill Development

1. Assistance for Training and Skill Development available to the units in the:
   a) Garment & Apparel, Footwear, Toys, and Accessories sector as per Chapter 9.3 of IPP, 2025.
   b) High Value-Add Manufacturing as per Chapter 9.10 of IPP, 2025.
2. A one-time reimbursement of ₹13,000 per new employee shall be provided for skill development and training expenses.
3. The reimbursement will be available for a period of 5 years starting from 3 months prior to the date of commencement of commercial production.
4. The subsidy is applicable to units with employing more than a total of 250 employees, i.e. total number of employees should be more than 250 irrespective of expansion/diversification.
5. The duration of the training and skill development should be a minimum of 104 Hours or 13 working days.
6. The maximum number of employees eligible for this assistance is 4,000.
7. This assistance will be provided only to Madhya Pradesh domicile employees.

6.16. Assistance for Employment Generation

1. This assistance is available only to the units in Garment & Apparel, Footwear, Toys, and Accessories sector as per Chapter 9.3 of IPP, 2025.
2. Employment Generation Assistance of upto ₹5,000 per month per new employee for a maximum period of 5 years for employees who join within the first 8 years after commencement of commercial operations.
3. The assistance period is capped at 10 years from the date of commencement of commercial production, i.e., Employees hired in the eighth year will be eligible for the subsidy only for the next two years from their date of appointment.
4. Employment Generation Assistance shall be available to a new employee only once, for a maximum cumulative period of five years, irrespective of whether the employee leaves and rejoins the same unit at a later time i.e. if an employee rejoins, the previously claimed assistance period shall be counted towards the total five-year limit.

   Further it is clarified that, the assistance shall be available for new employee only once irrespective of the expansion/diversification by unit.
5. The subsidy is applicable to units with employing more than a total of 250 employees, i.e. total number of employees should be more than 250 irrespective of expansion/diversification.
6. Conditions for Eligibility:
   a. The assistance will be subject to maintaining a minimum average percentage of total Madhya Pradesh domicile employees in the unit irrespective of the expansion/diversification, as follows:
      i. Within 1 year from the commencement of production: 50%
      ii. Within 3 years from the commencement of production: 75%
      iii. Within 5 years from the commencement of production: 90%
   b. If the aforementioned conditions are not fulfilled, the assistance shall be reduced proportionately.

6.17. Reimbursement of Stamp Duty and Registration Charges

1. This incentive is available for the units coming up in:

a. Garment & Apparel, Footwear, Toys, and Accessories sector as per Chapter 9.3 of IPP, 2025.

2. These units will be reimbursed 100% of the stamp duty and registration fee charged on the land lease.
3. The subsidy is applicable to units that take land on lease in industrial areas established by the State Government.

6.18. INCENTIVE FOR SETTING UP OF TESTING FACILITY

1) Incentive for setting up of testing facility is available for the following sectors under IPP, 2025:

a) Pharmaceuticals as per Chapter 9.5 of IPP, 2025:

(i) 50% of the Capital Investment shall be reimbursed, subject to a maximum limit of ₹1 Crore.

(ii) The capital investment shall include the investment done in plant and machinery, equipment's, testing lab building, and other related infrastructure.

(iii) The testing facility shall furnish the requisite certifications/permissions from the competent authority recognised by Government of India/Government of Madhya Pradesh.

(iv) The testing facility involved in experimentation on animals shall be registered under the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA) and controlled by The Institutional Animal Ethics Committee (IAEC).

b) Biotechnology as per Chapter 9.6 of IPP, 2025:

(i) 50% of the Capital Investment shall be reimbursed, subject to a maximum limit of ₹1 Crore.

(ii) The capital investment shall include the investment done in plant and machinery, equipment's, testing lab building, and other related infrastructure.

(iii) The testing facility shall furnish the requisite certifications/permissions from the competent authority

recognised by Government of India/Government of Madhya Pradesh.

(iv) The testing facility must be registered under the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA) and controlled by The Institutional Animal Ethics Committee (IAEC).

c) Medical Devices as per Chapter 9.7 of IPP, 2025:

(i) 50% of the Capital Investment shall be reimbursed, subject to a maximum limit of ₹1 Crore.

(ii) The testing facility shall furnish the requisite certifications/permissions from the competent authority recognised by Government of India/Government of Madhya Pradesh.

d) Electric Vehicle as per Chapter 9.8 of IPP, 2025:

(i) Investment in in-house testing facilities, including battery testing, shall be considered under Eligible Fixed Capital Investment (EFCI).

(ii) The maximum eligible investment under EFCI shall be 50% of the cost of Plant & Machinery, Factory Sheds and Buildings as defined under sections 3.3.1 and 3.3.2.

(iii) The testing facility shall furnish the requisite certifications/permissions from the competent authority recognised by Government of India/Government of Madhya Pradesh.

2) The unit should apply for claiming the incentive within 180 days of the date of establishment of the testing facility, during the eligibility period determined by SLEC for Investment Promotion Assistance.

3) MD, MPIDC may condone the delay in submitting the applications if valid reason is provided.

6.19. Concession in Development Charges

1) The Concession in Development Charges is available for the following sectors under IPP, 2025:

a) For Garment & Apparel, Footwear, Toys, and Accessories as per Chapter 9.3 of IPP, 2025 and Renewable Energy Equipment Manufacturing as per Chapter 9.9 of IPP, 2025:

(i) In addition to the effective rebate on land premium as per the prevalent Madhya Pradesh State Industrial Land and Building Management Rules, units shall be provided a 50% concession on the development charge levied by MPIDC.

(ii) The MPIDC shall reimburse this concession to the unit after the commencement of commercial production.

b) For Aerospace and Defence Production Promotion as per Chapter 9.4 of IPP, 2025 and Electric Vehicle Manufacturing as per Chapter 9.8 of IPP, 2025:

(i) In addition to the effective rebate on land premium as per the prevalent Madhya Pradesh State Industrial Land and Building Management Rules, units shall be provided a 25% concession on the development charge levied by MPIDC.

(ii) The MPIDC shall reimburse this concession to the unit after the commencement of commercial production.

7. ASSISTANCE FOR PRIVATE INDUSTRIAL PARK DEVELOPERS

i. Assistance shall be provided for setting up of food parks, or any other industrial parks related to manufacturing.

ii. The Private Park developer shall submit the proposal for establishment of Private Industrial Park along with Detailed Project Report and other necessary documents to MPIDC (ref- Form 6). The eligibility shall be subject to the following conditions:

a. The private industrial park should be 10 acres or more.

b. The investment in Private Industrial Park by the developer should be ₹125 Crore or more.

c. The private industrial park should have minimum 5 manufacturing units.

iii. SLEC shall provide in-Principle approval of the proposal and based on the proposal, broadly defining the following:

a. Timeline for the completion of the project.

b. Investment.

c. Infrastructure to be developed.

iv. The timeline for the completion of the project as determined by SLEC can be extended twice for a period of 1 year each by MD, MPIDC based on merits of the reason of delay.

v. If the developer fails to complete the project, despite the extension provided, the in-Principle approval granted by SLEC shall stand cancelled.

vi. The developer of the Private Industrial Park can file an appeal within 180 days in SLEC against the cancellation of the approval of project.

vii. SLEC shall be authorised to review the appeal and take decision on the basis of merits of the case.

viii. The Private Industrial Park developer shall submit the application in the prescribed format (ref-Form 7) within 180 days of completion of the industrial park along with the supporting documents to the Managing Director, MPIDC for sanctioning assistance.

ix. The eligibility for the Assistance shall be determined by SLEC. The developer shall furnish work completion certificates, CA certificates and CE certificates for the investment in Private Industrial Park.

x. The private industrial park shall comply with the guidelines issued by the competent authority, as amended from time to time.

xi. Developer Continuity Obligation: Any developer availing assistance under the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2025 for setting up a Private Industrial shall not exit, transfer, or assign their role as the developer during the assistance disbursal period and additional three (3) years thereafter.

Any proposed change in ownership, management, or developer status during this period shall require prior written approval from the MD, MPIDC.

xii. <u>Fiscal Incentives:</u>

a. **Reimbursement of Stamp Duty and Registration Charges:** 100% reimbursement of stamp duty and registration charges

shall be provided on the purchase of land for the industrial parks.

b. Fixed Capital Assistance for Infrastructure Development:

- Developers of private industrial parks are eligible for fixed capital assistance.
- Assistance will be in the form of reimbursement of ₹20 lakh per acre or 50% of the fixed capital investment done in infrastructure development, whichever is lower, subject to a maximum of ₹40 crore per project.

Fixed Capital investment shall include expenditure in Infrastructure Development as below:

a. Internal Road development
b. Internal Power Infrastructure
c. Internal Water Infrastructure
d. Internal Drainage Infrastructure
e. Internal Gas Pipeline
f. Compound Walls
g. Any other relevant infrastructure

- The investments done by the developer from the date of submission of proposal till the completion of infrastructure, as per the conditions stipulated by SLEC, shall be considered for the calculation of assistance. The developer shall furnish CE certificate certifying completion of the infrastructure.
- The investments done in Land and infrastructure for dwelling units shall not be eligible for this assistance.
- The fixed capital assistance shall be sanctioned on milestone basis (ref-Form- 8) as provided below-
  - **First Instalment:** First instalment of 50% of the assistance shall be released after completion of infrastructure construction.

- **Second Instalment:** Second instalment of 50% shall be provided after the establishment of 5 industrial units, i.e., after the commencement of commercial production of 5 units.

  The developer shall furnish the IEMs/Udhyog Aadhar of the 5 units along with the affidavit and CE certificate for the same.

c. Green Industrialization Assistance:

- Capital Subsidy for Waste Management Systems:
  - For setting up of Common waste management infrastructure, including Effluent Treatment Plants (ETP), Sewage Treatment Plants (STP), and pollution control devices, etc. are eligible to receive a capital subsidy of 50% on investment made for setting up of Waste Management Systems, with a maximum limit of ₹5 Crore.
  - A capital subsidy of 50% on investment made for setting up of Waste Management Systems with Zero Liquid Discharge (ZLD), subject to a maximum cap of ₹10 Crore.
  - The financial assistance shall be sanctioned in two equal annual instalments.

xiii. The units coming up in the industrial park shall be granted incentives as per the provisions specified in Chapter 8 or Chapter 9 of IPP 2025 or under the policy framework of the respective department governing the industrial sector of the unit.

8. ASSISTANCE FOR DEVELOPING PLUG AND PLAY FACILITIES FOR MANUFACTURING/SERVICES SECTORS AND UNITS ESTABLISHING IN PLUG AND PLAY PARKS

i. Assistance shall be provided for the development of Plug and Play parks for the manufacturing and service sectors.

ii. The Plug and Park Developer shall submit the proposal for the establishment of Plug and Play infrastructure along with the Detailed

Project Report and other necessary documents to MPIDC (ref-Form 6). The eligibility shall be subject to the following conditions:

a. The investment in Plug and Play Park by the developer should be ₹125 Crore or more.
b. The private industrial park shall comply with the guidelines of Town and Country Planning, as amended from time to time.

iii. SLEC shall provide in-Principle approval of the proposal and based on the proposal, broadly defining the following:
   a. Timeline for the completion of the project.
   b. Investment.
   c. Infrastructure to be developed.
   d. Common Facility Centres (CFCs) to be developed.

iv. The timeline for the completion of the project as determined by SLEC can be extended twice for a period of 1 year each by MD, MPIDC based on merits.

v. If the developer fails to complete the project, despite the extension provided, the in-Principle approval granted by SLEC shall stand cancelled.

vi. The developer of the Plug and Play Park can file an appeal within 180 days in SLEC against the cancellation of the approval of the project.

vii. SLEC shall be authorised to review the appeal and take a decision on the basis of merits of the case.

viii. The developer of the Plug and Play Park shall submit the application in the prescribed format (Form 7) within 180 days of completion of the infrastructure along with the supporting documents to the Managing Director, MPIDC for sanctioning assistance.

ix. The eligibility for assistance shall be determined by SLEC. The developer shall furnish work completion certificates, CA certificates, and CE certificates for the investment in Plug and Play Park.

x. Developer Continuity Obligation: Any developer availing assistance under the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2025 for setting up a Plug and Play Park shall not exit, transfer, or assign their

role as the developer during the assistance disbursal period and additional three (3) years thereafter.

Any proposed change in ownership, management, or developer status during this period shall require prior written approval from the MD, MPIDC.

xi. Fiscal Incentives:

a. Fixed Capital Assistance for Infrastructure Development:

- Developers of Plug and Play parks are eligible for fixed capital assistance.
- Assistance will be in the form of reimbursement of 25% on the investment made towards fixed infrastructure, subject to a maximum of ₹25 Crore.
- Fixed Capital investment shall include expenditure in Infrastructure Development as below:
    i. Internal and approach Road development
    ii. Internal Power Infrastructure
    iii. Internal Water Infrastructure
    iv. Internal Drainage Infrastructure
    v. Internal Gas Pipeline
    vi. Compound Walls
    vii. Any other relevant infrastructure
    viii. Building
- The investments done by the developer from the date of submission of proposal till the completion of infrastructure, as per the conditions stipulated by SLEC, shall be considered for the calculation of assistance. The developer shall furnish CE certificate certifying completion of the infrastructure.
- The investments done in Land and infrastructure for dwelling units shall not be eligible for this assistance.
- The fixed capital assistance shall be sanctioned on milestone basis (ref- Form 8) as provided below-

- **First Instalment:** 50% of the assistance shall be released after the completion of infrastructure construction.
- **Second Instalment:** 25% shall be provided upon achieving a minimum occupancy of 25%, supported by the Rent Agreement.
- **Third Instalment**: 25% shall be provided upon achieving a minimum occupancy of 40%, supported by the Rent Agreement.
- The developer shall furnish the IEMs/Udhyog Aadhar of the established units along with the affidavit and CE certificate for the same.

b. Green Industrialization Assistance:

- Capital Subsidy for Waste Management Systems:
  - For setting up of Common waste management infrastructure, including Effluent Treatment Plants (ETP), Sewage Treatment Plants (STP), and pollution control devices, etc. are eligible to receive a capital subsidy of 50% on investment made for setting up of Waste Management Systems, with a maximum limit of ₹5 Crore.
  - A capital subsidy of 50% on investment made for setting up of Waste Management Systems with Zero Liquid Discharge (ZLD), subject to a maximum cap of ₹10 Crore.
  - The financial assistance shall be sanctioned in two equal annual instalments.

c. Subsidy on Common Facility Centres:

- Developers shall be eligible for capital assistance of 25% on the investment made for the establishment of Common Facility Centres (CFCs).
- The SLEC shall define the CFCs based on the project report on case-to-case basis.

- This assistance shall be subject to a maximum of ₹25 Crore.
- The amenities included in the green industrialization assistance shall not be included in the CFCs. In a broad sense, the CFCs may include, but not limited to the following:
  a. Shared testing laboratories for industrial quality control.
  b. Research & Development (R&D) centres for innovation in manufacturing.
  c. Skill development centres to train and upskill the industrial workforce.
  d. Logistics and warehousing facilities to support industrial supply chains.

xii. <u>For rental assistance in case of units established in Plug and Play Parks:</u>

a. The units occupying plug and play facilities developed by private Plug & Play developer under this scheme shall be provided with a 50% rental subsidy for 5 years (Maximum of ₹10 per square ft/ month for 5 years).
b. The facility shall be available to the manufacturing as well as service sector.
c. It is clarified that service sector does not include repairs, consultancy services, law firms, pathology, clinics, and any other sector as identified by SLEC from time to time.
d. For claiming rental assistance, units must submit rent agreement and CA certificate for rent paid by the unit.
e. To claim rental assistance the units occupying plug and play spaces shall submit form (ref- Form 9) with necessary documents, within 180 days from the start of start of the commercial operations.

f. Units which have taken plug & play spaces on concessional monthly rentals offered by either Private or Government developer will not be eligible to take rental assistance.

g. This rental subsidy shall also to available to the units occupying plug and play facilities developed by MPIDC.

9. TERMS AND CONDITIONS

1. Incentives and financial assistance under this policy shall be applicable only to the large-scale manufacturing units, standalone Research and Development Facilities, Industrial Testing / Certification Labs or Private Park Developers or Plug and Play Facility Developers.
2. MPIDC will be the nodal agency for the implementation of this Policy. Investors shall have to register their proposal with the Single Window System of MPIDC and use the Intention to Invest Number/ Intention Number to avail incentives under this policy.
3. Units which have already been sanctioned incentives under IPP 2014 or earlier policies or which have commenced the Commercial Production before the notification of this policy, shall not be eligible for benefits under this policy.
4. In any case, the gross investment assistance given to the unit shall not exceed the total amount of investment made by the unit in Fixed Capital Investment (excluding Garment, Toy, Footwear and Accessories units where the capping shall be 200%).
5. If an industry qualifies for incentives under multiple policies of the Madhya Pradesh Government, the investor shall be eligible to receive benefits under only one policy of their choice unless specifically mentioned in the policy that it is over and above IPP, 2025. This is subject to the condition that the cumulative assistance may not be more than the investment amount in FCI (excluding Garment, Toy, Footwear and Accessories units where the capping shall be 200%).
6. If a manufacturing unit wishes to avail financial assistance from Government of India over and above its eligibility under this Policy, it may do so, subject to the condition that the cumulative assistance

may not be more than the investment amount in FCI (excluding Garment, Toy, Footwear and Accessories units where the capping shall be 200%).

7. For units manufacturing fuel-grade ethanol, at least 75% of the total produce should be supplied to the Oil Manufacturing Companies (OMCs). If this condition is not fulfilled in any claim year, that unit shall not be eligible for assistance in that particular year.

8. The unit shall remain in production during the assistance period and for the next 3 years thereafter. In case the unit is closed for more than 6 months during this period, the entire amount of assistance will be recovered along with the interest rate compounded annually @ 10%.

9. It will be mandatory to keep the investments in EFCI, as defined in Section 3.3, for which assistance is sanctioned during the period of assistance and for 3 years thereafter.

10. There shall be no alteration or reduction in the EFCI and change in the location of the unit on which the assistance is sanctioned during the period of assistance and for 3 years thereafter.

11. Change in ownership of investments in EFCI, during the period of assistance and thereafter for 3 years, shall not be done without obtaining prior permission from Managing Director, MPIDC. If such a change is made after obtaining permission, then all the responsibilities and rights of the previously established unit under Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2025 will be applicable to the new/changed unit.

12. To avail benefits under Industrial Promotion Policy -2025 it shall be mandatory for industrial units to provide 70% of the total employment to domicile of Madhya Pradesh.

13. Mega Industrial Units shall be eligible for sanction of special packages on a case-to-case basis by Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP).

14. Any industry declared as defaulter by the State and Central Government and their undertakings shall not be eligible for assistance under this policy.

15. If a unit gives false declaration for obtaining incentive under the policy or incentive are availed by an ineligible unit, the amount of incentive is liable to be recovered from the date of availing of such incentive with the interest rate compounded annually @ 10%.

10. APPEAL

An appeal against the decision of the State Level Empowered Committee can be made through MPIDC before the "Cabinet Committee on Investment Promotion" (CCIP) within three months from the date of receipt of the decision. The CCIP will be able to relax the delay in late appeals based on merits.

11. AMENDMENT/RELAXATION/REPEAL

Notwithstanding anything contained in the provisions under the scheme, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh at any time:

- Will be able to modify or cancel this scheme,
- Will be able to relax the implementation of the provisions of this scheme,
- Can issue instructions and guidance with a view to facilitate the implementation of the Scheme or to remove discrepancies and to interpret the provisions of the Scheme.

12. JURISDICTION

Any dispute, controversy, or claim arising out of or in connection with the MP Industrial Promotion Policy 2025, including any issues related to its interpretation, performance, or breach, shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts located in the state of Madhya Pradesh, India.

13. ANNEXURE – A LIST OF PRIORITY BLOCKS

"Priority Block" refers to blocks where no large industrial unit has been established. The list of priority blocks shall be revised by the department in every 2 years.

As per existing list of priority blocks.

14. ANNEXURE – B LIST OF INELIGIBLE INDUSTRIES

#	LIST OF INELIGIBLE INDUSTRIES
1.	All types of mining activity (where there is no value addition)
2.	Any industry declared ineligible by the Government of India and Government of Madhya Pradesh from time to time
3.	Beer and liquor (excluding winery, microbrewery)
4.	Central and State Government undertakings*
5.	Manufacturing of all kinds of pan masala and gutka
6.	Manufacturing of Charcoal
7.	Manufacturing of Tobacco and tobacco-based products
8.	Thermal Power Generation Plants
9.	Pressing of iron/steel scrap into blocks or any other shapes (other than vehicle scrapping as per GoI notification)
10.	Publishing and Printing processes of all types
11.	Sawmilling and planing of wood
12.	Slaughterhouse and industries based on meat
13.	Stone crusher and grinding of minerals, excluding M Sand and Ready-mix concrete

* CCIP after considering proposals on a case-to-case basis may provide a customized package.

15. ANNEXURE – C PROCESS OF CCIP APPLICATION

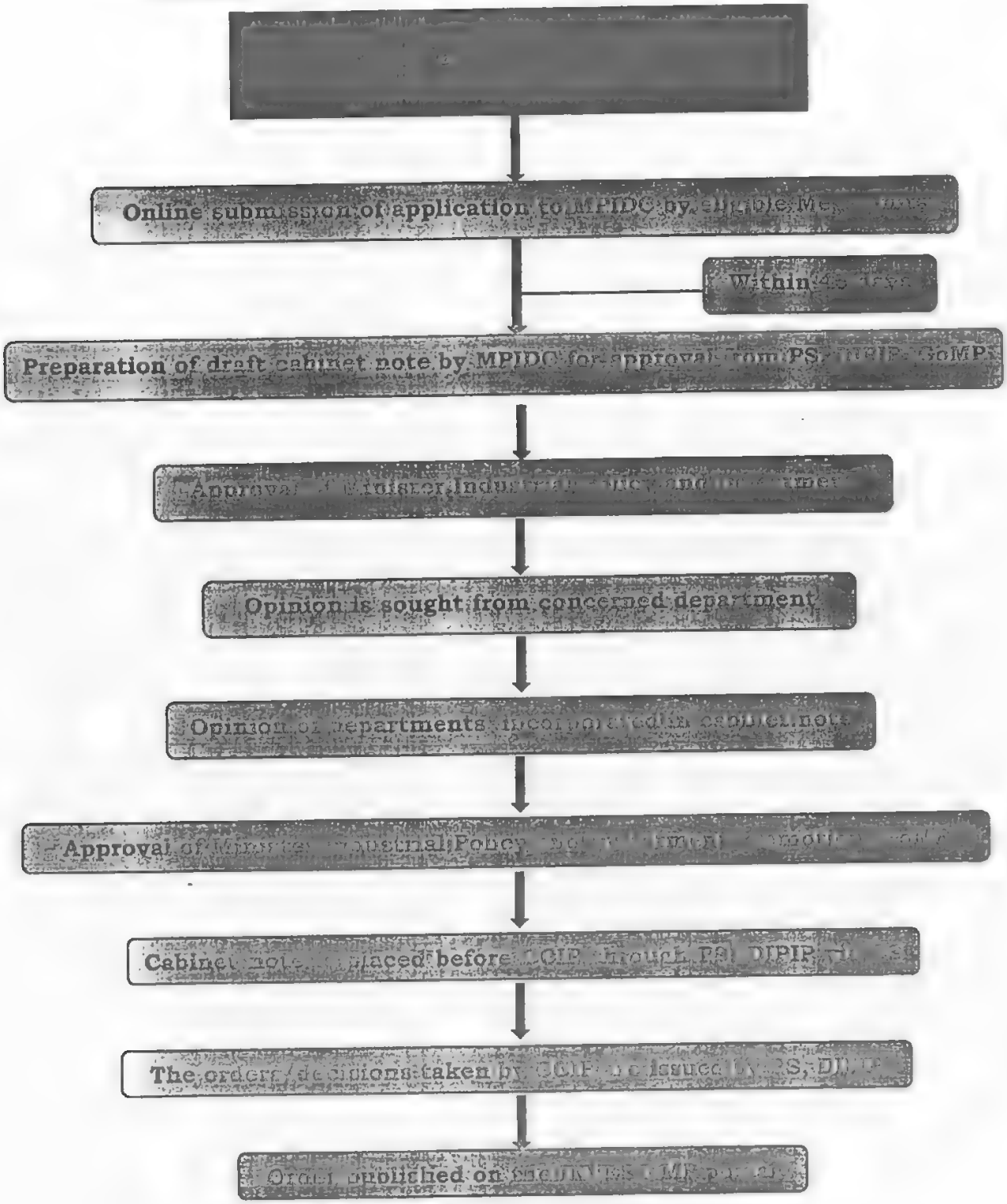

16. FORMS (INDICATIVE)

Form 1: CABINET COMMITTEE ON INVESTMENT PROMOTION (CCIP)

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(Govt. of Madhya Pradesh Undertaking)
21, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, 462011

Subject: Application for Customized Package of Incentives before Cabinet Committee on Investment Promotion

A	**General Information and Address**					
1	Name of the Industrial Unit					
2	Intention to Invest Number					
3	Applicant Name					
4	Constitution Type					
5	Correspondence Adress					
6	Block Name (Priority / Not Priority)					
B	**Contact Details**					
1	Directors / MD / Project Head					
	S.No.	**Name**	**Designation**	**Mobile / Phone**	**Fax**	**Email**
2	Name of the Authorized Person(s) *[as per the Board Resolution passed for the project]*					
	S.No.	**Name**	**Designation**	**Mobile / Phone**	**Fax**	**Email**
3	Local Office / Contact Person					
	Name	**Address**		**Mobile / Phone**	**Fax**	**Email**
C	**Project Information**					
1	Brief Description of the proposal					
2	Location of the Proposed Unit			Mention name of the **Village, Tehsil, District.**		
3	Type of Land (Developed/Developing/Undeveloped)					
4	Type of Ownership of Land (Government or Private)					

<table>
<tr><td>5</td><td>Land Details</td><td colspan="4">**Provide details as per <u>Annexure II</u> appended with this application.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">6</td><td>Power</td><td colspan="2">Sourced from a DISCOM</td><td colspan="2">Captive Generation (if any)</td></tr>
<tr><td>Connection Required (Whether 33/132/ 220 kV) - if any other please specify</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Load Required (in kVA)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Load Required (in kW)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Proposed/Probable Daily consumption
(in kWh)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Proposed/Probable Yearly consumption (in kWh)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Water (Monthly Consumption)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">8</td><td>Fuel (Monthly Consumption)</td><td colspan="3">Amount</td><td>Unit</td></tr>
<tr><td>Coal</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>Diesel</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>Furnace</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>Natural Gas</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>Wood</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>Any other</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">9</td><td rowspan="10">Employment Details
(In Numbers)</td><td>Type</td><td>Category</td><td>Existing</td><td>Proposed</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Direct</td><td>Managerial</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Supervisory</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Skilled</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Semi-Skilled</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Unskilled</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Others</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Indirect</td><td>Indirect</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Note: For Unit falling under Expansion/ Diversification Category, also provide details as per <u>Annexure III</u> appended with this application.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Date of Commencement of Operations</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>10</td><td>Probable / Actual Date of Commercial Production</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Proposed/Actual No. of working days in a year</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

12	Category		
	Sector		
	Type		
	Scale of Industry		

D	**Investment Details (In case of a New or Expansion/Diversification/Technical Upgradation Unit)**		
**Amount in ₹ Lakh(s)*			
**	**Note:** In case the project is to be executed in a phase-wise manner, then bifurcate the column below into number of phases and provide investment details thereof.		
1	Land *(For Rented premises, capitalized value of the same be indicated)*		
2	Building		
3	Plant & Machinery		
4	Infrastructure Development		
	Road		
	Water		
	Power		
	Any Other *(please specify)*		
5	Other Fixed Assets		
6	Green Industrialization Measures (ETP/STP/ZLD etc.)		
7	Captive Power Plant (Coal/Solar/Any other) *(if any, Please specify)*		
8	R&D, Quality Certification, Patents, IPR etc.		
9	Investment in any other head(s) *(Please specify)*		
10	Pre-operative Expenses		
11	Working Capital		
12	Total Eligible Investment {**Sum: D2 to D3**}		
13	Total Fixed Capital Investment {**Sum: D1 to D7**}		
14	Grand Total {**Sum: D1 to D11**}		
**	**Note:** For Unit falling under Expansion/Diversification/Technical Upgradation Category, also provide details as per **Annexure III** appended with this application.		

E	**Means of Finance (In ₹)**							
1	Share capital/Own funds							
2	Term Loan Details		Term Loan for Plant & Machinery	Term Loan for Building	Working Capital	Any other	Total Term Loan	

3	Unsecured Loans							
4	Other *(if any)*							

F	**Manufacturing Activity Details**					
1	**Main Products**					
	S.No	**Name of Product**	**Installed Capacity (Annual)**	**Unit**	**Value (In ₹)**	**Model of Storage & Handling**
**	**Note:** For Unit falling under Expansion/Diversification/Technical Upgradation Category, also provide details as per **Annexure IV** appended with this application.					
2	**By Products**					
	S.No	**Name of Product**	**Installed Capacity (Annual)**	**Unit**	**Value (In ₹)**	**Model of Storage & Handling**

G	**Raw Material Requirement (Product Wise)**						
	S.No	**Name of Product**	**Name of the Raw Materials**	**Yearly Requirement Quantity**	**Yearly Requirement (In ₹)**	**Indigenous or Imported**	**Model of Storage & Handling**

H	**Details of Machinery**						
	S.No	**Name of the Equipment / Machinery**	**Purpose**	**No.**	**Horse Power**	**Value (In ₹)**	**Dimension and Floor space requirement (SQM)**

I	**Other required information**		
1	Current Status of the Project		
2	Revenue accrual (benefits) to the Government on account of various taxes.		
3	A brief note on Company's Corporate Social Responsibility (CSR)		
4	IEM (Part I) – Issued by Secretariat / Industrial License for Industrial Approval Issued by Govt. of India		

5	IEM (Part II) – Issued by Secretariat / Industrial License for Industrial Approval Issued by Govt. of India (In case of eligible unit already in production)		

J	List of Incentives / Concession Requested			
S. No.	Incentives / Concession	Brief Pertaining to Incentives / Concession	Policy Type	Consequential Benefits to the State

K	Financial Implications to the State in case it extends fiscal incentives beyond Policy			
S. No.	Type of Incentive	Total Concession Amount Sought by the Company (in ₹ Cr.)	Amount as per the provision under Industrial Promotion Policy, 2014. (in ₹ Cr.)	Approximate financial Implication to the State Government in case it extends concessions and reliefs beyond policy. (in ₹ Cr.)
-	A	B	C	(B minus C)

Applicant/Representative

Date: .....
Place: .....

Signature: .....
Name: .....
Designation: .....

* * *

Annexure – I

Checklist of documents to be annexed with General Application Form)

1. Company's profile.
2. Detailed project report.
3. Company's balance sheet for the last 3 year.
4. Memorandum of Association and Article of Association.
5. IEM (Part – A) filed with Government of India.
6. Current status of the project indicating effective steps taken so far to implement the project.
7. Time schedule for implementation of the project (if already into production, specify the date).
8. A brief note on company's Corporate Social Responsibility.
9. Board resolution.
10. GST Registration Number (GSTN).
11. Intention to Invest number.
12. Proof of submission of application fee.
13. Details of land for the project as per Annexure II.
14. CA and CE certificate for the current investment and employment (for details as provided in annexure III).

Annexure – II

Land Details for CCIP Application

1. **Land taken from MPIDC (Yes/No):** _____ (if yes provide details below)

a. Developed/Developing Industrial Area of MPIDC

S.No.	Name of Industrial Area	Plot No.	Size of the Land Parcel (in sq.m.)	Total Cost Incurred	Current Status of Land Allotment	Name of Document Attached
Total						

b. Un-Developed land (in possession of MPIDC)

S.No.	Name of Village, Tehsil, District	Plot / Khasra / Survey No.	Size of the Land Parcel (in sq.m.)	Total Cost Incurred	Current Status of Land Allotment	Name of Document Attached
Total						

2. **Land taken from Government (other than MPIDC) (Yes/No):** _____ (if yes provide details below)

S.No.	Name of Village, Tehsil, District	Plot / Khasra / Survey No.	Size of the Land Parcel (in sq.m.)	Total Cost Incurred	Current Status of Land Allotment	Total Lease Period (in years)	Name of Document Attached
Total							

3. **Private Land Acquired (Yes/No):** _____ (if yes provide details below)

S.No.	Name of Village, Tehsil, District	Plot / Khasra / Survey No.	Size of the Land Parcel (in sq.m.)	Total Cost Incurred	Current Status of Land Allotment	Name of Document Attached
Total						

Name: _____

Designation: _____

Sign & Stamp

Annexure – III

For Projects under Expansion/ Diversification Category

A. Existing Employment (before commencement of proposed expansion/ diversification) -

Type	Category	Existing
Direct	Managerial	
	Supervisory	
	Skilled	
	Semi-Skilled	
	Unskilled	
	Others	
Indirect	Indirect	
-	Total	

B. Existing Investment (before commencement of proposed expansion/ diversification)

S.No.	Particular	Investment in existing unit as on the last day of preceding financial year (₹ in lakh)
1	Land *(For Rented premises, capitalized value of the same be indicated)*	
2	Building	
3	Plant & Machinery	
4	Infrastructure Development	
	Road	
	Water	
	Power	
	Any Other *(please specify)*	
5	Other Fixed Assets	
6	Green Industrialization Measures (ETP/STP/ZLD etc.)	
7	Captive Power Plant (Coal/Solar/Any other)	
	(if any, Please specify)	
8	R&D, Quality Certification, Patents, IPR etc.	
9	Investment in any other head(s) *(Please specify)*	
10	Grand Total	

Annexure – IV

Items of Manufacture & Annual Capacity
(In case of Expansion/Diversification/Technology Upgradation)

S. No.	Name of the Item	Existing Annual Capacity or Average Production of last 3 years (Whichever is more)

Signature & Stamp

Place: _____

Name: _____

Date: _____

Post: _____

Form 2: Common Application Form (General Information) For Eligibility Determination In SLEC

a. General Information:

1.	**Name of the company**		
2.	**Name of the unit/Project**		
3.	**GST Number and date of issue** *(GST certificate to be enclosed)*		
4.	**Proposal ID number under Intention to Invest and Date** *(Copy of Intention to invest to be enclosed)*		
5.	**Date of Commercial Production**		
6.	**Unit address** *(Land registration/ lease deed documents to be enclosed)*	1. District	
		2. Block	
		3. If Priority Block	Yes/No
		4. Address	(Plot number, Industrial Area, Location of the unit, District)
7.	**Type of land**	1. MPIDC Ind. Area	
		2. Pvt. Ind. Estate	
		3. Other area	
8.	**Name of the Authorized signatory** *(Board resolution to be enclosed)*		
9.	**Mobile No.**		
10.	**E-mail ID**		
11.	**Office Landline No.**		

12.	**Constitution of the unit (Select one)** *(ROC documents and deeds to be enclosed)*				
	Proprietorship	Partnership	LLP	Pvt Ltd.	Public Ltd.
13.	Name of the Proprietor/ partner/ Managing Director				
14.	Email Address				
15.	Mobile Number				
16.	**Type of Unit (Select one)**				
17.	New unit	Expansion	Diversification		Technological Upgradation
18.	IEM Part A/License No. and Date of Issue (Government of India) *(IEM Part A to be enclosed)*				
19.	IEM Part B/License No. and Date of Issue (Government of India) *(IEM Part B to be enclosed)*				
20.	Total Investment in the project *(CA certificate in prescribed format as per Annexure 1/2 to be enclosed)*				
21.	Turnover of the company as on date of commercial production (as per MSMED Act 2006) *(CA certificate in prescribed format as per Annexure 1/2 to be enclosed)*				
22.	If FDI, % of FDI in equity *(CA certificate in prescribed format as per Annexure 1/2 to be enclosed)*				
23.	Contribution of the company towards Corporate Social Responsibility (CSR) and CER in MP in the past 3 years.				
24.	Sector of the manufactured product		(Select any one) a. Agri, Dairy and Food Processing b. Textile c. Garment & Apparel, Footwear, Toys and Accessories d. Aerospace and Defence e. Pharmaceuticals f. Biotechnology g. Medical Devices h. EV Manufacturing i. Renewable Energy Equipment		

		Manufacturing j. High Value Add Manufacturing k. General Manufacturing (Any other manufacturing, please specify)
25.	**Means of finance in the current Project (in ₹Crores)** (*Self-attested copy of term loan sanction order from Bank/Financial institutions recognized by RBI in case of financed units to be enclosed)*	
i.	Promoter's equity	
ii.	Term loan	
iii.	Foreign Direct Investment (FDI)	
iv.	Total	
26.	Whether the unit is an exporting unit?	Yes/No
27.	**Document to be enclosed:** i. Affidavit under the MP Investment Promotion Scheme – Annexure 5	

b. Details in case of new units:

1	**Details of product (s) manufactured and capacity** (*IEM to be enclosed)*		
	Product (s) manufactured	Annual Installed Capacity	
	i.		
	ii.		
	iii.		
2	**Details of investment in fixed assets in ₹ Crores in case of NEW units** *(CA certificate in prescribed format as per Annexure 1 to be enclosed)*		
	Land		
	Building		
	Plant & machinery (as per MSMED Act 2006)		
	Other assets (if any), please specify		
	Total		
3	**Electricity Connection Details for new units** *(Agreement b/w unit and discom to be enclosed along with electricity bill)*		
i.	Connection Date		
ii.	Connection type (33/132/220 KV)		
iii.	Power Load		
iv.	Meter details		
4	**Employment Details** *(Affidavit in prescribed format Annexure - 3 to be enclosed)*		
	No. of employees Domicile of MP	No. of employee's non-domicile of MP	Total no. of employees

5	**Details of differently abled employees** *(Affidavit in prescribed format Annexure - 3 to be enclosed)*	
	No. of differently abled employees	Percentage of differently abled employees with respect to total no. of employees

c. <u>Details for Expansion/ Diversification/ Technological Upgradation</u>

1	**1st Commercial Production date**				
2	**Details of product and capacity** ***(IEM and CE certificate for verifying production of last 3 years- Annexure-4 to be enclosed)***				
	Product manufactured	**Capacity Before expansion/ diversification/ Technological Upgradation**		**Capacity After expansion/ diversification/ Technological Upgradation**	**Total expansion/ diversification/ Technological Upgradation**
		As per IEM	**As per average of last 3 years production**	**As per IEM**	
	i.				
	ii.				
	iii.				
3	**Value of fixed assets in ₹ Crores** *(CA certificate in prescribed format as per Annexure 2 to be enclosed)*				
	Details	**Existing Gross Block investment upto date.....before expansion/ diversification/ Technological Upgradation**	**Investment under expansion/ diversification during last 2 years from..... upto COD.....**	**Additional Investment after COD From..... to ..... i.e., One year (In ₹)**	**Total expansion/ diversification/ Technological Upgradation**
i.	Land				
ii.	Building				
iii.	Plant & machinery				
iv.	Other assets				
v.	Total				

4	**Electrical Connection Details** *(Agreement b/w unit and discom to be enclosed along with electricity bill)*			
	Details	**Before expansion/ diversification/ Technological Upgradation**	**After expansion/ diversification/ Technological Upgradation**	**Total expansion/ diversification/ Technological Upgradation**
i.	Connection Date			-
ii.	Connection type (33/132/220 KV)			
iii.	Power Load			
iv.	Meter details			

5	**Employment Details** *(Affidavit in prescribed format Annexure – 3 to be enclosed)*			
	Details	**Before expansion/ diversification/ Technological Upgradation**	**After expansion/ diversification/ Technological Upgradation**	**Total**
	No. of employees Domicile of MP			
	No. of employee's non-domicile of MP			
	Total no. of employees			

6	**Details of differently abled employees** *(Affidavit in prescribed format Annexure - 3 to be enclosed)*	
	No. of differently abled employees	Percentage of differently abled employees with respect to total no. of employees

d. <u>For the Eligibility Determination of IPA/ Technological Upgradation</u>

Sr. no.	**Details of Investment (EFCI) as per Section 3.3 of the scheme**			
1.	**Investment Area**	**Existing Investment (in case of expansion/diversification/technological upgradation)**	**Investment in the current project upto COD**	**Total Amount (₹)**
i.	Plant and Machinery			
ii.	Factory Sheds and Buildings			
iii.	In-house R&D			

iv.	Captive Power (Renewable Energy)			
v.	Energy-Saving Devices			
vi.	a. Cost of Imported Second-hand Machinery			
	b. Cost of refurbishment (if any)			
vii.	Total investment			
2	First claim year (current year/ next year) (As defined under section 6.1(iv))			
3	First raw material purchase date			
4	First sales date			
5	Necessary licenses obtained for manufacturing of product (s) by competent authority (eg: Food Processing license, FSSAI/ API manufacturing license, etc)			

Documents to be enclosed:

i. CA Certificate for IPA in case of new unit or expansion and diversification, as the case may be in prescribed format, as in Annexure- 6/8

ii. CE Certificate for IPA in case of new unit or expansion and diversification, as the case may be in prescribed format, as in Annexure- 7/9

iii. CA and CE certificate for technological upgradation in the prescribed format, as per Annexure 10 and 11

iv. Copy of first purchase and sales bill

v. Attach all the necessary licenses obtained for manufacturing activity by competent authority (food license/ FSSAI/ Mandi license/ API manufacturing license, etc.)

e. Interest Subsidy

S no.	Details	
i.	Total investment in plant & machinery for which loan has been taken	
ii.	Investment in Plant and Machinery used in the main manufacturing process as defined in Section 6.14 (4) of the scheme	
iii.	Total sanctioned term loan on plant and machinery bank wise	
iv.	Total sanctioned term loan on plant and machinery used in the main manufacturing process as defined in Section 6.14 (4) of the scheme, bank wise	
v.	Amount of loan disbursed with dates by the bank	
vi.	Rate of interest charged by Bank	

Documents to be enclosed:

i. Attested copy of the detailed sanction letter and loan disbursement letter of the loan amount sanctioned by each lending bank/financial institution.

ii. Copies of the certificate attested by each lending bank in the prescribed format regarding loan disbursed as per Annexure 12.

iii. Repayment Schedule approved by each lending bank/financial institution on the loan approval date as per Annexure 13.

f. Export Freight Subsidy for Transportation of Goods

Sr. No.	Details	
1.	Product/Goods being transported for exports	
2.	Distance between the location of the unit and the port/ Air Cargo Facility/ International Border (distance in KM).	
3.	The Mode of Transportation of goods (Air, Rail, Road)	

g. Mandi Fee Reimbursement

Sr. No.	Details	
1.	Valid License No. and Date, issued by Mandi Board for Food Processing and Commercial activity	
	Documents to be enclosed: i. Copy of License issued by Mandi Board for Food Processing and Commercial activity.	

h. Training and Skill Development

Sr. No	Details	
1.	Total number of employees in the project	

2.	Number of MP Domicile Employees that have been provided Training till CoD	

i. Employment Generation

Sr. No	Details	
1.	Total number of employees in the project	
2.	Number of MP domicile employees	
3.	Average percentage of MP Domicile Employees out of total employment	
4.	Number of newly employed workers till CoD	

j. Stamp Duty and Registration Charges/ Concession in Development charges

Sr. No.	Details	
1.	Land area (in acres)	
2.	Cost of Land:	
a.	Land Premium (in ₹))	
b.	Development charges	
c.	Other Charges	
d.	Total Cost of Land	
3.	Amount of stamp duty paid (in ₹)	
4.	Amount of registration charges paid (in ₹)	
	Documents to be enclosed: i. Self-attested copy of land allotment letter ii. Self-attested copy of registered lease deed	

This is to Certify that:

I / We hereby certify that the particulars given above and in the appended enclosures are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that no material facts have been concealed or suppressed.

Place:
Date:

Signature of authorized signatory:
Name:
Designation:

Form 3: APPLICATION FORM FOR CLAIMING INCENTIVES

1.	Name and Location of the unit	
2.	Type of Unit (New/Expansion/Diversification/ Technological Upgradation)	
3.	Proposal ID and date under Intention to Invest	
4.	Date of Commencement of Commercial Production of the unit	
5.	SLEC meeting, number and date for Eligibility determination	
6.	Name of assistance and corresponding eligibility period as determined by SLEC *(Copy of SLEC intimation letter to be attached)*	i. ii. iii. iv. Any others (please specify)
7.	Any subsidy, rebate, grant, concession availed from Government of India, for the project, if yes, please specify its details and amount of the subsidy	
8.	Any subsidy, rebate, grant, concession availed from other department of Government of Madhya Pradesh	
9.	Contribution of the company towards Corporate Social Responsibility (CSR)/CER in MP in the past 3 years.	
	Documents to be enclosed: i. Claim affidavit for availing incentives under IPP 2025 in the prescribed format, as per Annexure 14 ii. Copy of Cancelled cheque for receiving assistance to be enclosed	

a. Incentives under IPA/Technological Upgradation

1.	Claim year		
2.	**Details of annual production, sales, export, FDI and employment**		
	Details	**Quantity**	**Value (in ₹)**
i.	Total Annual Production of claim year (in case of expansion, mention the production of installed and expanded capacity separately)		
ii.	Total Annual Sales of claim year		
iii.	Annual Export of claim year (in case of expansion/diversification only for the expanded or diversified unit)		
iv.	Production quantity and value in previous years (if the application is for second year onwards)		
v.	Sales quantity and value done in previous years (if the application is for second year onwards)		

vi.	Total employment (new/expansion/diversification) in claim year (.....year) *(Affidavit for employment to be enlcosed, as per Annexure-3)*		
4.	Amount of assistance received in preceding years of the claim year (year-wise) i. .....(year 1) ii. .....(year 2) iii. .....(year 3) iv. .....(year 4) v. .....(year 5) vi. .....(year 6)		
5.	FDI Equity in the claim year		
Documents to be enclosed: i. CA Certificate for Total Production, Sales, Exports and FDI equity in the claim year, as per Annexure 15. ii. Board resolution regarding the authorized signatory iii. GST return 1 and 3B of the claim year iv. For units producing fuel-grade ethanol, the certificate of supply to Oil Manufacturing Companies (OMCs)			

b. <u>Green Industrialization Assistance</u>

1	**Description of established amenities,** ETP/ STP/ ZLD/ Pollution Control Devices/ others (please specify)	**Expenditure (In ₹ Crores)**
	Total Expenditure	
	Documents to be enclosed: i. Certificate/assessment by Chartered Engineer and Chartered Accountant certifying expenditure incurred in setting up of amenities (including section wise expenditure verification and investment start and completion dates). ii. CTE and CTO issued by the MPPCB iii. Certificate from Pollution Control Board in respect of the establishment and operation of respective amenities. iv. For the disbursement of second instalment, unit must present affidavit and CE certificate for verification of operational status of the facility.	

c. <u>Infrastructure Development Assistance</u>

#	**Description**	**Expenditure (In ₹ Crores)**
1.	Road	
2.	Water	
3.	Power	

4.	Gas Pipeline	
5.	Drainage	
6.	Sewage	
7.	**Documents to be enclosed:** i. Certificate/assessment by Chartered Engineer and Chartered Accountant certifying expenditure incurred in setting up of amenities (including section wise expenditure verification and investment start and completion dates). The CA and CE certificate should include details of the infrastructure developed: • Period of investment • The distance and type of the approach road to the factory gate from the main road and the name of the main road. • The distance of the water source to the factory gate and the name of the water source. • Details of the power station supplying electricity, approval from the Madhya Pradesh Electricity Distribution Company, and verification of electrification completion. • Distance from the main drainage/sewage infrastructure and necessary approvals for the establishment of sewage and drainage systems. • Details of the gas pipeline connection, including the supplier's name, distance from the main line, and necessary approvals. ii. Copy of work completion report by Contractor/MPEB/any other competent authority iii. Any other details of established amenities (if required)	

d. Assistance for IPR

1.	Details of IPR Applied for	Patent/ Copywrite/ Trademark/ GI
2.	Date of obtaining IPR	
3.	Type of IPR (Please ✓ the appropriate box)	Domestic ☐ International ☐
4.	Fee Paid for acquisition of IPR	
5.	Amount claimed (₹)	

Documents to be enclosed:

i. Copy of IPR Certificate received

ii. Invoice pertaining to application fee & processing fee of IPR application with proof of payment (Net Banking/NEFT/RTGS/DD/Cheque)

iii. Any other document deemed relevant

e. Assistance for Organic Certification

1.	Details of Organic Certification Applied for	
2.	Date of obtaining Organic Certification	

3.	Fee paid for acquisition of Organic Certification	
4.	Amount claimed (₹)	

Documents to be enclosed:

i. Copy of Organic Certification received

ii. Invoice pertaining to application & processing of Organic Certification application with proof of payment (Net Banking/NEFT/RTGS/DD/Cheque)

iii. Any other document deemed relevant

f. Incentives To Provide Employment to Differently Abled Persons

S No.	Total Number of Employees	No. of differently abled employees	Percentage of differently abled employees with respect to total no. of employees
1.			
2.	**Training and Skill Development**		
Number of Employees Trained		Expenditure incurred for Training	Total Amount Claimed
3.	**Employees' Provident Fund (EPF)**		
Total No. of employees for EPF		Total EPF Contribution	Total Amount Claimed
4.	**Employee State Insurance (ESI)**		
Total No. of employees for ESI		Total ESI Contribution	Total Amount Claimed
5.	**Insurance Premium**		
Total Number of Differently Abled Employees not covered under Ayushman Bharat Scheme2018		Total Amount of Insurance Premium Paid	Total Amount Claimed

Documents to be enclosed:

i. List of trained Employees along with details of the ITI.

ii. Details of the EPF/ESI contribution.

iii. Details of the Insurance Premium paid for the insurance of differently abled employees who are not eligible for free insurance under the Ayushman Bharat Scheme 2018.

g. Cost of International Technology Transfer

S no.	Details	
1.	Name of the vendor unit	
2.	GST details of the vendor unit	
3.	Brief Description of Technology Transfer	
4.	Duration of Technology Transfer	
5.	Expenditure done	
6.	Amount claimed (₹)	

Documents to be enclosed:

i. GST Certificate of the vendor unit

ii. Copy of Transfer of Technology Agreement along with all the supporting documents.

iii. Invoice pertaining to expenditure with proof of payment (Net banking/NEFT/RTGS/DD/Cheque)

iv. Any other document deemed relevant

h. Export Freight Subsidy

S No.	Details	
1.	Period of Claim	
2.	Name of the products being exported along with their HSN codes	
3.	Quantity and value of goods being transported	
4.	Distance between the location of the unit and the port of unloading, Air Cargo Facility, or International Border (distance in KM).	
5.	The Mode of Transportation of goods (Air, Water, Rail, Road)	
6.	Total Transport Freight Cost incurred	
7.	Total Subsidy Amount Claimed	
Documents to be enclosed: i. CA certificate verifying the details of the transport freight cost (based on the e-way bill/ transportation invoices and balance sheet), as in Annexure 20.		

i. Mandi Fee Reimbursement

1.	Claim period	
2.	Amount of the mandi fee paid in Madhya Pradesh during the claim year	
3.	Subsidy amount as per the calculation of MP State Agricultural Marketing Board, Department of Farmer Welfare and Agriculture development	
	Documents to be enclosed: i. Subsidy calculation sheet by MP State Agricultural Marketing Board, Department of Farmer Welfare and Agriculture development	

j. Power Tariff rebate

1.	Claim period	
2.	Units consumed	
3.	Subsidy amount as per the calculation by DISCOM	
	Documents to be enclosed: i. Subsidy calculation sheet by DISCOM	

k. Quality Certification

1.	Details of Quality Certification obtained	
2.	Date of obtaining quality certification	
3.	Type of quality certification (Please	Domestic ☐

	✓ the appropriate box)	International ☐
4.	Fee Paid for acquisition of quality certification	
5.	Amount claimed (in ₹)	
Documents to be enclosed: i. Copy of Quality Certificate received ii. Invoice pertaining to application fee & processing fee of quality certification application with proof of payment (Net Banking/NEFT/RTGS/DD/Cheque) iii. Any other document deemed relevant		

l. Interest Subsidy

1.	Quarterly claim period	
2.	Subsidy amount as per the calculation of bank	
3.	Sanctioned subsidy during previous years till date	
	Documents to be enclosed: i. Quarterly Due diligence certificate at the time of claim, as in Annexure 16 ii. Quarterly statement for claiming interest subsidy, as in Annexure 17	

m. Details for Training and skill development subsidy

S No	Details	Amount
1.	Claim Period	
2.	Amount spent on the training of MP Domicile employees in the claim period	
	Documents to be enclosed: i. Affidavit in prescribed format (Annexure: 18) ii. Details of the employees (Annexure: 18; Format A)	

n. Details for Employment Generation subsidy

Sr. No	Details	
1.	Claim Period	
2.	Total number of employees during claim year	
3.	Number of employees domicile of Madhya Pradesh	
4.	Claim amount (in ₹)	
	Documents to be enclosed: i. Affidavit in prescribed format, as in Annexure: 19 ii. Details of the employees, as in Annexure: 19; Format B	

o. Details of Project Cost of Apparel Training Institute

S no.	Head	Details
1.	**Name of Apparel Training facility**	
2.	**Location**	
3.	**Training Capacity (No. of persons)**	
4.	**No. of Trainers**	
5.	**Trainer Trainee Ratio**	
6.	**Type of Training to be provided**	
7.	**Project Cost (Rs Cr)** Break-up of Costs incurred in following heads - a. Machinery for the training b. Training Building c. Allied infrastructure related solely to training activities. Please Specify	
	Documents to be enclosed: i. Certificate/assessment by Chartered Engineer and Chartered Accountant certifying expenditure incurred in setting up of amenities (including item wise expenditure verification and investment start and completion dates)	

p. Details of Project Cost of Testing Facility

S no.	Head	Details
1.	**Location**	
2.	**Brief objective & purpose of Testing facility**	
3.	**Project Cost (Rs Cr)** Break-up of costs incurred in following heads - a. Plant & Machinery b. Equipment c. Testing lab building d. Testing related Software e. Others, Please Specify	
4.	**Documents to be enclosed:** i. DPR of the project. ii. Certificate/assessment by Chartered Engineer and Chartered Accountant certifying expenditure incurred in setting up of testing facilities (including section wise expenditure verification and investment start and completion dates). iii. Copy of documents for registration under Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA) and controlled by The Institutional Animal Ethics Committee (IAEC) /Certifications or permissions from the competent authority recognized by the GoI or GoMP	

This is to Certify that:

I / We hereby certify that the particulars given above and in the appended enclosures are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that no material facts have been concealed or suppressed.

Place:
Date:

Signature of authorized signatory:
Name:
Designation:

Form 4: Details of Standalone R&D for Eligibility Determination

S no.	Head	Details
1.	Name of Company	
2.	Name of Project	
3.	GST Registration Number (copy to be enclosed)	
4.	Proposal ID No. under Intention to Invest & Date (copy to be enclose)	
5.	Date of Commencement of commercial operation	
6.	Location	
7.	Registered address of Unit	
8.	Type of Land (Registry to be enclosed)	Govt Land Private Land
9.	Authorized Signatory (Board Resolution to be enclosed)	Name Mobile No. Email ID Office Landline
10.	Name of the Managing Director with email and mobile	
11.	IEM part A no. and date (copy to be enclosed)	
12.	IEM part B no and date (copy to be enclosed)	
13.	Electricity connection type and power load (copy to enclosed of Agreement and Electricity bill)	
14.	Total no of Employees	
15.	Brief objective & purpose of R&D facility	
16.	Project Cost (Rs Cr) Break-up of Costs incurred in following heads - a) Plant & Machinery b) Main laboratory premises c) R&D related Software d) Office building e) Administrative building f) Restrooms/Washrooms g) Allied infrastructure related solely to R&D activities. h) Others, Please Specify	
17.	Means of Finance	
18.	**Documents to be enclosed:** 1) DPR of the project. 2) Certificate/assessment by Chartered Engineer/Chartered Accountant certifying expenditure incurred in setting up of amenities (including item wise expenditure verification and investment start and completion dates). 3) Copy of documents for registration/recognition of the In House/Standalone facility with the Department of Scientific and Industrial Research, Government of India (DSIR)/ Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) 4) Affidavit as per Industrial Investment Promotion scheme 2025 (annexure 5) 5) For annual disbursements, the unit must provide an affidavit certifying that the R&D unit is functional, supported by annual reports submitted to CSIR/DSIR or any other government agency, along with electricity bills.	

This is to Certify that:

I / We hereby certify that the particulars given above and in the appended enclosures are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that no material facts have been concealed or suppressed.

Place:

Date:

Signature of Authorized Signatory:

Name:

Designation:

Form 5: CLAIM FORM FOR STANDALONE R&D UNITS

Sr. no.	Head	Details
1.	Name of Project	
2.	Proposal ID No. under Intention to Invest & Date (copy to be enclose)	
3.	Date of Commencement of commercial operation	
4.	Location	
5.	SLEC Approval Date (Intimation letter to be enclosed)	
6.	Installment Year --------	
7.	Authorized Signatory (Board Resolution to be enclosed)	Name
		Mobile No.
		Email ID
		Office Landline
8.	Total no of Employees	
9.	Brief details of the project undertaken *(annual reports submitted to CSIR/DSIR or any other government agency to be enclosed)*	
10.	**Documents to be enclosed:** i. Affidavit as per Industrial Investment Promotion scheme 2025, as in Annexure 5 ii. For annual disbursements, the unit must provide an affidavit certifying that the R&D unit is functional, supported by annual reports submitted to CSIR/DSIR or any other government agency, along with electricity bills.	

This is to Certify that:

I / We hereby certify that the particulars given above and in the appended enclosures are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that no material facts have been concealed or suppressed.

Place:

Date:

Signature of Authorized Signatory:

Name:

Designation:

Form 6: Application Format by Developer for Assistance for Proposed Private Industrial Park/Industrial Plug and Play Facility

To,
The Managing Director,
MP Industrial Development Corporation
HO Bhopal
Madhya Pradesh.

Subject: Regarding providing assistance for setting up of Private Industrial Park/Industrial Plug and Play Facility under "Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2025".

I/We have proposed to establish a Private Industrial Park/Industrial Plug and Play Facility in District ..... Madhya Pradesh. The detailed information for providing assistance under the "Madhya Pradesh Investment Promotion Scheme 2025" is as follows:

#	Details and Information	
1.	Name of the Agency/Institution/Developer	
2.	Proposal ID under Intention to invest and date	
3.	Contact Address: Telephone: E-mail:	
4.	Registered Office Address: Telephone: E-mail:	
5.	Full Address of the Site of the Private Industrial Park/Industrial Plug and Play Facility	
6.	Proposed area of the Private Industrial Park (in acres) / Industrial Plug and Play Facility Land Area in acres/ Carpet Area (in sq. ft.)	
7.	Proposed maximum occupancy of Private Industrial Park/Plug and Play facility	
8.	In case of Private Industrial Park Name of Industries proposed to be Established (Minimum Five)	
9.	Proposed date of Completion of Establishment/Development (on milestone basis)	
10.	Proposed expenditure in Infrastructure Development	
11.	• Proposed expenditure in establishing waste management systems (such as Effluent Treatment Plant, Sewage Treatment Plant, pollution control devices, etc.) • Proposed Expenditure in establishing Zero Liquid Discharge facility	
12.	Details of Proposed Common Facility Centers to be Established (only for Plug and Play facility)	
13.	Proposed Expenditure in establishing Common Facility Centers as mentioned in above point 12	
14.	Necessary Permissions Obtained as on date	

Documents to be enclosed:
1. Copy of GST registration certificate
2. Copy of Proposal ID under intention to invest
3. Copy of Board Resolution for authorized signatory
4. Copy of Detailed Project Report
5. Land Related Documents
6. Layout map and plan

This is to Certify that:

I / We hereby certify that the particulars given above and in the appended enclosures are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that no material facts have been concealed or suppressed.

Place:
Date:

Signature of Authorized Signatory:
Name:
Designation:

Form 7: Application Format by Developer for Assistance for Established Private Industrial Park/Industrial Plug and Play Facility

To,
The Managing Director,
MP Industrial Development Corporation
HO Bhopal
Madhya Pradesh.

Subject: Regarding providing assistance for setting up of Private Industrial Park/Industrial Plug and Play Facility under "Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2025".

I/We have established a Private Industrial Park/Industrial Plug and Play Facility in District ....., Madhya Pradesh. The detailed information for providing assistance under the "Madhya Pradesh Investment Promotion Scheme 2025" is as follows:

1.	Name of the Agency/Institution/Developer	
2.	SLEC approval Date	
3.	GST Number and Date	
4.	Proposal ID under Intention to invest and date	
5.	Commencement of commercial operation date	
6.	Authorized signatory: Name Telephone: E-mail:	
7.	Registered Office Address: Telephone: E-mail:	
8.	Full Address of the Site of the Private Industrial Park/Industrial Plug and Play Facility	
9.	Type of land	Govt /Private
10.	Area of the Private Industrial Park (in acres) / Industrial Plug and Play Facility Land Area in acres/ Carpet Area (in sq. ft.)	
11.	Maximum total occupancy	
12.	Current occupancy as on date of application	
13.	Name of current occupants For Industrial Park: land allotment papers and status of the projects to be enclosed For Plug and play Park: rent agreements and status of the projects to be enclosed	
14.	Actual Expenditure in Stamp Duty and Registration charges for purchase of land (only applicable for Private Industrial Parks)	
15.	Expenditure in Infrastructure Development (ii) Internal and approach Road development (iii) Internal Power Infrastructure (iv) Internal Water Infrastructure (v) Internal Drainage Infrastructure (vi) Internal Gas Pipeline (vii) Compound Walls (viii) Any other please specify ***Building (only for Plug and Play)***	
16.	• Expenditure in establishing waste management systems (such as Effluent Treatment Plant, Sewage Treatment Plant, pollution control devices, etc.). • Expenditure in establishing Zero Liquid	
	Discharge facility	

17.	Details of Common Facility Centers Established (only for Plug and Play facility)	
18.	Expenditure in establishing Common Facility Centers as mentioned in the above Point 17	
19.	Necessary Permissions Obtained (copy to be enclosed)	

Documents to be enclosed:

1. Intimation letter of SLEC
2. Copy of GST registration certificate
3. Copy of Proposal ID under intention to invest
4. CE certificate for completion of infrastructure
5. Copy of Board Resolution for authorized signatory
6. Land Related Documents
7. Certificate/assessment by Chartered Engineer and Chartered Accountant certifying expenditure incurred in setting up of amenities (including section wise expenditure verification and investment start and completion dates).
8. Consent to Establish and Consent to Operate issued by the MPPCB
9. Certificate from Pollution Control Board in respect of the establishment and operation of respective amenities.
10. Layout map and plan approved by the competent authority
11. Work Completion certificate issued by Contractor/any other competent authority, for the infrastructure developed as approved by SLEC.
12. Milestone Certificate as per Form 8
13. Copy of cancelled cheque

This is to Certify that:

I / We hereby certify that the particulars given above and in the appended enclosures are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that no material facts have been concealed or suppressed.

Place:

Date:

Signature of Authorized Signatory:

Name:

Designation:

Form 8: MILESTONE COMPLETION CERTIFICATE FOR PRIVATE INDUSTRIAL PARK/ PLUG AND PLAY FACILITY

#	Description	Details
	For Private industrial park:	
1.	Date of land allocation	
2.	Capital expenditure made till date	
3.	Status of construction (as per CE certificate)	
4.	Status of occupancy	
	For Plug and Play Park	
1.	Date of building permission	
2.	Capital expenditure made till date	
3.	Status of construction (as per CE certificate)	
4.	Status of occupancy	

Documents to be enclosed:

i. Chartered Accountant Certificate, highlighting the capital investment. To be re-submitted while applying for respective instalments.

ii. Chartered Engineer Certificate, highlighting the completion of the infrastructure of the private industrial park. To be re-submitted while applying for respective instalments.

iii. Building Permission proofs issued by concerned government departments.

iv. Proof of occupancy,

   a. Sale/lease deed/rental agreement to the units occupying the spaces.

   b. List of IT/ITeS/ESDM units occupying the space,

v. Any other document deemed relevant.

This is to Certify that:

I / We hereby certify that the particulars given above and in the appended enclosures are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that no material facts have been concealed or suppressed.

Place:

Date:

Signature of Authorized Signatory:

Name:

Designation:

FORM 9: RENTAL SUBSIDY FOR UNITS ESTABLISHED IN PLUG AND PLAY PARKS

S No.	Description	
1.	Name of unit and address	
2.	Manufacturing unit or Service sector unit	Manufacturing/ Service sector
3.	Brief description of unit	
4.	Is the rent already subsidized by the developer	Yes/No
5.	Facility developed by MPIDC or Private developer	
	Rental space details	
6.	Address of the office (as mentioned in rent agreement)	
7.	Date of rent agreement	
8.	Rental space area (in sq. ft.)	
9.	Monthly Rental rate as mentioned in rent agreement (in ₹/sq. ft.) *(Registered Rental Agreement mentioning the area of the facility and components of the rented space to be enclosed)*	
	For Claim	
1.	Date of the SLEC (copy of intimation letter of SLEC decision)	
2.	Eligibility period as determined by SLEC	
3.	Period for which reimbursement is being claimed (dd/mm/yy to dd/mm/yy)	
4.	Total Rent Paid	
5.	Assistance received till previous year (in case of first year onwards)	
	Documents to be enclosed: i. CA Certificate for rent paid, as in Annexure 22 ii. Claim Affidavit iii. Any other document deemed relevant.	

This is to Certify that:

I / We hereby certify that the particulars given above and in the appended enclosures are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that no material facts have been concealed or suppressed.

Place:
Date:

Signature of Authorized Signatory:
Name:
Designation:

17. ANNEXURES

Annexure 1: CA CERTIFICATE FOR VERIFICATION OF FCI, TURNOVER AND FDI FOR NEW UNIT

I/We.....hereby certify that M/s..... have invested in the following Fixed Capital Assets upto commercial operation date (COD) ..... at their unit situated at ..... for manufacturing of product(s).....

Details of investment

S. No.	Details	Amount (in ₹ Lakhs)
1	Land	
2	Building	
3	Plant and Machinery (as per MSMED Act 2006)	
4	Furniture and Fixtures	
5	ETP, STP, Pollution control devices	
6	Others (Please Specify)	

I/we also certify that the turnover of the company in last two years, in FY..... and .....in FY.....

In case of FDI, percentage of FDI in equity is..... Verified on the basis of the FLA return.

We have checked the books of accounts, invoices etc. of the unit and certify that therefore said information is found to be true.

Name.....

Signature & Seal.....

Membership No .....

Place:
Date:

Note: Above details should be certified by the Chartered Accountant on his letter head only.

Annexure 2: CA CERTIFICATE FOR FCI, TURNOVER AND FDI IN CASE OF EXPANSION AND/OR DIVERSIFICATION AND/OR TECHNOLOGICAL UPGRADATION

I/We.....hereby certify that M/s..... have invested in the following Fixed Capital Assets upto commercial operation date (COD) ..... at their unit situated at ..... for manufacturing of product (s) .....

Details of investment

Sr. No	Details	Existing Gross block Investment upto date..... (In ₹)	Investment under expansion/ diversification/ technological upgradation during last 2 years from..... upto COD.....	Total investment (in ₹ Lakhs)
1	Land			
2	Building			
3	Plant and Machinery (as per MSMED Act 2006)			
4	Furniture and Fixtures			
5	ETP, STP, Pollution control devices			
6	Others (Please Specify)			

I/we also certify that the turnover of the company in last two years, in FY..... ..... and .....in FY.....

In case of FDI, percentage of FDI in equity is..... Verified on the basis of the FLA return.

We have checked the books of accounts, invoices etc. of the unit and certify that therefore said information is found to be true.

Name.....

Signature & Seal.....

Membership No .....

Place:

Date:

Note: Above details should be certified by the Chartered Accountant on his letter head only.

Annexure 3: AFFIDAVIT FOR EMPLOYMENT UNDER IPP 2025

I, ... Designation..... Unit name & location..... under new/expansion/diversification/Technological Upgradation unit hereby declares that unit has provided following employment on date of commercial production...../claim year FY..... (from date..... to.....)

Details of Employees

S.No.	Category of employee	Employee Domicile of M.P.	Employees non-domicile of MP	Total Employees	No. of differently abled employees	% of employee domicile of M.P.	% of differently abled employees

The list of the employees along with their Aadhar Cards' information, EPF Details of permanent employees, Payment Vouchers to Contractor for Contract Employees backed up with EPF details, Wages/Payroll Register and any other relevant document shall be preserved for eligible period of assistance and additional three years.

Signature of MD/ CFO/Proprietor/
Partner Of Organization
Name .....
Designation.....

Verification

I, above deponent hereby state and verify that the contents of this affidavit are true to my personal knowledge and belief, and nothing has been concealed. In case of any concealment and misrepresentation of facts mentioned above I shall be solely responsible for that and shall ensure to return the sanctioned assistance with penal interest compounded annually @ 10% per annum.

Place:
Date:

Signature of MD/ CFO/Proprietor/
Partner of Organization
Name .....
Designation.....

Annexure 4: CE CERTIFICATE TO CERTIFY THE CAPACITY OF PLANT AND MACHINERY IN CASE OF EXPANSION

This is to certify the capacity of the plant & machinery installed at the unit situated at .....

Name of the product	CoD of existing plant	Production Capacity of the existing plant	Average Annual Production in the last 3 years	CoD of Expansion*	Capacity enhanced

**In case of multiple expansions/diversification mention capacity enhanced every time as on CoD*

It is certified that

1. This certificate is issued after the physical inspection of P&M installed, at the factory on.....
2. All plant & machinery is commissioned and in running condition.
3. The capacity is calculated on the basis of inspection and verification of the machines, user manuals and other related documents.
4. The capacity is calculated for one shift per day (8 hrs/ 12 Hours) considering ..... no of working days.

It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respect and no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld.

(Chartered Engineer)

Place

Date:

Annexure 5: AFFIDAVIT UNDER THE MP INVESTMENT PROMOTION SCHEME 2025

(To be notarized on a stamp paper of not less than ₹1000/-)

I/We hereby solemnly affirm and declare that:

1. The information provided by me/us in the application submitted to MPIDC under the Madhya Pradesh Investment Promotion Scheme 2025/2014 on the date ..... is true.
2. I/We am/are not a declared defaulter or insolvent by the State Government or any enterprise of the State Government.
3. Under the Investment Promotion Assistance/ technological upgradation, full payment of the Fixed Capital Investment worth ..... has been made, and the application for assistance has been submitted only for the paid amount. The installed machinery, equipment and Building are new and of good quality.

   The developed industrial infrastructure has been built for the unit/industrial park/Plug & Play Infrastructure/Dedicated Export Parks mentioned in the application is of ₹..... and is of good quality. (If applicable)

   AND/OR

   The established waste management system/systems of ₹..... have been developed for the unit mentioned in the application and comply with the prescribed standards. (If applicable)

   AND/OR

   For mandi fee reimbursement, the agricultural produce is purchased from the State of Madhya Pradesh and the investments of ₹..... is done in main processing machinery upto date of commercial production.

   AND/OR

   Under Export Freight Subsidy for Transportation of Goods the assistance is claimed for goods manufactured in the unit established in Madhya Pradesh and transported from factory premises to international borders/seaports/air cargo for the purpose of exports. (If applicable)

   AND/OR

   The term loan of ₹..... obtained for purchase of Plant & Machinery from lending Banks i.e. ..... is utilized for the same.

   AND/OR

   Other incentives claimed under the Madhya Pradesh Investment Promotion Scheme 2025 are as per the provisions as mentioned in the scheme.

   OR

   Under Standalone Research and Development Facilities, Industrial Testing/Certification Labs full payment of Fixed Capital Investment of ₹..... has been made on which assistance is claimed. (If applicable)
4. I/We hereby pledge that if I/We violate any of the conditions/provisions mentioned in the above notification/rules, the department shall have full authority to cancel/withdraw the benefit as per the rules. Furthermore, I/We shall be responsible for repaying the benefit/assistance amount at an interest rate compounded annually @ 10% per annum.

5. I/We will keep the unit operational during the assistance period and for at least three years thereafter.
6. In the event that the unit does not remain operational as per Scheme 2025, the promoter shall be responsible for repaying the benefit/assistance amount.
7. We have obtained all the necessary legal approvals, consents, and permissions required for establishing the industry.

Signature of MD/ CFO/Proprietor/
Partner Of Organization
Name .....
Designation.....

Verification

I, above deponent hereby state and verify that the contents of this affidavit are true to my personal knowledge and belief, and nothing has been concealed. In case of any concealment and misrepresentation of facts mentioned above I shall be solely responsible for that and shall ensure to return the sanctioned assistance with penal interest compounded annually @ 10% per annum.

Place:

Date:

Signature of MD/ CFO/Proprietor/
Partner of Organization
Name .....
Designation.....

Annexure 6: CA CERTIFICATE FOR IPA IN CASE OF NEW UNIT

I/We..... hereby certify that M/s..... have invested in the following Fixed Assets upto commercial operation date (COD) ..... at their unit situated at ..... for manufacturing of product (s).....

Description of Fixed Assets

#	Name of the Fixed Capital Assets	Investment during last 3 years, from..... to COD..... (In ₹)	Additional Investment after COD From .... to ..... i.e., One year (In ₹)	Total Investment (In ₹)
1.	Details of Plant and Machinery section wise, like processing, packaging, etc. as per Sections 3.3.2, 3.3.3 and 3.3.4.			
A				
B				
C				
	Total			
2.	In-house R&D			
3.	Captive Power (Renewable Energy)			
4.	Energy-Saving Devices			
5.	Imported Second-hand Machinery			
6.	Testing facility (for EV manufacturing)			
7.	Total investment			

Description of Building

S. No	Expenditure in Building	Investment during last 3 years, from..... to COD..... (In ₹)	Additional Investment after COD From .... to ..... i.e., One year (In ₹)	Total Investment (In ₹)
1.	Factory Shed			
2.	Godown			
3.	Admin Building			
4.	Rest Room			
5.	Labour Room			
6.	Sanitary Room			
7.	Guard Room			
8.	Other (specify name)			
	Total			

The above-mentioned plant & machinery and building is as defined under the section 3.3 of the Madhya Pradesh Investment Promotion Scheme, 2025.

We have checked the books of accounts, invoices etc. of the unit and certify that therefore said information is found to be true. We also certify that all the payment have been made against the above mentioned Fixed Assets as well as building/shed and no credit is raised there against in the books of account of the unit. Except for the imported secondhand machinery, all the fixed assets as well as building/shed mentioned above is new and is in good condition.

Name.....

Signature & Seal.....

Membership No .....

Place:

Date:

Note: Above details should be certified by the Chartered Accountant on his letter head only.

Annexure 7: CE CERTIFICATE FOR IPA IN CASE OF NEW UNIT

I have visited the plant site of M/s..... to inspect and verify the installation of the Fixed Assets upto the commercial operation date for the manufacturing of .....

This is to certify that the following Fixed Assets have been installed, and Building is erected at their unit situated at.....

All plant & machinery and Building is commissioned and in running condition.

Description of Fixed Assets

S.No	Name of Fixed Assets	Investment during last 3 years, from..... to COD..... (In ₹)	Additional Investment after COD From .... to ..... i.e., One year (In ₹)	Total Investment (In ₹)
1.	Details of Plant and Machinery section wise, like processing, packaging, etc. as per Sections 3.3.2, 3.3.3 and 3.3.4.			
A				
B				
C				
	Total			
2.	In-house R&D as per			
3.	Captive Power (Renewable Energy)			
4.	Energy-Saving Devices			
5.	Imported Second-hand Machinery*			
6.	Testing facility (for EV manufacturing)			
7.	Total investment			

* The imported second-hand machinery, mentioned at point 5 above, has the life-expectancy of minimum 10 years as per list attached *(please attach the duly certified list of the second-hand machinery with life expectancy and cost of each machinery)*

Description of Building

S. No.	Description of the work	Investment during last 3 years, from..... to COD..... (In ₹)	Additional Investment after COD From .... to ..... i.e., One year (In ₹)	Total Investment (In ₹)
1.	Factory Shed			
2.	Godown			
5.	Admin Building			
6.	Rest Room			
7.	Labour Room			
8.	Sanitary Room			
9.	Guard Room			
10.	Other (specify name)			

The above-mentioned plant & machinery and building is as defined under the section 3.3 of the Madhya Pradesh Investment Promotion Scheme, 2025.

- **Date of installation/commissioning.....**
- **Date of inspection.....**
- **Except for the imported second hand machinery, All plant & machinery and Building mentioned above is new- Yes/No**

This certificate is issued after inspection and verification of the machines, Building and document. It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respect no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld.

Name.....

Signature & Seal.....

Membership No. .....

Place:
Date:

Note: Above details should be certified by the Chartered Engineer on his letter head only.

Annexure 8: CA CERTIFICATE FOR IPA IN CASE OF EXPANSION AND/OR DIVERSIFICATION

I/We.....hereby certify that M/s.....is undertaking investment in fixed capital assets for the purpose of **expansion/diversification** at the existing unit located at ....., leading to an increase in **installed capacity/product line addition.**

Description of Fixed Assets

#	Name of the Fixed Capital Assets	Existing Gross block Investment upto date..... (In ₹)	Investment under expansion/ diversification during last 2 years from..... upto COD.....	Additional Investment after COD From..... to ..... i.e., One year (In ₹)	Total Investment (C+D)
	A	B	C	D	E
1.	Details of Plant and Machinery section wise, like processing, packaging, etc. as per Sections 3.3.2, 3.3.3 and 3.3.4.				
A					
B					
C					
	Total				
2.	In-house R&D as per				
3.	Captive Power (Renewable Energy)				
4.	Energy-Saving Devices				
5.	Imported Second-hand Machinery				
6.	Testing Facility (for EV manufacturing)				
7.	Total investment				
			Total C+D		

Description of Building

S. No.	Expenditure in Building	Existing Gross block Investment upto date..... (In ₹)	Investment under expansion/ diversification during last 2 years from..... upto COD.....	Additional Investment after COD From .... to ..... i.e., One year (In ₹)
	A	B	C	D
1.	Factory Shed			
2.	Godown			

3.	Admin Building			
4.	Rest Room			
5.	Labour Room			
6.	Sanitary Room			
7.	Guard Room			
8.	Other (specify name)			
			Total (C+D)	

The above-mentioned plant & machinery and building is as defined under the section 3.3 of the Madhya Pradesh Investment Promotion Scheme, 2025.

We have checked the books of accounts, invoices etc. of the unit and certify that therefore said information is found to be true. We also certify that all the payment have been made against the above mentioned Fixed Assets as well as building/shed and no credit is raised there against in the books of account of the unit. Except for the imported secondhand machinery, all the fixed assets as well as building/shed mentioned above is new and is in good condition.

Name.....

Signature & Seal.....

Membership No.....

Place:

Date:

Note: Above details should be certified by the Chartered Accountant on his letter head only.

Annexure 9: CE CERTIFICATE FOR IPA IN CASE OF EXPANSION AND DIVERSIFICATION

I have visited the plant site of M/s.....to inspect and verify the installation of the Fixed Capital Assets for the manufacturing of ..... at their existing unit located at .....

This investment has been made for the purpose of **expansion/diversification**, leading to an increase in **installed capacity/product line addition**.

All plant & machinery and Building is commissioned and in running condition.

Description of Fixed Assets

#	**Name of the Fixed Capital Assets**	**Existing Gross block Investment upto date..... (In ₹)**	**Investment under expansion/ diversification during last 2 years from..... upto COD.....**	**Additional Investment after COD From..... to ..... i.e., One year (In ₹)**	**Total Investment (C+D)**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	Details of Plant and Machinery section wise, like processing, packaging, etc. as per Sections 3.3.2, 3.3.3 and 3.3.4.				
A					
B					
	Total				
2.	In-house R&D as per				
3.	Captive Power (Renewable Energy)				
4.	Energy-Saving Devices				
5.	Imported Second-hand Machinery				
6.	Testing Facility (for EV manufacturing)				
7.	Total investment				
			Total C+D		

*The imported second-hand machinery, mentioned at point 5 above, has the life-expectancy of minimum 10 years as per list attached *(please attach the duly certified list of the second-hand machinery with life expectancy and cost of each machinery)*

Description of Building

S. No.	Description of the work	Investment upto COD..... (In ₹)	Additional Investment after COD From .... to ..... i.e., One year (In ₹)	Total Investment (In ₹)
1.	Factory Shed			
2.	Godown			
5.	Admin Building			
6.	Rest Room			
7.	Labour Room			
8.	Sanitary Room			
9.	Guard Room			
10.	Other (specify name)			

The above-mentioned plant & machinery and building is as defined under the section 3.3 of the Madhya Pradesh Investment Promotion Scheme, 2025.

- **Date of installation/commissioning**.....
- **Date of inspection**.....
- **Except for the imported second-hand machinery, All plant & machinery and Building mentioned above is new- Yes/No**

This certificate is issued after inspection and verification of the machines, Building and document. It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respect no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld.

Name.....

Signature & Seal.....

Membership No. .....

Place:
Date:

Note: Above details should be certified by the Chartered Engineer on his letter head only.

Annexure 10: CA CERTIFICATE FOR TECHNOLOGICAL UPGRADATION

I/We.....hereby certify that M/s..... is undertaking investment in plant and machinery for the purpose of **Technological Upgradation** at the existing unit located at .....

Description of Plant and Machinery:

#	Name of Plant and Machinery	Existing Gross block Investment upto date..... (In ₹)	Investment under expansion/ diversification during last 2 years from..... upto COD.....	Total Investment (C+D)
	A	B	C	E
1.	Details of Plant and Machinery section wise undergoing upgradation			
A				
B				
C				
	Total			
2.	Total investment			

Details of the product for which technological upgradation is being undertaken:

#	Name of the product	Original date of production of the product	Original installed capacity of the product	Date of production of the product after technological upgradation	Total installed capacity after technological upgradation

It is certified that, the above mentioned investment is made only in up gradating existing machinery and the product (s) for which the technological upgradation is being undertaken was in production since last 7 years.

We have checked the books of accounts, invoices etc. of the unit and certify that therefore said information is found to be true. We also certify that all the payment has been made against the above-mentioned Plant and Machinery and no credit is raised there against in the books of account of the unit., all the plant & machinery mentioned above is new and is in good condition.

Name.....

Signature & Seal.....

Membership No.....

Place:

Date:

Note: Above details should be certified by the Chartered Accountant on his letter head only.

Annexure 11: CE CERTIFICATE FOR TECHNOLOGICAL UPGRADATION

I have visited the plant site of M/s.....to inspect and verify the installation of the Plant and Machinery for the manufacturing of ..... at their existing unit located at .....

Description of Plant and Machinery:

#	Name of the Plant and Machinery	Existing Gross block Investment upto date..... . (In ₹)	Investment under expansion/ diversification during last 2 years from..... upto COD.....	Total Investment (C+D)
	A	B	C	E
1.	Details of Plant and Machinery section wise undergoing upgradation			
A				
B				
C				
	Total			
2.	Total investment			

Details of the product for which technological upgradation is being undertaken:

#	Name of the product	Original date of production of the product	Original installed capacity of the product	Date of production of the product after technological upgradation	Total installed capacity after technological upgradation

It is certified that, the above mentioned investment is made only in up gradating existing machinery and the product (s) for which the technological upgradation is being undertaken was in production since last 7 years.

- **Date of installation/commissioning.....**
- **Date of inspection.....**
- **All plant & machinery mentioned above is new- Yes/No**

This certificate is issued after inspection and verification of the machines, and document. It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respect no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld.

Name.....

Signature & Seal.....

Membership No. .....

Place:
Date:

Note: Above details should be certified by the Chartered Engineer on his letter head only.

Annexure 12: BANK CERTIFICATE

(Bank Certificate to be furnished by the lending institution to MPIDC along with first quarterly claim)

CERTIFICATE

We ..... Bank ..... Branch certify that:

I. Out of total Rupee Term Loan of ₹..... Lacs sanctioned to M/s.....

(Under Consortium Banking Arrangement, if applicable) the loan to the extent of ₹..... Lakhs is covered for the investment made in plant and machinery, as defined in section 6.14 (4) of the scheme of ₹ ..... Lakhs. The Bank wise eligibility is given here under:

(Amount in ₹ Lakhs)

Name of the Bank and branch	**Amount of disbursed Term Loan taken for P&M under IPP 2025**

II. Further certified that the Bank has exercised due care to ensure & satisfy that the Term Loan sanctioned & disbursed has been utilized for purchase of Plant & Machinery and has been erected in the Plant situated at_____ (M.P.)

III. The details of Repayment Schedule, sanctioned term loan, the quarterly interest payable thereupon as per the terms of original sanction dated_____ along with the computation of quarter-wise subsidy entitlement under the IPP 2025 for 5 year period in case of textile units and 7 year period in case of Garment and Apparel, Footwear, Toys and Accessories, commencing from_____ (date of commencement of commercial production) to _____ given in the enclosed prescribed format is correct. We undertake to intimate to MPIDC immediately upon the revision, if any, in the original sanctioned repayment schedule.

We have exercised due diligence in furnishing the above information and certify that it is correct.

Date:

Place:

Name.....

Designation.....

Branch.....

(Bank Seal)

Annexure 13: LOAN REPAYMENT SCHEDULE

Repayment Schedule, Interest accrual and Quarterly Reimbursement of Interest Subsidy	
Name and Address of Unit	
Name of the Bank and Branch	
Sanctioned Term-loan amount for Plant and Machinery as defined in section 6.14 (4) of the scheme	
Disbursed Loan amount	
Date of commencement of commercial production	

1	2	3	4			5	6	7
S.No.	Quarter (Starting with date of commencement of commercial production)	Amount of the approved term-loan outstanding at the start of the quarter	Amount of instalment			Amount of the approved term-loan outstanding at the end of the quarter	Rate of Interest	Interest reimbursement admissible under IPP 2025
			Principle	Interest	Total			

Name, Designation and Seal and Signature of Authorised Signature of Financial institution/bank

Annexure 14: AFFIDAVIT FOR CLAIMING INCENTIVES UNDER IPP 2025

Madhya Pradesh Investment Promotion Scheme 2025

(Verified by Non-Judicial Notarized Stamp Paper not less than ₹1000/-)

I/We, _____s/o.....Age: _____Resident of_____Promoter/Partner/Managing Director/Director of the unit _____do hereby solemnly affirm and declare that:

1. I/We have submitted a claim application under the "Madhya Pradesh Investment Promotion Scheme 2025" for the unit (name)_____ located at _____.
2. I/We have not received any financial assistance or subsidy from the State Government or any other source for the same claim/component.
3. I/We are not declared insolvent by the State Government or any other enterprise of the State Government.
4. The unit has been operational during the applied claim year_____, as well as in the preceding claim years. The production in the previous claim year is as follows:
    1. Claim Year (---------): _____ MT/No.
    2. Claim Year (---------): _____ MT/No.
    3. Claim Year (---------): _____ MT/No.
    4. Claim Year (---------): _____ MT/No.
    5. Claim Year (----------): _____ MT/No.
5. Details of Assistance:

a) Under the Investment Promotion Assistance, the actual production in the applied claim year _____ is _____ MT/No., out of which total sales for the applied claim year amount to ₹_____. The total exports in the applied claim year amount to_____MT/No., valued at ₹_____. Total employment in the applied claim year stands at [Number]_____.

b) In case of textiles/garments, the interest subsidy at the rate of ------% has been deposited in bank/financial institutions. The interest subsidy claimed for the quarter _____ is at the rate of 5% amounting to ₹ _____. Assistance of ₹_____ has been received till date during the eligibility period. (if applicable)

c) Under the Infrastructure Development Assistance, assistance of ₹ _____ has been received under the scheme. (if applicable)

d) Under the Green Industrialization Assistance, capital subsidy of ₹ _____ has been received till date for establishing waste management systems and Effluent Treatment Plants (ETP). (if applicable)

e) Under the Basic Investment Promotion Assistance (BIPA), the expenditure done in EFCI as defined in Section 3.3 is ₹_____The assistance claimed in the claim year_____ is amounting to ₹_____. The Investment Promotion Assistance received till date during the eligibility period is ₹_____.

f) Under the Mandi Fees Reimbursement, the assistance claimed for the year_____ is ₹ _____. The total assistance received is as per the eligible investment in Plant and Machinery of ₹ _____ is ₹_____ till date. (if applicable)

g) Under the export freight subsidy, the assistance clamed for the year_____is ₹_____. The total assistance received is ₹_____till date. (if applicable)

h) Under the Skill Development & Training incentive, ₹13,000 per new MP-domicile employee has been claimed for a period of 5 years. A total of _____ employees have been trained in the previous years, and the assistance received till date is ₹_____ (if applicable).

i) The assistance received under any other head of the Industrial Promotion Policy – 2025, _____ (please specify the name of assistance received) is ₹_____ till date.

5. I/We declare that I/we have received total assistance of ₹..... from MPIDC as on ..... (Date). I/We declare that I/we have received total assistance of ₹..... from Government of India under the ..... (policy/ scheme) as on ..... (Date). Total assistance received till date ₹..... against FCI of ₹.....

6. I/We fully understand that under the Industrial Promotion Policy – 2025, under section 9.4 'in no case shall the investment assistance or any other assistance under this policy exceed the fixed capital investment made by the investor'.

7. I/We, the undersigned, declare that no assistance has been availed from any other State agency apart from what has been mentioned above under the fixed capital investment for which, investment assistance has been granted.

8. I/We declare that if any information/statement mentioned above is found to be incorrect or misleading or if it is found that any component/benefit has been availed wrongly, then I/We shall be liable to return the entire amount of assistance received along with interest compounded annually @ 10% per annum without any objection or delay.

9. I/We further declare that all the information provided from point 01 to 08 is completely true and factual. If any falsehood is detected at any point, the department may take appropriate action against me/us.

Signature of MD/ CFO/Proprietor/
Partner Of Organization

Name .....

Designation.....

Annexure 15: CA Certificate for Claiming IPA/Technological Upgradation

This is to certify that M/s ....., having its registered office at ....., is applying for claiming Investment Promotion Assistance under unit/Expansion/ Diversification/Technological Upgradation for the claim year .....

The unit has the production, sales, exports and FDI details as mentioned below:

	Details	**Quantity**	**Value (in ₹)**
i.	Total Annual Production of claim year (in case of expansion, mention production of installed and expanded capacity separately)		
ii.	Total Annual Sales of claim year		
iii.	Annual Export of claim year (in case of expansion/diversification only for the expanded or diversified unit)		

In case of FDI, percentage of FDI in equity is.....for the claim year..... Verified on the basis of the FLA return.

The above details have been verified from the books of accounts, GST returns (GSTR-1 & GSTR-3B), financial statements, and relevant supporting documents of M/s..... [Unit Name].

This certificate is issued based on the documents and information submitted by the entity and is true and correct to the best of our knowledge and belief.

Name.....

Signature & Seal.....

Membership No .....

Place:
Date:

Note: Above details should be certified by the Chartered Accountant on his letter head only.

Annexure 16: DUE DILIGENCE CERTIFICATE

(To be submitted by the Bank along with every quarterly interest subsidy claim)

We..... Bank..... Branch has exercised due diligence in furnishing the information in the enclosed prescribed format for claim of interest subsidy @5% to M/s..... Under the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2025 for the quarter ..... to .....

We hereby certify that the claim of ₹..... on the term loan disbursed by us to M/s..... for the period .....to..... is in order.

I. The term loan for which interest certificate is issued and interest Reimbursement claimed is only that portion of the total Term Loan disbursed by our Bank to M/s..... which has been utilized for acquiring/erection of Plant & Machinery and no other amount of loan has been considered for claiming interest reimbursement.

II. The interest and instalment of the principal amount of loan becoming due during the quarter have been paid and there has been no default in payment of interest and principal amount. No penal interest/charges are included in the claimed amount.

III. The amount of interest reimbursement claim does not include any amount which has already been subsidized wholly or partially under any other scheme.

IV. The interest reimbursement claim is lower than/restricted to the amount of reimbursement claim requirement submitted to MPIDC along with the approved repayment Schedule.

V. We have exercised due diligence in furnishing the above information and certify that it is correct. We shall own responsibility for any wrong calculations of interest subsidy claimed and omissions/ misrepresentations, if any, in the above information.

VI. No Claim has been made pertaining to NPA.

Date:

Place:

Authorised Signatory of the Bank

Name:

Designation:

Annexure 17: QUARTERLY STATEMENT FOR CLAIMING INTEREST SUBSIDY UNDER IPP 2025

Quarterly Statement for Claiming Interest Subsidy Sanctioned under IPP 2025

(Interest Subsidy on the Term Loan Disbursed by M.P. State Financial Corporation/ Nationalized Bank/ Other Financial Institutions)

Name of the unit Claiming

Financial Assistance

Date of Production of Unit

S No.	Amount of sanctioned term loan taken for P&M	Amount of Term Loan disbursed till the Quarter ending.....	Opening Balance of Term Loan at the start of quarter (as on .....)			Rate of interest on Term Loan and interest amount due during quarter		Interest Subsidy Rate	Amount of interest reimbursement entitled	
			Total	Days	Amount	Rate of interest on Term Loan	Interest amount during quarter on Loan for P&M		Till the end of Last Quarter	For Current Quarter
1	2	3	4 (a)	4 (b)	4 (c)	5 (a)	5 (b)	6	7 (a)	7 (b)
			Total							

Subsidy Claim for Period:

Qtr. Ended:

Loan Amount:

Loan Account No.

Bank Name:

Branch Address:

IFSC Code

Beneficiary Name

Beneficiary Account No.

ROI

Name: ....

Designation..

Signature & official seal of authorized signatory of Bank

Annexure 18: AFFIDAVIT FOR AVAILING TRAINING AND SKILL DEVELOPMENT SUBSIDY

(To be submitted on notarized Stamp Paper of not less than ₹1000/-)

I, ... Designation ..... Unit name & location ..... under new/expansion/diversification unit hereby declares that unit has following employment in the year .....

	Employees with MP Domicile			Employees with Non-MP Domicile			Total
	Direct	Contract	Total	Direct	Contract	Total	
New Employees							
Previous Employees							
Total							
% of employees with MP Domicile							

Details of employees:

No. of Trainees out of the New MP Domicile Employees above -..... (To whom training for a minimum period of ..... days has been imparted)

Employees' details have been provided in the Format A attached with this annexure. The copies of ECR, Wages/Payroll register ESI details, and any other relevant document shall be preserved by the unit for the eligible period of assistance and additional three years and produced on demand to MPIDC.

Signature of MD/ CFO/proprietor/ partner of organisation

Name .....

Designation.....

Verification

I, above deponent hereby state and verify that the contents of this affidavit are true to my personal knowledge and belief, and nothing has been concealed. In case of any concealment and misrepresentation of facts mentioned above I shall be solely responsible for that and shall ensure the return the assistance sanctioned with the penal interest compounded annually @ 10% per annum.

Place:

Date:

Signature of MD/ CFO/proprietor/ partner of organisation

Name .....

Designation.....

FORMAT A: EMPLOYEES DETAILS FOR TRAINING COST REIMBURSEMENT AND EMPLOYMENT GENERATION SUBSIDY FOR THE YEAR .....

Name of the Unit

Employees Details for Training Cost Reimbursement and Employment Generation Subsidy under Special garment package for the period .../.../..... To .../.../..... (12 months)

#	Name of Employee	Type of Employee (Contractual/Permanent)	Designation (Managerial/Skilled/ Semiskilled/ unskilled)	Date of Joining	UAN	Gender	Aadhaar ID	Address	District	Permanent resident (Yes/No)

SIGNATURE OF AUTHORIZED SIGNATORY

NAME .....

DESIGNATION.....

Annexure 19: AFFIDAVIT FOR AVAILING ASSISTANCE FOR EMPLOYMENT GENERATION

(To be submitted on notarized Stamp Paper of not less than ₹1000/-)

I, ... Designation..... Unit name & location ..... under new/expansion/diversification unit hereby declares that unit has following employment in the year.....

Details of employees:

	Employees with MP Domicile			Employees with Non-MP Domicile			Total
	Direct	Contract	Total	Direct	Contract	Total	
New Employees							
Previous Employees							
Total							
% of employees with MP Domicile							

The list of the employees in prescribed format (Annexure 19; Format B) along with their Aadhar Cards' information, EPF Details of permanent employees, Payment Vouchers to Contractor for Contract Employees backed up with EPF details, Wages/Payroll Register, and any other relevant document shall be preserved for eligible period of assistance and additional three years.

Signature of MD/ CFO/proprietor/ partner of organisation

Name.....

Designation.....

Verification

I, above deponent hereby state and verify that the contents of this affidavit are true to my personal knowledge and belief and nothing has been concealed. In case of any concealment and misrepresentation of facts mentioned above I shall be solely responsible for that and shall ensure the return the assistance sanctioned with the penal interest compounded annually @ 10% per annum.

Place:
Date:

Signature of MD/ CFO/proprietor/ partner of organisation

Name .....

Designation.....

FORMAT B: EMPLOYEE DETAILS FOR ASSISTANCE UNDER IPP 2025/ ASSISTANCE FOR EMPLOYMENT GENERATION UNDER GARMENT, FOOTWEAR, TOYS AND ACCESSORIES POLICY

Name of the Unit

Employees Details for Employment Generation Subsidy for the period .../.../..... to .../.../..... (12 months)

#	Name of Employee	UAN	Type of Employee (Contractual /Permanent)	DOJ*	DOL**	Salary (PM)	Month												Period of training	Type of Training	MP Domicile Status	Gender
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				

*DOJ – Date of Joining

**DOL – Date of Leaving

SIGNATURE OF AUTHORIZED SIGNATORY

NAME .....

DESIGNATION .....

Annexure 20: CA Certificate for Verifying the Details of the Export Freight Cost

This is to certify that M/s....., having its registered office at ....., with GSTIN ....., has incurred freight/transportation expenses amounting to ₹..... for the transportation of goods exported via [Road/Rail/Air/Water] from ..... to ..... for the claim year.....

The details of the transportation expenses are as follows:

Products exported	Transporter Name	From	To	Mode of Transport	Freight Amount (₹)

It is also certified that the unit has manufactured the aforementioned products at its facility in the State of Madhya Pradesh. The transportation costs have been verified against transportation invoices, E-Way Bills, and supporting financial records.

Name.....

Signature & Seal.....

Membership No.....

Place:

Date:

Note: Above details should be certified by the Chartered Accountant on his letter head only.

Annexure 21: CA Certificate for Private Industrial Park/ Plug and Play Facility

We hereby certify that ..... having its unit at..... operating in the .....have made the following fixed capital investment during the period of Investment from..... To.....

Sr. No.	Fixed Capital Investment	Fixed Capital Investment Amount (in ₹)
1	**For Industrial Park**	
2	**Cost of development of infrastructure**	
	Internal Roads	
	Internal Power Infrastructure	
	Internal Water Infrastructure	
	Sewage & drainage network	
	Internal Gas Pipeline	
	Others, please specify	
3	**Green Industrialization facilities (ETP, STP, ZLD)**	
	ETP/STP	
	ZLD	
	Others, please specify	
	Total Cost of Infrastructure Development	

Sr. No.	Fixed Capital Investment	Fixed Capital Investment Amount (in ₹)
1	**For Plug and Play Park**	
	Internal and Approach Roads	
	Internal Power Infrastructure	
	Internal Water Infrastructure	
	Sewage & drainage network	
	Internal Gas Pipeline	
	Others, please specify	
	Building	
2	**Building Construction**	
	Civil construction	
7	**Green Industrialization facilities (ETP, STP, ZLD)**	
	ETP/STP	
	ZLD	
	Others, please specify	
8	**Cost of development of Common Infrastructure Facilities**	
	Testing facilities	
	R&D facilities	
	Other common facilities (please mention)	
	Total Fixed Capital investment	

Annexure 22: CA CERTIFICATE FOR RENT PAID

This is to certify that M/s....., having its registered office at....., is a [Manufacturing/Service Sector] unit operating in a Plug-and-Play facility developed by .....[Government/Private Developer]. The unit has entered into a registered rent agreement for the premises located at .....[Rental Space Address] on .....[Date of Rent Agreement], with a total rental space of .....[Area in sq. ft.].

As per the rent agreement, the monthly rental rate is ₹.....[Rate per sq. ft.], and the unit has paid the following rental amounts:

Claim year for which reimbursement is claimed	**Annual Rent Paid (₹)**	**Rental Subsidy Claimed (₹)** (50% of Rent Paid, max ₹10/sq. ft.)

The above rental payments have been verified from the rent agreement, payment receipts, and financial records provided by M/s .....**[Unit Name]**.

This certificate is issued based on the documents and information submitted by the unit and is true and correct to the best of our knowledge and belief.

Name.....

Signature & Seal.....

Membership No.....

Place:

Date:

Note: Above details should be certified by the Chartered Accountant on his letter head only.

भोपाल, दिनांक 1 मई 2025

क्रमांक एफ IPI–5–0028–2025–A -11.– प्रदेश में लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग अधोसंरचना को सहायता प्रदान किये जाने हेतु विभागीय आदेश दिनांक 24 फरवरी 2025 द्वारा जारी "मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक नीति" 2025, अंतर्गत प्रावधानित सुविधा/सहायता उपलब्ध कराने एवं दिशा–निर्देश जारी करने हेतु राज्य शासन, एतदद्वारा संलग्नक अनुसार मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक प्रोत्साहन योजना 2025 जारी करता है.

2. यह योजना मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक नीति, 2025 के जारी होने के दिनांक 24 फरवरी 2025 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शाश्वत सिंह मीना, उपसचिव.

Government of Madhya Pradesh

MPIDC MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD

INVEST MADHYA PRADESH –INFINITE POSSIBILITIES-

MADHYA PRADESH LOGISTICS SCHEME 2025

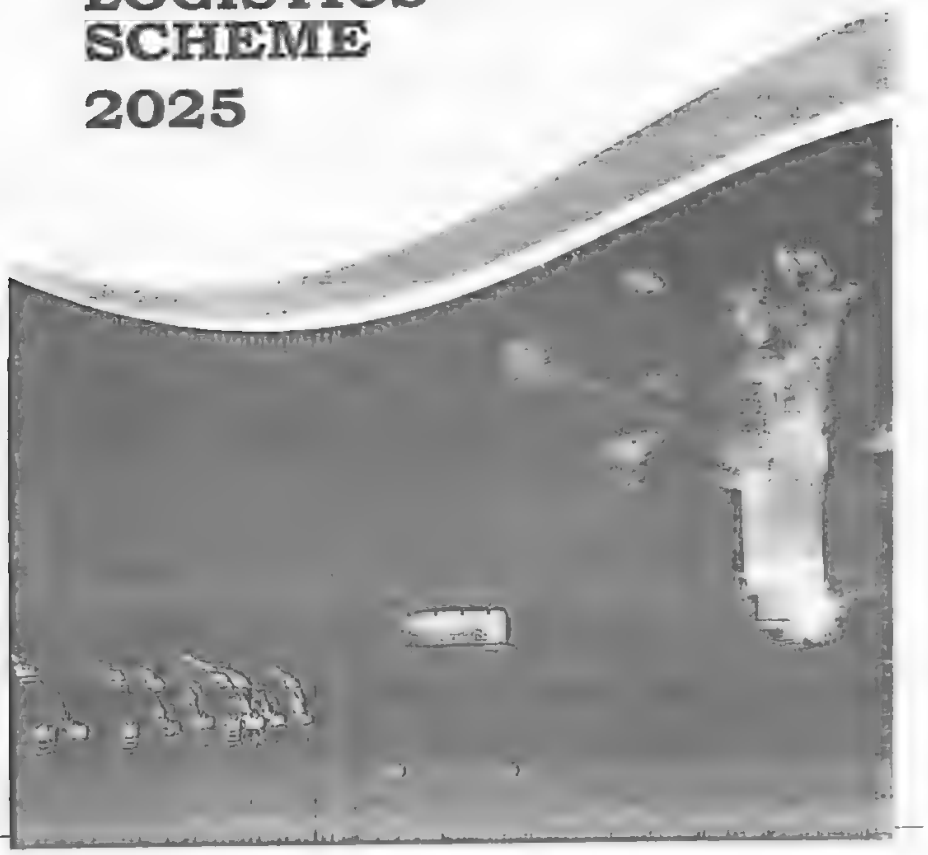

Contents

Contents .....

1. Preface .....
2. Policy Period and Scope of Effectiveness of the Scheme. .....
3. Definitions: .....
4. Eligibility .....
5. Application Procedure .....
6. Fiscal Incentives: Logistics Parks, ICDs and MMLPs .....
7. Other Conditions .....
8. Appeal .....
9. Amendment/Relaxation/Repeal .....
10. Jurisdiction .....
11. Annexure .....

Form 1: Application form for proposal of establishment of Logistic Infrastructure
Form 2: Application for claiming Assistance for Logistic Infrastructure
Form 3: Application form for conversion of Agri Produce Warehouse into Industrial Produce Warehouse

12. Affidavit .....

Department of Industrial Policy and Investment Promotion

Government of Madhya Pradesh

Scheme for Financial Assistance for Logistics and Warehousing Infrastructure under Madhya Pradesh Logistics Policy 2025.

1. Preface

The Government of Madhya Pradesh is committed to developing a robust and future-ready logistics and warehousing ecosystem to drive the state's economic growth and enhance the state's competitiveness on national and global platforms. To achieve this, the state has introduced the **Madhya Pradesh Logistics Policy 2025",** notified on February 24, 2025.

To enable its effective implementation, the government is introducing **Madhya Pradesh Logistics Scheme 2025.**The scheme provides a comprehensive operational framework that outlines:

A. Eligibility criteria for enterprises and investors
B. Definitions of infrastructure categories
C. Quantum and types of financial assistance
D. Governance and approval mechanisms, and
E. Disbursement procedures.

By ensuring standardization, transparency, and clarity, the scheme serves as a crucial reference for investors and the department, reinforcing Madhya Pradesh's commitment to establishing itself as a premier logistics hub, supported by world-class logistics infrastructure, and as a leading destination for industry, investment, and employment generation.

2. Policy Period and Scope of Effectiveness of the Scheme.

2.1 This scheme will remain in effect for the effective duration of the Madhya Pradesh Logistic Policy 2025.

2.2 Logistic enterprises commencing production after the date of notification of the Madhya Pradesh Logistic Policy 2025, shall be eligible to avail the benefits of this scheme.

2.3 It is clarified that Logistic Infrastructure with investment more than ₹125 Crore shall be implemented under this scheme.

3. Definitions:

3.1 Fixed Capital Investment:

Fixed Capital Investment (FCI) for the purpose of this Scheme refers to the expenditure incurred on tangible, immovable, and directly operational infrastructure and assets, essential for establishing logistics and warehousing facilities as defined under the MP Logistics Policy 2025. FCI computed for the purpose of calculating financial incentives and investment assistance under the policy shall include the following components but not limited to:

I. Internal roads, Railway sidings, Air strips, Cargo terminal
II. Power related infrastructure
III. Water infrastructure including wastewater drainage
IV. Telecom and other utilities
V. Investment in Plant & Machinery including the foundation, & cost of transportation, erection, installation (excluding consultancy charges and labour charges)
VI. All handling equipment including automated handling equipment, measurement equipment.
VII. Safety equipment, generator sets, transformers, maintenance equipment etc.
VIII. Pollution Control devices
IX. ICT and logistics management systems
X. Buildings shall include the main building, warehouse, office building, administrative building, restrooms/washrooms, and allied infrastructure related to Logistic activities like Container yards, Cargo handling zones.

Components which shall not be considered for computing of Fixed Capital Investment:

I. Cost of land

ii. Cost of development of land, preliminary and pre-operative expenses, interest during the period, consultant fees, margin money for working capital shall not be considered as fixed capital investment for the purpose of calculating subsidy.
iii. Loading and unloading charges
iv. Commissioning cost
v. Captive Power Plants
vi. Boundary wall and gate, Used machinery/ equipment for facility
vii. Dwelling units, guest houses, canteens
viii. Interest during construction
ix. Used/refurbished machinery (unless imported, with minimum 10-year life and compliance certification)
x. Vehicles used for external transportation (only intra-park utility vehicles are eligible)
xi. Equipment not directly related to logistics services.

3.2 Commencement of Operation Date (COD)

Completion of construction / COD will be considered when the first consignment of goods has been received at the facility.

3.3 Air Freight Station (AFS) / Air Cargo Complex (ACC)

As notified by the Ministry of Civil Aviation, AFS is an off-airport common user facility equipped with fixed installations of minimum requirement and offering services for handling and temporary storage of import and export cargo, etc. ACC is defined as a facility within the airport or off-airport augmenting the air cargo movement capacity. ACC should provide facilities such as handling, storage, cargo clearance and other allied facilities for smooth operations.

3.4 Container Freight Station (CFS)

CFS is a facility for handling and temporary storage for customs bonded or non-bonded cargo under customs control and empty containers. The CFS may offer allied facilities for smooth operations.

3.5 Inland Container Depot/Dry Ports

ICD should have rail and road connectivity. Inland Container Depots (ICDs) and Container Freight Stations (CFSs) are dry ports and are responsible for handling and temporary storage of import / export goods including completion of customs formalities at these locations. They should have provisions to house customs and other agencies, who would be involved to clear goods for home use, warehousing, temporary admissions, re-export, temporary storage for onward transit and outright export. Transshipment of cargo can also take place from such stations. ICD should have rail and road connectivity.

3.6 Logistics Parks

Logistics Parks are designated areas that provide a range of logistics services such as freight handling facility, cargo aggregation/segregation, distribution, storage (open, closed, and ambient), and container freight services. These parks are equipped with infrastructure including internal roads, power lines, communication facilities, water pipelines, sewage and drainage systems, and other necessary amenities to support efficient logistics operations.

The Parks will include but not limited to:

i. Bulk and Break-bulk cargo terminals
ii. Freight Transfer Hubs/truck terminals
iii. Industrial Plots
iv. Intermodal container terminals
v. Infrastructure for value added and ancillary industries & commercial activity
vi. Logistics Services
vii. Sector-specific Inward & Outward logistics
viii. Warehousing Storage System

3.7 Multi Modal Logistics Parks (MMLPs)

Multi Modal Logistics Parks have facilities for cargo aggregation/segregation, distribution, inter-modal transfer and handling and storage of containers and cargo, open/closed storage, temperature-controlled/ambient storage, custom bonded

warehouse, material handling etc. Services relating to aggregation, dis-aggregation, processing, assembling, storage and distribution of commodities, both for national and international transit are carried out in an integrated facility with parking and value-added services.

3.8 Private Freight Terminal (PFT) /Gati Shakti Cargo Terminal (GCT)

PFT/ GCT are facilities for the purpose of bulk handling of goods for transport by road or rail. Private Freight Terminal will be a privately owned Freight Terminal as defined by Ministry of Railways. Greenfield PFT means a new PFT on private land; Brownfield PFT refers to an existing private siding converted into PFT.

3.9 Warehouse

"Warehousing" (as per warehousing Development and Regulation Act, 2007) means, "any premises (including any protected place) conforming to all the requirements including manpower specified by the Authority by regulations wherein the warehouseman takes custody of the goods deposited by the depositor and includes a place of storage of goods under controlled conditions of temperature and humidity.

3.10 Indian Green Building Council

The Indian Green Building Council (IGBC), promotes sustainable practices in the building industry and provides a rating system to assess and certify buildings based on their socio-economic and environmental issues. The green concepts will also address national priorities such as water conservation, energy efficiency, reduction in fossil fuel use for commuting & transportation, conserving natural resources etc.
The IGBC Green Building Rating System is based on the principles of LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

i. Gold Certification:

A Gold rating highlights a nationally recognized, top-quality green building. Buildings achieving this level demonstrate outstanding

performance in areas like water efficiency, energy savings, and resource utilization.

ii. Platinum Certification:

The Platinum rating is the highest level, showing global excellence in eco-friendly construction. Buildings achieving this level demonstrate leadership in sustainable practices, exceeding national standards and setting benchmarks for future green building projects.

4. Eligibility

A. Enterprises eligible for assistance under this policy should be:

A new unit/projects which commences operation during the operative period of this scheme.

AND

An enterprise which has filed a separate Intention to Invest proposal with MPIDC and IEMs (Industrial Entrepreneur Memorandum) Part-A and Part-B/ Udyog Aadhar Memorandum, from Government of India.

AND

In which new electricity connection has been obtained from the electricity distribution company.

AND

Should be registered under the GST Act.

B. Eligibility as per Policy:

I. Warehousing means "Industrial Warehousing" and shall be only used for non-agricultural products. The units storing primary agricultural produce shall not be eligible for these incentives.

II. Logistics Park must have all required necessary statutory permissions/approvals, approval of layout plan from the Competent Authorities.

III. Logistics and Warehousing Infrastructure shall mandatorily start operations within 3 years from the date of approval/sanction or decided determined by SLEC and shall continue to be operational for a minimum period of 10 years after completion or from approval date, otherwise, Financial Assistance disbursed will be recovered.

5. Application Procedure

1. To be Eligible for availing incentives under this policy, investor shall submit an 'Intention to Invest' application on the INVEST portal.
2. The investor shall submit the proposal for establishment of Logistic infrastructure to MPIDC on the INVEST portal.

3. The eligibility shall be subject to the following conditions:

3.1. For Logistics Parks, ICDs and MMLPs

S. No.	Area of the Park/ facility	Minimum width of approach road	Minimum Fixed Capital Investment (excluding land)
1	25 acres to 75 acres	12 meters	₹ 50 crores
2	More than 75 acres	18 meters	₹ 100 crores

Investment more than ₹500 crore on Fixed Capital Investment (FCI) in Logistics Parks, Inland Container Depots (ICDs), or Multi-Modal Logistics Parks (MMLPs) shall qualify for classification under 'Mega Industry' status and shall be eligible for sanction of special package by the Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP) on case-to-case basis.

3.2 For other Logistics and Warehousing Infrastructure: Private Freight Terminal (PFT) /Gati Shakti Cargo Terminal (GCT), Container Freight Station (CFS) Air Freight Station (AFS) / Air Cargo Complex (ACC)

S. No.	Area of Logistics and	Minimum width of approach road	Minimum Fixed Capital Investment (excluding land)

	Warehousing Infrastructure		
1	5 to 10 Acres	10 meters	₹ 10 crores
2	10 acres to 50 acres	12 meters	₹ 50 crores
3	More than 50 acres	18 meters	₹ 100 crores

Investment more than ₹75 crore in Fixed Capital Investment (FCI) for other Logistics and Warehousing Infrastructure: Private Freight Terminal (PFT) /Gati Shakti Cargo Terminal (GCT), Container Freight Station (CFS) Air Freight Station (AFS) / Air Cargo Complex (ACC), shall qualify for classification under 'Mega Industry' status and shall be eligible for sanction of special package by the Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP) on case-to-case basis.

4. Based on the application, State Level Empowered Committee (SLEC) shall accord in-principal approval based on the merits of the proposal and shall broadly determine the following:

   I. Timeline for the completion of the project (maximum 3 years)
   II. The quantum of Investment.
   III. The nature and scope of Infrastructure to be developed.

5. The project completion timeline, as determined by the SLEC, may be extended by the Managing Director, MPIDC, on merit, for a maximum of two occasions, with each extension not exceeding a period of one (1) year.
6. In the event the investor fails to complete the project within the stipulated timeline, including extensions granted by MD MPIDC, the in-principal approval accorded SLEC shall stand cancelled.
7. The investor may file an appeal before the SLEC against the cancellation of project approval, within a period of one hundred and eighty (180) days from the date of such cancellation order.
8. SLEC shall be authorized to review the appeal and shall take decision based on the merits of the case.
9. After commencement of Operations date (COD), the investor shall submit an application, in the prescribed format (Form-2), along with all necessary supporting documents, to the Managing

Director, MPIDC, for the purpose of sanctioning assistance, within one hundred and eighty (180) days from COD the date of completion of the Logistics Infrastructure Project.

10. SLEC may condone any delays in submission of the application for claim on the basis of genuine reason for such delay.
11. The eligibility for the Assistance shall be determined by SLEC. The developer/investor shall furnish Work Completion Certificates, along with certificates from a Chartered Accountant (CA) and a Chartered Engineer (CE), substantiating the investment made in the logistics infrastructure.
12. The Managing Director, MPIDC is empowered to sanction and disburse incentives as per the eligibility determined by SLEC.
13. Disbursement of sanctioned incentives shall be made through e-payment to the bank account of the investor.
14. No interest shall be payable to the applicant in case of any delay in disbursement.

6. Fiscal Incentives: Logistics Parks, ICDs and MMLPs

6.1 Investment Assistance

6.1.1 Logistics Parks, ICDs and MMLPs shall be eligible for Investment Assistance on Fixed Capital Investment as defined:

S. No.	Area of the Park/ facility	Investment Assistance Percentage	Maximum Limit
1	25 acres to 75 acres	30%	₹ 50 Crore
2	More than 75 acres	30%	₹ 75 Crore

The investments made by the investor from the date of submission of the proposal until the completion of the project, in accordance with the terms and conditions stipulated by SLEC, shall be considered for the purpose of calculation of the eligible assistance. The investor shall submit a Chartered Engineer's (CE) Certificate certifying the completion of the logistics infrastructure.

The sanction shall be done on milestone basis as below:

First Instalment: First installment of 40% of the assistance shall be released after Completion of construction / COD (whichever is earlier)
Second Instalment: 30% of the assistance shall be sanction on completion of one year from Commencement of Operation.
Third Instalment: Remaining 30% of the assistance shall be sanctioned on completion of two year from Commencement of Operation.

For disbursement of 2nd and 3rd installment the investor must present an affidavit and copy of GST return certified by CA for verification of the operational status.

6.1.2 Stamp Duty and Registration Fees

1. The investor shall be reimbursed 100% of the stamp duty and registration fee.
2. The maximum limit of the assistance shall be ₹ 5 Crores.
3. The subsidy is applicable to units that has taken land on lease in the industrial areas established by the State Government or on purchase of private land.

6.1.3 Assistance for Certified Green Logistics Parks and MMLP

1. The investor shall be reimbursed 50% of the certification fee for Indian Green Building Council (IGBC) for Gold and Platinum certification.
2. The maximum limit of the assistance shall be ₹ 20 lakhs.
3. Reimbursement shall be done after obtaining the certification from Indian Green Building Council (IGBC)

6.1.4 External Infrastructure Development Assistance

This assistance shall be available to the facility that are established on:

- Private land

- Undeveloped Government land

The capital subsidy of 50%, up to a maximum of ₹ 5 crore on expenditure incurred for developing the following essential infrastructure shall be made available:

- Road: The approach road to the facility main gate from the main road.
- Power: Power line for sourcing electricity from the main line.
- Drainage and Sewage: Necessary infrastructure developed for the establishment of drainage or sewage infrastructure from the facility main gate to the main drainage/sewage infrastructure.
- Rail integration lengths and nearest station.
- Water: Water pipeline from main connection to premises.

6.2 Investment Assistance

Other Logistics and Warehousing Infrastructure: Private Freight Terminal (PFT) /Gati Shakti Cargo Terminal (GCT), Container Freight Station (CFS) Air Freight Station (AFS) / Air Cargo Complex (ACC)shall be eligible for Investment Assistance on Fixed Capital Investment as follows:

Area of Logistics and Warehousing Infrastructure	Investment Assistance Percentage	Maximum cap in ₹
5 to 10 Acres	30%	5 Cr
10 acres to 50 acres	30%	15 Cr
More than 50 acres	30%	25 Cr

The investments made by the investor from the date of submission of the proposal until the completion of the project, in accordance with the terms and conditions stipulated by SLEC, shall be considered for the purpose of calculation of the eligible assistance. The investor shall submit a Chartered Engineer's (CE) Certificate certifying the completion of the logistics infrastructure.

The sanction shall be done on milestone basis as provided below-

1. First Instalment: First installment of 40% of the assistance shall be released after Completion of construction / COD (whichever is earlier)
2. Second Installment: 30% of the assistance shall be sanction on completion of one year from Commencement of Operation.
3. Third Installment: Remaining 30% of the assistance shall be sanction on completion of two year from Commencement of Operation.

For disbursement of 2nd and 3rd installment the investor must present an affidavit and copy of GST return certified by CA for verification of the operational status.

6.2.1 Stamp Duty and Registration Fees

1. The investor shall be reimbursed 100% of the stamp duty and registration fee.
2. The maximum limit of the assistance shall be ₹ 5 Crores.
3. The subsidy is applicable to units that take land on lease in industrial areas established by the State Government or on purchase of private land.

6.2.2 External Infrastructure Development Assistance

This assistance shall be available to the facility that are established on:

- Private land
- Undeveloped Government land

The capital subsidy of 50%, up to a maximum of ₹ 3 crore on expenditure incurred for developing the following essential infrastructure shall be made available:

- Road: The approach road to the facility main gate from the main road.
- Power: Power line for sourcing electricity from the main line.
- Drainage and Sewage: Necessary infrastructure developed for the establishment of drainage or sewage infrastructure from the facility main gate to the main drainage/sewage infrastructure.
- Water: Water pipeline from main connection to premises.

6.3 Assistance for the Conversion of Agricultural Produce Warehouses to Industrial Warehouses.

1. The agriculture produce warehouse converting into industrial warehousing shall be eligible for reimbursement of 40% of the total cost of conversion to industrial warehouses.
2. The maximum assistance shall be limited to Rs 1 Crore.
3. Agricultural produce warehouses with minimum storage capacity of 10,000 MT shall be eligible for conversion to industrial warehouses.
4. The agricultural warehouse must be registered with competent authority of the state government.
5. The converted industrial warehouse must be as per the prevalent norms of Town and Country Planning.

The conversion shall include, but shall not be limited to, the following activities:

1. Cargo handling infrastructure like industrial dock levelers, steel tiles, anchor plates, or metal grids embedded in concrete for loading and unloading platforms, ensuring the capability to handle the heavy impact of industrial goods.
2. High-efficiency lighting suitable for industrial operations along with air turbo ventilation for enhanced airflow and operational efficiency.
3. Industrial-grade flooring with load-carrying capacity sufficient for handling industrial goods.
4. Systems and IT hardware and software required for warehousing.
5. Packaging and handling facilities.

6.3.1 Application procedure for Conversion of Agricultural Produce Warehouses to Industrial Warehouses

1. The unit/agency shall submit the application for conversion of agriculture produce warehouse into industrial warehouse within 180 days of commencement of commercial operation, post conversion.
2. The date of COD for the industrial warehouse, post-conversion, shall be deemed to be the date when first consignment of goods has been received or execution of the first rent agreement.
3. SLEC may condone delays in submission of application for claim.

4. The eligibility for the Assistance shall be determined by SLEC.
5. The warehouse unit shall furnish a Work Completion Certificate, along with certificates from a Chartered Accountant (CA) and a Chartered Engineer (CE),
6. substantiating the investment made and completion activities for conversion into the logistics infrastructure.
7. The Managing Director, MPIDC is empowered to sanction and disburse incentives in accordance with the eligibility as determined by the SLEC.
8. Disbursement of the sanctioned incentives shall be made through the e-payment to the bank account of the applicant.
9. No interest shall be payable in case of any delay in disbursement.
10. The applicant shall comply with all applicable laws, rules and regulations and obtain all necessary approvals and clearances from the concerned authorities for construction and operation of the warehouse.

7. Other Conditions

1. This scheme is applicable specifically to logistics and warehousing infrastructure and pertaining to non-agricultural storage and logistics operations only.
2. If the investor qualifies for incentives under more than one policy of the Government Madhya Pradesh, the investor shall be eligible to receive benefits under only one policy of their choice.
3. If an investor seeks additional financial assistance from the Government of India, the combined subsidy from both the Central and State Governments shall not exceed actual investments done by the unit in FCI.
4. The logistics facility shall mandatorily commence operations within a period of three (3) years from the date of approval or sanction or decided determined by SLEC and shall remain operational for a minimum period of ten (10) years. In the event of non-compliance, the financial assistance disbursed will be recovered.

   In case the facility remains non-operational for a continuous period exceeding six (6) months within the said tenure, the entire amount of assistance disbursed shall be recovered along with penal interest at the rate of ten percent (10%) annually.

5. The investor shall not transfer the ownership of the facility during the assistance period and for a further period of three (3) years thereafter.
6. It will be mandatory to maintain the Fixed Capital Investment (FCI) as defined in section 3.1, for which assistance has been sanctioned, in good working condition during the assistance period and for 3 years thereafter.
7. There shall be no alteration or change in the location of the facility or any part thereof nor any modification to the FCI made under the scheme.
8. In the event of change in the ownership of the Fixed Capital Investment (FCI), as defined in Section 3.1, during the assistance period and for a further period of three (3) years thereafter, such change shall only be made with the prior written approval of the Managing Director, MPIDC.
   Upon grant of such approval and transfer of ownership, all rights, duties, liabilities, and obligations under the Madhya Pradesh Logistics Scheme 2025 shall be binding upon the new owner or successor entity, who shall be deemed to have assumed the same in entirety.
9. For availing the assistance under this scheme, the investor should comply with all applicable provisions of the Town and Country Planning Guideline.
10. Any entity declared insolvent or defaulter by the State and Central Government and their undertaking shall not be eligible for assistance under this Policy.

8. Appeal

An appeal against the decision of the State Level Empowered Committee can be made through MPIDC before the "Cabinet Committee on Investment Promotion" (CCIP) within three (3) months from the date of receipt of the decision.

9. Amendment/Relaxation/Repeal

Notwithstanding anything contained in the provisions under the scheme, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh at any time:

- Will be able to modify or cancel this scheme,
- Will be able to relax the implementation of the provisions of this scheme,
- Can issue instructions and guidance with a view to facilitate the implementation of the Scheme or to remove discrepancies and to interpret the provisions of the Scheme.

10. Jurisdiction

Any dispute, controversy, or claim arising out of or in connection with the MP Logistic Policy 2025, including any issues related to its interpretation, performance, or breach, shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts located in the state of Madhya Pradesh, India.

11. Annexure

Form1:

(indicative)

Application Format by investor for Assistance in Setting up Logistic Park/Multi Model Logistic Park and Logistics and Warehousing Infrastructure: Private Freight Terminal (PFT) /Gati Shakti Cargo Terminal (GCT), Container Freight Station (CFS) Air Freight Station (AFS) / Air Cargo Complex (ACC)

To,
The Managing Director,
MP Industrial Development Corporation
HO Bhopal
Madhya Pradesh.

Subject: Regarding providing assistance for setting up of logistic park/multi model logistic park / Logistics and Warehousing Infrastructure: Private Freight Terminal (PFT) /Gati Shakti Cargo Terminal (GCT)/ Container Freight Station (CFS)/ Air Freight Station (AFS) / Air Cargo Complex (ACC) under "Madhya Pradesh logistic Policy 2025".

I/We have proposed to establish a logistic infrastructure---------- in District ....., Madhya Pradesh. The detailed information for providing assistance under the "Madhya Pradesh logistic Scheme 2025" is as follows:

S. N	Details and Information	
1.	Name of the Agency/Institution/ investor	
2.	Proposal ID under Intention to invest and date	
3.	Contact Address: Telephone: E-mail:	
4.	Registered Office Address: Telephone: E-mail:	
5.	Full Address of the Site of the logistic Facility	
6.	Proposed area of the logistic facility / Land Area in acres/ Carpet Area (in sq. ft.)	
7.	Proposed Activity (Anyone): i.Multi Modal Logistics Park ii.Logistics Park iii.Inland Container Depot/Dry Ports iv.Private Freight Terminal (PFT)/Gati Shakti Cargo Terminal (GCT), v.Container Freight Station (CFS) vi.Air Freight Station (AFS) / Air Cargo Complex (ACC)	
8.	Proposed maximum occupancy of logistic facility (as applicable)	
9.	Name of Infrastructures proposed to be Established	
10.	Proposed Utility to be developed	

11.	Proposed date of Completion of Establishment/Development	
12.	Proposed expenditure in Logistic Infrastructure	
13.	Necessary Permissions Obtained as on date	

You are requested approve the assistance under the "Madhya Pradesh Logistic Scheme 2025".

Documents to be enclosed:

1. Project Report
2. Layout map and plan
3. Photocopy of permissions obtained, if any
4. Self-attested Copy of registered Lease Deed/Lease cum sale deed and /or land allotment letter
5. Other relevant documents

Declaration:

I/We hereby certify that the particulars given above and in the appended enclosures are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that no material facts have been concealed or suppressed.

Date: .....

Place: .....

Applicant/Authorized Signatory

Signature

Name: .....

Post: .....

Seal: .....

Form 2
(indicative)

Claim Form for investor Assistance in Setting up Logistic Park/Multi Model Logistic Park, Logistics and Warehousing Infrastructure: Private Freight Terminal (PFT) /Gati Shakti Cargo Terminal (GCT), Container Freight Station (CFS) and Air Freight Station (AFS) / Air Cargo Complex (ACC)

To,
The Managing Director,
MP Industrial Development Corporation
HO Bhopal
Madhya Pradesh.

Subject: Regarding providing assistance for established logistic park/multi model logistic park and Logistics Infrastructure, Private Freight Terminal (PFT) /Gati Shakti Cargo Terminal (GCT), Container Freight Station (CFS) Air Freight Station (AFS) / Air Cargo Complex (ACC) under "Madhya Pradesh Logistic Policy 2025".

I/We have established a ----------logistic Facility in District ....., Madhya Pradesh. The detailed information for providing assistance under the "Madhya Pradesh Logistic Scheme 2025" is as follows:

S.N	**Details and Information**	
1.	Name of the Agency/Institution/Investor	
2.	SLEC approval Date *(Intimation letter of SLEC to be enclosed)*	
3.	GST Number and Date *(copy to be enclosed)*	
4.	Proposal ID under Intention to invest and date *(copy to be enclosed)*	
5.	Established Activity (Anyone) I.Multi Modal Logistics Park II.Logistics Park III.Inland Container Depot/Dry Ports IV.Private Freight Terminal (PFT) /Gati Shakti Cargo Terminal (GCT), V.Container Freight Station (CFS) VI.Air Freight Station (AFS) / Air Cargo Complex (ACC)	
6.	Commencement of commercial operation date *(copy of CA/CE certificate to be enclosed for completion of infrastructure as defined in clause3.2 of this scheme)*	
7.	Authorized signatory: Name Telephone: E-mail: *(copy of board resolution for authorized signatory to be enclosed)*	

8.	Registered Office Address: Telephone: E-mail:	
9.	Full Address of the Site of the logistic Facility	
10.	Type of land	Govt /Private
11.	Area of the logistic Facility Land Area in acres/ Carpet Area (in sq. ft.)	
12.	Maximum total occupancy	
13.	Expenditure done in FCI *(Head wise expenditure certificate by CA and CE)*	
14.	Actual Expenditure in Stamp Duty and Registration charges for purchase of land (Enclose the land documents: lease deed / registration documents)	
15.	Expenditure in External Infrastructure Development a) Road b) Rail c) Power d) Drainage *(CA and CE expenditure certificate, map, and approved layout to be enclosed)*	
16.	Green logistic certification for Indian Green Building Council (IGBC) for Gold and Platinum certification (certificate to be enclosed)	
	1. IGBC Registration Number	
	2. Type of Certification Obtained	☐ Gold ☐ Platinum
	3. Date of Certification	___ / ___ / _____
	4. IGBC Certification Fee Paid (₹)	
17.	Necessary Permissions Obtained (copy to be enclosed)	

You are requested to approve the assistance under the "Madhya Pradesh Logistic Scheme 2025". Information regarding the agency's bank account, bank and branch name, and IFSC code is enclosed for incentive sanction and disbursement.

Documents to be enclosed:

1. Notarized affidavits and declarations as per prescribed format
2. Layout map and plan approved by the competent authority
3. Copy of permissions obtained, for operations
4. Work Completion certificate of the infrastructure developed as approved by SLEC.
5. The CA and CE certificate for FCI must include period of investment and details of the investment done in FCI as defined at 3.1 of this scheme
6. The Certificate/assessment by Chartered Engineer and Chartered Accountant certifying expenditure incurred in external infrastructure as defined in 6.1.4 & 6.2.2 of the scheme should include details of the infrastructure developed:

- Period of investment
- The distance and type of the approach road to the Logistic Facility gate from the main road and the name of the main road.
- Details of the power station supplying electricity, approval from the Madhya Pradesh Electricity Distribution Company, and verification of electrification completion.
- Distance from the main drainage/sewage infrastructure and necessary approvals for the establishment of sewage and drainage systems.
- Details of the rail integration lengths and nearest station or point of integration details, approval from the concerned Divisional Railway Manager (DRM) and other clearances.
- Connection details, and necessary approvals for the establishment of sewage and drainage systems.

7. For disbursement of 2nd and 3rd installment the investor must present an affidavit and copy of GST return certified by CA for verification of the operational status.

Declaration:

I/We hereby certify that the particulars given above and in the appended enclosures are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that no material facts have been concealed or suppressed.

Date: .....
Place: .....

Applicant/Authorized Signatory

Signature

Name: .....

Post: .....

Seal: .....

Form 3

(indicative)

Assistance for the Conversion of Agricultural Produce Warehouses to Industrial Warehouses.

S No	**Section A:** Applicant and Warehouse Details	Details
1.	Name of Applicant/Organization	
2.	Type of Entity	☐ Proprietorship ☐ Partnership ☐ Pvt Ltd ☐ LLP ☐ Other (Specify: _____)
3.	Registered Address	
4.	Contact Person Name	
5.	Designation	
6.	Phone/Mobile Number	
7.	Email ID	
8.	PAN Number	
9.	GST Number	
Section B: Warehouse and Conversion Details		Details
1.	Location of Warehouse	
2.	Registration No. with Competent Authority	
3.	Date of Original Registration as Agricultural Warehouse (*Registration Certificate as Agricultural Warehouse to be enclosed)*	___ / ___ / _____
4.	Capacity of warehouse	
5.	Date of Completion of Conversion Work (*Chartered Engineer's Completion Certificate to be enclosed*)	___ / ___ / _____
6.	Date of commencement of operation (enclose rent agreement or bill of first consignment of goods)	
7.	Converted Use (e.g. Industrial Storage, specify the goods that can be stored)	
Section C: Financial Details Component-Wise Cost Breakup		Amount (₹)
1.	Flooring	Amount (₹)
2.	Lighting & Electricals	

3.	IT Infrastructure	
4.	Civil Renovations	
5.	Safety & Security Systems	
6.	Other (Specify: _____)	
7.	Total Conversion Cost (*CA and CE expenditure certificate to be enclosed)*	

Documents to be enclosed:

1. Detailed Cost Sheet of Conversion Work
2. Pre-Conversion Photographs
3. Post-Conversion Photographs
4. CA certificates for investment, specifying investment period and breakup of major investments head wise as mentioned in 6.3.1
5. CE certificate for investment, specifying investment period and major investments head wise as mentioned in 6.3.1
6. Copies of Approvals from Regulatory Bodies

Declaration:
I/We hereby certify that the particulars given above and in the appended enclosures are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that no material facts have been concealed or suppressed.

Date: .....
Place: .....

Applicant/Authorized Signatory

Signature

Name: .....

Post: .....

Seal: .....

12. Affidavit

Under the Madhya Pradesh Logistic Scheme 2025
(On Non-Judicial Stamp Paper of value not less than ₹ 1000 and duly Notarized)

I/We, _____ s/o _____

Age: _____ Resident of _____
Promoter/Partner/Managing Director/Director of the firm _____ do hereby solemnly affirm and declare that:

1. I/We have submitted application under the "Madhya Pradesh Logistic Scheme 2025" for the unit _____ located at _____. The information provided is true to the best of my/our knowledge.
2. The developed logistic infrastructure is applicable for storage of non-agricultural produce and logistics operations only. The logistic infrastructure, operation/storage capacity is _____.
3. For establishing logistics/warehousing infrastructure, the expenditure incurred under the fixed capital investment is ₹ _____.
4. Under the conversion of Agriculture warehouse to Industrial warehouse the expenditure incurred under the fixed capital investment is ₹ _____. (if applicable)
5. The expenditure incurred for conversion of Agriculture warehouse to industrial warehouse are according to the provisions as mentioned in the MP Logistic Policy 2025(if applicable)
6. Amount of disbursed incentives received in the years prior to the claim year (year-wise) details:
   ₹ _____ received in years _____ (as applicable for each incentives year wise details).
7. The developed logistic infrastructure is new and of good quality.
8. I/We hereby pledge that if I/We violate any of the conditions/provisions mentioned in the above notification/rules, the department shall have full authority to cancel/withdraw the benefit as per the rules. Furthermore, I/We shall be responsible for repaying the benefit/assistance amount at an interest rate of 10% annually.
9. I/We will start logistics/warehousing infrastructure operational within 3 years from the date of approval/sanction or decided determined by SLEC and shall continue to be operational for a minimum period of 10 years from completion or from approval date.
10. In the event, the logistics/warehousing infrastructure does not remain operational as per MP Logistic Scheme 2025, the promoter shall be responsible for repaying the benefit/assistance amount.
11. Any entity declared insolvent or defaulter by the State and Central Government and their undertaking shall not be eligible for assistance under this Policy.

12. We have obtained all the necessary legal approvals, consents, and permissions required for establishing the logistics infrastructure.

Place:
Date:

Signature of MD/CFO/ Proprietor/Partner of Organization

Name: .....

Phone: .....

(Seal)

//Verification//

I, _____, do hereby solemnly affirm and declare that the information provided by me from points 01 to 12 is true, accurate, and complete to the best of my knowledge and belief. I further understand and acknowledge that in the event any part of the information is found to be false, misleading, or incorrect, I shall bear full responsibility and shall be liable for any consequences arising therefrom.

Place:

Date:

Signature of MD/CFO/ Proprietor/Partner of Organization

Name: .....

Phone: .....

भोपाल, दिनांक 1 मई 2025

क्रमांक एफ IPI–5–0029–2025 A–11.– प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्धेश्य से विभाग के आदेश दिनांक 24 फरवरी 2025 द्वारा जारी "मध्यप्रदेश एक्सपोर्ट नीति, 2025" अंतर्गत प्रावधानित सुविधा/सहायता उपलब्ध कराने एवं दिशा–निर्देश जारी करने हेतु राज्य शासन, एतदद्वारा संलग्नक अनुसार मध्यप्रदेश निर्यात प्रोत्साहन योजना 2025 जारी करता है.

2. यह योजना मध्यप्रदेश निर्यात संवर्धन नीति, 2025 के जारी होने के दिनांक 24 फरवरी 2025 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शाश्वत सिंह मीना, उपसचिव.

Government of Madhya Pradesh

MPIDC
MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

INVEST MADHYA PRADESH
— INFINITE POSSIBILITIES —

MADHYA PRADESH EXPORT PROMOTION SCHEME 2025

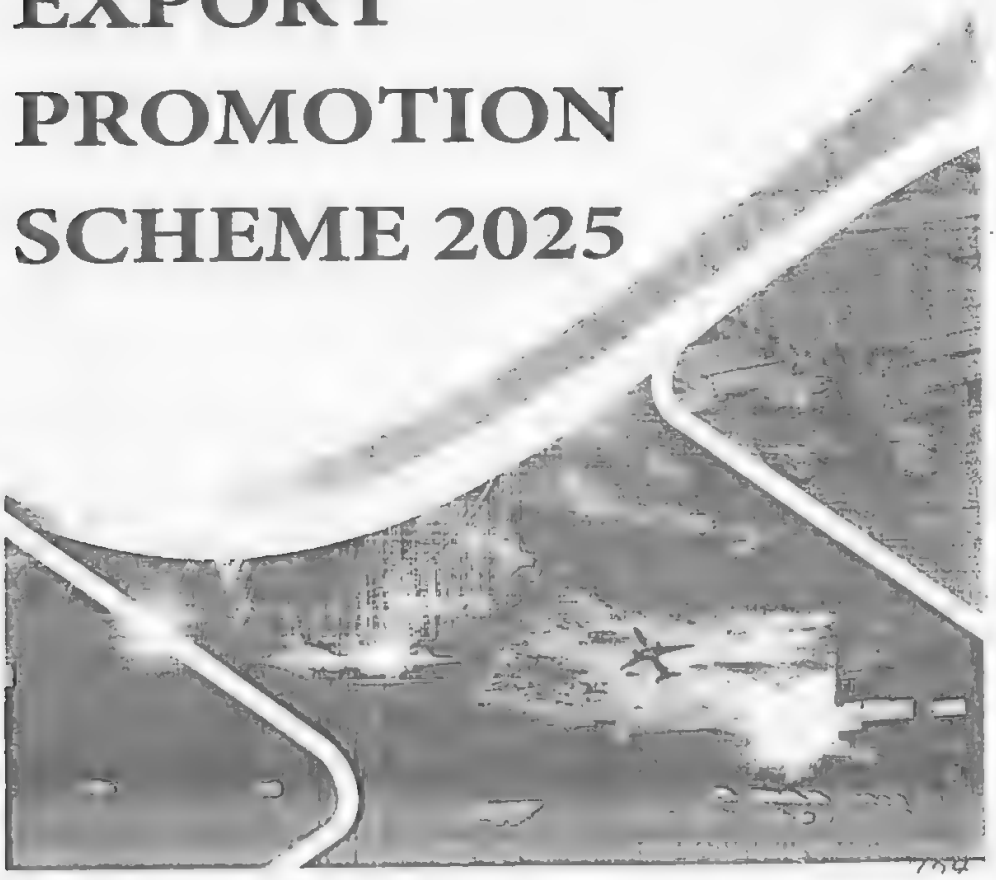

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION .....

2. PERIOD AND SCOPE OF EFFECTIVENESS OF THE SCHEME .....

3. DEFINITIONS .....

3.1. EXPORT .....

3.2. EXPORTER .....

3.3. FREE ON BOARD/ FREIGHT ON BOARD / FOB .....

3.4. GREEN CERTIFICATION .....

3.5. OTHER DEFINITIONS .....

4. ELIGIBILITY .....

5. APPLICATION PROCEDURE .....

5.1. For Eligibility determination .....

5.2. For Claims .....

6. FINANCIAL INCENTIVES .....

6.1. Assistance for First-Time Exporters (AFTE) .....

6.2. Export Multiple .....

6.3. Export Freight Assistance .....

6.4. Export Infrastructure Assistance .....

6.5. Export Turnover Incentive and Export Growth Accelerator Assistance .....

6.6. Export Marketing Assistance .....

6.7. Export Green Documentation Assistance .....

6.8. Export Financial Assistance .....

7. ASSISTANCE FOR DEVELOPERS OF DEDICATED EXPORT PARKS (DEP) .....

8. OTHER CONDITIONS .....

9. APPEAL .....

10. AMENDMENT/RELAXATION/REPEAL .....

11. JURISDICTION .....

12. FORMS (INDICATIVE) .....

FORM I: COMMON APPLICATION FORM FOR ELIGIBILITY DETERMINATION .....

FORM II: APPLICATION FORM FOR CLAIMING INCENTIVES .....

Form III: Application Format by Developer for Assistance for Setting up Dedicated Export Park .....

Form IV: Claim Form for Developer of Dedicated Export Park .....

Annexure 1: CA certificate for Value Addition in State and Minimum 25% Export.....

Annexure 2: CA certificate To Avail Incentives.....

Annexure 3: CA Certificate for Dedicated Export Parks .....

Annexure 4: Affidavit For Claim - Declaration/Undertaking (Mandatory).....

Annexure 5: Export Performance Details.....

ABBREVIATIONS

AFTE	Assistance for First Time Exporters
AGMARK	Agricultural Marketing Certification
BEE	Bureau of Energy Efficiency
BIPA	Basic Investment Promotion Assistance
BIS	Bureau of Indian Standards
BRAP	Business Reform Action Plan
CBAM	Carbon Border Adjustment Mechanism
CETP	Common Effluent Treatment Plant
CFC	Common Facility Centre
CSDDD	Corporate Sustainability Due Diligence Directive
DEP	Developers of Dedicated Export Parks
EFCI	Eligible Fixed Capital Investment
EM	Export Multiple
EODB	Ease of Doing Business
EU ETS	European Union Emission Trading System
EU	European Union
EV	Electric Vehicle
FDI	Foreign Direct Investment
FSSAI	Food Safety and Standards Authority of India
GoI	Government of India
GoMP	Government of Madhya Pradesh

ICD	Inland Container Depots
IPP 2025	Industrial Promotion Policy 2025
IPR	Intellectual Property Rights
IPS 2025	Investment Promotion Scheme 2025
ISO	International Organization for Standardization
MPERC	Madhya Pradesh Export Promotion Council
ONDC	Open Network for Digital Commerce
R&D	Research and Development
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals
RFID	Radio Frequency Identification
SECR	Streamlined Energy and Carbon Reporting
STP	Sewage Treatment Plant
ULIP	Unified Logistics Interface Platform
ZLD	Zero Liquid Discharge

1. INTRODUCTION

To enable effective implementation of the Export Promotion Policy 2025 notified on 24th Feb 2025, the government is introducing the Madhya Pradesh Export Promotion scheme 2025. The scheme outlines a comprehensive guideline to be followed by an exporter based out of Madhya Pradesh and intending to avail incentives under the Export Promotion Policy 2025.

By ensuring standardization, transparency, and clarity, it serves as a key reference for investors and the department, reinforcing Madhya Pradesh's commitment to becoming an export hub.

2. PERIOD AND SCOPE OF EFFECTIVENESS OF THE SCHEME

1. This scheme will remain in effect for the effective duration of the Madhya Pradesh Export Promotion Policy 2025.
2. This scheme outlines the benefits and assistances available over and above the provisions of Industrial Promotion Policy (IPP).

3. DEFINITIONS

3.1. EXPORT

As defined in Investment Promotion Scheme 2025

3.2. EXPORTER

For the purposes of the Export Promotion Policy 2025, exporter will be defined as any industrial unit holding a valid Import-Export Code (IEC) issued by DGFT, engaged in exporting goods.

3.3. FREE ON BOARD/ FREIGHT ON BOARD / FOB

FOB value of exports means the value of goods at the time of crossing the customs frontier of India, including all expenses up to the point of shipment (such as inland freight, port handling, packaging, and loading), but excluding ocean freight and insurance.

3.4. GREEN CERTIFICATION

Green Certification refers to the formal recognition by authorized bodies that a unit's operations, products, or services meet specific environmental standards aimed at reducing carbon emissions and promoting sustainability. Various international standards and certifications exist across regions such as Europe, the United States, and Japan, etc and can be eligible certifications for assistance under this policy.

3.5. OTHER DEFINITIONS

As applicable and defined in Investment Promotion Scheme 2025

4. ELIGIBILITY

1. The applicant must be a Large Scale/MSME unit as defined in Investment Promotion Scheme 2025/MSME Promotion Scheme 2025.
2. The manufacturing units commencing production after the notification of Madhya Pradesh Export Promotion Policy 2025, shall be eligible to avail benefits of this scheme.
3. The company must be registered with the Director General of Foreign Trade (DGFT) and possess a valid Import Export Code (IEC).
4. The exporter must possess an RCMC (Registration-Cum-Membership Certificate) issued by an Export Promotion Council, Commodity Board, or Development Authority recognized by DGFT.
5. Only direct exports shall qualify for incentives. Deemed exports (sales within India that are treated as exports) will not be eligible.
6. Manufacturing units that export at least 25% of their total production in the claim year shall only be eligible for incentives under this policy.
7. The exporting unit must not be a defaulter of State Government or Central Government and its undertakings.

5. APPLICATION PROCEDURE

5.1. FOR ELIGIBILITY DETERMINATION

i. To be eligible for claiming incentives under this policy, exporters must have an Intention to Invest number.

ii. Exporters seeking incentives under the Madhya Pradesh Export Promotion Policy 2025 shall submit the application within 180 days from the commencement of commercial production against the aforementioned intention to invest, online on INVEST portal (Ref Form I).

iii. In case of delay, the State Level Empowered Committee shall determine the eligibility as mentioned below:

   a) If application is received within 01 year and after 180 days from the date of commencement of commercial production, then on the merit of reason of delay either delay may be condoned OR deduction on pro-rate basis may be made in assistance amount.

   b) If application is received after 1 year and 180 days from date of commencement of commercial production, then on the merit of

reason of delay, the delay may be condoned OR deduction on pro-rate basis may be made in assistance amount or case may be rejected.

iv. The application must be accompanied by the necessary enclosures as specified, along with affidavits duly attested by a notary on stamp paper.

v. SLEC shall determine the eligibility of the unit for Export Promotion Policy and Export turnover incentive, Export growth accelerator assistance, and Export Freight Subsidy.

vi. After approval by the State Level Empowered Committee, the Secretary of the Committee shall issue an official order specifying the sanctioned incentives including rate, eligibility period of assistance, maximum limit of assistance, etc.

vii. A unit can apply for reconsideration of the case to the SLEC only once.

5.2. FOR CLAIMS

i. After eligibility determination by SLEC, the unit shall apply for claim online on the INVEST portal. (ref Form -II).

ii. The application must be accompanied by the necessary enclosures as specified in, along with affidavits duly attested by a notary on stamp paper.

iii. MD, MPIDC is empowered to sanction and disburse incentives as per the eligibility determined by SLEC.

iv. Incentives, i.e. Assistance for First-Time Exporters, Export Marketing Assistance, Export Green Documentation Assistance, Export Infrastructure Assistance, and Export Financial Assistance shall be approved, sanctioned and disbursed by MD MPIDC. However, these claims shall be processed only after the determination of eligibility under Export Promotion Policy 2025.

v. The sanctioned assistance amount shall be disbursed to the unit via e-payment.

vi. After the sanction of assistance amount, no interest will be payable in case of delay in disbursement.

6. FINANCIAL INCENTIVES

6.1. ASSISTANCE FOR FIRST-TIME EXPORTERS (AFTE)

i. First-time exporters based in Madhya Pradesh shall be eligible for this assistance to offset initial export-related costs.

ii. Unit shall be eligible to avail the assistance only once during the policy period.

iii. Assistance for Registration-cum-Membership Certification (RCMC) (Ref Form-II)

a. The State shall reimburse actual expenses incurred for obtaining the Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) including prescribed fees, documentation charges, legal charges, etc, excluding consultancy charges, subject to a maximum of ₹10 lakh per unit.

b. For availing this subsidy, the unit shall furnish CA certificate certifying the expenses incurred.

iv. Assistance for insurance premium (Ref Form - II)

a. The State shall also reimburse export insurance premium costs, up to a ceiling of ₹25 lakh per unit.

b. Units can combine the amount of multiple insurance premiums paid during the first twelve months after Commencement of Commercial Production.

v. The claim shall be submitted not later than 180 days after the end of the financial year. MD, MPIDC may condone the delay, if any.

6.2. EXPORT MULTIPLE

As per process outlined in Investment Promotion Scheme 2025.

6.3. EXPORT FREIGHT ASSISTANCE

As per process outlined in Investment Promotion Scheme 2025.

6.4. EXPORT INFRASTRUCTURE ASSISTANCE

i. A one-time capital subsidy of 25% on eligible investment made towards the creation of export-supporting infrastructure.

ii. The maximum subsidy available under this sub-scheme shall be ₹1 crore per unit.

iii. Eligible infrastructure components shall include but may not be limited to testing laboratories, research and development centres, quality control/ certification facilities, and export incubation centres.

iv. If the investment made in any infrastructure component i.e. testing laboratories, research and development centres, etc is included in EFCI under Investment Promotion Scheme 2025, the same shall not be eligible for incentives under this assistance.

v. For availing export infrastructure assistance, the units shall submit the claim within 24 months from the date of the commencement of commercial production along with the CA/ CE certificate. (Ref Form - II)

vi. MD, MPIDC may condone the delay in submitting the applications if valid reason is provided.

6.5. EXPORT TURNOVER INCENTIVE AND EXPORT GROWTH ACCELERATOR ASSISTANCE

1. The incentive shall be applicable on incremental export from the second year of export operations (i.e. 12 months after date of first export consignment) and shall be provided for a maximum period of five years.
2. The claim shall be submitted on the annual basis not later than 180 days after the end of every financial year during the eligibility period. MD, MPIDC may condone the delay.
3. For availing these incentives, the unit shall furnish CA certificate verifying the annual turnover, annual incremental FOB value of Exports, etc. (Ref Form - II)

i. Export Turnover Assistance

a. To reward sustained export growth, eligible units shall receive an incentive equivalent to 10% of the annual incremental Free on Board (FOB) value of exports.

b. The total assistance available under this sub-scheme shall not exceed ₹2 crore per unit for the entire scheme / policy period.

c. This assistance shall be maximum for 5 years.

ii. Export Growth Accelerator Assistance

a. The sectors eligible under this scheme shall include:

i. Footwear and accessories
ii. Gems and jewellery
iii. Toys and accessories
iv. Optical, medical, and surgical instruments
v. Plastics and rubber
vi. Furniture
vii. Electric vehicle components
viii. Advanced Chemistry Cell components

ix. Electronics
x. Drones
xi. White goods
xii. Capital goods

b. Eligible units shall receive an additional incentive of 5% on the annual incremental FOB value of exports.

c. The incentive shall be capped at ₹30 lakh per unit per annum.

d. This assistance shall be maximum for 5 years.

6.6. EXPORT MARKETING ASSISTANCE

i. The State shall reimburse 75% of expenses incurred by export units for participation in national and international trade fairs, exhibitions, and buyer-seller meets.

ii. The assistance can include Registration/ Participation Charges, Stall charges, transportation charges (upto 3 people) and any other relevant expenditure.

iii. The claim shall be submitted on the annual basis not later than 180 days after the end of every financial year during the eligibility period. MD, MPIDC may condone the delay.

iv. For availing this subsidy, the unit shall furnish CA certificate certifying the expenses incurred. (Ref Form - II)

v. The maximum assistance shall be limited to ₹5 lakh per unit per annum.

vi. Unit should apply to avail this assistance on an annual basis, for up to five years.

6.7. EXPORT GREEN DOCUMENTATION ASSISTANCE

i. The State shall reimburse up to 50% of expenses incurred by export units on documentation and certification for green and sustainable exports.

ii. The assistance shall be limited to ₹20 lakh per unit per annum and shall be available for a duration of five years.

iii. The claim shall be submitted on the annual basis not later than 180 days after the end of every financial year during the eligibility period. MD, MPIDC may condone the delay.

iv. Under the aforementioned financial limit or time limit, a unit can apply for reimbursement of expenses incurred for registering more than one certification/ documentation. Each unit shall be eligible to avail this assistance for multiple documentation as a single claim on an annual basis, for up to five years.

v. Eligible activities shall include certifications related to but not limited to green energy, energy efficiency, IGBC Gold/Platinum standards, and compliance with national and international environmental regulations such as EU ETS, CBAM, and Net-Zero frameworks. These certifications shall be issued by recognized / reputed national or international organisations/ institutions only.

vi. For availing this subsidy, the unit shall furnish CA certificate certifying the expenses incurred.

6.8. Export Financial Assistance

i. Exporting units shall be eligible for an interest subsidy of up to 5% on pre-shipment and post-shipment rupee export credit.

ii. The claim shall be submitted on the annual basis not later than 180 days after the end of every financial year during the eligibility period. MD, MPIDC may condone the delay.

iii. Unit must submit the Letter of Credit, Order copy, Commercial Invoice, Bank certificate for export credit sanctioned and disbursed, Repayment schedule, etc.

iv. Under the aforementioned financial limit or time limit, a unit can apply for reimbursement of expenses incurred for more than one shipment/ consignment. Each unit shall be eligible to avail this assistance for multiple shipments/ consignments as a single claim on an annual basis, for up to five years.

v. The total assistance under this sub-scheme shall not exceed ₹50 lakh per unit over a five-year period.

7. Assistance for Developers of Dedicated Export Parks (DEP)

1. The assistance for developing DEPs shall be applicable exclusively to private sector participants. Projects or ventures developed under the Public-Private Partnership (PPP) model shall be determined on case-to-case basis.

2. The Park developer shall submit the proposal for establishment of Dedicated Export Park along with Detailed Project Report and other necessary documents to MPIDC (Ref Form III). The eligibility shall be subject to the following conditions:

   a. Dedicated Export Parks (DEPs) shall be developed over a minimum area of 25 acres, with at least 70% of their occupants being export-oriented units (EOUs).

b. To qualify as an EOU, the company must have a proven track record of exporting more than 25% of their production over the last three financial years.

c. For new establishment to qualify as an EOU, the company must export more than 25% of their production atleast once in the first three (3) financial years. Unit shall submit a self-declaration on stamp paper for this purpose.

d. At least 20% of the allotted plots in the DEP shall be reserved for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

e. Each DEP shall include shared infrastructure and common facilities including but not limited to:

i. Utilities and logistics infrastructure

ii. Internal transportation systems

iii. Warehousing

iv. Common facilities for processing, sorting, packaging, labelling, and marking

v. Port and terminal infrastructure

vi. Custom clearance facilities

3. SLEC shall provide in Principle approval of the proposal and based on the proposal, broadly defining the following:

a. Timeline for the completion of the project.

b. Investment.

c. Infrastructure to be developed.

4. The timeline for the completion of the project as determined by SLEC can be extended twice for a period of 1 year each by MD, MPIDC based on merits.

5. If the developer fails to complete the project, despite the extension provided, the in-principle approval granted by SLEC shall stand cancelled.

6. The developer of the Dedicated Export Park can file an appeal within 180 days in SLEC against the cancellation of the approval of project.

7. SLEC shall be authorised to review the appeal and take decision on the basis of merits of the case.

8. The Dedicated Export Park developer shall submit the application in the prescribed format (Form IV) within 180 days of completion of the Export

Park along with the supporting documents to the Managing Director, MPIDC for sanctioning assistance.

9. The eligibility for the Assistance shall be determined by SLEC. The developer shall furnish work completion certificates, CA certificates and CE certificates for the investment in Dedicated Export Park.

10. The following fiscal incentives are available for the developers of Dedicated Export Parks:

a. Reimbursement of Stamp Duty and Registration Charges:

100% reimbursement of stamp duty and registration charges shall be provided on the purchase of land for setting up the DEP.

b. Fixed Capital Assistance for Infrastructure Development: Reimbursement of 50% of the fixed capital investment or ₹20 Lakh per acre on fixed infrastructure, whichever is lower, subject to a maximum of ₹40 Crores per project.

i. Fixed capital assistance shall exclude investment on land and infrastructure meant for dwelling units and common processing facilities and waste management systems.

ii. The assistance shall be released in two equal instalments of 50% each, on a milestone basis.

c. Assistance for Common Processing Facilities: Capital assistance of up to 25% shall be provided for the development of common processing, testing, quality assurance, and research and development (R&D) facilities. Such facilities may include, but are not limited to, infrastructure for sorting, packaging, labelling, and marketing, subject to a maximum assistance cap of ₹25 Crores. It shall be mandatory for the park developer to include a customs clearance facility in the park.

d. Green Industrialization Assistance:

i. A capital subsidy of 50%, up to a maximum of ₹5 Crores, shall be provided for the establishment of waste management systems such as Effluent Treatment Plants (ETPs), Sewage Treatment Plants (STPs), and other pollution control devices.

ii. An additional capital subsidy of 50%, up to a maximum of ₹10 Crores, shall be provided for setting up Zero Liquid Discharge (ZLD) systems.

11. For any further clarification/ information the provisions outlined in the Investment Promotion Scheme 2025 for Private Industrial Park shall be adhered to.

8. OTHER CONDITIONS

1. Incentives and financial assistance under this policy shall be applicable only to the manufacturing units or dedicated export park developer.
2. The incentives application shall be processed and disbursed by the respective departments/ nodal agency depending upon the category of industrial unit i.e. either Department of MSME or Department of Industrial Policy and Investment Promotion through its nodal agencies.
3. Exports must comply with the Foreign Trade Policy (FTP) of India and all regulatory norms.
4. Products restricted under India's negative export list or those under government embargo (under restricted or prohibited export items listed under DGFT's ITC (HS) classification) are not eligible.
5. The company shall submit a brief annual export report detailing shipments, revenue, and impact on employment. (Annexure – 5).
6. All the other Terms and Conditions outlined in Investment Promotion Scheme 2025 shall be met (if applicable).

9. APPEAL

An appeal against the decision of the State Level Empowered Committee can be made through MPIDC before the "Cabinet Committee on Investment Promotion" (CCIP) within three months from the date of receipt of the decision. The CCIP will be able to relax the delay in late appeals based on merits.

10. AMENDMENT/RELAXATION/REPEAL

Notwithstanding anything contained in the provisions under the scheme, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh at any time:

- Will be able to modify or cancel this scheme,
- Will be able to relax the implementation of the provisions of this scheme,
- Can issue instructions and guidance with a view to facilitate the implementation of the Scheme or to remove discrepancies and to interpret the provisions of the Scheme

11. JURISDICTION

Any dispute, controversy, or claim arising out of or in connection with the MP Export Promotion Policy 2025, including any issues related to its interpretation, performance, or breach, shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts located in the state of Madhya Pradesh, India.

12. FORMS (INDICATIVE)

These forms are in continuation to the forms outlined in Investment Promotion Scheme 2025.

FORM I: COMMON APPLICATION FORM FOR ELIGIBILITY DETERMINATION

Please fill all applicable/ relevant sections of Form 2 (Investment Promotion Scheme 2025) in addition to the information required below			
1	Import Export Code		
2	Date of obtaining Certification		
3	Registration-cum-Membership Certification (RCMC) ID		
4	Date of obtaining Certification		
5	Validity: Yes/ No		
6	Validity End Date		
7	Sector	i) Footwear and accessories, ii) Gems and Jewellery, iii) Toys and accessories, iv) Optical, photographic, medical and surgical instruments, v) Plastic and rubber, vi) Furniture, vii) EV Transport equipment, viii) ACC cell components, ix) Electronics, x) Drones, xi) White Goods, xii) Capital Goods xiii) Others, please specify ----------	
8	**Details of product (s) to be exported and capacity (IEM to be enclosed) (CA certificate as per Annexure 1, if applicable)**		
	Product (s) manufactured	Total annual capacity of each product manufactured	Value Addition in MP (Approximate value)
i			
ii			
iii			
iv			
v			
9	Certificate of Origin from Madhya Pradesh	Yes/ No	

This is to Certify that:

I / We hereby certify that the particulars given above and in the appended enclosures are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that no material facts have been concealed or suppressed.

Place:

Date:

Signature of authorized signatory:

Name:

Designation:

FORM II: APPLICATION FORM FOR CLAIMING INCENTIVES

Please fill all applicable/ relevant sections of Form 3 (Investment Promotion Scheme 2025) in addition to the information required below

i. Incentives under AFTE

Registration-cum-Membership Certification (RCMC)	
Registration ID	
Date of obtaining Certification	
Total expenditure incurred for obtaining the Certification i. RCMC Fees ii. Legal fees iii. Documentation Charges iv. Any other charges	
Amount claimed (₹)	
For Registration cum Membership Certification	
1. Copy of Certification received. 2. Invoice pertaining to application & processing of Certification application with proof of payment (Net Banking/NEFT/RTGS/DD/Cheque). 3. Any other document deemed relevant. 4 CA certificate certifying the expenses incurred	
Export Insurance Premiums	
Insurance Policy Number	
Date of obtaining Insurance	
Amount Insured (₹)	
Premium Paid (₹)	
Add details of multiple Insurance Premiums for first 12 months in separate Rows	
Documents to be submitted	
For Insurance of exports	
1. Copy of Insurance policy 2. CA certificate based on the invoice certifying the insurance premium paid 3. Any other document deemed relevant.	

ii. Incentives under Export Infrastructure Assistance

Export Infrastructure Assistance	
Description	Expenditure (In Crores)

Documents to be Attached:

a. Certificate/assessment by Chartered Engineer/Chartered Accountant certifying expenditure incurred in setting up of amenities (including item wise expenditure verification).
b. Attach a brief overview of the established Infrastructure developed.

iii. Export Turnover Incentive and Export Growth Accelerator Assistance

(i)	Name of the products exported		
	Details	**Quantity**	**Value (in ₹)**
(ii)	Annual Export of claim year (in case of expansion/diversification only for the expanded or diversified unit)		
(iii)	Free on Board (FOB) Value of previous year, Year.....		
(iv)	Free on Board (FOB) Value of current year, Year.....		

Documents to be Attached:

a. Certificate by Chartered Accountant certifying FOB value and Annual Exports as per Annexure 2.
b. Any other relevant document.

iv. Export Green Documentation Assistance

1	Details of Certification Applied for	
2	Certifying Agency	
3	Date of commercial production	
4	Date of Obtaining the Certification	
5	Period of Validity	
6	Type of Certification (Please ✓ the appropriate box)	Domestic ☐ International ☐
7	Fee Paid for the certification	
8	Amount Claimed	

Documents to be submitted:

a. CA certificate for Statement of expenditure
b. Copy of Certificate received
c. Invoice pertaining to application fee & processing fee of certification with proof of payment (Net Banking/NEFT/RTGS/DD/Cheque)
d. Any other document deemed relevant

v. Export Financial Assistance

1	Type of Credit	Pre-Shipment ☐ Post-Shipment ☐
2	Amount of Credit/ Loan	
3	Interest Charged by Bank	
4	Period of Credit	
5	Amount Claimed	

Documents to be submitted:

a. CA certificate for interest paid
b. Letter of Credit, Order copy, Commercial Invoice (as applicable)
c. Bank certificate for export credit sanctioned and disbursed (if available)
d. Repayment schedule (if applicable)
e. Any other document deemed relevant

Additional Documents to be enclosed:

i. CA certificate as per Annexure 1 for value addition and for certifying minimum 25% export of the total production.
ii. Any other document deemed relevant.

vi. Export Marketing Assistance

1.	Name and details of the event	
2.	Domestic or International	
3.	Date of the event participated	
4.	Expenditure incurred (head wise) for upto 3 people (in ₹)	

Documents to be Enclosed:

i. Certificate/assessment by Chartered Accountant certifying expenditure incurred in participating in the marketing event (including item wise expenditure verification).

ii. Attach a brief overview of the marketing event participated and its outcomes.

This is to Certify that:

I / We hereby certify that the particulars given above and in the appended enclosures are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that no material facts have been concealed or suppressed.

Place:

Date:

Signature of authorized signatory:

Name:

Designation:

FORM III: APPLICATION FORMAT BY DEVELOPER FOR ASSISTANCE FOR SETTING UP DEDICATED EXPORT PARK

To,
The Managing Director,
MP Industrial Development Corporation
HO Bhopal
Madhya Pradesh.

Subject: Regarding providing assistance for setting up of Dedicated Export Park under "Madhya Pradesh Export Promotion Policy 2025".

I/We have proposed to establish a Dedicated Export Park in District ....., Madhya Pradesh. The detailed information for providing assistance under the "Madhya Pradesh Export Promotion Scheme 2025" is as follows:

#	**Details and Information**	
1.	Name of the Agency/Institution/Developer	
2.	Proposal ID under Intention to invest and date	
3.	Contact Address: Telephone: E-mail:	
4.	Registered Office Address: Telephone: E-mail:	
5.	Full Address of the Site of the Dedicated Export Park	
6.	Proposed area of the Dedicated Export Park (in acres)	
7.	Proposed maximum occupancy of Dedicated Export Park	
8.	Name of Industries proposed to be Established (70% Export Oriented Units)	
9.	Proposed date of Completion of Establishment/Development (on milestone basis)	
10.	Proposed expenditure in Infrastructure Development	
11.	• Proposed expenditure in establishing waste management systems (such as Effluent Treatment Plant, Sewage Treatment Plant, pollution control devices, etc.) • Proposed Expenditure in establishing Zero Liquid Discharge facility	
12.	Details of Proposed Common Processing Facilities to be Established	
13.	Proposed Expenditure in establishing Common Processing Facilities as mentioned in point 12	
14.	Necessary Permissions Obtained as on date	

Documents to be enclosed:

i. Copy of GST registration certificate
ii. Copy of Proposal ID under intention to invest
iii. Copy of Board Resolution for authorized signatory
iv. Copy of Detailed Project Report
v. Land Related Documents
vi. Layout map and plan

This is to Certify that:

I / We hereby certify that the particulars given above and in the appended enclosures are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that no material facts have been concealed or suppressed.

Place:
Date:

Signature of authorized signatory:
Name:
Designation:

FORM IV: CLAIM FORM FOR DEVELOPER OF DEDICATED EXPORT PARK

To,
The Managing Director,
MP Industrial Development Corporation
HO Bhopal
Madhya Pradesh.

Subject: Regarding providing assistance for setting up of Dedicated Export Park under "Madhya Pradesh Export Promotion Policy 2025".

I/We have established a Dedicated Export Park in District ....., Madhya Pradesh. The detailed information for providing assistance under the "Madhya Pradesh Export Promotion Scheme 2025" is as follows:

1.	Name of the Agency/Institution/Developer	
2.	SLEC approval Date	
3.	GST Number and Date	
4.	Proposal ID under Intention to invest and date	
5.	Commencement of commercial operation date	
6.	Authorized signatory: Name Telephone: E-mail:	
7.	Registered Office Address: Telephone: E-mail:	
8.	Full Address of the Site of the Park	
9.	Type of land	Govt /Private
10.	Area of the Park (in acres)	
11.	Maximum total occupancy	
12.	Current occupancy as on date of application	
13.	Name of current occupants:	
14.	Actual Expenditure in Stamp Duty and Registration charges for purchase of land	
15.	Expenditure in Infrastructure Development i. Internal Road development ii. Internal Power Infrastructure iii. Internal Water Infrastructure iv. Internal Drainage Infrastructure v. Internal Gas Pipeline vi. Compound Walls vii. Any other please specify	
16.	• Expenditure in establishing waste management systems (such as Effluent Treatment Plant, Sewage Treatment Plant, pollution control devices, etc.).	

	• Expenditure in establishing Zero Liquid Discharge facility	
17.	Details of Common Processing Facilities Established	
18.	Expenditure in establishing Common Processing Facilities as mentioned in point 17	
19.	Necessary Permissions Obtained	

Documents to be enclosed:

1. Intimation letter of SLEC
2. Copy of GST registration certificate
3. Copy of Proposal ID under intention to invest
4. CE certificate for completion of infrastructure
5. Copy of Board Resolution for authorized signatory
6. Land Related Documents
7. Certificate/assessment by Chartered Engineer and Chartered Accountant certifying expenditure incurred in setting up of amenities (including section wise expenditure verification and investment start and completion dates), Ref Annexure 3.
8. Consent to Establish and Consent to Operate issued by the MPPCB
9. Certificate from Pollution Control Board in respect of the establishment and operation of respective amenities.
10. Layout map and plan approved by the competent authority
11. Work Completion certificate issued by Contractor/any other competent authority, for the infrastructure developed as approved by SLEC.
12. Milestone Certificate as per Form 8 of Investment Promotion Scheme 2025
13. Copy of cancelled cheque

This is to Certify that:

I / We hereby certify that the particulars given above and in the appended enclosures are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that no material facts have been concealed or suppressed.

Place:

Date:

Signature of authorized signatory:

Name:

Designation:

Annexure 1: CA CERTIFICATE FOR VALUE ADDITION IN STATE AND MINIMUM 25% EXPORT

CHARTERED ACCOUNTANTS CERTIFICATE

This is to certify that M/s ....., having its registered office at ....., is applying for claiming incentives under Exports Promotion Scheme under new unit/Expansion/ Diversification for the claim year .....

Amount in ₹

Details of product (s)				
Product (s) manufactured	Total annual capacity of each product manufactured	Export Quantity	Export Value	Value Addition in MP (Approximate value)

The above details have been verified from the books of accounts, GST returns (GSTR-1 & GSTR-3B), financial statements, and relevant supporting documents of M/s..... [Unit Name].

This certificate is issued based on the documents and information submitted by the entity and is true and correct to the best of our knowledge and belief.

Name.....
Signature & Seal.....
Membership No .....

Place:
Date:

Note: Above details should be certified by the Chartered Accountant on his letter head only.

Annexure 2: CA CERTIFICATE TO AVAIL INCENTIVES

(Export Turnover Assistance and Export Growth Accelerator Assistance)

CHARTERED ACCOUNTANTS CERTIFICATE

This is to certify that M/s ....., having its registered office at ....., is applying for claiming Exports Turnover Assistance under new unit/Expansion/ Diversification for the claim year .....

OR / AND

This is to certify that M/s ....., having its registered office at ....., operating in ..... sector (*Footwear and accessories, Gems and Jewellery, Toys and accessories, Optical, photographic, medical and surgical instruments, Plastic and rubber, Furniture, EV Transport equipment, ACC cell components, Electronics, Drones, White Goods, Capital Goods*) is applying for claiming Exports Growth Accelerator Assistance under new unit/Expansion/ Diversification for the claim year .....

The unit has the exports & Free on Board (FOB) value details as mentioned below:

Amount in ₹

1.	Name of the products exported		
	Details	**Quantity**	**Value (in ₹)**
2.	Annual Export of claim year (in case of expansion/diversification only for the expanded or diversified unit)		
3.	Total Production in claim year		
4.	Free on Board (FOB) Value of previous year, Year.....		
5.	Free on Board (FOB) Value of current year, Year.....		

The above details have been verified from the books of accounts, GST returns (GSTR-1 & GSTR-3B), financial statements, and relevant supporting documents of M/s..... [Unit Name].

This certificate is issued based on the documents and information submitted by the entity and is true and correct to the best of our knowledge and belief.

Name.....

Signature & Seal.....

Membership No .....

Place:

Date:

Note: Above details should be certified by the Chartered Accountant on his letter head only.

Annexure 3: CA CERTIFICATE FOR DEDICATED EXPORT PARKS

(Certificate for DEP Assistance)

We hereby certify that ..... having its unit at..... operating in the .....have made the following fixed capital investment during the period of Investment from..... To.....

S. No.	Fixed Capital Investment	Fixed Capital Investment Amount (in ₹)
1	**For Export Park**	
2	**Cost of development of infrastructure**	
	Internal Road and Approach Road	
	Internal Power Infrastructure	
	Internal Water Infrastructure	
	Sewage & drainage network	
	Internal Gas Pipeline	
	Others, please specify	
3	**Cost of development of Common Processing Facilities**	
	Testing facilities	
	R&D facilities	
	Custom Clearances Related Facility (Mandatory)	
	Logistics Facilities	
	Transportation Infrastructure	
	Warehouses	
	Common Processing, Sorting, Packaging, Labelling	
	Port and Terminal Facilities	
	Other common facilities (please mention)	
4	**Green Industrialization facilities (ETP, STP, ZLD)**	
	ETP/STP	
	ZLD	
	Others, please specify	

Annexure 4: AFFIDAVIT FOR CLAIM - DECLARATION/UNDERTAKING (MANDATORY)

(On Non-Judicial Stamp Paper of ₹ 1000)

I/We, _____, S/o, D/o, W/o _____, residing at _____, in my/our capacity as the authorized representative of M/s _____, having registered office at _____, do hereby solemnly affirm and declare as follows:

1. I/We have applied for assistance under the Madhya Pradesh Export Promotion Policy 2025 to _____ and affirm that the information provided in the application dated _____ is true and correct to the best of my/our knowledge and belief.
2. I/We hereby certify that the entity _____for whom the application has been made have not been penalized under any of the following Acts (as amended from time to time):
    - The Customs Act, 1962,
    - The Central Excise Act1944,
    - Foreign Trade (Development & Regulation) Act1992,
    - The Foreign Exchange Management Act, 1999; and
    - The Conservation of Foreign Exchange, Prevention of Smuggling Activities Act, 1974
    - GST Acts
3. I/We am/are not a declared defaulter or insolvent by the State Government/ Central Government or any of its undertakings.
4. None of the Directors/Partners/ Proprietor/Karta/Trustees of the company/firm/HUF/Trust, (as the case may be), is/are a Director(s)/Partner(s)/ Proprietor/Karta/ Trustee in any other Company/ firm / entity which is on the Denied Entity List (DEL) of DGFT.
5. I/We undertake to abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended from time to time, the Rules and Orders framed there under the Foreign Trade Policy and the Handbook of Procedures
6. I hereby declare that exports made on re-export basis and deemed exports have not been included and also any exports with disclaimer has not been counted as per status holder provisions detailed in Foreign Trade Policy.
7. I hereby declare that only such exports has been taken into account for seeking recognition, which has been realized by me in our bank account directly from overseas.
8. The developed industrial infrastructure has been built for the Dedicated Export Park mentioned in the application is of ₹..... and is of good quality. (If applicable)

9. The established waste management system/systems of ₹..... have been developed for the unit mentioned in the application and comply with the prescribed standards. (If applicable)
10. The established Common Facility Centres ..... of ₹..... have been developed for the unit mentioned in the application and comply with the prescribed standards. (If applicable)
11. The assistance received for Development of Dedicated Export Park is of ₹..... till date and is of good quality. (If applicable)

12. That I/We affirm the receipt of the following incentives as per the prescribed norms:

    a. Under Assistance for First-Time Exporters (AFTE) the claim for Registration-cum-Membership Certification is_____ against which has received ₹_____ and the claim for export insurance premium is ₹_____ against which has received ₹_____.
    b. With respect to Export Infrastructure Assistance has received one-time subsidy of ₹_____ on export infrastructure (testing labs, R&D centres, export incubation centres, etc) investment, up to ₹1 Crore.
    c. Under Export Turnover Assistance has received ₹_____on annual incremental Free Onboard (FOB) value, till date.
    d. Under Growth Accelerator Assistance for sector _____ has received ₹_____ as additional assistance on annual incremental Free Onboard (FOB) value, till date.
    e. Under Export Marketing Assistance has claimed ₹_____and received ₹_____reimbursement till date.
    f. Under Export Green Documentation Assistance has received ₹_____till date.
    g. Has claimed ₹_____as subsidy on bank interest rates on pre and post-shipment and received ₹_____reimbursement till date.

13. Has received ₹_____ as subsidy/ assistance/ reimbursement from _____ Department/ Nodal Agency, Government of Madhya Pradesh under the _____ Policy/ Scheme as on _____.

14. I/We declare that I/we have received total assistance of ₹..... from Government of India under the .....(policy/ scheme) as on .....(Date).

15. I/We fully understand that under the Industrial Promotion Policy – 2025, under clause 10.1.4 'in no case shall the investment assistance or any other assistance under this policy exceed the fixed capital investment made by the investor'.

16. I/We undertake to utilize the incentive amount claimed strictly for the purpose mentioned in the application and will not misuse the released amount for any benefits not prescribed under the policy.

17. I/We hereby pledge that if I/We violate any of the conditions/provisions mentioned in the above notification/rules, the department shall have full authority to cancel/withdraw the benefit as per the rules. Furthermore, I/We shall be responsible for repaying the benefit/assistance amount at an interest rate of 10%.

18. That I/We will keep the unit operational during the assistance period and for at least three years thereafter.

19. That in the event the unit does not remain operational as per regulations, I/We shall be responsible for repaying the benefit/assistance amount.

20. That we have obtained all necessary legal approvals, consents, and permits required for establishing the industry.

21. That I/We acknowledge that non-compliance with any of the above conditions may lead to legal action, recovery of the assistance amount, and disqualification from future incentives under the policy.

Place:

Date:

Signature of MD/ CFO/Proprietor/
Partner Of Organization
Name .....
Designation.....

Verification

I, above deponent hereby state and verify that the contents of this affidavit are true to my personal knowledge and belief, and nothing has been concealed. In case of any concealment and misrepresentation of facts mentioned above I shall be solely responsible for that and shall ensure to return the sanctioned assistance with penal interest compounded annually @ 10% per annum.

Place:

Date:

Signature of MD/ CFO/Proprietor/
Partner of Organization
Name .....
Designation.....

Annexure 5: EXPORT PERFORMANCE DETAILS

11(a): Year on year export details

Statement of Exports / Deemed Exports / Foreign Exchange Earned

Type of Exports in USD (FOB / FOR value / Foreign Exchange Earned)	Current Year in USD (Specify Period)	Previous Year 1 in USD	Previous Year 2 in USD	Previous Year 3 in USD
1. Exports of goods without Weightage				
2. Exports of services without Weightage				
3. Exports with Double Weightage				
4. FOR value converted in USD for Deemed Exports under FTP				
5. Exports Value converted in USD for receipts in ₹ under para 2.53 of FTP				

6. Exports of SEZs / EOUs / EHTPs /STPs/ BTPs units, if clubbing is sought				
7. Total (in USD)				

Note 1: A shipment / service transaction can be included only once in one of the categories eligible for double weightage. Note 2: If the exports are in any other currency other than USD like Euro, ₹ etc, these shall be converted to USD on the date of realization as per rate notified by customs for export purposes.

11(B): Export Product details

Details of exports of Top 5 Merchandise HS lines and Top 5 service exports (if any) in the last financial year:

Sl no.	HS Code as per ITC HS (AT 6 DIGIT LEVEL)
1	
2	
3	
4	
5	
	% age of Top 5 items in total merchandise exports of last financial year - ..... %

For information dissemination on DGFT Portal of List of Status Holders, the following details are to be provided by all Star Export Houses:

5. Brief Description of the Business (in 100 word):
6. Link of the Website:
7. Email ID for Business Enquires:
8. Number of employees as on 31st March of Last Financial year:

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2025

क्र. बी-1876–दो–2–63–2024.– श्री एम.व्ही.आर.बालाजी शर्मा, डी.आर.–कम–पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 24 से 30 अप्रैल 2025 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम.व्ही.आर.बालाजी शर्मा, डी.आर.–कम–पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.व्ही.आर.बालाजी शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डी.आर.–कम–पी.पी.एस., के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (एन).

जबलपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2025

क्र. ए-2321–तीन–10–40–78–(भाग–8).– मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक बी–5762–तीन–10–47–98(भाग–6), दिनांक 29 नवम्बर, 2022 जो, मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 23 दिसम्बर 2022 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है. उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 37 सिविल जिला सागर तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:–

सारणी

अनु. क्र.	सिविल जिले का नाम	जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय	
		स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37.	सागर	सागर	8	सागर	6*	सागर	10
		खुरई	3	खुरई	2	खुरई	3
		रेहली	2	रेहली	1	रेहली	1
		बण्डा	2	बण्डा	3	बण्डा	1
		बीना	2	बीना	1	बीना	2
		देवरी	2	देवरी	1	देवरी	1
				मालथौन	1	गढ़ाकोटा	1
						शाहगढ़	1
						केसली	1

No. A-2321-III-10-40-78-VIII.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (No.19 of 1958) and the previous Notification No. B-5762-III-10-47/98-VI, dated 29th November, 2022, issued by High Court, which was published in the Madhya Pradesh Gazette dated 23rd December 2022, the following amendment is made. In the said notification, in the table, for the serial number 37 Civil District Sagar the following entries are substituted namely:-

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Court of District Judges		Court of Civil Judges Senior Division		Court of Civil Judges Junior Division	
		Place	Number of Courts	Place	Number of Courts	Place	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37.	Sagar	Sagar	8	Sagar	6*	Sagar	10
		Khurai	3	Khurai	2	Khurai	3
		Rehli	2	Rehli	1	Rehli	1
		Banda	2	Banda	3	Banda	1
		Bina	2	Bina	1	Bina	2
		Deori	2	Deori	1	Deori	1
				Malthone	1	Garhakota	1
						Shahgarh	1
						Kesli	1

जबलपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2025

क्र. बी-1915–तीन–10–42–75.– एतद्द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित न्यायाधीशगण, अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-1915-III-10-42-75.- The Judges named in the Column No. (3) of the following Table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No. (2) of the Table in addition to his place of posting for the period mentioned in column No. (4) for holding Link Court :-

TABLE

S. No.	Place, where Link Court is to be held (District)	Name of the Officer and designation	Period in a month for which Link Court is to be held
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	**Nepanagar** (Burhanpur)	Shri Ravi Verma, I[st] Civil Judge Junior Division, Burhanpur	One Week
2.	**Mandhata** (Khandwa)	Shri Mehtab Singh Baghel, Civil Judge Senior Division, Punasa	10 Days
3.	**Rahatgarh** (Sagar)	Shri Himanshu Paliwal, X[th] Civil Judge Junior Division, Sagar	15 Days
4.	**Jaitpur** (Shahdol)	Shri Laxman Rohit, II[nd] Civil Judge Junior Division, Burhar	15 Days

क्र.–बी-1917–तीन–10–42–75 (खुरई–मालथौन).– उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक बी–5417–तीन–10–42–75, दिनांक 3 दिसम्बर 2024, जहां तक कि उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश संवर्ग की श्रंखला न्यायालय, मालथौन (जिला सागर) से है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. खुरई–मालथौन श्रंखला न्यायालय की बैठक एतद्द्वारा समाप्त की जाती है.

No. B-1917-III-10-42-75-Khurai-Malthone:- High Court Notification No. B-5417-III-10-42-75, dated 3rd December 2024, so far as it relates to holding Link Court of Civil Judge Cadre at Malthone (District Sagar) is hereby stands cancelled. The sitting of Khurai-Malthone Link Court is hereby discountinued.

माननीय न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

मुकेश रावत, रजिस्ट्रार (डिस्ट्रिक्ट इसटब्लिशमेंट).

जबलपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2025

क्र. बी-2043–दो–2–55–2017.– सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 15 से 17 अप्रैल 2025 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 अप्रैल 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 से 20 अप्रैल 2025 तक, के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. सी-3097–दो–2–13–2014.– श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 15 से 17 अप्रैल 2025 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 अप्रैल 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 से 20 अप्रैल 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशांत हुद्दार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3100–दो–2–27–2024.– श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय

अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 15 से 16 अप्रैल 2025 तक, दो दिन का क़म्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती वर्षा शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-3102–दो–2–43–2020.– श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 13 से 15 मई 2025 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सोहाने, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3104–दो–2–5–2023.– श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 28 अप्रैल से 2 मई 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 अप्रैल 2025 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 एवं 4 मई 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3106–दो–2–57–2024.– श्री सुधीर कुमार चौधरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हरदा को दिनांक 15 से 17 अप्रैल 2025 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 अप्रैल 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 से 20 अप्रैल 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार चौधरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुधीर कुमार चौधरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (एम).

जबलपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2025

क्र. B-1890–दो–2–7–2019.– श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 21 से 24 अप्रैल 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 20 अप्रैल 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2025

क्र. C-3000–दो–3–420–80–भाग–बारह.– श्री दिनेश नायक, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2017 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी–3096, दिनांक 22 जुलाई 2017 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय, रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक–643/2015 ऑल इण्डिया जजेस एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.

क्र. C-2998–दो–3–420–80–भाग–बारह.– श्री दिनेश नायक, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा क्रमांक 1127–इक्कीस–ब (एक)–2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक–643–2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6(1) की कण्डिका क्रमांक–(i)(ii) एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक–सी–3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार– श्री दिनेश नायक की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2017 को उनके खाते में 204 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 214 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान : 204 दिवस

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान : 192 (192/2=96 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन).

क्र. C-3002–दो–2–13–2010.– श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर को दिनांक 7 से 12 अप्रैल 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 अप्रैल 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 अप्रैल 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3004–दो–2–33–2024.– श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 21 से 22 अप्रैल 2025 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 20 अप्रैल 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3006–दो–2–59–2015.– श्री राजदीप सिंह ठाकुर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:–

1. दिनांक 1 से 3 अप्रैल 2025 तक, तीन दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.

2. दिनांक 1 से 5 अप्रैल 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 अप्रैल 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजदीप सिंह ठाकुर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजदीप सिंह ठाकुर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3008–दो–2–23–2020.– श्री काशीनाथ सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:–

1. दिनांक 17 से 26 मार्च 2025 तक, दस दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

2. दिनांक 21 से 24 मार्च 2025 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति, गुजरात ज्युडिशियल अकादमी द्वारा आयोजित दिनांक 22 से 23 मार्च 2025 को दो दिवसीय "West Zone-I Regional Conference on Court Dockets: Explosion and Exclusion (P-1445)" में शामिल होने अहमदाबाद (गुजरात) जाने हेतु प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एम.व्ही.आर.बालाजी शर्मा, डी.आर–कम–पी.पी.एस.